

# भारत का विधान

मंत्री हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी

48, बाई का बाग इलाहाबाद

पहली बार 3000 ] सन् 1950 ई० [ कीमत सात रुपए आठ आने

मुद्रक—

श्री अशर्फी राय शर्मा  
अशोक प्रेस, महेन्द्र, पटना .

## पहली बात

छब्बीस नवम्बर सन् 1949 को विधान सभा ने भारत के विधान को अपना कर भारत की दफ्तरी भाषा के सबाल का फैसला कर दिया और देश भर ने शान्ति का सांस लिया। भारत की दफ्तरी भाषा (official language) का नाम हिन्दी रखा गया। वह हिन्दी क्या होगी इसकी तकसील दफा 343 और 351 में खोल कर दी गई। वह दोनों दफा यह हैं :—

“343—(1)यूनियन की दफ्तरी भाषा देवनागरी लिखावट में हिन्दी होगी।

“यूनियन के दफ्तरी मतलबों के लिये हिन्दुओं का जो रूप काम में लाया जायगा वह हिन्दुस्तानी, हिन्दुओं का अन्तरक्रौमी रूप होगा।

x x x x x”

“351—यूनियन का फर्ज होगा कि हिन्दी भाषा के फैलाव को बढ़ाए, और उसका इस तरह विकास करे कि वह भारत की मिली जुली कलचर के सब अंगों को जाहिर करने का साधन बन सके, और, उसकी आत्मा को छेड़े बिना, जो जो रूप, जो शैली और जो मुहावरे हिन्दुस्तानी में और आठवीं पट्टी में दर्ज भारत की दूसरी भाषाओं में काम में आते हैं उनको उसमें रचा पचा कर, और, जहां कहीं जरूरी या चाहनी हो, उसकी शब्दावली के लिये पहले संस्कृत से और फिर दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर, उसे माला-माला करे।”

आठवीं पट्टी में दर्ज भाषाएं यह हैं:—1. आसामी, 2. बंगला, 3. गुजराती, 4. हिन्दी, 5. कन्नड़, 6. कश्मीरी, 7. मलयालम, 8. मराठी, 9. उड़िया, 10. पंजाबी, 11. संस्कृत, 12. तमिल, 13. तेलगू, 14. उर्दू।

इस तरह जिस हिन्दी को विधान में व्याख्या की गई है उसमें और उस भाषा में कोई फरक नहीं रह जाता जो भारत के बहुत बड़े भाग की

जनबोली है, जो पेशावर से आसाम तक और हिमालय से रासकुमारी तक बोली या समझी जाती है, और जिसे देसी और बिदेसी दोनों ने सैकड़ों बरस पहले हिन्दुस्तान की बोली जानकर हिन्दुस्तानी नाम दिया था. यही एक ऐसी भाशा रही है जो सच्चे मानी में भारत की मिलीजुली कलचर के सब अंगों को जाहिर करती है और अपनी आत्मा को नुकसान पहुँचाए बिना भारत की दूसरी भाशाओं के ही नहीं बाहर की भाशाओं के भी शब्द, शैलियाँ और मुहाविरों को अपने अन्दर समा कर अपने आपको मालामाल करने की सकत रखती है. हमारे देश की इसी भाशा को विधान ने हिन्दी नाम दिया है. जिन लोगों को भारत की इस मिलीजुली कलचर से प्रेम है और जो भारत को एक शक्तिशाली और गठा हुआ देश बनाना चाहते हैं उन्होंने विधान की इस दफा का खुले दिल से स्वागत किया. पर विधान का जो हिन्दी अनुवाद सरकार की तरफ से निकला है वह न तो विधान की ऊपर लिखी दफाओं को निभाता मालूम होता है और न बहुत से पत्रकारों और समझदारों की नज़र चढ़ पाया है. जनता को उसके समझ में न आने की शिकायत तो है ही. उस अनुवाद की आत्मा हिन्दी है यह कहना कठिन है. फिर हिन्दुस्तानी या किसी दूसरी देसी भाशा के रूप, शैली और मुहाविरों उसमें कैसे निभते. गुजराती, कन्नड़, उर्दू वगैरा में से किसी एक दो के इक्का दुक्का शब्द लेकर विधान की दफा के अक्षर भले ही निभाए गए हों रुढ़ नहीं निभाई गई. अनुवाद करने वालों ने संस्कृत का इतना अधिक सहारा लिया है कि बेचारी हिन्दी तो दब कर रह गई.

संसार की भाशाओं के इतिहास से पता चलता है कि जब तक कोई भाशा किसी प्राचीन भाशा की शब्दावली के बोझ से दबी रहती है तब तक वह कभी तरक्की नहीं कर पाती. मिसाल के लिये जब तक अंगरेज़ी भाशा लातीनी, यूनानी जैसी पुरानी भाशाओं के बोझ से दबी रही, वह तरक्की न कर सकी. जब शेक्सपियर और उसके साथियों ने उस पर से इन भाशाओं का जुआ उतार फेंका उसके बाद ही अंगरेज़ी भाशा ऐसी फली फूली कि आज संसार की भाशाओं में उसका नाम सबसे आगे लिया जाता है. अब अगर अंगरेज़ी



### तीन

भाषा के सब चालू शब्दों को निकाल कर उनकी जगह लातीनी और यूनानी के शब्द भर दिये जाय और उनके रूप भी लातीनी और यूनानी के व्याकरण के अनुसार बनाए जाय तो अंगरेजी भाषा का क्या हाल होगा यह हम सहज ही में समझ सकते हैं. सरकार की ओर से निकले हिन्दी अनुवाद की भाषा कुछ ऐसी ही हो गई है. 'मिलावट' की जगह 'अपमिश्रण', 'गोद लेना' की जगह 'दत्तकग्रहण', 'कम करना' की जगह 'अल्पीकरण', 'दिवाला' (Insolvency) की जगह 'शोधाक्षमता', 'इकहरे बदलते वोट' (Single transferable vote) की जगह 'एकल संक्रमणीय मत', 'परची' (Ballot) की जगह 'शक्ताका', 'बुढ़ापा पेनशन' (Old age pension) की जगह 'वार्धक्य निवृत्ति वेतन', 'साख' (Credit) की जगह 'आकलन', 'बेवसीयती' (Intestacy) की जगह 'इच्छापत्रहीनत्व', 'वधार लेना' की जगह 'वध्वारग्रहण', 'किया माना गया' की जगह 'कर्तुमभिप्रेत', 'जुआ' की जगह 'घूँत', 'तखमीन' (Estimate) की जगह 'प्राक्कलन', 'इस काम से' की जगह 'एतद्द्वारा', 'मिलीजुली कलचर' (Composite culture) की जगह 'सामाजिक (?) संस्कृति', इसी तरह के सैकड़ों नहीं हजारों शब्द इस अनुवाद में भरे पड़े हैं.

इससे हिन्दी की हमें कोई भलाई होती दिखाई नहीं देती. इस तरह की भाषा भारत की मिली जुली कलचर को तो किसी भी तरह जाहिर नहीं करती. वह न कहीं बोली जाती है और न देश के किसी भाग की भाषा है. उसे समझने में तो क्या पढ़ने में भी कष्ट होता है. फिर उसमें हिन्दी हिन्दुस्तानी की रवानी और उसके मुहावरे आ ही कैसे सकते हैं.

अंगरेजी मूल को ही देखिये कि उसे शुरू से आखिर तक पढ़ जाइये और शायद एक बार भी आपको किसी शब्द के माने समझने के लिये कोश का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और इस अनुवाद को देखिये कि बिना अंगरेजी मूल को देखे और पग पग पर उसकी शब्दावली का सहारा लिये इसका समझना लगभग असम्भव है.

जनता की जरूरत और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तानी कलचर सोसाइटी ने यह मुनासिब समझा कि हमारे

विधान का एक ऐसा अनुवाद तैयार किया जाय जिसकी भाषा वही हो जो विधान की दफा 343 और 351 में बताई गई है, जिसमें अंगरेजी मूल का अर्थ व्यों का त्यों आ जाय और जिसे देश की जनता पढ़ सके और समझ सके.

हमारे अनुवाद करने वालों ने भाषा की सरलता और मुहाबिरे का तो ध्यान रखा ही है उनकी यह भी कोशिश रही है कि अंगरेजी मूल का हर शब्द और हर वाक्य जिन मानों में आया है ठीक वही माने अनुवाद में भी आ जाय. इसके लिये यह जरूरी नहीं कि एक अंगरेजी शब्द के लिये हर जगह एक ही हिन्दी का शब्द रखा जाय. शब्दों के ठीक ठीक माने प्रसंग से ही जाने जाते हैं. अंगरेजी मूल में कई जगह एक एक शब्द कई कई अर्थों में आया है. हिन्दी में उसका एक ही शब्द से अर्थ करने में अर्थ का अनर्थ हो सकता था. इसलिये अनुवाद करने वालों ने कहीं कहीं एक अंगरेजी शब्द के लिये, जहां जैसा जंचा, एक से अधिक हिन्दी शब्द रखे हैं, जैसे—‘public service’ में पबलिक का अर्थ ‘सरकारी’ है तो ‘public welfare’ में पबलिक का अर्थ ‘जनता की’, ‘civil court’ में ‘civil’ का अर्थ ‘दीवानी’ है तो ‘civil service’ में ‘civil’ का अर्थ ‘नागरी’ है, ‘adopt’ का अर्थ कहीं ‘गोद लेना’ है तो कहीं ‘अपनाना’, ‘constitution’ का अर्थ कहीं ‘विधान’ है तो कहीं ‘बनाबट’. फिर भी अनुवादकों ने यह कोशिश की है कि जहां तक हो सके एक अंगरेजी शब्द के लिये एक ही हिन्दी शब्द आवे .

इंडिया का अनुवाद ‘भारत’ और ‘हिन्द’ दोनों किया गया है. इस विधान के आरंभ होने से पहले वाले ‘इंडिया’ को अनुवादकों ने ‘हिन्द’ कहा है, और जहां कहीं इंडिया का मतलब उस पूरे देश से है जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल थे वहां भी इंडिया का अर्थ ‘हिन्द’ किया गया है. और सब जगह ‘भारत’ अर्थ किया गया है.

गवरनर शब्द का अर्थ ‘रियासतपति’ किया गया है, पर विधान के आरंभ होने से पहले के सूबों के गबरनरों को गवरनर ही कहा गया है.

## पांच

विधान के भाग पांच और भाग छै की बहुत सी दफाएँ मिलती जुलती हैं. अनुवाद में इन दोनों भागों की जवाबी दफाओं का जहां तक ठीक समझा गया एक सा अनुवाद किया गया, पर भाग छै की कुछ दफाओं के अनुवाद की वाक्य रचना में कहीं कहीं अन्तर भी है क्योंकि शुरु के फार्म छप जाने के बाद अनुवादकों को बाद की वाक्य रचना ज्यादा अच्छी मालूम हुई. इससे मतलब में जरा भी फरक नहीं पड़ा है. इसी तरह की एक दो मिसालें और भी हैं.

जहां तक हो सका अनुवाद करने वालों ने उन शब्दों से काम लिया है जो उत्तर भारत में आम तौर पर बोले और समझे जाते हैं. दूसरी प्रांतीय भाशाओं के भी चालू शब्द जहां तहां लिये गए हैं. यूनानी, अंगरेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ़ारसी, अरबी जैसी भाशाओं के जो शब्द हिन्दी में चल पड़े हैं और देश के कोने कोने में समझे जाते हैं, उनसे भी इस अनुवाद में काम लिया गया है.

आज अंगरेजी भाशा संसार की सब भाशाओं से आगे है. उसका मूल कारन यही है कि अंगरेजी लेखक संसार की लगभग सभी भाशाओं से शब्द लेकर अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में कभी नहीं हिचके. अंगरेजी भाशा का मूल आधार पुरानी जर्मैनिक भाशा का एक अंग पुरानी सेक्सन भाशा है, पर आजकल की अंगरेजी के तीन चौथाई से भी अधिक शब्द दूसरी भाशाओं से लिये हुए हैं, जिनमें अरबी, तुर्की, चीनी, जापानी, हिन्दुस्तानी और अफ्रीकी भाशाएँ भी शामिल हैं. अंगरेजी में हिन्दुस्तानी से लिये शब्दों की गिनती अब हज़ारों में होती है और इन शब्दों को सिर्फ़ आम बोल चाल की भाशा में ही नहीं क़ानूनी भाशा तक में जगह मिल गई है. इन शब्दों को अंगरेजी ने अपने अन्दर पूरी तरह पचा लिया है. हिन्दी में भी यह पाचन शक्ति हमेशा से थी और है. आज हमें इस पाचन शक्ति को कायम रखना और बढ़ाना है. पड़ौसी प्रान्तों की भाशाओं से तो बहुत कुछ हिन्दी ने लिया ही है इसे दक्खिन की भाशाओं से भी अभी बहुत कुछ लेना है. और जैसे जैसे नए भारत का संसार के दूसरे देशों से मेल जोल

बढ़ता जायगा वैसे वैसे चीनी, जापानी, बर्मी, श्यामी, हिन्दीचीनी, इन्डोनेशी आदि भाशाओं के शब्द भंडार भी हिन्दी के लिये खुल जायंगे और हिन्दी के लेखकों को जहां तक भी हो सके उनसे लाभ उठाने की कोशिश करनी होगी. हिन्दी का जो विशाल भवन तैयार हो रहा है उसके दरवाजे हमें बन्द नहीं खोल कर रखने होंगे जिससे उसमें हमेशा ताज़ा हवा आती रहे.

शब्दों के चुनने में अनुवाद करने वालों ने एक और सिद्धान्त का भी ध्यान रखा है. एक ही माने रखने वाले अलग अलग मूल के दो शब्द कभी कभी अलग अलग मानों में इस्तेमाल होने लगते हैं. इससे भाशा की शक्ति बढ़ती है. हिन्दी में भी एक ही अर्थ रखने वाले अलग अलग मूल के अनेक शब्द हैं. उन्हें विशेष मानों में लगाना अब हमारा काम है. अनुवाद करने वालों ने इस तरह के कुछ शब्दों को अलग अलग मानी में बरता है, जैसे :— Rule—नियम; Regulation—क्रायदा; Article—दफा; Clause—धारा; Minister—बखीर; Secretary—मंत्री; Road—सड़क; Way—मार्ग.

हिन्दी का धातु भंडार अथाह है. पर शब्द भंडार अभी इतना बढ़ा नहीं है कि आजकल के सब विचारों और पदार्थों के लिये काफी हो. इसलिये नए शब्द बनाना भी जरूरी हो जाता है. इसके लिये संस्कृत, अरबी, लातीनी, यूनानी जैसी प्राचीन भाशाओं से तत्सम शब्द ले लेना या उनके व्याकरण की मदद से बना लेना सहज है पर यह वही मार्ग है जिसे हम 'कन्ने काटना' (escapism) कहते हैं. किसी भी जीती जागती भाशा के लिये यह विनाश का मार्ग है. जहां जरूरत हो वहां हम संस्कृत से और दूसरी भाशाओं से भी शब्द ले सकते हैं पर जो शब्द हम बनाएँ वह हमारे मुहाविरे और हमारे व्याकरण के अनुकूल होने चाहिएं. अनुवाद करने वालों ने इसी सिद्धान्त पर कुछ नए शब्द बनाए हैं, जैसे :—Adjustment—बैठबिठाव; Successor—पदगाही; International—अन्तर-क्रौमी; Corporation—एकतनी; Entry—अन्तरी; Contingency—जोगाजोग; Import—आयासी; Export—निकासी; Appointment—नियोजन.

कुछ पुरानी ध्वनियां जैसे व्य, य्, ष व्रजभाषा आदि में और खड़ी बोली में क्रम से अनुस्वार, नकार और 'श', 'स' या 'ख' की ध्वनियों में बदल गई हैं और बदलती जा रही हैं. जब हिन्दी की खड़ी बोली में संस्कृत तत्सम शब्दों की बाढ़ आई तभी से यह ध्वनियां संस्कृत तत्सम शब्दों के रास्ते हिन्दी में फिर रख दी गईं, पर अब भी हम इनको आम बोल चाल में नहीं बोलते. 'कञ्चन' को 'कंचन', 'कारण' को 'कारन', रोष को 'रोश', 'विष' को 'बिष' और 'वर्षा' को 'बरखा' कहते ही हैं. इसीलिये अनुवादकों ने इन ध्वनियों को नहीं रखा. उन्होंने इनका चालू रूप अपनाया है. इससे शब्दों के बोलने में मदद मिलती है और लिखावट भी काफ़ी सरल हो जाती है.

हमारी पहल बात कुछ लम्बी हो गई पर यह सब इसलिये लिखा गया है कि भाषा के संबंध में तरह तरह के विचार लोगों में फैल रहे हैं. हिन्दी एक भाषा है और उन सबकी है जो उसे बोलते हैं. इस भाषा को ऐसा रूप नहीं देना चाहिये कि फिर वह इने गिने आदमियों की ही चीज रह जाय. यह भाषा सैकड़ों बरस से भारत के बड़े भाग की भाषा रही है और अब यह सारे देश की अन्तर-रियासती भाषा है या होने जा रही है. विधान की दफा 351 में इस भाषा के सम्बन्ध में हमें वह बीज नज़र आते हैं जिनको अगर सचाई से और ठीक ठीक पानी मिलता रहा तो भारत की सूबाई और फिरकावारी गुटबन्दी मिट कर भारत के लोग सच्चे मानों में एक 'नेशन' का रूप ले सकेंगे. बोली जिस तरह आदमी आदमी को पास लाती है उसी तरह आदमी आदमी को दूर भी कर सकती है. जाने अनजाने मुहत्तों से जगह जगह यह रीत चली आई है कि हुकूमत और पंडित लोग कुछ और बोली बोलते हैं और जनता कुछ और. इस तरह बोली के दो रूप हो जाते हैं. हुकूमत और पंडित तो जनता की बोली समझते हैं पर जनता उनकी बहुत कम बात समझ पाती हैं. हो सकता है यह ढंग उस समय काम देता हो जब देशों की बागडोर राजाओं और रईसों के हाथ में हुआ करती थी और विद्या पर पंडितों का इजारा था. अब

## आठ

जब कि हुक्मत की बागडोर कानूनी रूप से जनता के हाथ में मान ली गई है तब सरकार और जनता की दो अलग अलग बोलियों का होना बेजा और बड़ी ख़तरनाक बात है. जनता की बोली में ही हमारा अधिक से अधिक काम होना चाहिये. जनता का दिया विधान भी जनता की बोली में ही होना चाहिये. सरकार का सारा काम भी जहां तक हो सके उसी बोली में किया जाना चाहिये. विधान की दफ़ा 351 इसी सचार्ई को ध्यान में रख कर बनाई गई है.

अगर हिन्दी को सचमुच केवल दफ़्तरी भाशा से बढ़ते बढ़ते क्रौमी और अन्तरक्रौमी भाशा बनना है और फलना फूलना है और संसार की बड़ी बड़ी भाशाओं में अपना स्थान लेना है तो इसको खुली हवा में पनपना होगा, दूसरी देशी और विदेशी भाशाओं के साथ अपना मेलजोल बढ़ाना होगा और बिना हिचक नये शब्द, नए वाक्य और नए मुहाविरे अपने ढंग पर ढाल कर अपने अन्दर समाने होंगे. यही इसकी तरक्की का रास्ता है, यही कल्याण का मार्ग.

हम मानते हैं कि हमारे इस अनुवाद में भी सुधार की गुंजाइश है. भाशा के संबंध में विधान सभा ने विधान के अन्दर जो कुछ तय किया है उसके अनुसार हिन्दी को अभी बढ़ना और रूप लेना है. उसके दरवाजे अभी पूरी तरह खुले रखे गए हैं. अभी उसकी न कोई शैली आखिरी शैली है और न कोई शब्दावली आखिरी शब्दावली है. आगे के लिये यही एक उम्मीद का रास्ता है. इसीलिये हम विधान के इस अनुवाद को सरकार और जनता के सामने रख रहे हैं ताकि इसे पढ़कर देश के बहुत से लोग अपने विधान को समझ सकें और हमारे अनुवाद करनेवालों की यह छोटी सी कोशिश हिन्दी को कानूनी और क्रौमी रूप देने और बढ़ाने में सरकार और जनता दोनों को थोड़ी बहुत मदद दे सके.

40-A, हनुमान रोड,  
नई दिल्ली.  
15 अगस्त, 1950.

सुंदरलाल  
मंत्री हिन्दुस्तानी कल्लर सोसाइटी



### पढ़ने वालों से

सफा 34, दफा 78 में “बड़े वज़ीर” की जगह “प्रधान वज़ीर” पढ़िये. सफा 52, दफा 112 (3) (सी) में “बड़े खाते का खर्च” की जगह “करजा चुकाई कोश खर्च” पढ़िये. मुक़्त भर देखभाल के बाद भी अगर कहीं छापे, आदि की भूलें रह गई हों तो सुधार लेने की कृपा करें.



# भारत का विधान

## ब्योरा

सरलेख	सफा
	1

### भाग एक

#### यूनियन और उसका भूभाग

#### दफा

1	यूनियन का नाम और भूभाग	...	2
2	नई रियासतों को दाखिल करना या क़ायम करना	...	2
3	नई रियासतों का बनाना और मौजूदा रियासतों के छेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलना	...	2—3
4	दफा 2 और 3 के अधीन बने क़ानूनों में पहली और चौथी पट्टी के सुधार के लिए और पूरक, प्रसंगी और परिनामो मामलों के लिये बंधान	...	3

### भाग दो

#### नागरता -

5	विधान के आरम्भ होने पर नागरता	...	4
6	कुछ ऐसे लोगों के नागरता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में आ बसे हैं	...	4—5
7	पाकिस्तान में जा बसने वाले कुछ लोगों के नागरता के अधिकार	...	5
8	भारत के बाहर बसने वाले हिन्दी निकास के कुछ लोगों के नागरता के अधिकार	...	5
9	अपनी मरज़ी से किसी विदेशी राज की नागरता हासिल करने वाले लोगों का नागरता होना	...	6
10	नागरता के अधिकारों का जारी रहना	...	6

दफा	सफा
11 राजपंचायत का कानून बना कर न्याय के अधिकार की कायदाबन्दी करना ...	6

### भाग तीन

#### मूल अधिकार

##### आम

12 परिभाषा ...	7
13 मूल अधिकारों से मेल न खाने वाले या उनको कम करने वाले कानून ...	7

##### बराबरी का अधिकार

14 कानून के सामने बराबरी ...	7—8
15 धर्म, नसल, जात, जिनस या जन्मस्थान की बिना पर भेद भाव की मनाही ...	8
16 सरकारी कामगारी के मामलों में बराबरी के मौके ...	8—9
17 अछूतपन का अन्त ...	9
18 खिताबों का अन्त ...	9

##### आज़ादी का अधिकार

19 बोलने वगैरा की आज़ादी के बारे में कुछ अधिकारों की रक्षा ...	9—11
20 जुर्मों का दोशी ठहराए जाने के बारे में रक्षा ...	11
21 जान और निजी स्वतंत्रता की रक्षा ...	11
22 कुछ सूत्रों में गिरफ्तारी और नज़रबन्दी से रक्षा ...	11—13

##### शोशन के खिलाफ अधिकार

23 इनसानों के व्यापार और जबरी मजदूरी की मनाही ...	13
24 फ़ैक्टरियों वगैरा में बच्चों को काम पर लगाने की मनाही ...	13

##### धार्मिक आज़ादी का अधिकार

25 अन्तरात्मा को आज़ादी और किसी धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी ...	14
26 धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की आज़ादी ...	14

दक्ष	सफा
27 किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिये टैक्स देने के बारे में आज्ञादी ...	15
28 कुछ तालीमी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा-बन्दगी में हाज़िरी के बारे में आज्ञादी ...	15
<i>कलचरी और तालीमी अधिकार</i>	
29 कमीयनों के हितों की रक्षा ...	15
30 कमीयनों को तालीमी संस्थाएँ क्रायम करने और उनके प्रबन्ध करने का अधिकार ...	15—16
<i>जायदाद का अधिकार</i>	
31 जायदाद का जबरन हासिल करना ...	16—17
<i>विधानी उपायों का अधिकार</i>	
32 इस भाग में दिये अधिकारों पर अमल कराने के लिये उपाय ...	17—18
33 इस भाग में दिये अधिकारों के फ़ौजों के लिये लागू होने पर उनमें अदल बदल करने की राजपंचायत की शक्ति ...	18
34 जब किसी क्षेत्र में फौजी क़ानून लागू हो तो इस भाग में दिये अधिकारों पर रुकावट ...	18
35 इस भाग के बन्धानों को अमल में लाने के लिये क़ानून बनाना ...	18—19

### भाग चार

#### *राज की नीति के निर्देशक सिद्धान्त*

36 परिभाषा ...	20
37 इस भाग में आए सिद्धान्तों को लागू करना ...	20
38 लोगों की खुशहाली बढ़ाने के लिये राज का एक समाजी व्यवस्था को पक्का करना ...	20
39 नीति के कुछ सिद्धान्त जिन पर राज चलेगा ...	20—21
40 गाँव-पंचायतों का संगठन ...	21
41 काम, तालीम और कुछ सूरतों में सरकारी मदद पाने का अधिकार ...	21

दफ़ा	सफ़ा
42 काम की हालतों में न्याय और इन्सानियन का और जापा मदद का प्रबन्ध ...	21
43 कामगारों के लिये पेट भर मज़दूरी वगैरा ...	21
44 नागरों के लिये एक सी दीवानी पद्धत ...	21
45 बच्चों के लिये मुपन और जबरी तालीम का प्रबन्ध ...	21
46 पट्टी-दर्ज जातियों, पट्टी-दर्ज कबीलों और दूसरी निबल टुकड़ियों के तालीमी और आर्थिक हितों को बढ़ाना ...	21
47 तनपालन-तल और जीवनस्तर को ऊँचा करना और जन-तन्दुरुस्ती को सुधारना राज का फ़रज़ ...	22
48 खेती बाड़ी और पशु-पालन का संगठन ...	22
49 क़ौमी महत्व की यादगारों और जगहों और चीज़ों की रक्षा ...	22
50 काजकारी से न्यायकारी का अलग करना ...	22
51 अन्तर-क़ौमी शान्ति और सुरक्षा को बढ़ाना ...	22

## भाग पाँच

### यूनियन

#### खंड एक—काजकारी

#### राजपति और उप-राजपति

52 भारत का राजपति ...	23
53 यूनियन की काजकारी शक्ति ...	23
54 राजपति का चुनाव ...	23
55 राजपति के चुनाव का ढंग ...	23—24
56 राजपति की पद-भियाद ...	24—25
57 फिर चुनाव के लिये पात्रता ...	25
58 राजपति चुने जाने के लिये जोगताएँ ...	25
59 राजपति के पद की शर्तें ...	25—26
60 राजपति का हलफ़ उठाना या वचन भरना ...	26
61 राजपति पर दोष लगाने का दस्तूर ...	26—27

दफ़ा	सफ़ा
62 राजपति के पद की सूती को भरने के लिए चुनाव का समय और औसरी सूती भरने के लिये चुने आदमी की पद-भियाद ...	27
63 भारत का उप-राजपति ...	27
64 उप-राजपति पदनाते रियासत सदन का मसनदी होगा ...	27
65 राजपति की ना-भौजूदगी में या उसके पद की औसरी सूनियों के समय उप-राजपति का राजपति की जगह काम करना या उसके पद के काम निभारना ..	28
66 उप-राजपति का चुनाव ...	28—29
67 उप-राजपति की पद-भियाद ...	29
68 उप-राजपति के पद की सूती को भरने के लिये चुनाव का समय और औसरी सूती भरने के लिये चुने आदमी की पद-भियाद ...	29—30
69 उप-राजपति का इलफ़ उठाना या वचन भरना ...	30
70 दूसरे जोगाजोगों में राजपति के कामों को निभारना ...	30
71 राजपति या उप-राजपति के चुनाव के बारे में या उससे संबंध रखने वाले मामले ...	30
72 कुछ सूतों में माफ़ी वगैरा देने और सज़ाओं के हुकुम को रोके रखने या कम करने या बदलने की राजपति को शक्ति ..	31
73 यूनियन की काजकारी शक्ति का फैलाव ...	31—32
<b>वज़ीर मंडल</b>	
74 राजपति को सहायता और सलाह देने के लिये वज़ीर मंडल ...	32
75 वज़ीरों के बारे में दूसरे बन्धान ...	32—33
<b>भारत का सरमुखतार</b>	
76 भारत का सरमुखतार ...	33
<b>सरकारी काम का संचालन</b>	
77 भारत सरकार के काम का संचालन ..	33—34

दृष्टा	संका
78 राजपति को सूचना देने वगैरा के बारे में प्रधान वज़ीर के फ़रज़ ...	34
<b>खंड दो—राजपंचायत</b>	
<b>आम</b>	
79 राजपंचायत की बनावट ..	34
80 रियासत सदन की रचना ...	34—35
81 लोकसदन की रचना ..	35—36
82 भाग (सी) की रियासतों के और रियासतों को छोड़कर दूसरे भूभागों के प्रतिनिधान के बारे में खास बन्धान ...	36
83 राजपंचायत के सदनों की मुद्दत ...	36
84 राजपंचायत की मेम्बरी के लिये जोगता ...	37
85 राजपंचायत के इजलास, उसे बरखास्त करना और भंग करना ...	37
86 राजपति को सदनों में सर-बचन देने और संदेसे भेजने का अधिकार ...	37
87 हर इजलास के आरम्भ में राजपति का खास सर-बचन .	38
88 सदनों के बारे में वज़ीरों और सरमुखतार के अधिकार ...	38
<b>राजपंचायत के अफ़सर</b>	
89 रियासत सदन का मसनदी और उप-मसनदी ...	38
90 उप-मसनदी का पद सूना होना, उसका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना ...	38—39
91 उप-मसनदी को या किसी दूसरे आदमी को मसनदी के पद के फ़रज़ पूरे करने या मसनदी की जगह काम करने की शक्ति ...	39
92 मसनदी या उप-मसनदी उस समय सदारत नहीं करेगा जब कि उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो ...	39—40
93 लोक सदन का सभामुख और उप-सभामुख ...	40
94 सभामुख और उप-सभामुख का पद सूना होना, उनका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना ...	40

दफ़ा	सफ़ा
95 उप-सभामुख या किसी दूसरे आदमी को सभामुख के पद के फ़रज़ पूरा करने या सभामुख की जगह काम करने की शक्ति ...	40—41
96 सभामुख या उप-सभामुख सदारत नहीं करेगा जब कि उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो ...	41
97 मसनदी और उप-मसनदी और सभामुख और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते ...	41
98 राजपंचायत की मंत्रायत ...	41—42

#### काम का संचालन

99	मेम्बरों का हलफ़ उठाना या वचन भरना ...	42
100	सदनों में वोट लेना, सूनियाँ होने पर भी सदनों को काम करने की शक्ति, और कोरम ...	42—43

#### मेम्बरों की अजोगताएँ

101	सीटों का सूना होना ...	43—44
102	मेम्बरी के लिये अजोगताएँ ...	44
103	मेम्बरों की अजोगताओं के बारे में सवाल्लों पर फ़ैसला ...	44
104	दफ़ा 99 के अधीन हलफ़ उठाने या वचन भरने से पहले या जोग न होने या अजोग ठहराए जाने पर बैठने और वोट देने पर दंड ...	45

#### राजपंचायत और उसके मेम्बरों की शक्तियाँ, उनके

#### निजनियम और उनकी बरीयतें

105	राजपंचायत के सदनों की और उनके मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियाँ, निजनियम वगैरा ...	45—46
106	मेम्बरों की तनखाहें और भत्ते ...	46

#### क़ानूनकारी दस्तूर

107	बिल रखने और पास करने के बारे में बन्धान ...	46
108	कुछ सूतों में दोनों सदनों की मिछीजुली बैठक ...	46—48
109	नक़दी बिलों के बारे में ख़ास दस्तूर ...	48—49

दफ़ा	सफ़ा
110 “नक्रदी बिल” की परिभाषा	... 49—50
111 बिलों पर मंजूरी	... 50—51
<i>माली मामलों में दस्तूर</i>	
112 सालाना माली ब्योरा	... 51—52
113 तख्मीनों के बारे में राजपंचायत का दस्तूर	... 53
114 मद्-बटबारा बिल	... 53—54
115 पूरक, सहायक या अधिक देनगियां	... 54
116 हिसाब पर वोट, साख की वोट और अलग देनगियां	... 55
117 माली बिलों के बारे में खास बन्धान	... 56
<i>आम दस्तूर</i>	
118 दस्तूर के नियम	... 56—57
119 माली काम के सम्बन्ध में राजपंचायत के दस्तूर की क़ानून से क़ायदाबन्दी	... 57
120 राजपंचायत में काम में आने वाली भाषा	... 57—58
121 राजपंचायत में बहस पर रुकावट	... 58
122 राजपंचायत की कारवाई के बारे में अदालतें पूछताछ नहीं करेंगी	... 58
<i>खंड तीन—राजपति की क़ानूनकारी शक्तियां</i>	
123 राजपंचायत की छुट्टी के दिनों में राजपति को राजहुकुम जारी करने की शक्ति	... 58—59
<i>खंड चार—यूनियन की न्यायिकारी</i>	
124 आला अदालत का क़ायम होना और उसकी बनावट	... 59—60
125 जजों की तनखाहें वगैरा	... 61
126 कारकर सरजज का नियोजन	... 61
127 ज़रूरती जजों का नियोजन	... 61—62
128 आला अदालत की बैठकों में सेवामुक्त जजों का आना	... 62
129 आला अदालत एक नज़ीरी अदालत होगी	... 62
130 आला अदालत के बैठने की जगह	... 62
131 आला अदालत को पहली सुनवाई का अधिकार	... 63



दफ़ा	सफ़ा
132 कुछ सूत्रों में आला अदालत को हाईकोर्टों की अपीलें सुनने की अपीली अमलदारी ...	63—64
133 दीवानी मामलों के बारे में हाईकोर्टों की अपीलें सुनने की आला अदालत की अपीली अमलदारी ..	64—65
134 फ़ौजदारी मामलों के बारे में आला अदालत की अपीली अमलदारी ...	65—66
135 मौजूदा क़ानून के अधीन संघ अदालत की अमलदारी और शक्तियों से आला अदालत का काम ले सकना ...	66
136 आला अदालत का अपील की खास इजाज़त देना ...	66
137 आला अदालत की फ़ैसलों या हुकुमों पर नज़रसानी ...	66
138 आला अदालत की अमलदारी को बढ़ाना ...	66—67
139 आला अदालत को कुछ परवाने जारी करने की शक्तियाँ सौंपना ...	67
140 आला अदालत की सहायक शक्तियाँ ...	67
141 आला अदालत जो क़ानून ठहरा दे उस से सब अदालतें बंधी होंगी ...	67
142 आला अदालत को डिगरियों और हुकुमों पर अमल, और खोज वगैरा के बारे में हुकुम ...	67—68
143 राजपति को आला अदालत से राय लेने की शक्ति ..	68
144 दीवानी और न्यायकारी अधिकारियों का आला-अदालत की मदद के लिये काम करना	68
145 अदालत के नियम वगैरा ...	68—70
146 आला अदालत के अफसर और नौकर और खर्च ...	70—71
147 अर्थ ...	71

#### खंड पांच—भारत का दाब अफसर और सर पड़तालिया

148 भारत का दाब अफसर और सर पड़तालिया ....	71—72
149 दाब अफसर और सर पड़तालिया के फरज और शक्तियाँ...	73
150 दाब अफसर और सर पड़तालिया को हिसाब किताब के सम्बन्ध में निर्देश देने की शक्ति ...	73

दफ़ा	सफ़ा
151 पड़ताल की रिपोर्टें	73

### भाग छै

पहली पट्टी के भाग (ए) की रियासतें

खंड एक—ग्राम

152 परिभाषा	74
-------------	----

खंड दो—काजकारी

रियासतपति

153 रियासतों के रियासतपति	74
154 रियासत की काजकारी शक्ति	74
155 रियासतपति का नियोजन	74
156 रियासतपति की पद-सिंयाद	74—75
157 रियासतपति नियोजे जाने के लिये जोगनाएं	75
158 रियासतपति के पद की शर्तें	75
159 रियासतपति का हलफ़ उठाना या वचन भरना	75—76
160 कुछ जोगाजोगों में रियासतपति के काम निभारना	76
161 रियासतपति को कुछ सूतों में माफ़ी वगैरा देने और सज़ा के हुकुमों को रोके रखने, बाक़ी हुकुम रह कर देने या सज़ा का रूप बदल देने की शक्ति	76
162 रियासत की काजकारी शक्ति का फैलाव	76

वज़ीर मंडल

163 रियासतपति को सहायता और सलाह देने के लिये वज़ीर मंडल	77
164 वज़ीरों के बारे में दूसरे बन्धान	77—78

रियासत का सर वकील

165 रियासत का सर वकील	78
-----------------------	----

सरकारी काम का संचालन

166 किसी रियासत की सरकार के काम का संचालन	78—79
167 रियासतपति को सूचना देने वगैरा के बारे में बड़े वज़ीर के प्ररज़ा	79

दफ़ा	खंड तीन—रियासत की क़ानून सभा	सफ़ा
	आम	
168	रियासतों की क़ानून सभाओं की बनावट ..	79
169	रियासतों में खास सदनों का अन्त करना या बनाना ...	79—80
170	आम सदनों की रचना ...	80
171	खास सदनों की रचना ...	81—82
172	रियासत की क़ानून सभाओं की मुहत्त ..	82—83
173	रियासत की क़ानून सभा की मेम्बरी के लिये जोगता .	83
174	रियासत की क़ानून सभा के इजलास, उनका बरखास्त करना और भंग करना ...	83
175	रियासतपति को सदन या सदनों में सर-बचन देने या संदेसे भेजने का अधिकार ...	83—84
176	हर इजलास के आरम्भ में रियासतपति का खास सर-बचन .	84
177	सदनों के बारे में वज़ीरों और सरवकील के अधिकार ....	84
	रियासत की क़ानून सभा के अफ़सर	
178	आम सदन का सभामुख और उप-सभामुख ....	84
179	सभामुख और उप-सभामुख का पद सूना होना, उनका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना ...	85
180	उप-सभामुख को या किसी दूसरे आदमी को सभामुख के पद के फ़रज़ पूरा करने या सभामुख की जगह काम करने की शक्ति	85
181	जब उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो तब सभामुख या उप-सभामुख सदारत नहीं करेगा ...	85—86
182	खास सदन का मसनदी और उप-मसनदी ...	86
183	मसनदी और उप-मसनदी का पद सूना होना, उनका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना . ...	86—87
184	उप-मसनदी या किसी दूसरे आदमी को मसनदी के पद के फ़रज़ पूरा करने या मसनदी की जगह काम करने की शक्ति ...	87

दफा	सफा
185	जब उसको उसके पद से हटाने के लिए किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो तो मसनदी या उप-मसनदी सदारत नहीं करेगा 87
186	मसनदी और उप-मसनदी और सभामुख और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते ... 87—88
187	रियासत की क़ानून सभा की मंत्रायत ... 88

#### काम का संचालन

188	मेम्बरों का हलफ उठाना या वचन भरना 88
189	सदनों में वोट लेना, सीटें सूनी होने पर भी सदनों को काम करने की शक्ति और कोरम ... 88—89

#### मेम्बरों की अजोगताएं

190	सीटों का सूना होना ... 89—90
191	मेम्बरों के लिये अजोगताएं ... 90—91
192	मेम्बरों की अजोगताओं के बारे में सवालों का फैसला ... 91
193	दफा 188 के अधीन हलफ उठाने या वचन भरने से पहले या जोग न होने या अजोग ठहराए जाने पर सदन में बैठने और वोट देने पर दंड ... 91—92

#### रियासत की क़ानून सभाओं और उनके मेम्बरों की शक्तियां, निजनियम और बरीयतें

194	क़ानून सभाओं के सदनों, उनके मेम्बरों और उनकी कमे-टियों की शक्तियां, निजनियम वगैरा ... 92
195	मेम्बरों की तनखाहें और भत्ते ... 93

#### क़ानूनकारी दस्तूर

196	बिल रखने और पास करने के बारे में बन्धान ... 93
197	नक़दी बिलों को छोड़ कर दूसरे बिलों के सम्बन्ध में खास सदन की शक्तियों पर रुकावट ... 93—94
198	नक़दी बिलों के बारे में खास दस्तूर ... 94—95
199	“नक़दी बिलों” की परिभाषा ... 95—97
200	बिलों पर मंजूरी ... 97

दफ़ा	सफ़ा
201 विचार के लिये रखे हुए बिल	... 97—98
माली मामलों में दस्तूर	
202 सालाना माली ब्योरा	... 98—99
203 तख्तीनों के बारे में क़ानून सभा का दस्तूर	... 99
204 मद्-बटवारा बिल	... 99—100
205 पूरक, सहायक या अधिक देनगियां	... 100—101
206 हिसाब पर वोट, साख की वोट और अलग देनगियां	... 101—102
207 माली बिलों के बारे में खास बन्धान	... 102—103
आम दस्तूर	
208 दस्तूर के नियम	... 103
209 माली काम के सम्बन्ध में रियासत की क़ानून सभा के दस्तूर की क़ानून से क़ायदाबन्दी	... 103—104
210 क़ानून सभा में काम में आने वाली भाशा	... 104
211 क़ानून सभा में बहस पर रुकावट	... 104
212 क़ानून सभा की कारवाइयों के बारे में अदालतें पूछताछ नहीं करेंगी	... 104
खंड चार—रियासतपति की क़ानूनकारी शक्ति	
213 क़ानून सभा की छुट्टी के दिनों में रियासतपति को राज-हुकुम जारी करने की शक्ति	... 105—106
खंड पांच—रियासतों की हाईकोर्टें	
214 रियासतों के लिये हाईकोर्टें	... 106—107
215 हाईकोर्टें नज़ीरी अदालतें होंगी	... 107
216 हाईकोर्टों की बनावट	... 107
217 हाईकोर्ट के हर जज का नियोजन और उसके पद की शर्तें	... 107—108
218 आला अदालत से सम्बन्ध रखने वाले कुछ बन्धानों का हाईकोर्टों पर लागू होना	... 108
219 हाईकोर्टों के जजों का हज़र उठाना या वचन भरना	... 108—109
220 जजों की अदालतों में या किसी अधिकारी के सामने वकालत करने की मनाही	... 109

दफ्ता	सफा
221 जजों की तनखाहें वगैरा ..	109
222 किसी जज का एक हाईकोर्ट से दूसरी में तबादला ..	109
223 कारकर सरजज का नियोजन ...	109
224 हाईकोर्टों की बैठकों में सेवामुक्त जजों का आना ...	110
225 मौजूदा हाईकोर्टों की अमलदारी ...	110—111
226 कुछ परवाने जारी करने की हाईकोर्टों की शक्ति ...	111
227 हाईकोर्ट को सब अदालतों पर निगरानी रखने की शक्ति ..	111—112
228 कुछ मुकदमों का हाईकोर्ट में तबादला ...	112
229 हाईकोर्टों के अफसर, नौकर और खर्च ..	112—113
230 हाईकोर्टों की अमलदारी को बढ़ाना या कम करना ...	113
231 किसी रियासत की किसी ऐसी हाईकोर्ट की अमलदारी के सम्बन्ध में रियासतों की कानून सभाओं की कानून बनाने की शक्तियों पर रुकावटें जिस हाईकोर्ट की अमलदारी उस रियासत के बाहर भी हो ...	113—114
232 अर्थ ...	114—115
खंड छै—मातहत अदालतें	
233 ज़िला जजों का नियोजन ...	115
234 न्यायी नौकरी में ज़िला जजों को छोड़ कर और लोगों की भरती ...	115
235 मातहत अदालतों पर दबान ...	115
236 अर्थ ...	115—116
237 इस खंड के बन्धानों का मजिस्ट्रेटों की किसी खास जमात या जमातों पर लागू होना ...	116
भाग सात	
पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतें	
238 पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों पर भाग छै के बन्धानों का लागू होना ...	117—119
भाग आठ	
पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतें	
239 पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतों का शासन ....	120

दफ़ा	सफ़ा
240 मुकामी क़ानून सभाओं या सलाहकार मंडल या वज़ीर मंडल का बनाना या जारी रखना ...	120—121
241 पहली पट्टी के भाग ( सी ) की रियासतों के लिये हाईकोर्ट ...	121
242 कुर्ग ...	121—122

### भाग नौ

पहली पट्टी के भाग (डी) के भूभाग और वह दूसरे  
भूभाग जो उस पट्टी में दर्ज नहीं हैं

243 पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज भूभागों का और उन दूसरे भूभागों का शासन जो उस पट्टी में दर्ज नहीं हैं ...	123
---	-----

### भाग दस

पट्टी-दर्ज छेत्र और क़बायली छेत्र

244 पट्टी-दर्ज छेत्रों और क़बायली छेत्रों का शासन ...	124
---	-----

### भाग ग्यारह

यूनियन और रियासतों के बीच सम्बन्ध

खंड एक—क़ानूनकारी सम्बन्ध

क़ानूनकारी शक्तियों का बटवारा

245 राजपंचायत के बनाए और रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानूनों का फैलाव	125
246 राजपंचायत के बनाए और रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानूनों का विषय ...	125—126
247 कुछ अधिक अदालतों को क़ायम करने के लिये बन्धान करने की राजपंचायत को शक्ति ...	126
248 क़ानून बनाने की बची शक्तियाँ ...	126
249 क़ौमी हित के लिये रियासत तालिका के किसी मामले के बारे में राजपंचायत को क़ानून बनाने की शक्ति ...	126—127
250 अचानकी का कोई ऐलान अमल में होने की सूरत में रियासत तालिका के किसी भी मामले के बारे में राज- पंचायत को क़ानून बनाने की शक्ति ...	127

दफ़ां	सफ़ां
251 दफ़ा 249 और 250 के अधीन राजपंचायत के बनाए क़ानूनों का रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानून के साथ अनमेल	... 127—128
252 राजपंचायत को दो या अधिक रियासतों के लिये उनकी अनुमति से क़ानून बनाने की शक्ति और किसी दूसरी रियासत का ऐसे क़ानूनों को अपनाना	128
253 अन्तर-क़ौमी समझौतों पर अमल कराने के लिये क़ानून बनाना	... 128
254 राजपंचायत के बनाए क़ानूनों और रियासतों की क़ानून सभाओं के बनाए क़ानूनों में अनमेल	... 129
255 सिफ़ारिशों के और पहले से मंज़ूरियां लेने के दरकार होने को सिर्फ़ दस्तूरी मामला समझा जायगा	... 129—130

### ग़ंड दो

### शासनी संबंध

### आम

256 रियासतों की और यूनियन की ज़िम्मेदारी	... 130
257 कुछ सूतों में यूनियन का रियासतों पर दबान	.. 130—131
258 कुछ सूतों में रियासतों को शक्तियां बग़ैरा देने की यूनियन को शक्ति	.... 131—132
259 पहली पट्टी के भाग ( बी ) की रियासतों में हथियार बन्द फ़ौजें	... 132
260 भारत के बाहर भूभागों के संबंध में यूनियन की अमलदारी	... 132
261 सरकारी काम, लेखे और अदालती कारवाइयां	.. 132—133

### पानी के संबंध में झगड़े

262 अन्तर-रियासती नदियों या उनकी घाटियों के पानी के सम्बन्ध में झगड़ों का अदालती फ़ौसला	... 133
<i>रियासतों के बीच तालमेल</i>	
263 अन्तर-रियासती मंडल के बारे में बन्धान	... 133



दफ़ा

सफ़ा

## भाग बारह

माल, जायदाद, ठेके और नालिशें

खंड एक—माल

आम

264	अर्थ	...	134
265	क्रानून के अधिकार सिवा टैक्स नहीं लगाए जायगे	...	134
266	भारत के और रियासतों के मूठकोश और सरकारी हि़साब	...	134—135
267	जोगाजोग कोश	...	135
	यूनियन और रियासतों के बीच मालगुज़ारी का बटवारा		
268	वह महसूल जिन्हें यूनियन लगाए पर जिन्हें रियासतें जमा करें और खर्च की मदों में डाले	...	135—136
269	वह टैक्स जो यूनियन लगाए और जमा करे पर जो रियासतों के नाम कर दिये जायं	...	136—137
270	वह टैक्स जो यूनियन लगाए और जमा करे और जो यूनियन और रियासतों के बीच बाँटे जायं	..	137—138
271	कुछ महसूलों और टैक्सों पर यूनियन के मतलबों के लिये अधिक-टैक्स	...	138
272	वह टैक्स जो यूनियन लगाती है और जमा करती है और जो यूनियन और रियासतों के बीच बाँटे जा सकते हैं	..	138
273	पटसन और पटसन से बनी चीज़ों पर निकासी-महसूल के बदलें में देनगियां	..	138
274	जिन टैक्सों में रियासतों का हित हो उन पर असर डालने वाले बिलों पर राजपति की पहले से सिफ़ारिश दरकार	...	139
275	यूनियन की तरफ़ से कुछ रियासतों को देनगियां	.	139—140
276	पेशों, ब्योपारों, रोज़गारों और कामगारियों पर टैक्स	..	140—141
277	बचावे	...	141—142
278	कुछ माली मामलों के सम्बन्ध में पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों से समझौता	...	142

दफ़ा	सफ़ा
279 “असल वसूली” का हिसाब लगाना, वगैरा	143
280 माल कमीशन	143—144
281 माल कमीशन की सिफ़ारिशें	144

#### फुटकर माली बन्धान

282 खर्चा जो यूनियन या कोई रियासत अपने मालगुज़ारी में से कर सकती है	144
283 मूठकोश, जोगाजोग कोश और सरकारी हिसाबों में जमा हुई रकमों की रखवाली वगैरा	144—145
284 सायलों की जमा की हुई रकमों और उन दूसरी रकमों की रखवाली जो सरकारी नौकरों और अदालतों को मिलें	145
285 यूनियन की जायदाद का रियासती टैक्सों से बरी होना	146
286 माल की बिकरी या खरीद पर टैक्स लगाने के सम्बंध में रुकावटें	146—147
287 बिजली के टैक्सों से बरी होना	147—148
288 कुछ सूरतों में पानी या बिजली के बारे में रियासतों के टैक्सों से बरी होना	148
289 रियासत की जायदाद और आमदनी का यूनियन के टैक्सों से बरी होना	148—149
290 कुछ खर्चों और पेनशनों के बारे में बैठ-बिठाव	149—150
291 शासकों की निजी थैलियों की रकमें	150

#### खंड दो—उधार लेना

292 भारत सरकार का उधार लेना	150—151
293 रियासतों का उधार लेना	151

#### खंड तीन—जायदाद, ठेकें, अधिकार, देनदारियां, ज़िम्मेदारियां और नालिशें

294 कुछ सूरतों में जायदाद, देनदारियों, अधिकारों, देनदारियों और ज़िम्मेदारियों का विवरण	151—152
--	---------

दफ़ा	सफ़ा
295 दूसरी सूक्तों में जायदाद, लेनदारियों, अधिकारों, देन- दारियों और ज़िम्मेदारियों का विरसा	... 152—153
296 सरकारी ज़न्ती, या हक़ ख़तम हो जाने, या वारिस न रहने के कारन मिलने वाली जायदाद	... 153—154
297 भूभागी जल में जो कीमती चीज़ें हों वह यूनिअन को हासिल होंगी	... 154
298 जायदाद हासिल करने की शक्ति	... 154
299 ठेके	... 154—155
300 नाखिशें और कारवाइयाँ	... 155

### भाग तेरह

भारत के भूभाग के अन्दर ब्योपार, तिजारत  
और अन्तर-ब्योहार

301 ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार की आज्ञादी	... 156
302 ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार पर रुकावटें लगाने की राजपचायन की शक्ति	... 156
303 ब्योपार और तिजारत के बारे में यूनिअन और रियासतों की क़ानूनकारी शक्तियों पर रुकावटें	... 156
304 रियासतों के बीच ब्योपार, तिजारत और अन्तर-ब्योहार पर रुकावटें	... 156—157
305 दफ़ा 301 और 303 का सौज़्दा क़ानूनों पर असर	... 157
306 पहली पट्टी के भाग (बी) की कुछ रियासतों को ब्योपार और तिजारत पर रुकावटें लगाने की शक्ति	... 157
307 दफ़ा 301 से 304 तक के मतलबों पर अमल कराने के लिये अधिकारी का नियोजन	... 158

### भाग चौदह

यूनिअन और रियासतों के अधीन नौकरियाँ  
खंड एक—नौकरियाँ

308 अर्थ	... 159
----------	---------

दफ़ा	सफ़ा
309 यूनिन की या किसी रियासत की नौकरी करने वाले लोगों की भरती और नौकरी की शर्तें	... 159
310 यूनिन की या किसी रियासत की नौकरी करने वाले आदमियों की पद-मियाद	... 159—160
311 यूनिन या किसी रियासत के अधीन नागरी हैसियत से नौकरी करने वालों का बरखास्त किया जाना, हटाया जाना या रुतबा घटाया जाना	... 160—161
312 कुल-भारत नौकरियाँ	... 161—162
313 बिचवक्ती बन्धान	... 162
314 कुछ नौकरियों के मौजूदा अफ़सरों की रक्षा के लिये बन्धान	... 162

### खंड दो—सरकारी नौकरी कमीशन

315 यूनिन के लिये और रियासतों के लिये सरकारी नौकरी कमीशन	... 162—163
316 मेम्बरों का नियोजन और पद-मियाद	... 163—164
317 किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर का हटाया जाना और मुअत्तल किया जाना	... 164—165
318 कमीशन के मेम्बरों और अमले की नौकरी की शर्तों के बारे में क़ायदाबन्दी करने की शक्ति	... 165
319 कमीशन के मेम्बरों को मेम्बर न रहने के बाद पदों पर रहने के बारे में मनाही	... 166
320 सरकारी नौकरी कमीशनों के काम	... 166—169
321 सरकारी नौकरी कमीशनों के कामों को बढ़ाने की शक्ति	... 169
322 सरकारी नौकरी कमीशनों के खर्च	... 169
323 सरकारी नौकरी कमीशनों की रिपोर्टें	... 169—170

### भाग पंद्रह

#### चुनाव

324 चुनावों की निगरानी, निर्देशन और दबान एक चुनाव कमीशन के हाथ में रहेगा	... 171—172
--	-------------

दफ़ा

सफ़ा

- 325 धर्म, नसल, जात या ज़िन्स की बिना पर कोई आदमी किसी खास चुनाव चिट्ठे में शामिल होने का अपात्र न होगा और न शामिल किये जाने का दावा करेगा ... 172
- 326 लोक सदन के लिये और रियासतों के आम सदनों के लिये चुनाव बालिग वोट के आधार पर होंगे ... 172—173
- 327 क़ानून सभाओं के चुनावों के बारे में राजपंचायत को बन्धान करने की शक्ति ... 173
- 328 किसी रियासत की क़ानून सभा की उस क़ानून सभा के चुनावों के बारे में बन्धान करने की शक्ति ... 173
- 329 चुनाव के मामलों में अदालतों के दखल देने पर रोक ... 173—174

### भाग सोलह

कुछ जमातों से संबंध रखने वाले खास बन्धान

- 330 लोक सदन में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये सीटें अलग रखना ... 175
- 331 लोक सदन में ऐंग्लो इन्डियन समाज का प्रतिनिधान ... 175
- 332 रियासतों के आम सदनों में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के लिये सीटों का अलग रखा जाना ... 175—176
- 333 रियासतों के आम सदनों में ऐंग्लो इन्डियन समाज का प्रतिनिधान ... 176
- 334 सीटों का अलग रखा जाना और खास प्रतिनिधान दस साल बाद बन्द ... 176—177
- 335 नौकरियों और जगहों के लिये पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज क़बीलों के दावे ... 177
- 336 कुछ नौकरियों में ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये खास बन्धान ... 177—178
- 337 ऐंग्लो इन्डियन समाज के फ़ायदे के लिये तालीमी देन-गियों के बारे में खास बन्धान ... 178
- 338 पट्टी-दर्ज जातों, पट्टी-दर्ज क़बीलों वगैरा के लिये खास अफ़सर ... 178—179

दफ़ा	सफ़ा
339 पट्टो-दर्ज छेत्रों के शासन और पट्टी-दर्ज क़बीलों को भलाई पर यूनियन का दबान	179
340 पिछड़ी हुई जमातों की हालत की जाँच करने के लिये कमीशन का नियोजन	... 179—180
341 पट्टो-दर्ज जातें	.... 180
342 पट्टी-दर्ज क़बीले	... 180—181

## भाग सतरह

### दफ़्तरी भाशा

#### खंड एक—यूनियन की भाशा

343 यूनियन की दफ़्तरी भाशा	... 182
344 दफ़्तरी भाशा पर कमीशन और राजपंचायत की कमेटी	... 183—184

#### खंड दो

#### इलाक़ा भाशाएं

345 किसी रियासत की दफ़्तरी भाशा या भाशाएं	... 184
346 एक रियासत और दूसरी रियासत के बीच या किसी रियासत और यूनियन के बीच आपसी ब्योहार की दफ़्तरी भाशा	... 184—185
347 किसी रियासत की आबादी की किसी ठुकड़ी में बोली जाने वाली भाशा के बारे में खास बन्धान	... 185

#### खंड तीन—आला अदालत, हाईकोर्टों वगैरा की भाशा

348 आला अदालत में और हाईकोर्टों में और एक्टों, बिलों वगैरा के लिये काम में आने वाली भाशा	... 185—186
349 भाशा के संबंध में कुछ क़ानूनों के बनाए जाने के लिये खास दस्तुर	... 186

#### खंड चार—खास निर्देश

350 तकलीफ़ों के दूर कराने के लिये अरज़ी पत्रों में काम आने वाली भाशा	.... 187
351 हिन्दी भाशा के विकास के लिये निर्देश	... 187

दफ़ा

सफ़ा

## भाग अठारह

## अचानकी बन्धान

- 352 अचानकी का ऐलान ... 188—189
- 353 अचानको के ऐलान का असर ... 189
- 354 जब अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो तब साल-  
गुज़ारी के बटवारे के संबन्ध के बन्धानों का लागू होना .... 189
- 355 रियासतों की बाहरी हमले और भीतरी गड़बड़ी से रक्षा  
करना यूनियन का फ़रज़ ... 189—190
- 356 रियासतों में विधानी मशीन के फ़ेल हो जाने की सूत  
में बंधान ... 190—192
- 357 दफ़ा 356 के अधीन जारी हुए ऐलान के अधीन क़ानून-  
कारी शक्तियों से काम लेना .... 192—193
- 358 अचानकी के दौरान में दफ़ा 19 के बंधानों का  
मुअत्तल रहना .... 193
- 359 अचानक़ियों के दौरान में भाग तीन में दिये अधिकारों  
पर अमल का मुअत्तल रहना ... 193—194
- 360 माली अचानकी के बारे में बंधान ... 194—195

## भाग उन्नीस

## फ़ुटकर

- 361 राजपति और रियासतपतियों और राजप्रमुखों की रक्षा ... 196—197
- 362 देसी रियासतों के शासकों के अधिकार और  
निजनियम .... 197
- 363 कुछ सन्धिनामों, समझौतों बग़ैरा से पैदा होने वाले  
भूगर्भों में अदालतों के दख़ल देने पर रोक .... 197—198
- 364 बड़े बन्दरगाहों और हवाई अड्डों के लिये खास  
बधान .... 198—199
- 365 यूनियन के दिये निर्देशों पर न चल सकने या उन पर  
अमल न कर सकने का असर ... 199
- 366 परिभाषाएँ ... 199—203

दफ़ा	सफ़ा
367 अर्थ	... 204

## भाग बीस

### विधान में सुधार

368 विधान में सुधार के लिये दस्तूर	.... 205
------------------------------------	----------

## भाग इक्कीस

### आरज़ी और विचवक्ती बन्धान

369 रियासत तालिका के कुछ मामलों के बारे में राजपचायत को क़ानून बनाने की आरज़ी शक्ति, मानो वह मामले संग-चारी तालिका में हों	... 206
370 जम्मू और काश्मीर रियासत के संबंध में आरज़ी बंधान	.. 207—208
371 पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों के बारे में आरज़ी बन्धान	... 208
372 मौजूदा क़ानूनों का अमल जारी रहना और उनका अनुकूलन	... 208—210
373 कुछ सूतों में उन लोगों के बारे में जो रोकथामी नजर-बन्दी में हैं हुकुम देने की राजपति को शक्ति	... 210
374 संघ अदालत के जजों के बारे में और संघ अदालत में या कौंसिल समेत सम्राट के सामने चालू कारवाइयों के बारे में बन्धान	... 210—211
375 इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए अदालतों, अधिकारियों और अफ़सरों का काम करते रहना	212
376 हाईकोर्ट के जजों के बारे में बन्धान	.. 212
377 भारत के दाब अफ़सर और सर पड़तालिया के बारे में बन्धान	... 212—213
378 सरकारी नौकरी कमीशनों के बारे में बन्धान	... 213
379 कामचलाऊ राजपंचायत के और उसके सभामुख और उप-सभामुख के बारे में बन्धान	.. 213—215
380 राजपति के बारे में बन्धान	.. 215
381 राजपति का वज़ीर मंडल	... 215—216



382	पहली पट्टी के भाग (ए) की रियासतों के लिये काम चलाऊ कानून सभाओं के बारे में बन्धान	... 216—217
383	सूबों के गवरनरों के बारे में बन्धान	... 217
384	रियासतपतियों के वज़ीर मंडल	... 217
385	पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों में काम चलाऊ कानून सभाओं के बारे में बन्धान	... 217
386	पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों के लिये वज़ीरमंडल	... 217—218
387	कुछ चुनावों के मतलबों के लिये आबादी तय करने के बारे में खास बन्धान	... 218
388	काम चलाऊ राजपंचायत में और रियासतों की काम चलाऊ कानून सभाओं में औसरी सूनियों को भरने के बारे में बन्धान	... 218—220
389	डोमिनियन कानून सभा में और सूबों और देसी रियासतों की कानून सभाओं में पेश बिलों के बारे में बन्धान	... 220
390	विधान के आरंभ और 31 मार्च सन् 1950 के बीच जो रक़में मिलें या जुटाई जायं या जो खर्च किया जाय	... 220—221
391	कुछ जोगाजोगों में राजपति को पहली और चौथी पट्टियों में सुधार करने की शक्ति	... 221
392	कठिनाइयों को दूर करने की राजपति की शक्ति	... 221

### भाग बाईस

#### छोटा सरनामा, आरंभ, और रद्द

393	छोटा सरनामा	... 222
394	आरम्भ	... 222
395	रद्द	... 222

### पट्टियां

पहली पट्टी—	भारत की रियासतें और उसके भूभाग	... 223—225
-------------	--------------------------------	-------------

#### दूसरी पट्टी—

भाग (ए)—	राजपति के और पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के रियासतपतियों के बारे में बन्धान	... 226
----------	---	---------

- भाग (बी)—यूनियन के और पहली पट्टी के भाग (ए)  
और भाग (बी) की रियासतों के वज्जियों के  
बारे में बन्धान .... 227
- भाग (सी)—लोकसदन के सभामुख और उप-सभामुख,  
रियासत सदन के मसनदी और उप-मसनदी,  
पहली पट्टी के भाग (ए) की हर रियासत के  
आम सदन के सभामुख और उप-सभामुख,  
और ऐसी हर रियासत के खास सदन के मसनदी  
और उप-मसनदी के बारे में बन्धान ... 227—228
- भाग (डी)—आला अदालत के जजों के बारे में और पहली  
पट्टी के भाग (ए) की रियासतों की हाईकोर्टों  
के जजों के बारे में बन्धान ... 228—231
- भाग (ई)—भारत के दाब अफसर और सर पड़तालिया के  
बारे में बन्धान .... 231
- तीसरी पट्टी—हलफ या वचन के रूप .... 232—234
- चौथी पट्टी—रियासत सदन की सीटों का बटवारा .... 235—236
- पांचवी पट्टी—पट्टी-दर्ज छेत्रों और पट्टी-दर्ज कबीलों के शासन  
और दबान के बारे में बन्धान
- भाग (ए)—आम .... 237
- भाग (बी)—पट्टी-दर्ज छेत्रों और पट्टी-दर्ज कबीलों का  
शासन और दबान .... 237—239
- भाग (सी)—पट्टी-दर्ज छेत्र .... 239—240
- भाग (डी)—इस पट्टी में सुधार .... 240
- छठी पट्टी—आसाम के क्वाइली छेत्रों के शासन के बारे में बन्धान .... 241—259
- सातवीं पट्टी—
- तालिका एक—यूनियन तालिका .... 260—268
- तालिका दो—रियासत तालिका .... 268—273
- तालिका तीन—संगचारी तालिका .... 273—276
- आठवीं पट्टी—आशाएं .... 277

# भारत का विधान



# भारत का विधान

सरलेख

हम भारत के लोग गम्भीरता के साथ निश्चय करके कि भारत को खुद-मालिक लोकशाही जनराज बनाया जाय, और उसके सब नागरों के साथ :

इनसाफ़ हो, समाजी, धन-दौलती, और राजकाजी;  
सबको

आज़ादी हो, विचारों की, उन्हें जाहिर करने की,  
विश्वास, धर्म और पूजा बंदगी की;

सबको

बराबरी का दरजा और बराबरी के मौके मिलें; और  
सबमें

भाईचारा बढ़े, जिससे हर आदमी का मान और  
कौम की एकता बनी रहे;

अपनी विधान सभा में, नवम्बर उन्नीस सौ  
उनवांस के इस छब्बीसवें दिन, आज की इस कारवाई  
से, इस विधान को अपनाते हैं, क़ानून बनाते  
हैं, और खुद अपने को देते हैं.

## भाग एक

### यूनियन और उसका भूभाग

यूनियन का नाम  
और भूभाग

- 1—(1) इंडिया यानी भारत रियासतों का एक यूनियन होगा.  
(2) रियासतें और उनके भूभाग वह रियासतें और उनके भूभाग होंगे जो पहली पट्टी के भाग (ए), (बी) और (सी) में दर्ज हैं.  
(3) भारत के भूभाग में—  
(ए) रियासतों के भूभाग,  
(बी) वह भूभाग जो पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज हैं, और  
(सी) दूसरे ऐसे भूभाग जिन्हें हासिल कर लिया जाय, शामिल होंगे.

नई रियासतों को  
दाखिल करना या  
क्रायम करना

- 2—राजपंचायत, कानून बनाकर, जिन बन्धनों और शर्तों पर ठीक समझे, नई रियासतों को यूनियन में दाखिल कर सकती है या नई रियासतें क्रायम कर सकती है.

नई रियासतों का  
बनाना और मौजूदा  
रियासतों के क्षेत्रों,  
सीमाओं या नामों  
को बदलना

- 3—राजपंचायत कानून बनाकर—

- (ए) किसी रियासत का कोई भूभाग उससे अलग करके, या दो या दो से अधिक रियासतों को या उनके भागों को मिलाकर, या किसी भूभाग को किसी रियासत के किसी भाग से मिलाकर, एक नई रियासत बना सकती है;  
(बी) किसी रियासत का क्षेत्र बढ़ा सकती है;  
(सी) किसी रियासत का क्षेत्र घटा सकती है;  
(डी) किसी रियासत की सीमाएँ बदल सकती है;  
(ई) किसी रियासत का नाम बदल सकती है :

शर्तें कि इस मतलब के लिये कोई बिल राजपंचायत के किसी सदन में नहीं रखा जायगा जब तक कि राजपति उसकी सिफारिश न करे और जब तक कि, जहां उस बिल में आए हुए सुझाव से पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत या रियासतों की सीमाओं पर या नाम या नामों पर असर पड़ता है

वहां, राजपति ने उस बिल को रखने के सुझाव और बिल के बन्धानों दोनों के बारे में उस रियासत की या, जैसी सूरत हो, उनमें से हर रियासत की कानून सभा का मत मालूम न कर लिया हो.

4—(1) हर ऐसे कानून में जिसकी चरचा दफा (2) या दफा (3) में की गई है पहली पट्टी और चौथी पट्टी में सुधार करने के लिये ऐसे बंधान रहेंगे जो उस कानून के बंधानों पर अमल कराने के लिये जरूरी हों, और उसमें ऐसे पूरक, प्रसंगी या परिनामी बंधान भी रह सकेंगे जिन्हें राजपंचायत जरूरी समझे (राजपंचायत के या उस रियासत या उन रियासतों की कानून सभा या कानून सभाओं के प्रतिनिधान संबंधी बन्धानों समेत जिस रियासत या रियासतों पर उस कानून का असर पड़ता हो ).

दफा 2 और 3 के अधीन बने कानूनों में पहली और चौथी पट्टी के सुधार के लिये और पूरक, प्रसंगी और परिनामी मामलों के लिये बंधान

(2) ऊपर कहे किसी कानून को दफा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा जायगा.

## भाग दो

नमस्ता

विधान के आरम्भ होने पर <sup>जिसका</sup> 5—इस विधान के आरंभ होने पर वह आदमी जिसका भारत के भूभाग में निवास है और—

- (ए) जो भारत के भूभाग में पैदा हुआ था; या
- (बी) जिसके माँ बाप में से कोई भारत के भूभाग में पैदा हुआ था, या
- (सी) जो विधान के आरम्भ से ठीक पहले कम से कम पांच बरस तक आम तौर पर भारत के भूभाग में रहता रहा है,

भारत का नागरिक होगा।

कुछ ऐसे लोगों के नागरता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में आ बसे हैं

6—दफ्ता 5 में किसी बात के रहते भी, हर वह आदमी, जो उस भूभाग से जो इस समय पाकिस्तान में शामिल है भारत के भूभाग में आ बसा है, इस विधान के आरंभ होने पर भारत का नागरिक समझा जायगा, अगर—

- (ए) वह या उसके माँ बाप में से या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई उस हिन्द में पैदा हुआ था, जिसकी परिभाषा हिन्द सरकार एक्ट, 1935, में (जैसा वह एक्ट शुरू में बना था) की गई है; और
- (बी) (एक) उस सूरत में जब कि वह आदमी जुलाई 1948 के उन्नीसवें दिन से पहले इस तरह आ बसा है, अपने आ बसने की तारीख से वह आम तौर पर भारत के भूभाग में रहता रहा है, या
- (दो) उस सूरत में जब कि वह आदमी जुलाई 1948 के उन्नीसवें दिन या उसके बाद इस तरह आ बसा है, उसने, इस विधान के आरंभ होने से पहले, उस रूप में और उस ढंग से जो हिन्द डोमिनियन की सरकार ने तय कर दिया हो, एक अरबी हिन्द का नागरिक होने के



लिये उस अफसर को दी हो, जिसे हिन्द डोमिनियन की सरकार ने इस काम के लिये नियोजा हो, और उस अफसर ने उसे हिन्द का नागर रजिस्टर कर लिया हो :

शर्ते कि किसी आदमी की इस तरह रजिस्टरी नहीं की जायगी जब तक कि वह अपनी अरज्जी की तारीख से ठीक पहले कम से कम छै महीने तक भारत के भूभाग में न रह चुका हो.

7—दफा 5 और 6 मे किसी बात के रहते भी, कोई आदमी जो मार्च 1947 के पहले दिन के बाद भारत के भूभाग से उस भूभाग में जा बसा है जो इस समय पाकिस्तान में शामिल है, भारत का नागर नहीं समझा जायगा :

पाकिस्तान में जा बसने वाले कुछ लोगों के नागरता के अधिकार

शर्ते कि इस दफा की कोई बात उस आदमी पर लागू नहीं होगी, जो उस भूभाग में जो इस समय पाकिस्तान में शामिल है इस तरह जा बसने के बाद, एक ऐसे परमिट के अधीन भारत के भूभाग में लौट आया है, जो फिर बसने या पक्की वापिसी के लिये किसी कानून के अधिकार से या उसके अधीन जारी किया गया हो, और दफा 6 की धारा (बी) के मतलबों के लिये यह समझा जायगा कि हर ऐसा आदमी जुलाई 1948 के उन्नीसवें दिन के बाद भारत के भूभाग में आ बसा है.

8—दफा 5 में किसी बात के रहते भी, हर वह आदमी जो खुद या जिसके मां बाप में से या दादा दादी या नाना नानी में से कोई उस हिन्द में पैदा हुआ था, जिसकी परिभाषा हिन्द सरकार एक्ट, 1935, में (जैसा वह एक्ट शुरू में बना था) की गई है, और जो, आमतौर पर, इस तरह बताए हिन्द के बाहर किसी देश में रहता हो, भारत का नागर समझा जायगा अगर उसने, इस विधान के आरंभ से पहले या उसके बाद में एक अरज्जी उस रूप में और उस ढंग से जो हिन्द डोमिनियन की सरकार ने या भारत सरकार ने इस मतलब के लिये तय कर दिया हो, जिस देश में वह उस समय रह रहा हो, वहाँ पर भारत के राजदूती या बनिजदूती प्रतिनिधि को, भारत का नागर बनने के लिये दी हो, और उस राजदूती या बनिजदूती प्रतिनिधि ने उसे भारत का नागर रजिस्टर कर लिया हो.

भारत के बाहर बसने वाले हिन्दी निकास के कुछ लोगों के नागरता के अधिकार

अपनी मरजी से किसी विदेशी राज की नागरता हासिल करने वाले लोगों का नागर न होना

नागरता के अधिकारों का जारी रहना

राजपंचायत का कानून बनाकर नागरता के अधिकार की क्रयदा-बन्दी करना

9—दफा 5 की रू से कोई आदमी भारत का नागर नहीं होगा, न दफा 6 या दफा 8 की रू से भारत का नागर समझा जायगा, अगर उसने अपने मरजी से किसी विदेशी राज की नागरता हासिल कर ली है.

10—हर वह आदमी, जो इस भाग में ऊपर-लिखे बंधानों में से किसी के अधीन भारत का नागर है या समझा जाता है, भारत का नागर बना रहेगा, पर यह बात ऐसे हर कानून के बंधानों का ध्यान रखते हुए होगी जो राजपंचायत बनाए.

11—इस भाग में ऊपर-लिखे बंधानों की कोई बात राजपंचायत की इस शक्ति को कम नहीं करेगी कि वह नागरता हासिल करने, नागरता खतम होने और नागरता संबंधी दूसरे सब मामलों के बारे में कोई भी बंधन करे.

## भाग तीन

### मूल अधिकार

#### आम

12—जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, इस भाग में परिभाषा “राज” शब्द के अन्दर, भारत की सरकार और भारत की राज-पंचायत, हर रियासत की सरकार और वहाँ की कानून सभा, और भारत के भूभाग के अन्दर या भारत सरकार के दबान में सब मुकामी या दूसरे अधिकारी, शामिल हैं।

13—(1) इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले जितने कानून भारत के भूभाग में अमल में थे वह सब जहाँ तक इस भाग के बंधानों से बेमेल हैं उस बेमेल होने की हद तक रद्द हो जायेंगे।

मूल अधिकारों से मेल न खाने वाले या उनको कम करने वाले कानून

(2) राज कोई ऐसा कानून नहीं बनायगा जिससे लोगों के वह अधिकार छिन जायं या उनमें कमी आ जाय जो इस भाग में दिये गए हैं, और जो भी कानून इस धारा के खिलाफ बनेगा वह, उस खिलाफ होने की हद तक रद्द होगा।

(3) इस दफा में जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो,—

(ए) “कानून” शब्द के अन्दर वह सब राज हुकुम, हुकुम, छुट कानून, नियम, क़ायदे, नोटिस, रीत या रिवाज शामिल हैं जो भारत के भूभाग में कानून का असर रखते हैं।

(बी) “अमल में कानून” के अन्दर वह कानून शामिल हैं, जो इस विधान के आरम्भ से पहले भारत के भूभाग के अन्दर किसी कानून सभा या किसी दूसरे हक़दार अधिकारी ने पास किये हों या बनाए हों, और जो इससे पहले रद्द न कर दिये गए हों, भले ही ऐसा कोई कानून या उसका कोई भाग उस समय बिलकुल या किन्हीं खास क्षेत्रों में अमल में न हो।

#### बराबरी का अधिकार

14—राज, भारत के भूभाग के अन्दर किसी आदमी को, कानून कानून के सामने

बराबरी

के सामने बराबरी, या कानूनों के जरिये बराबर की रक्षा, देने से इनकार नहीं करेगा.

धर्म, नसल, जात,  
जिन्स या जन्म-  
स्थान की बिना  
पर भेदभाव की  
मनाही

15—(1) राज केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स, जन्म-स्थान या इनमें से किसी की बिना पर किसी नागर से भेद भाव नहीं करेगा.

(2) कोई नागर केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स, जन्म-स्थान या इन में से किसी की बिना पर नीचे लिखी बातों के बारे में किसी तरह की असक्त, देनदारी, रुकावट या शर्त के अधीन न होगा :—

(ए) दुकानों, आम जलपान घरों, होटलों और आम मनोरंजन की जगहों में जासकना; या

(बी) ऐसे कुओं, तलाबों, नहानघाटों, सड़कों और आम लोगों के आने जाने की जगहों का इस्तेमाल करना जिनका कुल या कुछ खर्च राज के रुपए से चलता हो या जो आम जनता के इस्तेमाल से लिये दे दी गई हों.

(3) इस दफ्ता की कोई बात राज को औरतों और बच्चों के लिये कोई खास बंधन करने से नहीं रोकेगी.

सरकारी कामगारी  
के मामलों में  
बराबरी के मौके

16—(1) राज के अधीन कामगारी से या किसी पद पर नियोजन से संबंध रखनेवाले मामलों में सब नागरों को बराबर के मौके मिलेंगे.

(2) कोई नागर केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स, वंश, जन्मस्थान, रिहाइश या इनमें से किसी की बिना पर राज के अधीन किसी कामगारी या पद के लिये अपात्र नहीं होगा न उससे भेदभाव किया जायगा.

(3) इस दफ्ता की कोई बात राजपंचायत को कोई ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी जिससे पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत के अधीन, या उस रियासत के भूभाग के अन्दर किसी मुकामी या दूसरे अधिकारी के अधीन, किसी क्रिस्म या क्रिस्मों की कामगारी के, या किसी पद पर नियोजन के, संबंध में, काम मिलने या नियोजन होने से पहले, उस रियासत के अन्दर रिहाइश की कोई शर्त हो.

(4) इस दफा की कोई बात राज को नागरों की किसी ऐसी पिछड़ी हुई जमात के लिये नियोजनों या जगहों को अलग रखने का कोई बन्धान करने से नहीं रोकेगी जिसके, राज की राय में, राज के अधीन नौकरियों में काफ़ी प्रतिनिधि नहीं हैं।

(5) इस दफा की किसी बात का किसी ऐसे क़ानून के अमल पर कोई असर नहीं होगा जो यह बन्धान करता है कि किसी धार्मिक या फिरक़ेवाराना संस्था के मामलों से संबंध रखने वाले किसी पद पर जो आदमी हों या उस संस्था की प्रबंध कमेटी का जो मेम्बर हो वह एक विशेष धर्म का माननेवाला या विशेष फिरक़े का ही हो।

17—‘अछूतपन’ का अन्त किया जाता है, और किसी रूप में भी अछूतपन बरतने की मनाही की जाती है। अछूतपन की बिना पर किसी को ज़बरदस्ती किसी असक्त के अधीन रखना जुर्म होगा जिसकी सज़ा क़ानून के अनुसार दी जा सकेगी।

अछूतपन का अन्त

18—(1) फ़ौजी या तालीमी संस्थाओं संबंधी उपाधियों को छोड़कर राज कोई खिताब नहीं देगा।

खिताबों का अन्त

(2) भारत का कोई नागर किसी विदेशी राज से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा।

(3) कोई आदमी जो भारत का नागर नहीं है, जब तक वह राज के अधीन किसी लाभ या भरोसे के पद पर है, राजपति की अनुमति बिना, किसी विदेशी राज से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा।

(4) कोई आदमी जो राज के अधीन किसी लाभ या भरोसे के पद पर है, राजपति की अनुमति बिना किसी विदेशी राज से या उसके अधीन कोई भेंट, वेतन, या किसी तरह का पद स्वीकार नहीं करेगा।

## आज़ादी का अधिकार

19—(1) सब नागरों को नीचे लिखे अधिकार होंगे :

- (ए) बोलने और विचार जाहिर करने की आज़ादी का;
- (बी) शांति से और बिना हथियार इकट्ठे होने का;
- (सी) सभाएँ या यूनियन बनाने का;
- (डी) भारत के सारे भूभाग में आज़ादी से आने जाने का;
- (ई) भारत के भूभाग के किसी हिस्से में बसने और बस जाने का;

बोलने वगैरा की आज़ादी के बारे में कुछ अधिकारों की रक्षा

- (एफ) जायदाद हासिल करने, रखने और दे देने का; और  
(जी) कोई पेशा अपनाने, या कोई धंधा, व्यापार या  
कारबार करने का.

(2) धारा (1) की उप-धारा (ए) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक कि उस क़ानून का संबंध अपमान-लेख, अपमान-वचन, मान-हानि, अदालत की तौहीन या ऐसे किसी मामले से है जो भलमंसी या सदाचार के खिलाफ है या जो राज की सुरक्षा की जड़ खोखली करता है, या जिसका झुकाव राज को उलट देने की तरफ है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा जिसका संबंध इन में से किसी से हो.

(3) उस धारा की उप-धारा (बी) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून जन-व्यवस्था के हितों में उस अधिकार से काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उस उप-धारा में दिया गया है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा.

(4) उस धारा की उप-धारा (सी) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून जन-व्यवस्था या सदाचार के हितों में उस अधिकार से काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उस उप-धारा में दिया गया है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा.

(5) उस धारा की उप-धारा (डी), (ई), और (एफ) की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून आम जनता के हितों में या किसी पट्टी-दर्ज क़बीले के हितों की रक्षा के लिये उन अधिकारों में से किसी से भी काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उन उप-धाराओं में दिये गए हैं, और न उन उप-धाराओं की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा.

(6) उस धारा की उप-धारा (जी) की किसी बात का

किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून आम जनता के हितों में उस अधिकार से काम लेने पर उचित रुकावटें लगाता है जो उस उप-धारा में दिया गया है, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा; और, विशेष कर, इस उप-धारा की किसी बात का किसी मौजूदा क़ानून के अमल पर वहाँ तक कोई असर नहीं होगा जहाँ तक वह क़ानून ऐसी पेशे-संबंधी या तकनीकी जोग-ताएँ तय करता है या किसी अधिकारी को उनके तय करने की शक्ति देता है जो किसी पेशे को अपनाने या कोई धन्धा, व्यापार या कारबार करने के लिये जरूरी हों, और न उस उप-धारा की किसी बात से राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोका जा सकेगा.

20—(1) कोई आदमी किसी जुर्म का दोशी नहीं ठहराया जायगा, जब तक कि वह किसी ऐसे क़ानून को न तोड़े जो जुर्म बताए जाने वाले काम के करने के समय अमल में था, और न उसे उससे अधिक दंड दिया जा सकेगा जो उस जुर्म के करने के समय अमल में रहने वाले क़ानून के अधीन दिया जा सकता था.

जुर्मों का दोशी ठहराए जाने के बारे में रक्षा

(2) किसी आदमी पर एक ही जुर्म के लिये एक बार से अधिक न मुक़दमा चलाया जायगा न एक बार से अधिक सज़ा दी जायगी.

(3) किसी आदमी को, जिस पर कोई जुर्म लगाया गया हो, अपने ख़िलाफ़ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जायगा.

21—न किसी आदमी की जान ली जायगी और न किसी की निजी स्वतंत्रता छीनी जायगी सिवाय जब कि क़ानून के क़ायम किये हुए दस्तूर के अनुसार ऐसा किया जाय.

जान और निजी स्वतंत्रता की रक्षा

22—(1) किसी ऐसे आदमी को जो गिरफ़्तार किया जाय, जितनी जल्दी हो सके, उसकी गिरफ़्तारी की बिना बताए बग़ैर, न हिरासत में रखा जायगा और न अपनी पसंद के वकील से सलाह करने और अपनी सफ़ाई दिलाने के उसके अधिकार से इनकार किया जायगा.

कुछ सूत्रों में गिरफ़्तारी और नज़रबन्दी से रक्षा

(2) हर आदमी को जिसे गिरफ़्तार किया जाय और हिरासत में रखा जाय, उसकी गिरफ़्तारी से चौबीस घंटे के अन्दर अन्दर पास से पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायगा.

इस चौबीस घंटे में गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक सफ़र के लिये जो समय जरूरी होगा वह नहीं गिना जायगा, और मजिस्ट्रेट के हुकुम के बिना किसी ऐसे आदमी को इस अरसे के बाद हिरासत में नहीं रखा जायगा.

(3) धारा (1) और (2) की कोई बात नीचे लिखे आदमियों पर लागू नहीं होगी :

(ए) किसी ऐसे आदमी पर जो उस समय शत्रु और विदेशी हो; या

(बी) किसी ऐसे आदमी पर जो रोकथामी नज़रबन्दो के लिये बन्धान करने वाले किसी क़ानून के अधीन गिरफ्तार या नज़रबन्द हो.

(4) रोकथामी नज़रबन्दी का बन्धान करने वाला कोई क़ानून किसी आदमी के तीन महीने से अधिक अरसे के लिये नज़रबन्द रखने का किसी को अधिकार नहीं देगा, जब तक कि—

(ए) एक सलाहकार बोर्ड ने, जिसमें ऐसे आदमी हों जो किसी हाईकोर्ट के जज हैं या रह चुके हैं या नियोजे जाने के योग हैं, तीन महीने के इस अरसे के बीत जाने से पहले, यह रिपोर्ट न दे दी हो कि उस बोर्ड की राय में ऐसी नज़रबन्दी के लिये काफ़ी कारन है :

शर्तकि इस उप-धारा की कोई बात धारा (7) की उप-धारा (बी) के अधीन राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में जो अधिक से अधिक अरसा बताया गया हो उससे अधिक किसी आदमी को नज़रबन्द रखने का किसी को अधिकार नहीं देगी; या

(बी) उस आदमी को धारा (7) की उप-धारा (ए) और (बी) के अधीन राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों के अनुसार नज़रबन्द न किया गया हो.

(5) जब किसी आदमी को रोकथामी नज़रबन्दी का बन्धान करने वाले किसी क़ानून के अधीन दिये हुए किसी हुकुम की तामील में नज़रबन्द किया जाय तो हुकुम देने वाला अधिकारी, जितनी जल्दी भी हो सकेगा, उस आदमी को



सूचना देगा कि वह हुकुम किन बिनाओं पर दिया गया है, और उसको उस हुकुम के खिलाफ अरजी पत्र देने का जल्दी से जल्दी मौका देगा.

(6) धारा (5) की किसी बात से यह दरकार नहीं होगा कि उस धारा में जिस हुकुम की चरचा की गई है उसे देनेवाला अधिकारी ऐसी बातों को प्रगट करे जिनको प्रगट करना वह जन-हित के खिलाफ समझता है.

(7) राजपंचायत कानून बनाकर तय कर सकती है कि—

(ए) किन हालातों में, और किस तरह की या किस किस तरह की सूरतों में किसी आदमी को धारा (4) की उप-धारा (ए) के बन्धानों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय लिये बिना, रोकथामी नज़रबन्दी का बन्धान करनेवाले किसी कानून के अधीन, किसी आदमी को तीन महीने से अधिक अरसे के लिये नज़रबन्द रखा जा सकता है;

(बी) रोकथामी नज़रबन्दी का बन्धान करनेवाले किसी कानून के अधीन, किस तरह की या किस किस तरह की सूरतों में, किसी आदमी को अधिक से अधिक कितने अरसे के लिये नज़रबन्द रखा जा सकता है; और

(सी) धारा (4) की उप-धारा (ए) के अधीन पूछताछ करने में सलाहकार बोर्ड को किस दस्तूर पर चलना होगा.

### शोशन के खिलाफ अधिकार

23—(1) इनसानों के व्यापार, और बेगार, और जबरी मजदूरी के इसी तरह के दूसरे रूपों, की मनाही की जाती है, और इस बन्धान को किसी तरह भी तोड़ना जुर्म होगा जिसकी सज़ा कानून के अनुसार दी जा सकेगी.

इनसानों के व्यापार और जबरी मजदूरी की मनाही.

(2) इस दफ़ा की कोई बात राज को सरकारी कामों के लिये जबरी सेवा लागू करने से नहीं रोकेगी और ऐसी सेवा लागू करने में केवल धर्म, नसल, जात या जमात या इनमें से किसी की बिना पर राज कोई भेदभाव नहीं करेगा.

24—चौदह बरस से कम उमर के किसी बालक को किसी फ़ैक्टरी या खदान में काम पर नहीं लगाया जायगा और न किसी और जोखम के काम पर लगाया जायगा.

फ़ैक्टरियों वगैरा में बच्चों को काम पर लगाने की मनाही

## धार्मिक आज़ादी का अधिकार

अन्तरात्मा की आज़ादी और किसी धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी

25—(1) जन-व्यवस्था, सदाचार, और तनदुरुस्ती का ध्यान रखते हुए, और इस भाग के दूसरे बन्धानों का ध्यान रखते हुए, सब लोग अन्तरात्मा की अज़ादी के, और अज़ादी के साथ अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने के अधिकार के, बराबर के हक़दार हैं.

(2) इस दफ़ा की किसी बात का किसी ऐसे मौजूदा क़ानून के अमल पर असर न होगा, न बह राज को कोई ऐसा क़ानून बनाने से रोकेगी, जो—

(ए) किन्हीं आर्थिक, माली, राजकाजी या दूसरे ऐसे दुनियावी कामों की क़ायदाबन्दी करता है या उन पर रुकावट लगाता है जिनका संबंध किसी धर्म पर अमल करने से है;

(बी) समाज की भलाई और समाज सुधार का, या हिन्दुओं की ऐसी धार्मिक संस्थाओं को जो जनता के लिये हों हिन्दुओं की सब जमातों और सब टुकड़ियों के लिये खोलने का, बन्धान करता है.

समझाव (1)—किरपान रखना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने में शामिल समझा जायगा.

समझाव (2)—धारा (2) की उप-धारा (बी) में हिन्दुओं की चरचा में सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वालों की चरचा शामिल समझी जायगी, और हिन्दू धार्मिक संस्थाओं की चरचा को भी इसी तरह समझा जायगा.

धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की आज़ादी

26—जन-व्यवस्था, सदाचार और तनदुरुस्ती का ध्यान रखते हुए, हर धार्मिक फ़िरक़े या उसकी हर टुकड़ी को अधिकार होगा कि—

(ए) धर्म और खैरात के मतलबों के लिये संस्थाएं क़ायम करे और चलाए;

(बी) धर्म के मामलों में अपने कामों का आप्र प्रबन्ध करे;

(सी) चल और अचल जायदाद की मालिक हो और इस तरह की जायदाद हासिल करे; और

(डी) क़ानून के अनुसार इस तरह की जायदाद का प्रबन्ध करे.

27—किसी आदमी को कोई ऐसे टैक्स देने के लिये मजबूर नहीं किया जायगा जिसकी वसूली की बाबत यह तय है कि वह किसी विशेष धर्म या धार्मिक फ़िरके को बढ़ाने या बनाए रखने के खर्च की मद में डाली जाय.

28—(1) किसी ऐसी तालीमी संस्था में जिसका कुल खर्च राज के रूप से चलता हो किसी धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जायगा.

(2) धारा (1)की कोई बात किसी ऐसी तालीमी संस्था पर लागू न होगी जिसका प्रबन्ध राज करता है पर जो किसी ऐसे देन या ट्रस्ट के अधीन क़ायम की गई हो, जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना दरकार हो.

(3) किसी भी आदमी के लिये जो किसी ऐसी तालीमी संस्था में जाता हो जो राज की तरफ से मानी हुई है या जिसे राज के रूप से सहायता मिलती है यह दरकार नहीं होगा कि वह किसी ऐसी धार्मिक शिक्षा में भाग ले जो उस संस्था में दी जाती हो, या किसी ऐसी धार्मिक पूजा बंदगी में हाज़िर हो जो उस संस्था में या उससे संबंध रखने वाली किसी जगह पर की जाती हो, जब तक कि उस आदमी ने या अगर वह नाबालिग है तो उसके संरक्षक ने इसके लिये अपनी अनुमति न दे दी हो.

### कलचरी और तालीमी अधिकार

29—(1) भारत के भूभाग में या उसके किसी भाग में बसने वाले नागरों की किसी ऐसी टुकड़ी को जिसकी अपनी अलग भाशा, लिखावट या कलचर है, उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा.

(2) राज से चलाई जाने वाली या राज के रूप से सहायता पाने वाली किसी तालीमी संस्था में किसी भी नागर को केवल धर्म, नस्ल, जात, भाशा या इनमें से किसी की बिना पर दाखिल करने से इनकार नहीं किया जायगा.

30—(1) सब कमीयतों को, चाहे वह धर्म के आधार पर हों चाहे भाशा के, अपनी पसन्द की तालीमी संस्थाएँ क़ायम करने और उनका प्रबन्ध करने का अधिकार होगा.

(2) तालीमी संस्थाओं के लिये सहायता मंजूर करने में राज

किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिये टैक्स देने के बारे में आज्ञादी

कुछ तालीमी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा बंदगी में हाज़िरी के बारे में आज्ञादी

कमीयतों के हितों की रक्षा

कमीयतों को तालीमी संस्थाएँ क़ायम करने और उनके प्रबन्ध करने का अधिकार

किसी तालीमी संस्था से इस बिना पर भेदभाव नहीं बरतेगा कि वह संस्था किसी कमीयत के प्रबन्ध में है, चाहे वह कमीयत धर्म के आधार पर हो और चाहे भाषा के.

### जायदाद का अधिकार

जायदाद का जबरन  
हासिल करना

31—(1) किसी आदमी को उसकी जायदाद से बेदखल नहीं किया जायगा जबतक कानून इसका अधिकार न दे.

(2) किसी जायदाद पर चाहे वह चल हो या अचल, और चाहे वह किसी तिजारती या उद्योगी कारबार में किसी तरह के हित के रूप में हो, या किसी ऐसी कम्पनी में किसी तरह के हित के रूप में हो जो किसी तिजारती या उद्योगी कारबार की मालिक है, किसी ऐसे कानून के अधीन जो इस तरह की जायदाद पर सरकारी कामों के लिये कब्जा करने या उसे हासिल करने का अधिकार देता है, तब तक कब्जा नहीं किया जायगा, न उसे हासिल किया जायगा जब तक कि उस कानून में जायदाद पर इस तरह कब्जा करने या उसे हासिल करने की नुकसान-भरपाई देने का बन्धान न हो, और या तो इस नुकसान-भरपाई की रकम तय कर दी गई हो या वह सिद्धान्त और वह ढंग बता दिये गए हों जिनसे नुकसान - भरपाई की रकम तय की जानी है और दी जानी है.

(3) धारा (2) में किसी रियासत की कानूनसभा के बनाए जिस कानून की चरचा की गई है उसका तब तक कोई असर नहीं होगा जब तक कि उसे राजपति के विचार के लिये अलग रखे जाने के बाद राजपति की मंजूरी न मिल गई हो.

(4) अगर कोई बिल इस विधान के आरम्भ होने पर किसी रियासत की कानून सभा में पेश था और वह उस कानून सभा में पास हो गया हो और उसके बाद राजपति के विचार के लिये अलग रखा गया हो और राजपति ने उस पर अपनी मंजूरी दे दी हो तो इस विधान में किसी बात के रहते भी, इस तरह मंजूर हुए कानून पर किसी अदालत में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि वह धारा (2) के बन्धानों के खिलाफ पड़ता है.

(5) धारा (2) की किसी बात का—

(ए) धारा (6) के बन्धान जिस क़ानून पर लागू होते हैं उसको छोड़कर किसी मौजूदा क़ानून के बन्धानों पर, या—

(बी) किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों पर, जो राज आगे चलकर—

(1) कोई टैक्स या दंड लगाने के मतलब के लिये बनाए, या

(2) जन-तन्दुरुस्ती को बढ़ाने या जान या माल को ख़तरे से बचाने के लिये बनाए, या

(3) किसी ऐसी जायदाद के बारे में जिसे क़ानून ने घरछुट जायदाद ठहरा दिया हो, हिन्द डोमिनियन की सरकार या भारत सरकार और किसी दूसरे देश की सरकार के बीच किसी समझौते की तामील में या किसी दूसरी तरह बनाए,

असर नहीं होगा.

(6) राज का कोई क़ानून जो इस विधान के आरंभ होने से पहले, अठारह महीने के अन्दर अन्दर बनाया गया हो, विधान के आरंभ होने के बाद तीन महीने के अन्दर राजपति के सामने उसकी सनद के लिये रखा जा सकता है; और इस पर अगर राजपति आमनोटिस निकालकर सनद कर दे तो उस क़ानून पर किसी अदालत में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि वह इस दफ़ा की धारा

(2) के बन्धानों के खिलाफ़ पड़ता है या कि वह हिन्द सरकार एक्ट, 1935, दफ़ा 299 की उपदफ़ा (2) के बन्धानों के खिलाफ़ है.

### विधानी उपायों का अधिकार

32—(1) इस भाग में दिये अधिकारों पर अमल कराने के लिये आला अदालत में मुनासिब कारवाइयों से फ़रियाद करने के अधिकार की गारंटी की जाती है.

(2) इस भाग में दिये अधिकारों में से किसी पर अमल कराने के लिये आला अदालत को शक्ति होगी कि ऐसे आदेश या हुक्म या परवाने, जिनमें परवाना तनतलबी, परवाना हुक्म, परवाना मनाही, परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिसल-मंगाई जैसे परवाने शामिल हैं, जो भी मुनासिब हो, जारी करे.

इस भाग में दिये अधिकारों पर अमल कराने के लिये उपाय

(3) धारा (1) और (2) से आला अदालत को जो शक्तियाँ दी गई हैं उन्हें कम किये बिना, राजपंचायत कानून बनाकर किसी दूसरी अदालत को उसकी अमलदारी की मुकामी सीमाओं के अन्दर उन सब शक्तियों या उनमें से किसी शक्ति से काम लेने का अधिकार दे सकती है, जिनसे आला अदालत धारा(2) के अधीन काम ले सकती है.

(4) इस दफा से गारंटी किया हुआ अधिकार मुअत्तल नहीं किया जायगा सिवाय इसके कि इस विधान में किसी दूसरी तरह का बन्धान कर दिया गया हो.

इस भाग में दिये अधिकारों के फ़ौजों के लिये लागू होने पर उनमें बदल बदल करने की राजपचायत की शक्ति

33—राजपंचायत कानून बनाकर यह तय कर सकती है कि इस भाग में दिये अधिकारों में से किसी को, हथियारबन्द फ़ौजों या उन फ़ौजों के लोगों के लिये जिनपर जन-व्यवस्था बनाए रखने का भार है लागू होने पर, कहां तक कम किया जा सकता है या रह किया जा सकता है, जिससे इस बात का पक्का भरोसा हो जाए कि फ़ौजें अपने फ़रजों का उचित पालन कर सकें और उनमें क्रायदादारी बनी रहे.

जब किसी क्षेत्र में फ़ौजी कानून लागू हो तो इस भाग में दिये अधिकारों पर रुकावट

34—इस भाग में ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत कानून बनाकर किसी आदमी को जो यूनियन की या किसी रियासत को नौकरी में है या किसी दूसरे आदमी को किसी ऐसे काम के बारे में बरीयत दे सकती है जो उसने भारत के भूभाग में किसी ऐसे क्षेत्र के अन्दर जहाँ फ़ौजी कानून लागू था व्यवस्था बनाए रखने या फिर से व्यवस्था क्रायम करने के सम्बन्ध में किया हो, या उस क्षेत्र में फ़ौजी कानून के अधीन अगर कोई सजा का हुकुम दिया गया हो, या सजा दी गई हो, या ज़बती का हुकुम दिया गया हो, या और कोई काम किया गया हो तो उसे सरदुरुस्त ठहरा सकती है.

इस भाग के बन्धानों को अमल में लाने के लिये कानून बनाना

35—इस विधान में किसी बात के रहते भी—

(ए) राजपंचायत को यह शक्ति होगी, और किसी रियासत की कानूनसभा को नहीं होगी, कि—

(एक) जिन मामलों के लिये दफा 16 की धारा (8), दफा 32 की धारा (8), और दफा 33 और 34 के

अधीन राजपंचायत कानून बना सकती है, उनमें से किसी के लिये; और

(दो) इस भाग में जिन कामों को जुर्म ठहराया गया है उनकी सजा तय करने के लिये;

कानून बनाए,

और राजपंचायत इस विधान के आरंभ होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उन कामों के लिये जिनकी उपधारा (दो) में चरचा की गई है, सजा तय करने के लिये कानून बनाएगी।

(बी) धारा (ए) की उपधारा (एक) में जिन मामलों की चरचा की गई है उनमें से किसी के बारे में, या उस धारा की उपधारा (दो) में जिस किसी काम की चरचा की गई है उसके लिये सजा का बन्धान करने वाला, कोई कानून जो भारत के भूभाग में इस विधान के आरम्भ होने से ठीक पहले लागू था, अपनी शर्तों के अधीन और उन अनुकूलनों या अदल बदल के अधीन जो दफा 372 के अधीन उस कानून में किये जायँ, तब तक लागू रहेगा जब तक कि राजपंचायत उसे बदल न दे, या रद्द न कर दे, या उसमें सुधार न कर दे।

समझाव :—इस दफा में “लागू कानून” शब्दों के वही मानी हैं जो दफा 372 में हैं।

## भाग चार

### राज की नीति के निर्देशक सिद्धान्त

परिभाषा

36—अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तो इस भाग में “राज” के वही मानी हैं जो भाग तीन में.

इस भाग में आए सिद्धान्तों को लागू करना

37—इस भाग में आए बन्धानों पर किसी अदालत के जरिये अमल नहीं कराया जा सकेगा, पर फिर भी इनमें बताए सिद्धान्त देश की हुकूमत की नींव हैं और कानून बनाने में इन सिद्धान्तों को लागू करना राज का फरज होगा.

लोगों की खुशहाली बढ़ाने के लिये राज का एक समाजी व्यवस्था को पक्का करना

38—राज की कोशिश होगी कि जितने भी असरदार ढंग से हो सके एक ऐसी समाजी व्यवस्था को पक्का करके और उसकी रक्षा करके, जिसमें समाजी, आर्थिक और राजकाजी इन्साफ़ क़ौमी जीवन की सब संस्थाओं में समाया हुआ हो, लोगों की खुशहाली को बढ़ाए.

नीति के कुछ सिद्धान्त जिनपर राज चलेगा

39—राज खास कर अपनी नीति को ऐसे चलायगा कि :—

(ए) सब नागरों को, नर और नारी को एक बराबर, रोज़ी के काफ़ी साधन मिलने का अधिकार हो;

(बी) समाज के माही साधनों की मिलकियत और उनपर दबान इस तरह बँटे हों कि जिससे सबका बहुत से बहुत भला हो ;

(सी) अर्थ-व्यवस्था के चलने का यह नतीजा न हो कि धन और पैदावार के साधन इस तरह कील दिये जाएँ जिससे आम लोग घाटे में रहें;

(डी) नर और नारी दोनों को बराबर काम के लिये बराबर का वेतन मिले;

(ई) नर नारी कामगारों की तन्दुरुस्ती और शक्ति और बालकों की कच्ची उमर का बुरा उपयोग न हो, और आर्थिक जरूरतों से मजबूर होकर नागरों को ऐसे रोज़गारों में न जाना पड़े जो उनकी उमर या शक्ति के अनुकूल न हों;



(एफ) शोशन से और नैतिक आवारगी और बेघरवारगी से बच्चों और नौजवानों को बचाया जाय.

40—राज गांव-पंचायतों का संगठन करने के लिये कदम उठाया जाय और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वराज की इकाइयों के रूप में काम करने के जोग बनाने के लिये जरूरी हों.

41—राज, अपनी आर्थिक सकत और विकास की सीमाओं के अन्दर रहते हुए, सबको काम पाने, तालीम पाने, और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अंगभंग हो जाने, और दूसरी अनकरी जरूरतों में सरकारी मदद पाने का अधिकार दिलाने का असरदार प्रबन्ध करेगा.

42—राज काम की हालतों में न्याय और इनसानियत का और औरतों को जापामदद दिलाने का प्रबन्ध करेगा.

43—राज उचित कानून बनाकर या आर्थिक संगठन करके या और जिस तरह हो जतन करेगा कि खेतिहरों, मिल-मजदूरों और दूसरे सब कामगारों को काम और पेटभर मजदूरी मिले, और वह ऐसी हालतों में काम करें जिनसे यह भरोसा हो जाय कि उनके रहन सहन का ढंग भले लोगों का सा है, और वे फुरसत के समय से, और समाजी और कलचरी अवसरों से पूरा लाभ उठा सकें, और खास कर राज देहातों में घरेलू उद्योगों को निजी या सहकारी आधार पर बढ़ाने का जतन करेगा.

44—राज इस बात का जतन करेगा कि भारत के सारे भूभाग में नागरों के लिये एक सी दीवानी पद्धत हो.

45—राज इस विधान के आरम्भ होने से दस बरस के अरसे के अन्दर सब बच्चों को उनके चौदह बरस की उमर पूरी करने तक मुफ्त और जबरी तालीम देने का जतन करेगा.

46—राज जनता की निबल टुकड़ियों के, और खास कर पट्टी-दर्ज जातियों और पट्टी दर्ज कबीलों के तालीमी और आर्थिक हितों को खास सावधानी से बढ़ाया जाय और समाजी अन्याय और सब तरह के शोशन से उनकी रक्षा करेगा.

गांव पंचायतों का संगठन

काम, तालीम और कुछ सूतों में सरकारी मदद पाने का अधिकार

काम को हालतों में न्याय और इनसानियत का और जापामदद का प्रबन्ध कामगारों के लिये पेटभर मजदूरी वगैरा

नागरों के लिये एकसी दीवानी पद्धत बच्चों के लिये मुफ्त और जबरी तालीम का प्रबन्ध

पट्टी-दर्ज जातियों, पट्टी-दर्ज कबीलों और दूसरी निबल टुकड़ियों के तालीमी और आर्थिक हितों को बढ़ाना

तनपालन तल और  
जीवनस्तर को ऊँचा  
करना और जन-  
तन्दुरुस्ती को सुधा-  
रना राज का फ़रज़

47—राज अपने लोगों की ख़ुराक में तनपालन-तल और उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना और जन-तन्दुरुस्ती का सुधारना अपने सबसे पहले फ़रज़ों में से मानेगा, और खास कर नशीले पानों और तन्दुरुस्ती बिगाड़नेवाली जड़ी-बूटियों की, सिवाय दवा के मतलबों के लिये, खपत बन्द कराने का जतन करेगा.

खेतीबाड़ी और पशु-  
पालन का संगठन

48—राज खेतीबाड़ी और पशुपालन का नई और साइंसी रीतियों के अनुसार संगठन करने का जतन करेगा, और खास कर गायों और बछड़ों और दूसरे दुधारी और भारवाही ढोरों की नसलों को बनाए रखने और सुधारने के लिये और उनके बध को रोकने के लिये क़दम उठायगा.

क्रौमी महत्व की  
यादगारों और  
जगहों और चीज़ों  
की रक्षा

49—राज के लिये लाज़मी होगा कि हर ऐसी यादगार या जगह या चीज़ को, जो कला या इतिहास की निगाह से दिलचस्प हो, और जिसे राजपंचायत ने क़ानून बनाकर क्रौमी महत्व का ठहरा दिया हो, लूट खसोट, रूप बिगाड़, बरबादी, हटाए जाने, दे डाले जाने या देश से बाहर भेजे जाने से, जैसी सूरत हो, बचावे.

काजकारी से न्याय-  
कारी का अलग  
करना

50—राज अपनी सरकारी नौकरियों से न्यायकारी को काजकारी से अलग करने के लिये क़दम उठायगा.

अन्तर-क्रौमी शान्ति  
और सुरक्षा को  
बढ़ाना

51—राज,

- (ए) अन्दर-क्रौमी शान्ति और सुरक्षा को बढ़ाने का;
- (बी) क्रौमों के बीच न्यायी और सम्मानी रिश्तों को बनाए रखने का;
- (सी) संगठित क्रौमों के एक दूसरे से बरताव में अन्तर-क्रौमी क़ानून और सन्धि-बन्धनों के लिये आदर बढ़ाने का; और
- (डी) अन्तर-क्रौमी मग़ाड़ों को पंचक़ैसले से निपटाने के लिये बढ़ावा देने का,  
जतन करेगा.

## भाग पाँच

### यूनियन

खंड एक—काजकारी

राजपति और उपराजपति

52—भारत का एक राजपति होगा.

भारत का राजपति

53—(1) यूनियन की काजकारी शक्ति राजपति को हासिल होगी और वह उससे खुद या अपने अधीन अफसरों के जरिये इस विधान के अनुसार काम लेगा. यूनियन की काजकारी शक्ति

(2) ऊपर बताए बन्धान की आमियत में कमी किये बिना यूनियन की बचाव फौजों की आला कमान राजपति को हासिल होगी और उस कमान से काम लेने की कायदाबन्दी कानून से की जायगी.

(3) इस दफा की किसी बात से—

(ए) जो काम किसी मौजूदा कानून ने किसी रियासत को सरकार या दूसरे अधिकारी को सौंपे हैं वह काम राजपति को तबदीले नहीं समझे जायंगे; या

(बी) राजपति को छोड़ दूसरे अधिकारियों को कानून बनाकर काम सौंपने से राजपचायत को नहीं रोका जायगा.

54—राजपति को एक चुनाव मंडल के मेम्बर चुनेंगे जिसमें—

राजपति का चुनाव

(ए) राजपचायत के दोनों सदनों के चुने हुए मेम्बर; और

(बी) रियासतों के आम सदनों के चुने हुए मेम्बर, होंगे.

55—(1) जहाँ तक बन पड़ेगा राजपति के चुनाव में अलग अलग रियासतों के प्रतिनिधान के पैमाने में एकरूपता होगी.

राजपति के चुनाव का ढंग

(2) रियासतों के बीच आपस में ऐसी एकरूपता लाने के लिये, और कुल रियासतों और यूनियन के बीच बराबरी रखने के लिये, राजपचायत का और हर रियासत के आमसदन का हर चुनाव हुआ मेम्बर चुनाव में जितने वोट देने का हकदार होगा उनकी तादाद नीचे लिखे ढंग से तय की जायगी :—

(ए) किसी रियासत के आमसदन के हर चुने हुए मेम्बर के इतने वोट होंगे जितने कि एक हजार के गुने हय

भागफल में हों जो रियासत की आबादी को आम-सदन के चुने हुए मेम्बरों की कुल गिनती से भाग देने से आए.

(बी) ऊपर बताए एक हज़ार के गुनों को लेने के बाद अगर बाक़ी पांच सौ से कम न हो तो हर उस मेम्बर का जिसकी चरचा उपधारा (ए) में की गई है, एक वोट और बढ़ जायगा.

(सी) राजपंचायत के दोनों सदनों के हर चुने हुए मेम्बर के वोटों की गिनती वही होगी जो उपधारा (ए) और (बी) के अधीन रियासतों के आम सदनों के मेम्बरों को दिए हुए वोटों की कुल गिनती को राजपंचायत के दोनों सदनों के चुने हुए मेम्बरों की कुल गिनती से भाग देने से आए, जिसमें आधे से अधिक टुक को एक गिना जायगा और बाकी टुकों को नहीं गिना जायगा.

(3) राजपति का चुनाव निसबती प्रतिनिधान के ढंग के अनुसार इकहरे बदलते वोट से होगा और ऐसे चुनाव में वोट बन्द परचियों से लिये जायंगे.

समझाव :—इस दफ़ा में “आबादी” शब्द के मानी वह आबादी है जो उस पिछले आखिरी गिनावे में मालूम की गई है जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं.

राजपति की पद-  
मियाद

56—(1) राजपति अपना पद संभालने की तारीख से पांच बरस की मियाद तक पद पर रहेगा :

शर्तें कि—

(ए) राजपति उप-राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है.

(बी) विधान तोड़ने पर राजपति उस ढंग से दोश लगाकर पद से हटाया जा सकता है जिसका बंधान दफ़ा 61 में किया गया है .

(सी) राजपति अपनी मियाद पूरी हो जाने पर भी अपने पदगाही के पद संभालने तक पद पर रहेगा.

(2) धारा (1) की शर्त की धारा (ए) के अधीन उप-राजपति के नाम इस्तीफे की सूचना उप-राजपति तुरन्त लोकसदन के सभामुख को देगा।

57—कोई आदमी जो राजपति के पद पर है या रह चुका है इस विधान के दूसरे बंधानों का ध्यान रखते हुए उस पद के लिये फिर चुने जाने का पात्र होगा।

फिर चुनाव के लिए पात्रता

58—(1) कोई आदमी राजपति चुने जाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह—

राजपति चुने जाने के लिए योग्यताएँ

(ए) भारत का नागरिक न हो,

(बी) अपनी उमर का पैंतीसवाँ बरस पूरा न कर चुका हो, और

(सी) लोकसदन का मेम्बर चुने जाने की योग्यता न रखता हो।

(2) कोई आदमी जो भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के अधीन या इन सरकारों में से किसी के दबान में किसी मुकामी या दूसरे अधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर है, राजपति चुने जाने का पात्र नहीं होगा।

समझाव :—इस दफ्ता के मतलबों के लिये कोई आदमी केवल इसी कारन किसी लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि वह यूनियन का राजपति या उप-राजपति या किसी रियासत का रियासत-पति या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख है या यूनियन का या किसी रियासत का वजीर है।

59—(1) राजपति न तो राजपंचायत के किसी सदन का मेम्बर होगा और न किसी रियासत की कानूनसभा का मेम्बर होगा, और अगर राजपंचायत के किसी सदन का या किसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर राजपति चुना जाय तो यह समझा जायगा कि उसने उस सदन की अपनी जगह उस तारीख से सूनी कर दी है जिस दिन उसने राजपति का पद संभाला।

राजपति के पद की शर्तें

(2) राजपति किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं रहेगा।

(3) राजपति को अपने सरकारी मकानों को बिना किराया दिये इस्तेमाल करने का अधिकार होगा, और वह उस वेतन, भत्तों

और निज़नियमों को पाने का हक़दार होगा जो राजपंचायत क़ानून बनाकर तय करे, और जब तक इसके लिये इस तरह प्रबन्ध न हो तब तक वह उस वेतन, भत्तों और निज़नियमों को पाने का हक़दार होगा जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

(4) राजपति का वेतन और भत्ते उसकी पद-मियाद के दौरान में घटाए नहीं जायेंगे.

राजपति का हलफ़  
उठाना या वचन  
भरना

60—हर राजपति और हर आदमी जो राजपति की जगह काम करेगा या उसके काम निभारेगा, अपना पद संभालने से पहले, भारत के सरजज या उसके मौजूद न होने पर आला अदालत के उस बड़े से बड़े जज के सामने जो मिल सके, नीचे दिये रूप में हलफ़ उठायगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा, यानी यह कि—

“मैं.....(नाम)..... ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत गम्भीरता से वचन भरता हूँ

के राजपति के पद पर रह कर वफ़ादारी से काम करूंगा ( या भारत के राजपति के काम वफ़ादारी से निभाऊंगा) और अपनी पूरी जोगता से विधान और कानून को बनाए रखूंगा, उनकी रक्षा और उनका बचाव करूंगा, और मैं भारत के लोगों की सेवा और उनकी भलाई में तन मन से लगा रहूंगा.”

राजपति पर दोष-  
लगाने का दस्तूर

61—(1) जब किसी राजपति पर विधान तोड़ने का दोष लगाना हो तो राजपंचायत का कोई एक सदन दोष-लेखा पेश करेगा,

(2) ऐसा कोई दोष-लेखा पेश नहीं किया जायगा जब तक कि—

(ए) दोष-लेखा पेश करने का सुझाव एक ऐसे ठहराव में न रखा गया हो जिसे पेश करने के इरादे का लिखा नोटिस उस सदन के मेम्बरों की कुल गिनती के कम से कम एक चौथाई के दसखत से कम से कम चौदह दिन पहले न दिया जा चुका हो, और उसके बाद वह ठहराव पेश न किया गया हो; और

(बी) उस सदन के कुल मेम्बरों की कम से कम दो तिहाई

ने ————— किया हो

(3) जब राजपंचायत का कोई सदन इस तरह दोश-लेखा पेश कर दे तो दूसरा सदन उस दोश-लेखे की जांच करेगा या जांच करायगा, और इस तरह की जांच में आने और अपना प्रतिनिधि भेजने का राजपति को अधिकार होगा.

(4) अगर जांच का नतीजा यह हो कि जिस सदन ने दोश-लेखे की जांच की थी या कराई थी उसके कुल मेम्बरों की कम से कम दो तिहाई बड़ीयत यह ठहराव पास कर दे कि जो दोश-लेखा राजपति के खिलाफ पेश किया गया था वह ठीक साबित हो गया है, तो उस ठहराव का यह असर होगा कि ठहराव के इस तरह पास होने की तारीख से राजपति अपने पद से हट जायगा.

62—(1) राजपति की पद-मियाद पूरी हो जाने से पैदा हुई सूनी को भरने के लिये चुनाव मियाद पूरी होने से पहले ही पूरा कर लिया जायगा.

(2) राजपति की मौत हो जाने, उसके इस्तीफा देने या हटाए जाने या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना हो जाने पर उस सूनी को भरने के लिये चुनाव सूनी होने की तारीख के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा और हर सूरत में उस तारीख से छै महीने के अन्दर किया जायगा, और सूनी को भरने के लिये जो आदमी चुना जाय वह, दफा 56 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, अपने पद संभालने की तारीख से लेकर पांच बरस की पूरी मियाद तक पद पर रहने का हकदार होगा.

63—भारत का एक उप-राजपति होगा.

64—उप-राजपति पदनाते रियासत सदन का मसनदी होगा और दूसरे किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा :

शर्तें कि जब जितने अरसे तक उप-राजपति राजपति की जगह काम करेगा या दफा 65 के अधीन राजपति के काम निभारेगा तब उस अरसे तक वह रियासत-सदन के मसनदी के पद के फरज अदा नहीं करेगा, और दफा 97 के अधीन रियासत सदन के मसनदी को मिलने वाली किसी तनखा या भत्ते का हकदार न होगा.

राजपति के पद की सूनी को भरने के लिये चुनाव का समय और औसरी सूनी भरने के लिये जुने आदमी की पद मियाद

भारत का उप-राज-पति  
उप-राजपति पदनाते रियासत सदन का मसनदी होगा

राजपति की नामौजूदगीमें या उसके पद की औसरी सूनियों के समय उप-राजपति का राजपतिकी जगह काम करना या उसके पद के काम निभारना

65—(1) राजपति की मौत हो जाने, उसके इस्तीफा देने या हटाए जाने या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना होने की सूरत में उप-राजपति उस तारीख तक राजपति की जगह काम करेगा जब तक कि उस सूनी को भरने के लिये इस खंड के बन्धानों के अनुसार चुना हुआ नया राजपति अपना पद न संभाल ले.

(2) नामौजूदगी, बीमारी या दूसरे किसी कारन से जब राजपति अपने काम निभारने के अजोग हो तब उप-राजपति उसके काम उस तारीख तक निभारेगा जिस तारीख को राजपति फिर से अपने फरज संभाल ले.

(3) उप-राजपति को उस अरसे में और उसके बारे में जब वह इस तरह राजपति की जगह काम कर रहा हो या उसके कामों को निभार रहा हो, राजपति की सब शक्तियां और बरीयतें होंगी, और वह उस वेतन, भत्तों और निजनियमों को पाने का हकदार होगा जो राजपंचायत कानून बनाकर तय कर दे, और जब तक इसके लिये इस तरह बन्धान नहीं किया जाता तब तक वह उस वेतन, भत्तों और निजनियमों का हकदार होगा जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

उप-राजपति का चुनाव

66—(1) उप-राजपति राजपंचायत के दोनों सदनों के मेम्बरों की मिलीजुली मिलनी में निसबती प्रतिनिधान के ढंग के अनुसार इकट्ठे बदलते वोट से चुना जायगा और ऐसे चुनाव में वोट बन्द परिचियों से लिये जायंगे.

(2) उप-राजपति राजपंचायत के किसी सदन या किसी रियासत की कानूनसभा के किसी सदन का मेम्बर नहीं होगा, और अगर राजपंचायत के किसी सदन या किसी रियासत की कानूनसभा के किसी सदन का कोई मेम्बर उप-राजपति चुना जाय तो यह समझा जायगा कि उसने उस सदन की अपनी जगह उस तारीख को सूनी कर दी जिस तारीख को उसने उप-राजपति का पद संभाला.

(3) कोई आदमी उप-राजपति चुने जाने का पात्र न होगा जब तक कि वह—

(ए) भारत का नागर न हो ;



- (बी) अपनी उमर का पैंतीसवां बरस पूरा न कर चुका हो; और  
(सी) रियासत सदन का मेम्बर चुने जाने की जोगता न रखता हो.

(4) कोई आदमी जो भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के अधीन या उन सरकारों में से किसी के दबान में किसी मुकामी या दूसरे अधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर है, उप-राजपति चुना जाने का पात्र न होगा.

समझाव:—इस दफा के मतलबों के लिये कोई आदमी केवल इसी लिये किसी लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि वह यूनियन का राजपति या उप-राजपति है या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख है या यूनियन या किसी रियासत का वज्जीर है.

67—उप-राजपति अपने पद संभालने की तारीख से पांच बरस की मियाद तक पद पर रहेगा:

उप-राजपति की  
पद-मियाद

शर्तें कि—

(ए) उप-राजपति राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है ;

(बी) उप-राजपति रियासत सदन के ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे रियासतसदन के उस समय के सब मेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया हो और जिसे लोकसभा ने मान लिया हो; पर इस धारा के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश न किया जायगा जबतक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दे दिया गया हो;

(सी) उप-राजपति अपनी मियाद पूरी हो जाने पर भी अपने पदगाही के पद संभालने तक पद पर बना रहेगा.

68—(1) उप-राजपति की पद-मियाद के पूरा हो जाने से पैदा हुई सूनी को भरने के लिये चुनाव मियाद पूरी होने से पहले ही पूरा कर लिया जायगा.

(2) उप-राजपति की मौत हो जाने, उसके इस्तीफा देने या हटाए जाने, या किसी दूसरे कारन से उसका पद सूना हो जाने पर उस

उप-राजपति के  
पद की सूनी  
को भरने के लिये  
चुनाव का समय  
और औसरी सूनी  
भरने के लिये चुने

आदमी की पद-  
मियाद

सूनी को भरने के लिये चुनाव, सूनी होने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा, किया जायगा, और सूनी को भरने के लिये जो आदमी चुना जाय वह दफ्ता 67 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए अपना पद संभालने की तारीख से लेकर पाँच बरस की पूरी मियाद तक पद पर रहने का हकदार होगा।

उप-राजपति का  
हलफ उठाना या  
वचन भरना

69—हर उप-राजपति अपना पद संभालने से पहले राजपति के सामने या किसी आदमी के सामने जिसे राजपति इस काम के लिए नियोजे नीचे लिखे रूप में हलफ उठायगा या वचन भरेगा, यानी कि—

“मैं.....(नाम).....ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के गम्भीरता से वचन भरता हूँ

उस विधान का जो कानून से कायम हुआ है सचार्ड से वफादार और भक्त रहूँगा और जो फरज मैं अब संभालने वाला हूँ उसे वफादारी के साथ निभारूँगा।”

दूसरे जोगाजोगों में  
राजपति के कामों  
को निभारना

70—किसी ऐसे जोगाजोग में जिसका इस खंड में बन्धान नहीं किया गया है, राजपति के काम निभारने के लिये राजपंचायत जैसा उचित समझे बन्धान कर सकती है।

राजपति या उप-  
राजपति के चुनाव  
के बारे में या  
उससे सम्बन्ध रखने  
वाले मामले

71—(1) राजपति या उप-राजपति के चुनाव से पैदा होने वाले या उसके बारे में सब संदेहों और झगड़ों की पूछताछ और उनका फैसला आला अदालत करेगी, और उसका फैसला आखिरी होगा।

(2) अगर किसी आदमी का राजपति या उप-राजपति चुना जाना आला अदालत रद्द ऐलान कर दे, तो राजपति के या उप-राजपति के, जैसी सूरत हो, अपने पद की शक्तियों से काम लेने और अपने फरज पूरा करने के दौरान में उसने, आला अदालत के फैसले की तारीख पर या उससे पहले, जो काम किये हों वह उस ऐलान के कारन नों-सरदुहस्त नहीं माने जायेंगे।

(3) इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए राजपति या उप-राजपति के चुनाव के संबंध में या उसकी बाबत किसी मामले की कायदाबन्दी राजपंचायत कानून बनाकर कर सकती है।

72—(1) किसी आदमी को जिसे किसी जुर्म का दोशी ठहराया गया हो माफ़ कर देने, उसकी सज़ा मुलतवी कर देने, उसे मुहलत देने या बाकी सज़ा माफ़ कर देने या उसकी सज़ा के हुकुम को रोक देने, सज़ा के बाकी हुकुम को रद्द कर देने, या सज़ा का रूप बदल देने की शक्ति राजपति को उन सब सूरतों में होगी—

कुछ सूरतों में माफ़ी वगैरा देने और सज़ाओं के हुकुम को रोक रखने या कम करने या बदलने की राजपति की शक्ति

(ए) जिनमें किसी फ़ौजी अदालत ने सज़ा दी हो या सज़ा का हुकुम दिया हो ;

(बी) जिनमें सज़ा या सज़ा का हुकुम किसी ऐसे क़ानून के अधीन जुर्म के लिये दिया गया हो जिस क़ानून का संबंध किसी ऐसे मामले से है जिस तक यूनियन की काजकारी शक्ति का फैलाव है ;

(सी) जिनमें हुकुम मौत की सज़ा का हुकुम है.

(2) धारा (1) की उपधारा (ए) की किसी बात का उस शक्ति पर कोई असर नहीं होगा जो यूनियन की हथियारबन्द फ़ौजों के किसी अफ़सर को किसी फ़ौजी अदालत के दिये हुए सज़ा के हुकुम को रोक देने, कम कर देने या बदल देने के लिये क़ानून से दी गई हो.

(3) धारा (1) की उपधारा (सी) की किसी बात का उस शक्ति पर कोई असर नहीं होगा जिससे उस समय लागू किसी क़ानून के अधीन किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख मौत की सज़ा को रोक देने, माफ़ कर देने या दूसरी सज़ा में बदल देने के लिये काम ले सकता हो.

73—(1) इस विधान के बंधानों के अधीन रहते हुए यूनियन की काजकारी शक्ति का फैलाव—

यूनियन की काजकारी शक्ति का फैलाव

(ए) उन मामलों तक होगा जिनके बारे में राजपंचायत को क़ानून बनाने की शक्ति है ;

भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में ऐसे मामलों तक न होगा जिनके बारे में रियासत की कानूनसभा को भी कानून बनाने की शक्ति है, सिवाय जब कि इस विधान में या राजपंचायत के बनाए किसी कानून में इसका साफ तौर पर बन्धान कर दिया गया हो.

(2) जबतक राजपंचायत कुछ और बन्धान न करे, तबतक इस दफा में किसी बात के रहते भी, कोई रियासत और किसी रियासत का कोई अफसर या अधिकारी उन मामलों में जिनके बारे में राजपंचायत को उस रियासत के लिये कानून बनाने की शक्ति है, ऐसी काजकारी शक्ति से काम ले सकता है या ऐसे काम कर सकता है जिससे कि वह रियासत या उसके अफसर या अधिकारी इस विधान के आरंभ से ठीक पहले काम ले सकते थे या काम कर सकते थे.

### वज़ीर मंडल

राजपति को सहायता  
और सलाह देने के  
लिये वज़ीर मंडल

74—(1) राजपति को उसके काम पूरा करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक वज़ीर मंडल होगा जिसका सरमुख प्रधान वज़ीर होगा.

(2) किसी अदालत में इस बात की पूछताछ नहीं की जा सकेगी कि वज़ीरों ने राजपति को कोई सलाह दी या नहीं और अगर दी तो क्या दी.

वज़ीरों के बारे में  
दूसरे बन्धान

75—(1) प्रधान वज़ीर का नियोजन राजपति करेगा, और दूसरे वज़ीरों का नियोजन राजपति प्रधान वज़ीर की सलाह से करेगा.

(2) वज़ीर अपने पद पर राजपति के इच्छाकाल तक रहेंगे.

(3) वज़ीरमंडल के वज़ीर सबके सब मिलकर लोकसदन को जिम्मेदार होंगे.

(4) किसी वज़ीर के अपना पद संभालने से पहले राजपति उससे तीसरी पट्टी में इस मतलब के लिये दिये हुए रूपों के अनुसार पद और राजदारी के हलफ़ उठवायागा.

(3) राजपति भारत सरकार के काम को अधिक आसानी से चलाने के लिये और उस काम को वज्जीरों में बांटने के लिये नियम बनायगा.

राजपति को सूचना देने वगैरा के बारे में बड़े वज्जीर के फ़रज़

78—बड़े वज्जीर का फ़रज़ होगा कि—

(ए) यूनियन के मामलों के शासन सम्बन्धी वज्जीर मंडल के सारे फ़ैसले और क़ानून बनाने के सब सुझाव राजपति को पहुँचावे;

(बी) यूनियन के मामलों के शासन सम्बन्धी और क़ानून बनाने के सुझाव सम्बन्धी जो बातें राजपति पूछे उसको बताए; और

(सी) राजपति के चाहने पर किसी ऐसे मामले को, जिस पर किसी एक वज्जीर ने फ़ैसला कर दिया है पर वज्जीर मंडल ने विचार नहीं किया है, वज्जीरमंडल के सामने विचार के लिये रखे.

### खंड दो—राजपंचायत

#### आम

राजपंचायत की बनावट

79—यूनियन की एक राजपंचायत होगी जिसमें राजपति और दो सदन होंगे, जो अलग अलग रियासत सदन और लोक सदन कहलायेंगे.

रियासत सदन की रचना

80—(1) रियासत सदन में—

(ए) बारह मेम्बर ऐसे होंगे जिनको धारा (3) के बन्धानों के अनुसार राजपति नामज़द करेगा; और

(बी) रियासतों के प्रतिनिधि होंगे जो दो सौ अड़तीस से अधिक नहीं होंगे.

(2) रियासत सदन में रियासतों के प्रतिनिधियों से भरी जाने वाली सीटों का बंटवारा उन बंधानों के अनुसार किया जायगा जो इस काम के लिये चौथी पट्टी में दिये हैं.

(3) धारा (1) की उपधारा (ए) के अधीन राजपति जिन मेम्बरों को नामज़द करेगा वे ऐसे आदमी होंगे जिन्हें इस तरह के मामलों के बारे में जैसे नीचे दिये गए हैं खास जानकारी या अमली तज़रबा हो, यानी :—

अदब-साहित्य, साइन्स, कला और समाजसेवा.

(4) रियासत सदन में पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत के प्रतिनिधियों को उस रियासत के आम सदन के चुने हुए मेम्बर निम्नवती प्रतिनिधान के ढंग पर इकट्ठे बटलते वोट से चुनेंगे.

(5) रियासत सदन में पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि उस ढंग से चुने जायेंगे जो राजपंचायत क़ानून बनाकर बतावे. •

81—(1), (ए) धारा (2) के और दफ़ा 82 और दफ़ा 331 के लोकसदन की  
बन्धानों के अधीन रहते हुए, लोकसदन के रचना  
मेम्बर पांच सौ से अधिक नहीं होंगे और  
उन्हें रियासतों के वोटर सीधे चुनेंगे.

(बी) उपधारा (ए) के मतलब के लिये एक रियासत में कई, या कई रियासतों का एक, या एक रियासत का एक, इस तरह रियासतों के भूभागी चुनाव-हलक़े बनाए जायेंगे, और ऐसे हर चुनाव-हलक़े को मिलने वाले मेम्बरों की तादाद इस तरह तय की जायगी जिससे कि यह पक्का हो जाय कि आबादी के हर सात लाख पचास हजार आदमियों पीछे एक से कम मेम्बर नहीं होगा, और हर पांच लाख पीछे एक से अधिक मेम्बर नहीं होगा.

(सी) हर भूभागी चुनाव-हलक़े को जो मेम्बर दिये जायेंगे उनकी गिनती, और उस हलक़े की आबादी की वह गिनती जो उस पिछले आखरी गिनावे में मालूम की जा चुकी है, जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं, इन दोनों में जहां तक हो सकेगा भारत के सारे भूभाग में एक ही अनुपात होगा.

(2) लोक सदन में उन भूभागों का प्रतिनिधान, जो भारत के भूभाग में शामिल हैं लेकिन किसी रियासत में शामिल नहीं हैं, वह होगा जो राजपंचायत कानून बनाकर तय कर दे.

(3) हर गिनावे के पूरा हो जाने पर, लोकसदन में अलग अलग भूभागी चुनाव-हलकों के प्रतिनिधान में वह अधिकारी उस ढंग से और उस तारीख से लागू होने के लिये घटत बढ़त करेगा जैसे राजपंचायत कानून बनाकर तय करदे:

शर्तें कि इस तरह की घटत बढ़त का लोकसदन के प्रतिनिधान पर तबतक कोई असर नहीं पड़ेगा जबतक कि उस समय का सदन भंग न हो जाय.

भाग (सी) की रियासतों के और रियासतों को छोड़कर दूसरे भूभागों के प्रतिनिधान के बारे में खास बन्धान

82—दफा 81 की धारा (1) में किसी बात के रहते भी, राज पंचायत कानून बनाकर, लोकसदन में, पहली पट्टी के भाग (धी) में दर्ज किसी रियासत के, या किसी ऐसे भूभागों के जो भारत के भूभाग में शामिल हैं पर किसी रियासत में शामिल नहीं हैं, उस धारा में जो बन्धान किया गया है उसको छोड़कर किसी दूसरे आधार पर या किसी दूसरे ढंग से प्रतिनिधान का बन्धान कर सकती है.

राज पंचायत के सदनों की सुझ

83—(1) रियासत सदन को भंग न किया जा सकेगा, पर हर दूसरे बरस के बीत जाने पर जितनी जल्दी हो सकेगा सदन के मेम्बरों में से करीब से करीब एक तिहाई, उन बन्धानों के अनुसार जो राजपंचायत कानून के जरिये इस काम के लिये बनादे, अलग हो जाया करेंगे.

(2) लोकसदन अगर पहले ही भंग न कर दिया गया हो तो जो तारीख उसकी पहली मिलनी के लिये तय की गई थी उससे पांच बरस तक चलेगा, और अधिक नहीं, और इस पांच बरस के अरसे के बीत जाने से ही लोकसदन भंग माना जायगा:

शर्तें कि किसी ऐसे समय में जब कोई अधिवेशन का ऐलान अमल में हो, राजपंचायत कानून बनाकर इस अरसे को एक और अरसे के लिये बढ़ा सकती है जो एक बार में एक बरस से अधिक न होगा, और जो किसी भी सूरत में ऐलान का अमल खतम होने के बाद से अधिक न चलेगा.

84—कोई आदमी राजपंचायत में कोई सीट भरने के लिये चुने जाने के जोग नहीं होगा जब तक कि वह —

राजपंचायत की  
मेम्बरी के लिये  
जोगता

(ए) भारत का नागर न हो;

(बी) रियासत सदन की सीट के लिये कम से कम तीस बरस की और लोकसदन की सीट के लिये कम से कम पच्चीस बरस की उमर का न हो; और

(सी) ऐसी और जोगताएँ न रखता हो जो इस काम के लिये राजपंचायत के बनाए हुए किसी कानून में या उसके अधीन बताई जायं.

85—(1) राज पंचायत के सदनों को हर बरस में कम से कम दो बार मिलने के लिये बुलाया जायगा और एक इजलास में उनकी आखरी बैठक और अगले इजलास में पहली बैठक की जो तारीख ठहराई गई हो उनके बीच छै महीने नहीं बीतने पायंगे.

राजपंचायत के  
इजलास, उसे बर-  
खास्त करना और  
भंग करना

(2) धारा (1) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपति समय समय पर—

(ए) राजपंचायत के सदनों को या किसी एक सदन को मिलने के लिये जिस समय और जिस जगह ठीक समझे बुला सकता है;

(बी) सदनों को बरखास्त कर सकता है;

(सी) लोकसदन को भंग कर सकता है.

86—(1) राजपति राजपंचायत के किसी भी सदन में या दोनों सदनों की मिलीजुली बैठक में सर-बचन दे सकता है और इस मतलब के लिये मेम्बरों की हाजरी तलब कर सकता है.

राजपति को सदनों  
में सर-बचन देने  
और संदेसे भेजने  
का अधिकार

(2) राजपति राजपंचायत के किसी भी सदन को किसी ऐसे बिल के बारे में जो उस समय राजपंचायत के सामने हो या किसी और मतलब के लिये संदेसे भेज सकता है, और जिस सदन को इस तरह का कोई संदेसा भेजा जाय वह जितनी जल्दी सुभीते के साथ कर सकेगा उस मामले पर सोच विचार करेगा जिस पर सोच विचार करने को उस संदेसे में कहा गया हो.



हर इजलास के आरंभ में राजपति का खास सर-बचन

87—(1) हर इजलास के आरंभ में राजपति राजपंचायत के दोनों सदनों को इकट्ठा करके सर-बचन देगा और राजपंचायत को उसके बुलाए जाने के कारन बतायगा।

(2) हर सदन के दस्तूर की क्रायदाबन्दी करने वाले नियमों में इस बात का बन्धान किया जायगा कि इस तरह के सर-बचन में जिन मामलों की चरचा की गई हो उनपर बहस करने के लिये समय रखा जाय और यह बहस सदन के और कामों से पहले हो।

सदनों के बारे में वज़ीरों और सर मुख्तार के अधिकार

88—हर वज़ीर को और भारत के सरमुख्तार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में या सदनों की किसी भी मिलीजुली बैठक में और राजपंचायत की किसी भी ऐसी कमेटी में, जिसके मेम्बरों में उसका नाम हो, बोले और दूसरी तरह कारवाई में हिस्सा ले, मगर वोट देने का हकदार वह इस दफ्ता की रू से नहीं होगा।

### राजपंचायत के अफ़सर

रियासतसदन का मसनदी और उप-मसनदी

89—(1) भारत का उप-राजपति पद-नाते रियासत सदन का मसनदी होगा।

(2) रियासत सदन जितनी जल्दी हो सकेगा, सदन के किसी मेम्बर को उसका उप-मसनदी चुन लेगा और जब जब उप-मसनदी का पद सूना होगा, सदन किसी दूसरे मेम्बर को अपना उप-मसनदी चुन लेगा।

उप-मसनदी का पद सूना होना, उसका इस्तीफ़ा देना और पद से हटाया जाना

90. कोई मेम्बर जो रियासत सदन के उप-मसनदी के पद पर हो—

(ए) अगर सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) किसी समय भी मसनदी के नाम अपनी दसखती लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे सकता है; और

(सी) सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया

जा सकता है जिसे सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया हो:

शर्तें कि धारा (सी) के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं किया जायगा जब तक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया गया हो.

91—(1) जब कभी मसनदी का पद सूना हो, या उस अरसे में जब उप-राजपति राजपति की जगह काम कर रहा हो या उसके काम निभार रहा हो, मसनदी के पद के फ़रज़ उप-मसनदी पूरे करेगा, या अगर उप-मसनदी का पद भी सूना हो तो रियासत सदन का वह मेम्बर करेगा जिसको राजपति इस मतलब के लिये नियोजे.

उप-मसनदी को या किसी दूसरे आदमी को मसनदी के पद के फ़रज़ पूरे करने या मसनदी की जगह काम करने की शक्ति

(2) रियासत सदन की किसी बैठक में मसनदी के मौजूद न रहने पर उप-मसनदी, या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी, जिसे सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा कोई आदमी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा दूसरा आदमी जिसे सदन तय करे, मसनदी की जगह काम करेगा.

92—(1) रियासत सदन की किसी बैठक में जब कि उप-राजपति को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी. या जब उप-मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-मसनदी, मौजूद होने पर भी सदारत नहीं करेगा, और दफ़ा 91 की धारा (2) के बंधान इस तरह की हर बैठक के बारे में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी उस बैठक के बारे में लागू होते जिसमें, मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता.

मसनदी या उप-मसनदी उस समय सदारत नहीं करेगा जबकि उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो

(2) जब रियासत सदन में उप-राजपति को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी को सदन में बोलने और दूसरी तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, पर दफ़ा 100 में किसी बात के रहते भी उस ठहराव

पर या ऐसी कारवाइयों के दौरान में किसी और मामले पर वह वोट देने का बिलकुल हकदार नहीं होगा।

लोकसदन का  
सभामुख और उप-  
सभामुख

93—लोक सदन जितनी जल्दी हो सकेगा सदन के दो मेम्बरों को अलग अलग सदनका सभामुख और उप-सभामुख चुनेगा और जब जब सभामुख या उप-सभामुख का पद सूना होगा, सदन किसी और मेम्बर को सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, चुनलेगा।

सभामुख और उप-  
सभामुख का पद  
सूना होना, उनका  
इस्तीफा देना और  
पद से हटाया  
जाना

94—कोई मेम्बर जो लोक सदन के सभामुख या उप-सभामुख के पद पर है—

(ए) अगर लोक सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) अगर वह मेम्बर सभामुख है तो उप-सभामुख के नाम और अगर वह मेम्बर उप-सभामुख है तो सभामुख के नाम किसी समय भी अपनी दसखती लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है; और

(सी) लोक सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत पास कर दे:

शर्तें कि धारा (सी) के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं किया जायगा जबतक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया जा चुका हो:

और शर्तें कि जब कभी लोक सदन को भंग किया जाय तो, सदन के भंग होने के बाद अगले लोक सदन की पहली मिलनी के ठीक पहले तक सभामुख अपना पद सूना नहीं करेगा।

उप-सभामुख या  
किसी दूसरे आदमी  
को सभामुख के  
पद के फ़रज़ पूरा  
करने या सभामुख  
को जगह काम  
करने की शक्ति

95—(1) जब कभी सभामुख का पद सूना होगा, उसके पद के फ़रज़ उप-सभामुख पूरे करेगा, या अगर उप-सभामुख का पद भी सूना हो तो लोकसदन का कोई ऐसा मेम्बर करेगा जिसका राजपति इस मतलब के लिये नियोजन कर दे।

(2) लोकसदन की किसी बैठक में सभामुख के मौजूद न रहने पर उप-सभामुख या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी जिसे सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा

कोई आदमी भी मौजूद नहीं है, तो कोई और ऐसा आदमी जिसे सदन तय करे, सभामुख की जगह काम करेगा।

96—(1) लोक सदन की किसी बैठक में जब कि सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख, या जब कि उप-सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-सभामुख, मौजूद होने पर भी, सदारत नहीं करेगा, और दफ्ता 95 की धारा (2) के बन्धान हर ऐसी बैठक के बारे में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी ऐसी बैठक के बारे में लागू होते जिसमें सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता।

(2) लोक सदन में सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये जब किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख को उस सदन में बोलने और दूसरी तरह कारबाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और दफ्ता 100 में किसी बात के रहते भी वह पहली बार तो उस ठहराव पर या उस कारबाई के दौरान में किसी भी दूसरे मामले पर वोट देने का हक़शार होगा पर बराबर के वोट आने की हालत में नहीं होगा।

97—रियासत सदन के मसनदी और उप-मसनदी को और लोक सदन के सभामुख और उप-सभामुख को वह तनखाहें और भत्ते मिलेंगे जो राजपंचायत क़ानून बनाकर अलग अलग तय कर दे और जब तक इसके लिये इस तरह का कोई बन्धान नहीं होता तब तक उनको वह तनखाहें और भत्ते मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं।

98—(1) राजपंचायत के हर सदन का अलग अलग मंत्रायती अमला होगा:

शर्तें कि इस धारा की किसी बात से यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह राजपंचायत के दोनों सदनों के लिये शामलाती जगहें बनाए जाने को रोकती है।

(2) राजपंचायत क़ानून बनाकर अपने किसी सदन के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने के लिये लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी कर सकती है।

सभामुख या उप-सभामुख 'सदारत नहीं करेगा जब कि उसको पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो

मसनदी और उप-मसनदी और सभामुख और उप-सभामुख को तनखाहें और भत्ते

राजपंचायत की मंत्रायत

(3) जब तक धारा (2) के अधीन राजपंचायत कोई बन्धान नहीं करती तब तक राजपति लोकसदन के सभामुख से या रियासत सदन के मसनदी से, जैसी सूरत हो, सलाह करने के बाद लोकसदन के या रियासत सदन के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने वाले लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क्रायदाबन्दी करनेवाले नियम बना सकता है, और जो नियम इस तरह बनाए जायंगे उनका असर उस धारा के अधीन बने हुए कानून के बन्धानों के अधीन होगा।

### काम का संचालन

मेम्बरों का हलफ़ उठाना या वचन भरना

99. राजपंचायत के हर सदन का हर मेम्बर अपनी सीट लेने से पहले राजपति के सामने या इस काम के लिये राजपति के नियोजे हुए किसी आदमी के सामने, उस रूप के अनुसार हलफ़ उठायगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा जो रूप इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया हुआ है.

सदनों में बोट लेना, सूनियां होने पर भी सदनों को काम करने की शक्ति, और कोरम

100—(1) सिवाय जबकि इस विधान में कुछ और बन्धान किया गया हो, किसी भी सदन की किसी बैठक में या दोनों सदनों की मिली जुली बैठक में सब सवाल, सभामुख को या उस आदमी को जो मसनदी या सभामुख की जगह काम कर रहा हो छोड़कर, उस समय मौजूद और वोट देने वाले सब मेम्बरों के वोटों की बड़ीयत से तय किये जायंगे.

मसनदी या सभामुख या वह आदमी जो उनकी जगह काम कर रहा हो पहले तो वोट नहीं देगा, मगर बराबर वोट आने की सूरत में उसको जिताऊ वोट देने का अधिकार होगा और वह उससे काम लेगा.

(2) राजपंचायत के हर सदन की शक्ति होगी कि उस सदन के मेम्बरों की कुछ सीटें सूनी होने पर भी काम करे, और राजपंचायत की हर कारवाई सरदुरुस्त होगी, भले ही बाद में यह पता चले कि कोई ऐसा आदमी सदन में बैठा, उसने वोट दिया या और किसी तरह कारवाई में भाग लिया जो ऐसा करने का हकदार नहीं था.

(3) जब तक राजपंचायत कानून बनाकर कोई दूसरा बन्धान नहीं करती तब तक राजपंचायत के हरसदन की मिलनी के लिये कोरम उस सदन के कुल मेम्बरों की गिनती का एक दसवाँ होगा.

(4) अगर किसी सदन की किसी मिलनी के दौरान में किसी समय कोरम न रहे तो मसनदी का या सभामुख का या उस आदमी का जो उनकी जगह काम कर रहा हो, फरज होगा कि या तो सदन को मुलतवी कर दे या उस मिलनी को कोरम पूरा हो जाने तक के लिये रोक दे.

### मेम्बरों की अजोगताएं

101—(1) कोई आदमी राजपंचायत के दोनों सदनों का मेम्बर नहीं होगा, और राजपंचायत कानून बनाकर इस बात का बन्धान करेगी कि अगर कोई आदमी दोनों सदनों का मेम्बर चुना जाय तो वह दोनों में से किसी एक सदन में अपनी सीट सूनी कर दे. सीटों का सुना होना

(2) कोई आदमी राजपंचायत और पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की कानून सभा, दोनों का मेम्बर नहीं होगा, और अगर कोई आदमी राजपंचायत और ऐसी किसी रियासत की कानूनसभा, दोनों का मेम्बर चुना जाय, तो उस अरसे के पूरा होने पर जो राजपति के बनाए नियमों में दिया हो, राजपंचायत में उस आदमी की सीट सूनी हो जायगी, जब तक कि उसने इससे पहले ही रियासत की कानून सभा में अपनी सीट से इस्तीफा न दे दिया हो.

(3) अगर राजपंचायत के किसी सदन का कोई मेम्बर—

(ए) दफ्ता 102 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अधीन हो जाए; या

(बी) मसनदी या सभामुख के नाम, जैसी सूरत हो, अपनी दुसखती लिखत भेजकर अपनी सीट से इस्तीफा दे दे, तो इस पर उसकी सीट सूनी हो जायगी.

(4) अगर राजपंचायत के किसी सदन का कोई मेम्बर साठ दिन के अरसे तक सदन की इजाजत बिना सदन की सब मिलनियों में नामौजूद रहे तो सदन उसकी सीट को सूनी ठहरा सकता है.

शर्त्त कि साठ दिन के इस अरसे के गिनने में वह अरसा नहीं गिना जायगा जब कि सदन बरखास्त रहा हो या लगातार चार दिन से अधिक के लिये मुलतवी कर दिया गया हो.

मेम्बरी के लिये 102—(1) वह आदमी राजपंचायत के किसी सदन का मेम्बर अजोगताएँ चुने जाने या मेम्बर होने के अजोग होगा—

(ए) जो भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, सिवाय किसी ऐसे पद के जिसे राजपंचायत ने क़ानून बनाकर यह ठहरा दिया हो कि उस पद पर रहने से कोई आदमी अजोग नहीं समझा जायगा;

(बी) जिसका दिमाग़ ठीक नहीं है और जिसे किसी अधिकारी अदालत ने ना-ठीक दिमाग़ का ठहरा दिया है;

(सी) जो ऐसा दिवालिया है जिसे अभी तक बरी नहीं किया गया है;

(डी) जो भारत का नागर नहीं है, या जो अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज का नागर बन गया है, या जो किसी विदेशी राज की भक्ति या उससे लगाव मान चुका है;

(ई) जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून से या उसके अधीन इसके लिये अजोग ठहराया गया है.

(2) इस दफ़ा के मतलबों के लिये कोई आदमी भारत सरकार या किसी रियासत की सरकार के अधीन केवल इन्हीं कारन किसी लाभ के पद पर नहीं समझा जायगा कि वह यूनियन का या उस रियासत का वज़ीर है.

मेम्बरों की अजोग- 103—(1) अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि राजपंचायत के किसी ताओं के बारे में सवाल पर फ़ैसला सदन का कोई मेम्बर दफ़ा 102 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अन्दर आ गया है या नहीं तो इस सवाल को राजपति के फ़ैसले के लिये भेजा जायगा और उसका फ़ैसला आख़री होगा.

(2) ऐसे किसी सवाल पर कोई फ़ैसला देने से पहले, राज-पति चुनाव कमीशन की राय लेगा और उस राय के अनुसार काम

104—अगर कोई आदमी दफा 99 की जरूरतों को पूरा करने से पहले, या जब वह यह जानता हो कि वह राजपंचायत के किसी सदन की मेम्बरी के जोग नहीं है, या उसे उसके अजोग ठहराया गया है, या राजपंचायत के बनाए किसी कानून के बन्धानों से उसको मेम्बर की तरह बैठने या वोट देने की मनाही की गई है, राजपंचायत के उस सदन में मेम्बर की तरह बैठेगा या वोट देगा तो जितने दिन वह इस तरह बैठेगा या वोट देगा, उस पर हर दिन के लिये पाँच सौ रुपये दंड लगाया जा सकेगा जो उससे यूनियन के क्ररजे के रूप में वसूल किया जायगा.

दफा 99 के अधीन हफ्ता उठाने या वचन भरने से पहले या जोग न होने या अजोग ठहराए जाने पर बैठने और वोट देने पर दंड

### राजपंचायत और उसके मेम्बरों की शक्तियाँ, उनके निज-नियम और उनकी बरीयतें

105—(1) इस विधान के बन्धानों और राजपंचायत के दस्तूर की क़ायदाबन्दी करने वाले नियमों और क़ायमी हुकुमों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत में बोलने की आज़ादी होगी.

राजपंचायत के सदनों की और उनके मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियाँ, निज-नियम वगैरा

(2) राजपंचायत के किसी मेम्बर ने जो कुछ राजपंचायत में या उसकी किसी कमेटी में कहा हो या जिस तरह वोट दिया हो उसके बारे में उस मेम्बर के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी, और राजपंचायत के किसी सदन की तरफ से या उसके हुकुम से जो कोई रिपोर्ट कागज़, वोट या कारवाई निकाली जाय उसके बारे में किसी आदमी के खिलाफ इस तरह की कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी.

(3) और बातों में राजपंचायत के हर सदन की और हर सदन के मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियाँ, निजनियम और बरीयतें वह होंगी, जो राजपंचायत समय समय पर कानून बनाकर तय करदे, और जब तक इस तरह न तय करदी जाएं तब तक वह होंगी जो इस विधान के आरम्भ के समय यूनाइटेड किंगडम (इंगलिस्तान) की पार्लिमेंट के हाउस आफ कामन्स को और उसके मेम्बरों और कमेटियों को हासिल हों.

(4) धारा (1), (2) और (3) के बन्धान जिस तरह राजपंचायत के मेम्बरों के सम्बन्ध में लागू होते हैं उसी तरह उन



लोगों के सम्बन्ध में लागू होंगे जिनको इस विधान की रू से राज-पंचायत के किसी सदन में या उसकी किसी कमिटी में बोलने का या किसी और तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार है.

मेम्बरों की तनखाहें और भत्ते

106—राजपंचायत के हर सदन के मेम्बर वह तनखाहें और भत्ते पाने के हक्कदार होंगे जो राजपंचायत समय समय पर कानून बनाकर तय करे, और जब तक इस बारे में इस तरह का बन्धान न किया जाय तब तक उनको उसी दर से और उन्हीं शर्तों पर भत्ते मिलेंगे जिनपर इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा के मेम्बरों को मिलते थे.

### कानूनकारी दस्तूर

बिल रखने और पास करने के बारे में बन्धान

107—(1) नक़दी बिलों और दूसरे माली बिलों के बारे में दफ़ा 109 और दफ़ा 117 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी भी बिल की पहल राजपंचायत के किसी भी सदन में की जा सकती है.

(2) दफ़ा 108 और 109 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, कोई बिल राजपंचायत के सदनों से पास हुआ उस समय तक नहीं समझा जायगा जब तक कि दोनों सदनों ने, या तो बिना सुधार या केबल ऐसे सुधारों के साथ जिन्हें दोनों सदनों ने मान लिया हो, उस बिल को मान न लिया हो.

(3) कोई बिल जो राजपंचायत के सामने पेश है सदनों के बरखास्त हो जाने के कारन गिर नहीं जायगा.

(4) कोई बिल जो रियासत सदन के सामने पेश है और जिसे लोकसदन ने पास नहीं किया है लोकसदन के भंग होने पर गिर नहीं जायगा.

(5) अगर कोई बिल लोकसदन में पेश है या लोकसदन से पास होकर रियासत सदन में पेश है, तो वह दफ़ा 108 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए लोकसदन के भंग होने पर गिर जायगा.

कुछ शर्तों में दोनों सदनों की मिली जुली बैठक.

108—(1) अगर किसी बिल के एक सदन से पास होकर दूसरे सदन को भेज दिये जाने के बाद—

(ए) दूसरे सदन ने बिल को नामंजूर कर दिया है; या

- (बी) बिल में जो सुधार करने हों, उनके बारे में सदनों की राय आखीर में मिली न हो; या  
(सी) दूसरे सदन में बिल के आने की तारीख से छै महीने से अधिक बीत गए हों और उस सदन ने उसे तब तक पास न किया हो,

तो राजपति, जबतक कि वह बिल लोकसदन के भंग होने के कारन गिर न गया हो, अगर सदनों की बैठकें हो रही हों तो संदेश भेज कर या अगर उनकी बैठकें नहीं हो रही हैं तो आम नोटिस निकाल कर दोनों सदनों को इत्तला दे सकता है कि वह उस बिल पर सोच विचार करने और वोट देने के लिये सदनों की एक मिली जुली बैठक बुलाने का इरादा रखता है.

शर्तें कि इस धारा की कोई बात किसी नक़दी बिल पर नहीं लगेगी.

(2) धारा (1) में जिस छै महीने के अरसे की चरचा की गई है उसका हिसाब लगाने में वह समय नहीं गिना जायगा जब उस धारा की उप-धारा (सी) में जिस सदन की चरचा की गई है वह बरखास्त रहा हो या लगातार चार दिन से अधिक के लिये मुलतवी कर दिया गया हो.

(3) जब राजपति ने धारा (1) के अधीन दोनों सदनों की मिली जुली बैठक बुलाने के इरादे का नोटिस दे दिया हो, तो कोई सदन बिल पर आगे कारबाई नहीं करेगा, पर राजपति नोटिस की तारीख के बाद किसी समय भी, जो मतलब नोटिस में बताया गया है उसके लिये सदनों की मिली जुली बैठक बुला सकता है, और अगर वह ऐसा करे तो जिस तरह वह बताए उस तरह सदनों की बैठक होगी.

(4) अगर दोनों सदनों की मिली जुली बैठक में ऐसे सुधारों के साथ (अगर कोई ऐसे सुधार हैं तो) जिन्हें मिली जुली बैठक ने मान लिया है, वह बिल दोनों सदनों के मौजूद और वोट देने वाले कुल मेम्बरों की बड़ीयत से पास हो जाय, तो इस विधान के मतलबों के लिये यह समझा जाएगा कि बिल को दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

शर्तें कि मिली जुली बैठक में—

(ए) अगर वह बिल एक सदन से पास हो कर दूसरे सदन में सुधारों के साथ पास नहीं होता और जिस सदन में बिल की पहल की गई थी उसको लौटा दिया जाता है तो उस बिल में सिवाय ऐसे सुधारों के (अगर कोई ऐसे सुधार हों तो) जो बिल के पास होने में देर हो जाने के कारण जरूरी हो गए हों, कोई और सुधार नहीं रखा जायगा.

(बी) अगर बिल इस तरह पास करके लौटा दिया गया है तो बिल में केवल ऊपर बताए सुधार और ऐसे दूसरे सुधार हो रखे जा सकेंगे जो उन मामलों से संगत हों जिनके बारे में सदनों की एक राय नहीं है;

और सदारत करने वाले आदमी का यह फैसला कि इस धारा के अधीन कौन से सुधार लिये जा सकते हैं, आखरी होगा.

(5) इस दफ्ता के अधीन मिली जुली बैठक हो सकती है, और उसमें बिल पास किया जा सकता है, भले ही राजपति के सदनों की बैठक बुलाने के इरादे का नोटिस दिये जाने के बाद लोक सदन भंग कर दिया गया हो.

नक्रदी बिलों के बारे में खास दस्तुर

109—(1) कोई नक्रदी बिल पहले रियासत सदन में नहीं रखा जायगा.

(2) नक्रदी बिल लोक सदन से पास होकर रियासत सदन को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा जायगा और रियासत सदन बिल के आने की तारीख से चौदह दिन के अरसे के अन्दर अन्दर अपनी सिफारिशों के साथ बिल लोक सदन को लौटा देगा, इस पर लोक सदन चाहे तो रियासत सदन की सारी सिफारिशें या कोई सी सिफारिश मान ले या न माने.

को, उन सुधारों के साथ जिनकी रियासत सदन ने सिफारिश की है और जिन्हें लोकसदन ने मान लिया है, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(4) अगर लोक सदन रियासत सदन की सिफारिशों में से किसी को भी नहीं मानता तो यह समझा जायगा कि नक़दी बिल को, बिना उन सुधारों में से किसी के जिनकी सिफारिश रियासत सदन ने की है, उसी रूप में जिसमें लोक सदन ने उसे पास किया था, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(5) अगर कोई नक़दी बिल लोक सदन से पास होकर सिफारिशों के लिये रियासत सदन को भेजा गया हो और ऊपर कहे चौदह दिन के अरसे के अन्दर लोक सदन को न लौटाया गया हो, तो यह समझा जायगा कि इस अरसे के बीत जाने पर उस बिल को, उसी रूप में जिसमें लोकसदन ने उसे पास किया था, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

110—(1) इस खंड के मतलबों के लिये वह बिल 'नक़दी बिल' "नक़दी बिल" की परिभाषा समझा जायगा जिसमें केवल वही बन्धान हों जिनका नीचे लिखे सब मामलों से या इनमें से किसी मामले से सम्बन्ध है, यानी—

- (ए) किसी टैक्स का लगाना, अन्त करना, उसमें छूट देना, उसे बदलना या उसकी क़ायदाबन्दी करना;
- (बी) रुपया उधार लेने की क़ायदाबन्दी करना, या भारत सरकार का कोई गारन्टी देना, या किसी ऐसी माली जिम्मेदारियों के बारे में, जो भारत सरकार ने ले रखी हों या जिन्हें वह लेने वाली हो, क़ानून में कोई सुधार करना;
- (सी) भारत के मूठकोश या जोगाजोग कोश की रखबाली, ऐसे किसी कोश में रुपया जमा करना, या उसमें से रुपया निकालना;
- (डी) भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्च की मदों में डालना;
- (ई) किसी खर्च को भारत के मूठकोश में से किये जाने

बाला खर्च ठहराना, या इस तरह के किसी खर्च की रकम को बढ़ाना;

(एफ) भारत के मूठकोश के हिसाब में या भारत के सरकारी हिसाब में रुपया वसूल करना या ऐसे रुपए की रखवाली करना या उसका निकास करना, या यूनियन या किसी रियासत के हिसाब किताब को पढ़तालना; या

(जी) (ए) से (एफ) तक की उपधाराओं में दर्ज मामलों में से किसी के साथ प्रसंग से आया हुआ कोई और मामला.

(2) किसी बिल को केवल इसी कारन नकदी बिल नहीं समझा जायगा कि वह जुरमाने करने, या रुपए पैसे का कोई दूसरा दंड देने, या लाईसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके लिये फीस मांगने या फीस देने, का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुकामी मतलबों के लिये किसी मुकामी अधिकारी या संस्था के कोई टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने या उसकी क्रायदाबन्दी करने का बन्धान करता है.

(3) अगर ऐसा कोई सवाल उठे कि कोई बिल नकदी बिल है या नहीं, तो इस पर लोकसदन के सभामुख का फैसला आखरी होगा.

(4) जब कोई नकदी बिल दफा 109 के अधीन रियासत सदन को भेजा जाय और जब कोई नकदी बिल दफा 111 के अधीन मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखा जाय, तो हर ऐसे बिल पर लोक सदन के सभामुख की दखलती सनद होगी कि वह बिल नकदी बिल है.

बिलों पर मंजूरी

111—जब कोई बिल राजपंचायत के सदनों से पास हो जाय तो उसे राजपति के सामने रखा जायगा, और राजपति ऐलान करेगा कि वह उस बिल पर मंजूरी देता है या उससे अपनी मंजूरी रोक देता है.

शर्तें कि किसी बिल के राजपति के सामने मंजूरी के लिये रखे जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके राजपति उस बिल को, अगर वह नकदी बिल नहीं है, तो एक ऐसे संदेसे के साथ सदनों को लौटा सकता है जिसमें यह प्रार्थना की गई हो कि वह बिल पर या उसके किन्हीं बताए हुए बन्धानों पर फिर से सोच विचार करें और खास कर इस बात को सोचें कि अगर राजपति ने अपने संदेसे में किन्हीं सुधारों की सिफारिश की है तो ऐसे किन्हीं सुधारों को ले लेना चाहिये या नहीं, और जब कोई बिल इस तरह वापिस किया जायगा तो उस संदेसे के अनुसार दोनों सदन बिल पर फिर से सोच विचार करेंगे, और अगर दोनों सदन बिल को फिर बिना सुधार या सुधारों के साथ पास कर देते हैं, और वह मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखा जाता है, तो राजपति उससे अपनी मंजूरी नहीं रोकेंगा।

### माली मामलों में दस्तूर

112—(1) राजपति हर माली साल के बारे में राजपंचायत के दोनों सदनों के सामने उस साल के लिये भारत सरकार की आमदनी और खर्च के तख्मीने का एक ब्योरा रखवायगा जिसकी चरचा इस भाग में “सालाना माली ब्योरा” कह कर की गई है।

(2) सालाना माली ब्योरे के अन्दर खर्च के जो तख्मीने रहेंगे उनमें यह रकममें अलग अलग दिखाई जाएंगी—

(ए) वह रकममें जो उस खर्च के लिये दरकार होंगी जिसे इस विधान में भारत के मूठकोश के खाते में पढ़ने वाला खर्च बताया गया है; और

(बी) वह रकममें जो उन दूसरे खर्चों के लिये दरकार होंगी जिनके बारे में यह सुभाव है कि वह भारत के मूठकोश में से किये जाएँ,

और उसमें मालगुजारी खाते खर्च और दूसरे खर्चों में फरक किया जायगा।

(3) नीचे लिखे खर्च वह खर्च होंगे जो भारत के मूठकोश के खाते में पढ़ेंगे—

(ए) राजपति का वेतन और भत्ते और उसके पद

सम्बन्धी दूसरे खर्च;

(बी) रियासत सदन के मसनदी और उप-मसनदी और लोकसदन के सभामुख और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते;

(सी) करजा खर्च जिसके लिये भारत सरकार देनदार है, जिसमें सूद-ब्याज, बट्टे खाते का खर्च और भुगतान खर्च, और उधार लेने, करजा जारी रखने और करजा चुकाने के सम्बन्ध में दूसरे खर्च शामिल होंगे;

(डी) (एक) वह तनखाहें, भत्ते और पेनशनें जो आला अदालत के जजों को या उनके बारे में दी जानी हों;

(दो) वह पेनशनें जो संघ अदालत के जजों को या उनके बारे में दी जानी हों ;

(तीन) वह पेनशनें जो किसी ऐसी हाईकोर्ट के जजों को या उनके बारे में दी जानी हों जिसकी अभिलेखकारी किसी ऐसे क्षेत्र में है जो भारत के भूभाग में शामिल है या जिसकी अभिलेखकारी इस विधान के आरंभ से पहले किसी समय भी किसी ऐसे क्षेत्र में थी जो पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियासत के जवाबी सूबे में शामिल था.

(ई) भारत के दाब अफसर और सर पड़तालिया को या उसके बारे में दी जाने वाली तनखाह, भत्ते और पेनशन;

(एफ) वह रकमों जो किसी अदालत या पंचायती अदालत के किसी फैसले, डिगरी या पंच फैसले को चुकाने के लिये दरकार हों;

(जी) कोई दूसरा खर्च जिसे यह विधान या राजपंचायत कानून बनाकर ऐसा खर्च ठहरा दे.

113—(1) उतने तखमीने जितनों का सम्बन्ध भारत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाले खर्च से है राजपंचायत के सामने वोट के लिये नहीं रखे जायेंगे, पर इस धारा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जाएगा कि वह राजपंचायत के किसी सदन में उन तखमीनों में से किसी पर बहस होने को रोकती है।

तखमीनों के बारे में राजपंचायत का दस्तूर

(2) उतने तखमीने जितनों का सम्बन्ध दूसरे खर्च से है देनगी की मांगों के रूप में लोक सदन के सामने रखे जायेंगे, और लोक सदन को यह शक्ति होगी कि वह किसी मांग को मंजूर कर ले या मंजूर करने से इनकार कर दे, या किसी मांग को उस मांग की दर्ज रकम में कुछ कमी करके मंजूर कर ले।

(3) राजपति की सिफारिश के बिना किसी देनगी की मांग नहीं की जायगी।

114—(1) दफ्ता 113 के अधीन लोक सदन के देनगियां पास कर देने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा, एक बिल रखा जाएगा जिस में भारत के मूठकोश में से नीचे लिखे खर्चों के लिये दरकार रुपयों को खर्च के मदों में डालने का बन्धान किया जाएगा—

मह-बटवारा बिल

(ए) जो देनगियां लोकसदन ने इस तरह पास कर दी हों; और

(बी) भारत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाले खर्च, पर जो किसी सूरत में भी राजपंचायत के सामने पहले से रखे हुए व्योरे में दिखाई रकम से अधिक न होंगे।

(2) ऐसे किसी बिल में राजपंचायत के किसी सदन में सुधार का कोई सुझाव नहीं रखा जाएगा जिससे इस तरह पास की हुई किसी देनगी की रकम घटाई बढ़ाई जा सके या उसके देन स्थान को बदल दिया जाए, या भारत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले किसी खर्च की रकम बदल दी जाए, और सद्धारत करने वाले आदमी का यह फैसला कि इस धारा के अधीन कोई सुधार लिया जा सकता है या नहीं आखरी होगा।



(3) दफा 115 और 116 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, भारत के मूठकोश में से कोई रुपया नहीं निकाला जाएगा सिवाय जब कि इस दफा के बन्धानों के अनुसार क़ानून पास कर के उसके ज़रिये बनी हुई खर्चों की मदों के अधीन ऐसा किया जाए.

पूरक, सहायक या  
अधिक देनगियां

115—(1), (ए) अगर दफा 114 के बन्धानों के अनुसार बने किसी क़ानून से किसी खास सेवा पर चालू माली साल के लिये खर्च किये जाने को अधिकारी हुई रक़म उस बरस के मतलबों के लिये नाक़ाफ़ी पाई जाय, या जब किसी चालू माली साल में किसी ऐसी नई सेवा के पूरक या सहायक खर्चों की ज़रूरत पैदा हो गई हो जिसका विचार उस साल के सालाना माली ब्योरे में नहीं किया गया था, या

(बी) अगर किसी माली साल की बाबत किसी सेवा के लिये मंज़ूर रक़म से अधिक कोई रुपया उस सेवा पर उस साल खर्च हो गया है,

तो राजपति राजपंचायत के दोनों सदनों के सामने उस खर्च के तख़्मीने की रक़म को दिखाने वाला दूसरा ब्योरा रखवाएगा या लोकसदन के सामने ऐसे अधिक खर्च की मांगें पेश कराएगा, जैसी सूरत हो .

(2) ऐसे किसी ब्योरे और खर्च या मांग के सम्बन्ध में, और ऐसी मांग के बारे में उस देनगी या खर्चों को पूरा करने के लिये भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्चों की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जानेवाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में, दफा 112, 113 और 114 के बन्धानों का वही असर होगा जो उनका सालाना माली ब्योरे और उसमें बताए खर्च या किसी देनगी की मांग, और उस खर्च या देनगी को पूरा करने के लिये भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्चों की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में होता है.

116—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, लोकसदन को यह शक्ति होगी कि—

हिसाब पर बोट,  
साख की बोट और  
अलग देनगियाँ

(ए) किसी देनगी पर बोट लेने के लिये दफ्ता 113 में जो दस्तूर बताया गया है उसके पूरा होने से पहले, और उस खर्च के बारे में दफ्ता 114 के बन्धानों के अनुसार कानून पास होने से पहले, किसी माली साल के किसी भाग के लिये खर्च के तखमीने की बाबत पहले से कोई देनगी मंजूर कर दे ;

(बी) भारत के साधनों पर किसी अचानक मांग को पूरा करने के लिये, उस सूरत में जब कि उस सेवा के फैलाव या अनिश्चित रूप के कारन वह मांग उन तफसीलों के साथ बयान नहीं की जा सकती जो आम तौर पर सालाना माली ब्योरे में दी जाती हैं, देनगी मंजूर कर दे ;

(सी) कोई ऐसी अलग देनगी जो किसी माली साल की किसी चालू सेवा का कोई भाग नहीं है, मंजूर कर दे ;

और राजपंचायत को शक्ति होगी कि कानून बनाकर, वह देनगियाँ जिन मतलबों के लिये मंजूर की गई हैं उनके लिये भारत के मूठकोश में से रुपए निकालने का अधिकार दे दे.

(2) धारा (1) के अधीन कोई देनगी मंजूर करने के सम्बन्ध में, और उस धारा के अधीन बनाए जाने वाले किसी कानून के सम्बन्ध में, दफ्ता 113 और 114 के बन्धानों का वैसा ही असर होगा जैसा कि सालाना माली ब्योरे में बताए किसी खर्च के बारे में कोई देनगी मंजूर करने के सम्बन्ध में, और ऐसे खर्च को पूरा करने के लिये भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्च की मदों में ढालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले कानून के सम्बन्ध में, होता है.

साली बिलों के बारे में खास बन्धान

117—(1) दफा 110 की धारा (1) की (ए) से (एफ़) तक की उप-धाराओं में जो मामले दर्ज हैं उनमें से किसी के लिये बन्धान करने वाला कोई बिल या सुधार नहीं रखा जा सकेगा, न पेश किया जा सकेगा, जब तक कि राजपति उसकी सिफारिश न करे, और इस तरह का बन्धान करनेवाला कोई बिल पहले रियासत सदन में नहीं रखा जायगा:

शर्तें कि किसी ऐसे सुधार को पेश करने के लिये जो किसी टैक्स को कम करने या उसका अंत करने का बन्धान करता हो, इस धारा के अधीन कोई सिफारिश दरकार न होगी.

(2) कोई बिल या सुधार केवल इसी कारन ऊपर बताए किसी मामले के लिये, बन्धान करने वाला नहीं समझा जायगा कि वह जुरमाने करने या रुपए पैसे का कोई दूसरा दंड देने या लाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके लिये फ़ीस मांगने या फ़ीस देने का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुकामी मतलबों के लिये किसी मुकामी अधिकारी या संस्था के कोई टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने या उसकी क्रायदाबन्दी करने का बन्धान करता है.

(3) अगर किसी बिल के कानून बन जाने और उस पर अमल होने से भारत के मूठकोश में से खर्च करना पड़े, तो उस बिल को राजपंचायत का कोई सदन पास नहीं करेगा जबतक कि राजपति ने उस बिल पर सोच विचार करने की उस सदन से सिफारिश न की हो.

### आम दस्तूर

दस्तूर के नियम

118—(1) इस विधान की शर्तों के अधीन रहते हुए राजपंचायत का हर सदन अपने दस्तूर और काम के संचालन की क्रायदाबन्दी करने के लिये नियम बना सकता है.

(2) जबतक धारा (1) के अधीन नियम नहीं बनते तब तक दस्तूर के जो नियम और जो क्रायमी हुकुम इस विधान के जारी होने से ठीक पहले हिन्दू डोमिनियन की कानून सभा के बारे में

सदन का मसनदी या लोकसदन का सभामुख, जैसी सूरत हो, उनमें अदल बदल और अनुकूलन कर सकता है.

(3) राजपति, रियासत सदन के मसनदी और लोक सदन के सभामुख से सलाह करके, दोनों सदनों की मिली जुली बैठकों के बारे में और उनके बीच आवा जाई के बारे में दस्तूर के नियम बना सकता है.

(4) दोनों सदनों की मिली जुली बैठक में लोक सदन का सभामुख या जब वह मौजूद न हो तो कोई ऐसा आदमी जिसे धारा (3) के अधीन बने दस्तूर के नियम तय करे बैठक का सदर होगा.

119—माली काम को समय के अन्दर पूरा करने के मतलब के लिये, राजपंचायत, कानून बना कर, किसी माली मामले के सम्बन्ध में या भारत के मूठकोश में से रुपए को खर्च की मर्दों में डालने वाले किसी बिल के सम्बन्ध में, राजपंचायत के हर सदन के दस्तूर की और काम के संचालन की क्रायदाबन्दी कर सकती है, और अगर इस तरह बने किसी कानून का कोई बन्धान दफा 118 की धारा (1) के अधीन राजपंचायत के किसी सदन के बनाए किसी नियम से या किसी ऐसे नियम या क्रायमी हुकुम से जो उस दफा की धारा (2) के अधीन राजपंचायत के सम्बन्ध में असर रखता हो मेल नहीं खाता, तो उस मेल न खाने की हद तक वह बन्धान ही चलेगा.

माली काम के सम्बन्ध में राजपंचायत के दस्तूर की कानून से क्रायदाबन्दी

120—(1) भाग सत्रह में किसी बात के रहते भी, पर दफा 348 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत का काम हिन्दी में या अंगरेजी में किया जायगा:

राजपंचायतमें काम से आनेवाली भाशा

शर्तें कि रियासत सदन का मसनदी या लोकसदन का सभामुख या उनकी जगह काम करने वाला कोई आदमी, जैसी सूरत हो, किसी ऐसे मेम्बर को जो हिन्दी में या अंगरेजी में अपने आपको पूरी तरह अदा न कर सकता हो, सदन में अपनी मातृ भाशा में बोलने की इजाजत दे सकता है.

(2) जब तक राजपंचायत कानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे, तब तक इस दफा का, इस विधान के आरम्भ से

पन्द्रह बरस का अरसा बीत जाने के बाद, वही असर होगा। मानो “या अंगरेजी में” ये शब्द इस दफा में से निकाल दिये गए हों।

राजपंचायत में  
बहस पर रुकावट

121—आला अदालत के या किसी हाईकोर्ट के किसी जज ने अपने फरज निभारने में जो कुछ किया हो उसके बारे में राजपंचायत में कोई बहस नहीं की जायगी, सिवाय उस समय जब कि राजपति को इस तरह की एक निवेदनी देने के लिये सुझाव पेश हो जिसमें, जैसा कि आगे चल कर बन्धान किया गया है, उस जज को हटाने के लिये प्रार्थना की गई हो।

राजपंचायत की  
कारवाई के बारे में  
अदालतें पूछना छ  
नहीं करेंगी

122—(1) राजपंचायत की किसी कारवाई की सरदुरुस्ती के बारे में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि उसमें दस्तूर की कोई बेक़ायदगी बताई गई है।

(2) राजपंचायत का कोई अफसर या मेम्बर, जिसको इस विधान से या इसके अधीन, राजपंचायत के दस्तूर की या काम के संचालन की क़ायदाबन्दी करने के लिये, या राजपंचायत में व्यवस्था बनाए रखने के लिये, शक्तियाँ हासिल हैं, उन शक्तियों से काम लेने के बारे में किसी अदालत की अमलदारी के अधीन न होगा।

### खंड तीन—राजपति की कानूनकारी शक्तियाँ

राजपंचायत की छुट्टी  
के दिनों में राजपति  
को राजहुकुम जारी  
करने की शक्ति

123—(1) अगर किसी समय, सिवाय जब कि राजपंचायत के दोनों सदनों का इजलास हो रहा हो, राजपति को यह भरोसा हो जाय कि सूरतें ऐसी हैं जिनमें उसे तुरन्त कारवाई करने की ज़रूरत है तो राजपति ऐसे राजहुकुम जारी कर सकता है जो उन सूरतों में उसे ज़रूरी मालूम हों।

(2) इस दफा के अधीन जो राजहुकुम जारी किया जायगा उसका वही बल और असर होगा जो राजपंचायत के किसी ऐक्ट का, पर हर ऐसे राजहुकुम को—

(ए) राजपंचायत के दोनों सदनों के सामने रखा जायगा, और राजपंचायत के फिर मिलने से छै हफ्ते बीत जाने पर या अगर इस अरसे के बीत चुकने से पहले ही दोनों सदनों ने उस राजहुकुम को नापसन्द करने के ठहराव पास कर दिये हैं तो

इनमें से दूसरे ठहराव के पास होने पर, वह राज-  
हुकुम आगे अमल में नहीं रहेगा; और

(बी) राजपति कभी भी वापस ले सकता है.

समझाव—जब राजपंचायत के सदनों को फिर से मिलने के लिये  
अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया हो, तो इस धारा के मतलबों  
के लिये छै हफ्ते का अरसा इन तारीखों में से पिछली तारीख से  
गिना जायगा.

(3) अगर और जहाँ तक, इस दफ्ता के अधीन कोई राज-  
हुकुम कोई ऐसा बन्धान करता है जिसे राजपंचायत को इस बिधान  
के अधीन कानून का रूप देने का अधिकार नहीं है, वहाँ तक वह  
राजहुकुम रद्द होगा.

### खंड चार—यूनिथन की न्यायकारी

124—(1) भारत की एक आला अदालत होगी जिसमें भारत  
का सरजज होगा और, जब तक राजपंचायत कानून बनाकर कोई  
अधिक गिनती न तय करे तब तक सात से अधिक दूसरे जज  
नहीं होंगे.

आला अदालत का  
कायम होना और  
उसकी बनावट

(2) आला अदालत के हर जज का नियोजन राजपति,  
आला अदालत के और रियासतों की हाईकोर्टों के इन जजों से  
सलाह करके, जिन्हें राजपति इस मतलब के लिये जरूरी समझे, एक  
हुकुमनामे से करेगा जिस पर उसके दसखत होंगे और मुहर  
होगी, और वह जज पैसठ बरस की उमर पूरी करने तक अपने  
पद पर रहेगा:

शर्तें कि सरजज को छोड़कर और किसी जज का नियोजन करने  
में भारत के सरजज की सलाह हमेशा ली जायगी:

और शर्तें कि—

(ए) कोई जज राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत  
भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है ;

(बी) धारा (4) में बताए ढंग से किसी भी जज को उसके  
पद से हटाया जा सकता है.

(3) कोई आदमी आला अदालत का जज नियोजे जाने

के जोग नहीं होगा जब तक वह भारत का नागर न हो, और

(ए) कम से कम पांच बरस तक किसी हाईकोर्ट का या लगातार दो या अधिक हाईकोर्टों का जज न रह चुका हो ; या

(बी) कम से कम दस बरस तक किसी हाईकोर्ट में या लगातार दो या अधिक हाईकोर्टों में वकील न रह चुका हो.

(सी) राजपति की राय में नामी कानून शास्त्री न हो.

समझाव (1)—इस धारा में “हाईकोर्ट” का अर्थ है वह हाईकोर्ट जिसकी अमलदारी भारत के भूभाग के किसी भाग में है या इस विधान के आरम्भ से पहले किसी समय थी.

समझाव (2)—इस धारा के मतलब के लिये उस अरसे को गिनने में जिसमें कोई आदमी वकील रहा है वह अरसा भी शामिल कर लिया जायगा जब वकील बनने के बाद उसने किसी ऐसे जजी के पद पर काम किया हो जो जिला जज के पद से नीचा न हो.

(4) आला अदालत का कोई जज अपने पद से हटाया नहीं जायगा, सिवाय जब कि राजपंचायत के हर सदन ने एक ही इजलास में किसी जज के इस बिना पर हटाए जाने के लिये एक निवेदनी राजपति के सामने रखी हो, कि उस जज का बद्ब्योहार या उसकी नाक्राबलियत साबित हो चुकी है, और उस निवेदनी का सदन के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने और सदन में उस समय मौजूद और वोट देने वाले मेम्बरों में से कम से कम दो तिहाई की बड़ीयत ने समर्थन किया हो, और इसके बाद राजपति एक हुकुम जारी करके उस जज को हटाए.

(5) धारा (4) के अधीन निवेदनी रखे जाने के लिये और किसी जज के बद्ब्योहार या नाक्राबलियत की जांच और सबूत के लिये जो दस्तूर होगा उसकी क्रायदाबन्दी राजपंचायत कानून बना कर कर सकती है.

(6) हर वह आदमी जो आला अदालत का जज नियोजा जाए अपना पद संभालने से पहले राजपति के सामने या किसी

दूसरे आदमी के सामने, जिसे राजपति ने इस काम के लिये नियोजित हो, उस रूप में हलफ उठायगा या वचन भरेगा जो इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया गया है और उस पर दसखत करेगा।

(7) कोई आदमी जो आला अदालत के जज के पद पर रह चुका है, भारत के भूभाग के अन्दर किसी अदालत में या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेगा, न काम करेगा।

125—(1) आला अदालत के जजों को वह तनखाहें दी जायंगी जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं। जजों को तनखाहें बगैरा

(2) हर जज वह निजनियम और भत्ते पाने का हकदार होगा और छुट्टी और पेनशन के बारे में उसके वह अधिकार होंगे जो समय समय पर राजपंचायत के बनाए कानून में या उसके अधीन तय कर दिये जायें, और जब तक इस तरह तय नहीं किये जाते तब तक उसको वह निजनियम, भत्ते और अधिकार मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में बताए गए हैं:

शर्तें कि किसी जज के नियोजन के बाद उसके निजनियमों या भत्तों में या छुट्टी या पेनशन के बारे में उसके अधिकारों में कोई ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे।

126—जब भारत के सरजज का पद सूना हो या जब नामौजूदगी या किसी और कारन से सरजज अपने पद के फरज पूरे न कर सके तो उसके पद के फरज उस अदालत के दूसरे जजों में से कोई एक ऐसा जज पूरा करेगा जिसका राजपति इस मतलब के लिये नियोजन करे। कारकर सर जज का नियोजन

127—(1) अगर किसी समय आला अदालत के इजलास करने या जारी रखने के लिये अदालत के जजों का कोरम पूरा न हो, तो भारत का सर जज, पहले से राजपति की अनुमति लेकर, किसी हाईकोर्ट के किसी ऐसे जज से, जो क्रायदे से आला अदालत के जज नियोजित जाने के जोग हो, और जिसे भारत का सरजज उस पद पर नामजद कर सके, उस हाईकोर्ट के सरजज से सलाह कर के, जितने अरसे के लिये जरूरी हो, आला अदालत की बैठकों ज़रूरी जजों का नियोजन



में जरूरती जज की हैसियत से आने के लिये लिख कर प्रार्थना कर सकता है.

(2) जिस जज को इस तरह नामजद किया गया हो उसका यह फरज होगा कि वह, अपने पद के और फरजों को पूरा करने से पहले, जिस समय और जितने अरसे के लिये उसकी हाजरी दरकार हो, आला अदालत की बैठकों में आए, और जब तक वह इस तरह आता रहेगा उसको आला अदालत के जज की पूरी अमलदारी, शक्तियां और निजनियम मिलेंगे और वह जज के फरज निभारेगा.

आला अदालत की बैठकों में सेवामुक्त जजों का आना

128—इस खंड में किसी बात के रहते भी, भारत का सरजज किसी समय भी, राजपति की पहले से अनुमति लेकर, किसी ऐसे आदमी से जो कभी आला अदालत के या संघ अदालत के जज के पद पर रह चुका है, प्रार्थना कर सकता है कि वह आला अदालत के जज की हैसियत से बैठे और काम करे, और हर वह आदमी जिससे इस तरह की प्रार्थना की गई हो, जब तक वह इस तरह बैठेगा और काम करेगा उन भत्तों का हकदार होगा जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे और उसे आला अदालत के जज की सारी अमलदारी, शक्तियाँ और निजनियम मिलेंगे, मगर वह किसी और तरह उस अदालत का जज नहीं समझा जायगा:

शर्तें कि इस दफा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी ऐसे आदमी को जिसकी चरचा ऊपर की गई है आला अदालत का जज बन कर बैठना और काम करना होगा जब तक कि वह ऐसा करने को राजी न हो जाय.

आला अदालत एक नज्जरी अदालत होगी

129—आला अदालत एक नज्जरी अदालत होगी और उसे अपनी तौहीन के लिये सजा देने की शक्ति समेत नज्जरी अदालत की सब शक्तियाँ होंगी.

आला अदालत के बैठने की जगह

130—आला अदालत देहली में या किसी और ऐसी जगह या जगहों में बैठेगी जो भारत का सर जज, राजपति की राजामन्दी से,

131—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, नीचे लिखे मामलों में पहली सुनवाई का अधिकार आला अदालत को होगा और किसी दूसरी अदालत को नहीं होगा—

आला अदालत को पहली सुनवाई का अधिकार

(ए) भारत सरकार और एक या अधिक रियासतों के बीच कोई झगड़ा; या

(बी) कोई ऐसा झगड़ा जिसमें भारत सरकार और एक या अधिक रियासतें एक तरफ हों और एक या अधिक रियासतें दूसरी तरफ हों; या

(सी) दो या अधिक रियासतों के बीच कोई झगड़ा.

यह अधिकार उस सूरत में और उस हद तक ही होगा जिस हद तक उस झगड़े में कोई ऐसा (कानूनी या बाक्याती) सवाल उठता हो जिस पर किसी कानूनी अधिकार का होना या उसका फैलाव निर्भर हो:

शर्तें कि सुनवाई का यह अधिकार उस झगड़े में नहीं होगा—

(एक) जिसमें एक फरीक पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत है, अगर वह झगड़ा किसी ऐसे संधिनामे, समझौते, मुआहदे, इकरारनामे, सनद या ऐसे ही किसी और पट्टे की किसी शर्त से उठा है जो इस विधान के आरंभ से पहले किया गया था या लिखा गया था और जो विधान के आरंभ के बाद अमल में रहा है या रखा गया है;

(दो) जिसमें एक फरीक कोई रियासत है, अगर वह झगड़ा किसी ऐसे संधिनामे, समझौते, मुआहदे, इकरारनामे, सनद या ऐसे ही किसी और पट्टे की किसी शर्त से उठा है जिसमें यह बन्धान कर दिया गया है कि इस अमलदारी का फैलाव उस तरह के झगड़े तक नहीं होगा.

132—(1) अगर भारत के भूभाग में कोई हाईकोर्ट यह सनद दे दे कि उसकी किसी दीवानी, फौजदारी या दूसरी कारवाई में इस विधान के अर्थ करने के बारे में कानून का कोई ठोस सवाल उठता है तो उस कारवाई में उस हाईकोर्ट के किसी फैसले, डिगरी या आखरी हुकुम की अपील आला अदालत में की जा सकेगी,

कुछ सूरतों में आला अदालत को हाईकोर्टों की अपीलें सुनने की अपीली अमलदारी

(2) जहाँ हाईकोर्ट ने उस तरह की सनद देने से इनकार कर दिया हो, वहाँ अगर आला अदालत को भरोसा हो जाए कि उस मुकदमे में विधान के अर्थ करने के बारे में कानून का कोई ठोस सवाल उठता है तो आला अदालत इस तरह के फैसले, डिगरी या आखरी हुकुम की अपील करने के लिये खास इजाजत दे सकती है।

(3) जहाँ इस तरह की सनद दे दी गई हो, या इस तरह इजाजत दे दी गई हो, वहाँ उस मुकदमे का कोई फरीक इस बिना पर कि किसी ऐसे सवाल का फैसला जिसकी चरचा ऊपर की गई है गलत दिया गया है, और आला अदालत की इजाजत से किसी दूसरी बिना पर भी, अपील कर सकता है।

समझाव—इस दफा के मतलबों के लिये “आखरी हुकुम” शब्दों में वह हुकुम शामिल है जो किसी ऐसे उठावे का फैसला करता हो जिसका फैसला अगर अपील करने वाले के हक में हो जाए तो वह मुकदमे को निबटाने के लिये काफी हो।

दीवानी मामलों के बारे में हाईकोर्टों की अपीलें सुनने की आला अदालत की अपीली अमलदारी

133—(1) भारत के भूभाग में हर हाईकोर्ट की किसी दीवानी कारवाई के अन्दर किसी फैसले, डिगरी या आखरी हुकुम की अपील आला अदालत में की जा सकेगी, अगर हाईकोर्ट यह सनद दे दे कि—

(ए) सबसे पहली अदालत में जिस चीज पर झगड़ा था और जिस पर अपील के समय तक झगड़ा चल रहा है, उसकी रकम या मालियत बीस हजार रुपए से कम नहीं थी और न है, या उस रकम से कम नहीं है जो राजपंचायत कानून बनाकर इस काम के लिये तय करदे ; या

(बी) उस फैसले, डिगरी या आखरी हुकुम में सीधे या ना सीधे उतनी ही रकम या मालियत की जायदाद के सम्बन्ध में कोई दावा या सवाल आ जाता है या

(सी) मुकदमा आला अदालत में अपील के कालिबल है;

और अगर उपधारा (सी) में जिस मुकदमे की चरचा की गई है उसको छोड़कर किसी और मुकदमे में, उस फ़ैसले, डिगरी या आखरी हुकुम में जिसकी अपील की गई है, ठीक निचली अदालत के फ़ैसले को ही पक्का किया गया हो, तो हाईकोर्ट यह भी सनद दे कि अपील में क़ानून का कोई ठोस सवाल आ जाता है।

(2) दफ़ा 132 में किसी बात के रहते भी, कोई फ़रीक़ जो धारा (1) के अधीन आला अदालत में अपील करे वह इस तरह के अपील की एक बिना यह भी रख सकता है कि मुकदमे में, इस विधान के अर्थ करने के सम्बन्ध में, क़ानून के किसी ठोस सवाल का फ़ैसला ग़लत दिया गया है।

(3) इस दफ़ा में किसी बात के रहते भी, किसी हाईकोर्ट के किसी एक जज के किसी फ़ैसले, डिगरी या आखरी हुकुम के खिलाफ़ आला अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकेगी, जबतक कि राजपंचायत क़ानून बना कर कोई और बन्धान न कर दे।

134—(1) आला अदालत को भारत के भूभाग में किसी फौजदारी मामले के बारे में आला अदालत की अपीली अमलदारी हाईकोर्ट की किसी फौजदारी कारवाई में किसी फ़ैसले, आखरी हुकुम या सज़ा के हुकुम की अपील सुनने का अधिकार होगा अगर हाईकोर्ट ने—

(ए) अपील में किसी मुलज़िम की बेगुनाही के हुकुम को उलट दिया हो, और उसको मौत की सज़ा दे दी हो ; या

(बी) कोई मुक़दमा अपने अधिकार के मातहत किसी अदालत से हटाकर जाँच के लिये अपने पास मंगवा लिया हो, और उसमें मुलज़िम को दोषी ठहराया हो और मौत की सज़ा दी हो; या

(सी) यह सनद दी हो कि मुक़दमा आला अदालत में अपील के क़ाबिल है:

शर्तें कि उपधारा (सी) के अधीन अपील उन बन्धानों के अधीन रहते हुए ही की जा सकेगी जो दफ़ा 145 की धारा (1) के अधीन

इस बारे में बनाए जायें और उन शर्तों के अधीन होगी जो हाईकोर्ट कायम कर दे या चाहे।

(2) राजपंचायत, कानून बना कर, उन शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए जो उस कानून में बताई गई हों, आला अदालत को भारत के भूभाग में किसी हाईकोर्ट की किसी फौजदारी कारवाई में किसी फैसले, आखरी हुकुम या सजा के हुकुम की अपील लेने और सुनने की और अधिक शक्तियाँ दे सकती है।

मौजूदा कानून के अधीन संघ अदालत की अमलदारी और शक्तियों से आला अदालत का काम ले सकना

135—जब तक राज पंचायत कानून बना कर कुछ और बन्धान न कर दे, तब तक आला अदालत की अमलदारी और शक्तियाँ किसी ऐसे मामले के बारे में भी होंगी जिस पर दफा 133 या दफा 134 के बन्धान लागू नहीं होते, अगर उस मामले के सम्बन्ध में उस अमलदारी और उन शक्तियों से किसी मौजूदा कानून के अधीन इस विधान के आरंभ से ठीक पहले संघ अदालत काम ले सकती थी।

आला अदालत का अपील की खास इजाजत देना

136—(1) इस खंड में किसी बात के रहते भी, आला अदालत, अपनी समझ से, किसी मुकदमे या मामले में, भारत के भूभाग के अन्दर की किसी अदालत या पंचायती अदालत के किसी फैसले, डिगरी, निबटारे, सजा के हुकुम या दूसरे हुकुम की अपील करने की खास इजाजत दे सकती है।

(2) धारा (1) की कोई बात किसी ऐसे फैसले, निबटारे, सजा के हुकुम या दूसरे हुकुम पर लागू नहीं होगी जो किसी ऐसी अदालत या पंचअदालत ने दिया हो जो अदालत या पंच अदालत हथियार बन्द फौजों से सम्बन्ध रखनेवाले किसी कानून से या उसके अधीन बनाई गई हो।

आला अदालत के फैसलों या हुकुमों पर नज़रसानी

137—राजपंचायत के बनाए किसी कानून के बन्धानों का या दफा 145 के अधीन बने किन्हीं नियमों का ध्यान रखते हुए, आला अदालत को हर फैसले पर जो उसने सुनाया हो या हर हुकुम पर जो उसने दिया हो नज़रसानी करने की शक्ति होगी।

आला अदालत को अमलदारी को

138—(1) आला अदालत को, यूनिशन तालिका में दर्ज किसी भी मामले के बारे में, वह अमलदारी और शक्तियाँ भी होंगी जो

(2) आला अदालत को किसी भी मामले के बारे में वह अमलदारी और शक्तियाँ भी होंगी जो भारत सरकार और किसी रियासत की सरकार आपस में खास समझौता करके उसे सौंप दें, अगर राजपंचायत कानून बना कर इस बात का बन्धान कर दे कि आला अदालत उस अमलदारी और उन शक्तियों से काम ले सकती है।

139—राजपंचायत, कानून बनाकर, दफा 32 की धारा (2) में बताए मतलबों को छोड़ कर किसी और मतलब के लिये, निर्देश, हुकुम, या परवाने जारी करने की शक्ति आला अदालत को सौंप सकती है; इन परवानों में परवाना तन-तलबी, परवाना हुकुम, परवाना मनाही,\* परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिसल-मंगाई जैसे या इनमें से कोई परवाने भी हो सकते हैं।

आला अदालत को कुछ परवाने जारी करने को शक्तियाँ सौंपना

140—राजपंचायत, कानून बना कर, आला अदालत को ऐसी पूरक शक्तियाँ सौंपने का बन्धान कर सकती है जो इस विधान के किसी बन्धान से बेमेल न हों और जिनको राजपंचायत इस मतलब के लिये जरूरी या चहीती समझे कि आला अदालत उस अमलदारी से अधिक असरदार ढंग से काम ले सके जो इस विधान में या इसके अधीन उस अदालत को दी गई हैं।

आला अदालत की सहायक शक्तियाँ

141—आला अदालत जो कानून ठहरा देगी उससे भारत के भूभाग के अन्दर की सब अदालतें बँधी होंगी।

आला अदालत जो कानून ठहरा दे उससे सब अदालत बँधी होंगी।

142—(1) अपनी अमलदारी से काम लेने में आला अदालत कोई ऐसी डिगरी जारी कर सकती है या कोई ऐसा हुकुम दे सकती है जो किसी ऐसे मुकद्दमे या मामले में, जो उसके सामने पेश हो, पूरा इन्साफ करने के लिये जरूरी हो, और उस डिगरी या उस हुकुम पर भारत के सारे भूभाग में उस ढंग से अमल कराया जा सकेगा जो राजपंचायत के बनाए किसी कानून में या उसके अधीन बताया गया हो, और जबतक इस काम के लिये इस तरह बन्धान न किया जाय तब तक उस ढंग से अमल कराया जायगा जो राजपति हुकुम देकर बताए।

आला अदालत को डिगरियों और हुकुमों पर अमल, और खोज वगैरा के बारे में हुकुम

(2) राज पंचायत के बनाए किसी ऐसे कानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो इस काम के लिये बना हो, आलाअदालत को भारत के सारे भूभाग में पूरी और हर तरह की शक्ति होगी कि वह किसी आदमी को हाज़िर कराने, किन्हीं कागज़ पत्रों को खोज निकलवाने या पेश कराने, या खुद अपनी किसी तौहीन वी जाँच कराने या उसकी सज़ा दिलाने के लिये कोई हुक्म जारी करे।

राजपति को आला  
अदालत से राय  
लेने की शक्ति

143—(1) अगर किसी समय राजपति को मालूम हो कि कोई ऐसा कानूनी या वाक्याती सवाल उठा है या उठ सकता है जो इस तरह का और इतने लोक महत्व का है कि उस पर आला अदालत की राय लेना समयोचित होगा, तो वह उस सवाल को सोच विचार के लिये आला अदालत के पास भेज सकता है, और आला अदालत, ऐसी सुनवाई के बाद जो वह ठीक समझे, उस सवाल पर अपनी राय की रिपोर्ट राजपति को भेज सकती है।

(2) दफ़ा 131 की शर्त की धारा (1) में किसी बात के रहते भी, राजपति, उस धारा में जिस तरह के फ़गड़े का जिक्र आया है, उसे राय के लिये आला अदालत के पास भेज सकता है, और आला अदालत, ऐसी सुनवाई के बाद जिसे वह ठीक समझे, उस फ़गड़े पर अपनी राय की रिपोर्ट राजपति को देगी।

दीवानी और न्याय-  
कारी अधिकारियों  
का आला अदालत  
की मदद के लिये  
काम करना

144—भारत के भूभाग के सब दीवानी और न्यायकारी अधिकारी आला अदालत की मदद के लिये काम करेंगे।

अदालत के नियम  
बग़ैरा

145—(1) किसी भी ऐसे कानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो राजपंचायत बनाए, आला अदालत, समय समय पर, राजपति की रज़ामन्दी से, अपने काम और दस्तूर की आम क़ायदाबन्दी के लिये, नियम बना सकती है, जिनमें नीचे लिखे नियम भी हो सकते हैं—

(ए) उस अदालत के सामने बकालत करने वाले लोगों के बारे में नियम ;

- (बी) अपीलें सुनने के दस्तूर के और अपीलों से सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे मामलों के बारे में नियम, जिनमें यह भी आजायगा कि कितने समय के अन्दर अदालत में अपीलों दाखिल हो जानी चाहियें;
- (सी) भाग (तीन) के जरिये दिये हुए अधिकारों में से किसी पर अमल कराने के लिये उस अदालत में कारवाई के नियम ;
- (डी) दफा 134 की धारा (1) की उपधारा (सी) के अधीन अपीलों लेने के बारे में नियम ;
- (ई) उन शर्तों के बारे में नियम जिनके अधीन उस अदालत के सुनाए हुए किसी फैसले या उसके किसी हुकुम पर नज़रसानी की जा सके, और इस तरह की नज़रसानी के लिये दस्तूर संबंधी नियम जिनमें यह भी आजायगा कि कितने समय के अंदर इस तरह की नज़रसानी के लिये अदालत में दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं ;
- (एफ़) उस अदालत के अन्दर किसी कारवाई के खर्चों और उस कारवाई के प्रसंगी खर्चों के बारे में, और उस अदालत की कारवाई के सम्बन्ध में ली जाने वाली फीसों के बारे में नियम ;
- (जी) जमानत की मंजूरी के बारे में नियम ;
- (एच) कारवाई रोक दिये जाने के बारे में नियम ;
- (आइ) किसी ऐसी अपील को झटपट निबटा देने के लिये बन्धान करनेवाले नियम जो अपील अदालत की निगाह में लचर हो या तंग करने के लिये या देर लगाने के लिये की गई हो ;
- (जे) दफा 317 की धारा (1) में जिस पूछताछ की चरचा की गई है उसके दस्तूर के नियम.

(2) धारा (3) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, जो नियम इस दफा के अधीन बनाए जायें उनमें यह तय किया जा सकता है



कि किसी मतलब के लिये कम से कम कितने जज बैठेंगे, और उनमें इस बात का बन्धान भी किया जा सकता है कि अकेले जजों और डिविजन अदालतों की क्या क्या शक्तियाँ होंगी.

(3) किसी ऐसे मुकदमे का फ़ैसला करने के लिये जिसमें इस विधान के अर्थ करने के सम्बन्ध में कानून का कोई ठोस सवाल उठता हो, या दफ़ा 143 के अधीन राय लेने के लिये आए हुए किसी मामले को सुनने के लिये, जो जज बैठेंगे उनकी गिनती कम से कम पाँच होगी:

शर्तें कि जहाँ दफ़ा 132 को छोड़कर इस खंड के किसी और बन्धान के अधीन अपील सुननेवाली किसी अदालत में पाँच से कम जज हैं, और अपील सुनने के दौरान में अदालत को भरोसा हो जाय कि अपील में, इस विधान के अर्थ करने के सम्बन्ध में, कानून का कोई ठोस सवाल उठता है, जिसका तय करना अपील के फ़ैसले के लिये जरूरी है, तो वह अदालत ऐसे सवाल को राय के लिये किसी ऐसी अदालत के पास भेज देगी जो इस धारा के अनुसार ऐसे किसी मुकदमे का फ़ैसला करने के लिये, जिसमें इस तरह का सवाल आता है, बनाई गई हो, और उस अदालत की राय आने पर उस राय के मुताबिक़ उस अपील का फ़ैसला कर देगी.

(4) आला अदालत सिवाय खुले इजलास के अपना कोई फ़ैसला नहीं देगी, और दफ़ा 143 के अधीन कोई रिपोर्ट नहीं करेगी जब तक कि वह रिपोर्ट ऐसी राय के मुताबिक़ न हो जो खुले इजलास में दी गई है.

(5) आला अदालत कोई फ़ैसला और ऐसी कोई राय नहीं देगी जबतक कि मुकदमे की सुनवाई के समय मौजूद जजों की बढ़ीयत उससे सहमत न हो, पर इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि वह किसी जज को जो सहमत नहीं है अपना अनमिल फ़ैसला या अनमिल राय देने से रोकती है.

से नियोजेगा, और वह अपने पद से केवल उसी ढंग से और उन्हीं बिनाओं पर हटाया जा सकेगा जिन पर आला अदालत का कोई जज हटाया जा सकता है.

(2) हर आदमी जो भारत का दाब अफसर और सर पड़तालिया नियोजा जाए, अपना पद संभालने से पहले, राजपति के या किसी ऐसे आदमी के सामने जिसको राजपति इस काम के लिये नियोजे, तीसरी पट्टी में इस मतलब के लिये दर्ज रूप के अनुसार, हलक ठाथगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा.

(3) दाब अफसर और सर पड़तालिया की तनखाह और नौकरी की दूसरी शर्तें वह होंगी जो राजपंचायत क़ानून बना कर तय करे, और जब तक इस तरह तय न हों तब तक वह होंगी जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं :

शर्तें कि दाबअफसर और सर पड़तालिया की तनखाह में, और छुट्टी या पेनशन के बारे में या सेवामुक्त होने की उमर के बारे में उसके अधिकारों में, उसके नियोजन के बाद, कोई ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.

(4) अपने पद से हट जाने के बाद दाब अफसर और सर पड़तालिया भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन और कोई पद लेने का पात्र न होगा.

(5) इस विधान के बन्धानों के और राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के अधीन रहते हुए, भारत पड़ताल और हिसाब महकमें में नौकरी करने वाले लोगों की नौकरी की शर्तें और दाब अफसर और सरपड़तालिया की शासनी शक्तियां वह होंगी जो कि, दाब अफसर और सर पड़तालिया से सलाह करने के बाद, राजपति नियम बनाकर तय करदे.

(6) दाब अफसर और सर पड़तालिया के दफ़तर के शासनी खर्च, जिसमें उस दफ़तर में नौकरी करने वाले लोगों को या उनके बारे में दी जाने वाली सब तनखाहें, भत्ते और पेनशनें भी शामिल होंगी, भारत के मूठकोश के खाते में पड़े'गे.

149. दाब अफसर और सर पड़तालिया यूनियन के, और रियासतों के और किसी दूसरे अधिकारी या संस्था के हिसाब किताब संबंधी ऐसे फरजों को पूरा करेगा और ऐसी शक्तियों से काम लेगा जो राजपंचायत के बनाए किसी कानून में या उसके अधीन बताई जायं, और जब तक इस काम के लिये इस तरह बन्धान नहीं किया जाता तब तक वह यूनियन और रियासतों के हिसाब किताब के संबंध में ऐसे फरज पूरा करेगा और उन शक्तियों से काम लेगा जो हिन्द डोमिनियन और सूबा के हिसाब किताब के संबंध में अलग अलग इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द के सर पड़तालिया को सौंपी गई थी या जिनसे वह काम ले सकता था.

दाब अफसर और सर पड़तालिया के फरज और शक्तियां

150—यूनियन के और रियासतों के हिसाब किताब उस रूप में रखे जायेंगे जो भारत का दाब अफसर और सर पड़तालिया, राजपति की रजामन्दी से, तय कर दे.

दाबअफसर और सरपड़तालिया को हिसाब किताब के संबंध में निर्देश देने की शक्ति पड़ताल की रिपोर्टें

151—(1) यूनियन के हिसाब किताब के संबंध में भारत के दाब अफसर और सर पड़तालिया की रिपोर्टें राजपति को दी जायेंगी, और राजपति उन्हें राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

(2) किसी रियासत के हिसाब किताब के संबंध में भारत के दाब अफसर और सर पड़तालिया की रिपोर्टें उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख को दी जायेंगी और रियासतपति या राजप्रमुख उनको उस रियासत की कानून सभा के सामने रखवायगा.



## भाग छै

### पहली पट्टी के भाग (ए) की रियासतें

#### खंड एक—आम

परिभाषा

152—इस भाग में, अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, “रियासत” शब्द के मानी हैं पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज कोई रियासत.

#### खंड दो—काजकारी

##### रियासतपति

रियासतों के  
रियासतपति

153—हर रियासत का एक रियासतपति होगा.

रियासत की  
काजकारी शक्ति

154—(1) रियासत की काजकारी शक्ति रियासतपति को हासिल होगी और वह उससे खुद या अपने अधीन अफसरों के जरिये इस विधान के अनुसार काम लेगा.

(2) इस दफा की किसी बात से—

(ए) जो काम किसी मौजूदा क़ानून ने किसी दूसरे अधिकारी को सौंपे हैं वह काम रियासतपति को तबदीले नहीं समझे जायेंगे; या

(बी) राजपंचायत को या रियासत की क़ानून सभा को इस बात से नहीं रोका जा सकेगा कि वह क़ानून बनाकर कोई काम रियासतपति के अधीन किसी अधिकारी को सौंपे.

रियासतपति का  
नियोजन

155—हर रियासत के रियासतपति को राजपति अपने दस-खती और मोहर लगे हुकुमनामे से नियोजेगा.

रियासतपति की  
पद-भियाद

156—(1) राजपति के इच्छाकाल तक रियासतपति पद पर रहेगा.

(2) राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत भेजकर

(3) इस दफा में ऊपर के बन्धानों के अधीन रहते हुए रियासतपति पद संभालने की तारीख से पाँच बरस की मियाद तक पद पर रहेगा:

शर्तें कि रियासतपति अपनी मियाद पूरी हो जाने पर भी अपने पदगाही के पद संभालने तक पद पर रहेगा.

157—कोई आदमी रियासतपति नियोजे जाने का पात्र न होगा जबतक कि वह भारत का नागर न हो और अपनी उमर का पैंतीसवाँ बरस पूरा न कर चुका हो.

रियासतपति नियोजे जाने के लिये जायगा

158—(1) रियासतपति राजपंचायत के किसी सदन का या पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन का मेम्बर नहीं होगा, और अगर राजपंचायत के किसी सदन का या किसी ऐसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर रियासतपति नियोजा जाए, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन की अपनी सीट रियासतपति का पद संभालने की तारीख को सूनी कर दी है.

रियासतपति के पद की शर्तें

(2) रियासतपति किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं रहेगा.

(3) रियासतपति बिना किराया दिये अपने सरकारी मकानों के इस्तेमाल करने का हकदार होगा और वह उन वेतनों, भत्तों और निजनियमों का भी हकदार होगा जो राजपंचायत कानून बना कर तय कर दे, और जबतक इस के लिये इस तरह बन्धान न हो तब तक वह उन वेतनों, भत्तों और निजनियमों का हकदार होगा जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

(4) रियासतपति के वेतन और भत्ते उसकी पद-मियाद के दौरान में घटाए नहीं जायेंगे.

159 -- हर रियासतपति और रियासतपति के काम निभारने वाला हर आदमी अपना पद संभालने से पहले उस रियासत के संबंध में अमलदारी रखनेवाली हाईकोर्ट के सरजज या उसके मौजूद न होने पर उस अदालत के उस बड़े से बड़े जज के सामने जो मिल

रियासतपति का हलफ उठाना या बचन भरना

सके नीचे दिये रूप में हलफ उठाएगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा, यानी यह कि—

“मैं.....(नाम)..... ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं गम्भीरता से वचन भरता हूँ कि मैं .....(रियासत का नाम) के रियासतपति के पद पर रहकर वफादारी से काम करूँगा (या रियासतपति के काम वफादारी से निभाऊँगा) और अपनी पूरी जोगता से विधान और कानून को बनाए रखूँगा, और उनकी रक्षा और उनका बचाव करूँगा, और मैं.....(रियासत का नाम) के लोगों की सेवा और उनकी भलाई में तन मन से लगा रहूँगा.”

कुछ जोगाजोगों में रियासतपति के काम निभारना

160—किसी ऐसे जोगाजोग में जिसका इस खंड में बन्धान नहीं किया गया है, किसी रियासत के रियासतपति के काम निभारने के लिये राजपति जैसा उचित समझे बन्धान कर सकता है.

रियासतपति को कुछ सूरतों में माफ़ी वगैरा देने और सज़ा के हुकुमों को रोके रखने, बाक़ो हुकुम रद्द कर देने या सज़ा का रूप बदल देने की शक्ति

161—हर रियासत के रियासतपति को यह शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे आदमी को माफ़ कर दे, उसकी सज़ा मुलतवी कर दे, उसे मुहलत दे दे, या बाक़ी सज़ा माफ़ कर दे, या उसकी सज़ा के हुकुम को रोके रखे या सज़ा के बाक़ी हुकुम को रद्द कर दे, या सज़ा का रूप बदल दे, जिसको किसी ऐसे कानून के खिलाफ़ जुर्म का दोशी ठहराया गया है जो किसी ऐसे मामले की बाबत है जिस तक रियासत की काजकारी शक्ति का फैलाव है.

रियासत की काजकारी शक्ति का फैलाव

162—इस विधान के बंधनों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की काजकारी शक्ति का फैलाव उन मामलों तक होगा जिनके बारे में उस रियासत की कानून सभा को कानून बनाने की शक्ति है:

शर्तें कि ऐसे किसी मामले में जिसके बारे में किसी रियासत की कानून सभा और राजपंचायत दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, रियासत की काजकारी शक्ति उस काजकारी शक्ति के अधीन और उससे हदियाई हुई होगी जो इस विधान से या राजपंचायत के बनाए किसी कानून से खुले तौर पर यूनियन को या उसके अधि-

## वज़ीर मंडल

163—(1) जिस हद तक कि इस विधान में या इसके अधीन रियासतपति को अपने काम या अपना कोई काम अपनी समझ से करने को कहा गया है, उसे छोड़ कर बाक़ी सब कामों के करने में रियासतपति को सहायता और सलाह देने के लिये एक वज़ीर मंडल होगा जिसका सरमुख बड़ा वज़ीर होगा .

रियासतपति को सहायता और सलाह देने के लिये वज़ीर मंडल

(2) अगर यह सवाल उठे कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके बारे में इस विधान के अनुसार या इसके अधीन रियासतपति को अपनी समझ से काम करना चाहिये तो इस सवाल पर रियासतपति अपनी समझ से जो फैसला दे वह आखिरी होगा, और रियासतपति जो कुछ करे उसकी सरदुरुस्ती पर इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि उसे अपनी समझ से काम करना चाहिये था या नहीं.

(3) वज़ीरों ने रियासतपति को कोई सलाह दी या नहीं और अगर दी तो क्या दी इस सवाल की पूछताछ किसी अदालत में नहीं की जायगी.

164—(1) बड़े वज़ीर का नियोजन रियासतपति करेगा और दूसरे वज़ीरों का नियोजन रियासतपति बड़े वज़ीर की सलाह से करेगा, और वज़ीर अपने पद पर रियासतपति के इच्छाकाल तक रहेंगे.

वज़ीरों के बारे में दूसरे बन्धान

शर्तें कि बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा की रियासतों में एक एक वज़ीर ऐसा होगा जिसके जिम्मे क़बाइली लोगों की भलाई का काम होगा, और इसके साथ साथ जिसके जिम्मे पट्टी-दर्ज जातियों और पिछड़ी हुई जमातों की भलाई का काम या कोई दूसरा काम भी हो सकता है.

(2) वज़ीरमंडल के वज़ीर सबके सब मिलकर रियासत के आम सदन को जिम्मेदार होंगे.

(3) किसी वज़ीर के अपना पद संभालने से पहले रियासतपति उससे तीसरी पट्टी में इस मतलब के लिये दिये हुए रूपों के अनुसार पद और राजदूरी के हलफ़ उठवायगा.

(4) कोई वज्जीर जो लगातार छै महीने के किसी अरसे तक उस रियासत की क़ानून सभा का मेम्बर न रहे, उस अरसे के बीत जाने पर, वज्जीर नहीं रहेगा.

(5) वज्जीरों की तनखाहें और भत्ते वह होंगे जो उस रियासत की क़ानून सभा समय समय पर क़ानून बनाकर तय करे, और जब तक रियासत की क़ानून सभा इस तरह तय न करे तबतक वह होंगे जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

### रियासत का सर वकील

रियासत  
सरवकील

का 165—(1) हर रियासत का रियासतपति किसी ऐसे आदमी को उस रियासत का सरवकील नियोजेगा जो हाईकोर्ट का जज नियोजे जाने की जोगता रखता हो.

(2) सरवकील का फ़रज़ होगा कि वह रियासत की सरकार को ऐसे क़ानूनी मामलों पर सलाह दे और ऐसे क़ानूनी ढंग के दूसरे फ़रज़ पूरा करे जो रियासतपति उसे समय समय पर भेजे या सौंपे, और उन कामों को निभारे, जो इस विधान से या उस समय लागू किसी दूसरे क़ानून से या इनके अधीन उसे दिये गए हों.

(3) सरवकील रियासतपति के इच्छाकाल तक अपने पद पर रहेगा और उसको वह मेहनताना मिलेगा जो रियासतपति तय करे.

### सरकारी काम का संचालन

किसी रियासत की  
सरकार के काम  
का संचालन

166—(1) हर रियासत की सरकार का सारा काजकारी काम रियासतपति के नाम से किया हुआ कहा जायगा.

(2) रियासतपति के नाम से दिये हुए हुकुमों और उसके नाम से किये हुए दूसरे पट्टों का सहीकरन उस ढंग से किया जायगा जो रियासतपति के बनाए हुए नियमों में बताया जाय और इस तरह सही किये हुए हुकुम या पट्टे की सरदुरुस्ती पर इस बिना पर कोई सबाल नहीं उठाया जायगा कि वह हुकुम रियासतपति ने नहीं दिया था वह पट्टा रियासतपति ने नहीं किया.

(3) रियासतपति रियासत की सरकार के काम को अधिक सुभीते से चलाने के लिये और उस काम को वज्जीरों में बाँटने के



में इस विधान के अनुसार या इसके अधीन रियासतपति को अपनी सम्मति से काम करना चाहिये.

167—हर रियासत के बड़े वज़ीर का फ़रज़ होगा कि—

(ए) वज़ीरमंडल के सारे फ़ैसले जिनका सम्बन्ध उस रियासत के मामलों के शासन से और क़ानून बनाने के सुझावों से है रियासतपति को पहुँचाए;

(बी) रियासत के मामलों के शासन सम्बन्धी और क़ानून बनाने के सुझावों सम्बन्धी जो बातें रियासतपति पूछे उसको बताए; और

(सी) राजपति के चाहने पर किसी ऐसे मामले को, जिस पर किसी एक वज़ीर ने कुछ फ़ैसला कर लिया है पर वज़ीर मंडल ने विचार नहीं किया है, वज़ीर मंडल के सामने विचार के लिए रखे.

खंड तीन—रियासत की क़ानून सभा :

आम

168—(1) हर रियासत की एक क़ानून सभा होगी जिसमें एक रियासतपति होगा, और जिसमें,

रियासतपति को सूचना देने बग़रा के बारे में बड़े वज़ीर के फ़रज़

रियासतों की क़ानून सभाओं की बनावट

(ए) बिहार, बम्बई, मदरास, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पच्छिम बंगाल की रियासतों में, दो दो सदन होंगे; और

(बी) दूसरी रियासतों में, एक सदन होगा.

(2) जहाँ रियासत की क़ानून सभा में दो सदन होंगे वहाँ एक 'खाससदन' कहलायगा और दूसरा 'आमसदन', और जहाँ केवल एक ही सदन होगा वहाँ वह 'आमसदन' कहलायगा.

169—(1) दफ़ा 168 में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत क़ानून बनाकर किसी रियासत में जहाँ खास सदन है उसका अन्त करने के लिये या किसी रियासत में जहाँ खास सदन नहीं है उसको बनाने के लिये बन्धान कर सकती है, अगर रियासत का आम सदन अपने कुल मेम्बरों की बड़ीयत से और उस समय मौजूद और वोट देने वाले सदन के कम से कम दो तिहाई मेम्बरों की बड़ीयत से इस बात के लिये एक ठहराव पास कर दे.

रियासतों में खास सदनों का अन्त करना या बनाना

(2) धारा (1) में जिस कानून की चरचा की गई है उसमें इस विधान में सुधार करने के लिये ऐसे बन्धान रहेंगे जो उस कानून के बन्धानों को अमल में लाने के लिये जरूरी हों, और ऐसे पूरक, प्रसंगी और परिनामी बन्धान भी रहेंगे जिन्हें राजपंचायत जरूरी समझे.

(3) उपर बताया कोई कानून दफा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा जायगा.

आम सदन की  
रचना

170—(1) दफा 333 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत के आम सदन में वे मेम्बर होंगे जो सीधे चुनाव से चुने गए हों.

(2) किसी भी रियासत के आम सदन में हर भूभागी चुनाव हलके का प्रतिनिधान, पिछले आखरी गिनावे के अनुसार जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं, उस चुनाव हलके की आबादी के आधार पर होगा, और आसाम के स्वाधीन जिलों और शिलांग की नगरायत और छावनी के चुनाव हलके को छोड़कर, आबादी के हर पिछ्तर हज़ार आदमियों पीछे एक से अधिक मेम्बर नहीं होगा:

शर्त कि किसी सूरत में भी किसी रियासत के आम सदन के मेम्बरों की कुल गिनती न पांच सौ से अधिक होगी और न साठ से कम.

(3) हर रियासत के हर भूभागी चुनाव हलके को जो मेम्बर दिये जायेंगे उनकी गिनती और उस चुनाव हलके की आबादी की वह गिनती जो उस पिछले आखरी गिनावे में मालूम की जा चुकी है जिसके संगत आंकड़े निकल चुके हैं, इन दोनों में जहाँ तक हो सकेगा सारी रियासत में एक ही अनुपात होगा.

(4) हर गिनावे के पूरा हो जाने पर, हर रियासत के आम सदन में अलग अलग भूभागी चुनाव हलकों के प्रतिनिधान में वह अधिकारी उस ढंग से और उस तारीख से लागू होने के लिये घटत बढ़त करेगा जिसे राजपंचायत कानून बनाकर तय कर दे :

शर्त कि इस तरह घटत बढ़त का आम सदन के प्रतिनिधान पर तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय का आम सदन भंग न हो जाय.

171—(1) जिस रियासत में खास सदन है, वहाँ उस सदन के खास सदनों की मेम्बरों की कुल गिनती उस रियासत के आम सदन के मेम्बरों की रचना कुल गिनती की एक चौथाई से अधिक नहीं होगी:

शर्तें कि किसी रियासत के खास सदन के कुल मेम्बरों की गिनती किसी भी सूरत में चालीस से कम न होगी.

(2) जब तक राजपंचायत क़ानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे तब तक किसी रियासत के खास सदन की रचना उस तरह होगी जिस तरह धारा (3) में बन्धान किया गया है.

(3) किसी रियासत के खास सदन के मेम्बरों की कुल गिनती में से—

(ए) एक तिहाई के जितने करीब हो सके उतनों का चुनाव वे चुनायतें करेंगी जिनमें उस रियासत के अन्दर की नगरायतों, जिज्ञा बोर्डों और ऐसी दूसरी मुकामी संस्थाओं के मेम्बर होंगे जो राजपंचायत क़ानून बना कर तय कर दे;

(बी) एक बारहवें के जितने करीब हो सके उतनों का चुनाव वे चुनायतें करेंगी जिनमें उस रियासत में बसनेवाले वे लोग होंगे जो कम से कम तीन बरस पहले से भारत के भूभाग की किसी विद्यापीठ के सनातक रह चुके हैं, या कम से कम तीन बरस से उनमें वे जोगताएँ रही हैं जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन ऐसी किसी विद्यापीठ के सनातक की जोगताओं के बराबर ठहरा दी गई हैं;

(सी) एक बारहवें के जितने करीब हो सके उतनों का चुनाव वे चुनायतें करेंगी जिनमें ऐसे आदमी होंगे जो कम से कम तीन बरस तक रियासत के अन्दर ऐसी तालीमी संस्थाओं में पढ़ाते रहे हैं जिनका दर्जा किसी दुसरकी स्कूल के दर्जे से कम नहीं है और जिनको राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन तय कर दिया गया है.

(डी) एक तिहाई के जितने करीब हो सके वतनों का चुनाव उस रियासत के आम सदन के मेम्बर उन लोगों में से करेंगे जो उस सदन के मेम्बर नहीं हैं;

(ई) बाक़ी को रियासतपति धारा (5) के बन्धानों के अनुसार नामजद करेगा.

(4) धारा (3) की उप-धारा (ए), (बी) और (सी) के अधीन जो मेम्बर चुने जायेंगे उनको ऐसे भूभागी चुनाव हलकों में से लिया जायगा जो राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन तय कर दिया गया हो, और उन उप-धाराओं के अधीन और उस धारा की उप-धारा (डी) के अधीन जो चुनाव होंगे वह निम्नवती प्रतिनिधान के ढंग पर इकट्ठे बदलते बोट से किये जायेंगे.

(5) धारा (3) की उप-धारा (ई) के अधीन रियासतपति जिन मेम्बरों को नामजद करेगा वे ऐसे आदमी होंगे जिन्हें इस तरह के मामलों के बारे में जैसे नीचे दिये गए हैं खास जानकारी या अमली तज़रबा हो, यानी :—

अदब-साहित्य, साइन्स, कला, सहकारी आन्दोलन और समाज सेवा.

रियासत की क़ानून  
सभाओं की सुदत

172—(1) हर रियासत का हर आम सदन, अगर पहले ही भंग न कर दिया गया हो, तो जो तारीख़ उसकी पहली मिलनी के लिये तय की गई थी, उससे पांच बरस तक चलेगा और अधिक नहीं, और इस पांच बरस के अरसे के बीत जाने से ही आम सदन भंग माना जाएगा:

शर्तें कि किसी ऐसे समय में जब कोई अधिवेशन का ऐलान अमल में हो, राजपंचायत क़ानून बना कर इस अरसे को एक और अरसे के लिये बढ़ा सकती है जो एक बार में एक बरस से अधिक न होगा, और जो किसी भी सूरत में ऐलान का अमल खतम होने के बाद छै महीने के अरसे से अधिक न चलेगा.

(2) किसी रियासत के खास सदन को भंग नहीं किया जा सकेगा, पर हर दूसरे बरस के बीत जाने पर जितनी जल्दी

हो सकेगा खास सदन के मेम्बरों में से क़रीब से क़रीब एक तिहाई, उन बन्धानों के अनुसार जो राजपंचायत क़ानून के जरिये इस काम के लिये बना दे, अलग हो जाया करेंगे.

173—कोई आदमी किसी रियासत की क़ानून सभा में कोई सीट भरने के लिये चुने जाने के जोग नहीं होगा, जब तक कि वह—

रियासत की क़ानून सभा की मेम्बरी के लिये जोगता

(ए) भारत का नागर न हो;

(बी) आम सदन की सीट के लिये कम से कम पन्चीस बरस की और खास सदन की सीट के लिये कम से कम तीस बरस की उमर का न हो; और

(सी) ऐसी और जोगताएँ न रखता हो जो इस काम के लिये राजपंचायत के बनाए हुए किसी क़ानून में या उसके अधीन बताई जायं.

174—(1) हर रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों को हर बरस में कम से कम दो बार मिलने के लिये बुलाया जायगा और एक इजलास में उनकी आख़री बैठक और अगले इजलास में पहली बैठक की जो तारीख़ ठहराई गई हो उन के बीच छै महीने नहीं बीतने पाएंगे.

रियासत की क़ानून सभा के इजलास, उनका बरखास्त करना और भंग करना

(2) धारा (1) के बंधानों के अधीन रहते हुए, रियासत-पति समय समय पर—

(ए) सदन को या दोनों में से किसी एक सदन को मिलने के लिये जिस समय और जिस जगह ठीक समझे बुला सकता है;

(बी) सदन को या सदनों को बरखास्त कर सकता है;

(सी) आम सदन को भंग कर सकता है.

175—(1) रियासतपति आम सदन में, या जहाँ रियासत में खास सदन भी है वहाँ उस रियासत की क़ानून सभा के किसी भी सदन में, या दोनों सदनों को इकट्ठा करके, सर-बचन दे सकता है, और इस मतलब के लिये मेम्बरों की हाज़री तलब कर सकता है.

रियासतपति को सदन या सदनों में सर-बचन देने या संदेसे भेजने का अधिकार

(2) रियासतपति रियासत की क़ानून सभा के सदन या

सदनों को किसी ऐसे बिल के बारे में जो उस समय कानून सभा के सामने हो, या किसी और मतलब के लिये, संदेसे भेज सकता है, और जिस सदन को इस तरह कोई संदेसा भेजा जाय वह जितनी जल्दी सुभीते के साथ कर सकेगा उस मामले पर सोच विचार करेगा जिस पर सोच विचार करने को उस संदेसे में कहा गया हो.

हर इजलास के  
आरंभ में रियासत-  
पति का खास सर-  
बचन

176—(1) हर इजलास के आरंभ में, रियासतपति आम सदन को, या जहाँ किसी रियासत में खास सदन भी है वहाँ दोनों सदनों को इकट्ठा करके, सर-बचन देगा, और कानून सभा को उसके बुलाए जाने के कारन बताएगा.

(2) सदन के या दोनों सदनों के दस्तूर की क़ायदाबन्दी करने वाले नियमों में इस बात का बन्धान किया जायगा कि इस तरह के सर-बचन में जिन मामलों की चरचा की गई है उन पर बहस करने के लिये समय रखा जाए, और यह बहस सदन के और कामों से पहले हो.

सदनों के बारे में  
बज़ीरों और सर-  
वकील के अधिकार

177—हर वज़ीर को और रियासत के सर वकील को यह अधिकार होगा कि वह रियासत के आम सदन में या जहाँ रियासत में खास सदन भी है वहाँ दोनों सदनों में बोले और दूसरी तरह कारवाई में हिस्सा ले और कानून सभा की किसी भी ऐसी कमेटी में जिस के मेम्बरों में उसका नाम हो बोले और दूसरी तरह कारवाई में हिस्सा ले, मगर वोट देने का हक़दार वह इस दफ़ा की रू से नहीं होगा.

### रियासत की कानूनसभा के अफ़सर

आम सदन का  
सभामुख और उप-  
सभामुख

178—हर रियासत का आम सदन जितनी जल्दी हो सकेगा उस सदन के दो मेम्बरों को अलग अलग उसका सभामुख और उप-सभामुख चुन लेगा, और जब जब सभामुख या उप-सभामुख का पद सूना होगा आम सदन किसी दूसरे मेम्बर को सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, चुन लेगा.

179—कोई मेम्बर जो किसी आम सदन के सभामुख या उप-सभामुख के पद पर हो—

(ए) अगर वह आम सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) किसी समय भी अगर वह मेम्बर सभामुख है तो उप-सभामुख के नाम और अगर वह मेम्बर उप-सभामुख है तो सभामुख के नाम, अपनी दस्तखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है; और

(सी) आम सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे आम सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया हो:

शर्तें कि धारा (सी) के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं किया जाएगा जबतक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया गया हो :

और शर्तें कि जब कभी आम सदन को भंग किया जाए तो भंग होने के बाद अगले आम सदन की पहली मिलनी के ठीक पहले तक सभामुख अपना पद सूना नहीं करेगा.

180—(1) जब कभी सभामुख का पद सूना होगा, उसके पद के फरज उप-सभामुख पूरे करेगा, या अगर उप-सभामुख का पद भी सूना हो तो आम सदन का कोई ऐसा मेम्बर करेगा जिसका रियासतपति इस मतलब के लिये नियोजन करदे.

(2) आम सदन की किसी बैठक में सभामुख के मौजूद न रहने पर उप-सभामुख, या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी जिसे आम सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा कोई आदमी भी मौजूद नहीं है तो कोई और ऐसा आदमी जिसे आम सदन तय करे, सभामुख की जगह काम करेगा.

181—(1) आमसदन की किसी बैठक में जब कि सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख, या जब कि उप-सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये

सभामुख और उप-सभामुख का पद सूना होना, उनका इस्तीफा देना और पद से हटाया जाना

उप-सभामुख को या किसी दूसरे आदमी को सभामुख के पद के फरज पूरा करने या सभामुख की जगह काम करने की शक्ति

जब उस को पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो

तब सभामुख  
या उप-सभामुख  
सदरत नहीं करेगा

किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-सभामुख, मौजूद होने पर भी, सदरत नहीं करेगा, और दफा 180 की धारा (2) के बन्धान हर ऐसी बैठक के बारे में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी ऐसी बैठक के बारे में लागू होते, जिसमें सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता.

(2) आम सदन में सभामुख को उसके पद से हटाने के लिये जब किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो सभामुख को उस सदन में बोलने और दूसरी तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और दफा 189 में किसी बात के रहते भी, केवल पहली बार उस ठहराव पर या ऐसी कारवाई के दौरान में किसी भी दूसरे मामले पर वह वोट देने का हकदार होगा, मगर बराबर के वोट आने की हालत में नहीं होगा.

खास सदन का  
मसनदी और उप-  
मसनदी

182—हर उस रियासत में जिसमें खास सदन है वह सदन जितनी जल्दी हो सकेगा सदन के दो मेम्बरों को अलग अलग खास सदन का मसनदी और उप-मसनदी चुनेगा, और जब जब मसनदी या उप-मसनदी का पद सूना होगा, सदन किसी दूसरे मेम्बर को मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, चुन लेगा.

मसनदी और उप-  
मसनदी का पद  
सूना होना, उनका  
इस्तीफा देना और  
पद से हटाया  
जाना

183—कोई मेम्बर जो किसी खास सदन के मसनदी या उप-मसनदी के पद पर है—

(ए) अगर वह खास सदन का मेम्बर न रहे तो अपना पद सूना कर देगा;

(बी) किसी समय भी अगर वह मेम्बर मसनदी है तो उप-मसनदी के नाम और अगर वह मेम्बर उप-मसनदी है तो मसनदी के नाम अपनी दसखती लिखत भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है; और

(सी) खास सदन के एक ऐसे ठहराव से अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे खास सदन के उस समय के कुल मेम्बरों की बड़ीयत ने पास किया हो:

शर्तें कि धारा (सी) के मतलब के लिये कोई ठहराव पेश नहीं



किया जाएगा जब तक कि उस ठहराव को पेश करने के इरादे का कम से कम चौदह दिन का नोटिस न दिया गया हो।

184—(1) जब कभी मसनदी का पद सूना होगा, उसके पद के फ़रज़ उप-मसनदी पूरे करेगा, या अगर उप-मसनदी का पद भी सूना हो तो खास सदन का कोई ऐसा मेम्बर करेगा जिसका रियासतपति इस मतलब के लिये नियोजन कर दे।

(2) खास सदन की किसी बैठक में मसनदी के मौजूद न रहने पर उप-मसनदी, या अगर वह भी मौजूद नहीं है तो कोई ऐसा आदमी जिसे खास सदन के दस्तूर के नियम तय करें, या अगर ऐसा कोई आदमी भी मौजूद नहीं है, तो कोई और ऐसा आदमी जिसे खास सदन तय करे, मसनदी की जगह काम करेगा।

185—(1) खास सदन की किसी बैठक में जब कि मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी, या जबकि उप-मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो उप-मसनदी, मौजूद होने पर भी सदारत नहीं करेगा, और दफ़ा 184 की धारा (2) के बन्धान हर ऐसी बैठक के बारे में वसी तरह लागू होंगे जिस तरह किसी ऐसी बैठक के बारे में लागू होते जिसमें मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, मौजूद न होता।

(2) खास सदन में मसनदी को उसके पद से हटाने के लिये जब किसी ठहराव पर विचार हो रहा हो तो मसनदी को उस सदन में बोलने और दूसरी तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और दफ़ा 189 में किसी बात के रहते भी, केवल पहली बार उस ठहराव पर या ऐसी कारवाई के दौरान में किसी भी दूसरे मामले पर वह वोट देने का हक़दार होगा, मगर बराबर के वोट आने की हालत में नहीं होगा।

186—आम सदन के सभामुख और उप-सभामुख को, और खास सदन के मसनदी और उप-मसनदी को, वह तनखाहें और भत्ते मिलेंगे जो उस रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर अलग अलग तय कर दे, और जब तक इसके लिये इस तरह का कोई

उप-मसनदी या किसी दूसरे आदमी को मसनदी के पद के फ़रज़ पूरा करने या मसनदी की जगह काम करने की शक्ति

जब उसको उसके पद से हटाने के लिये किसी ठहराव पर विचार किया जा रहा हो तो मसनदी या उप-मसनदी सदारत नहीं करेगा

मसनदी और उप-मसनदी और सभामुख, और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते

बन्धान नहीं होता तब तक उनको वह तनखाहें और भत्ते मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

रियासत की कानून  
सभा की मंत्रायत

187—(1) रियासत की कानून सभा के सदन या हर सदन का अलग अलग मंत्रायती अमला होगा :

शर्तों कि इस धारा की किसी बात से यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह जिस रियासत की कानून सभा में खास सदन है, वहाँ उस कानून सभा के दोनों सदनों के लिये शामिलती जगहें बनाए जाने को रोकती है.

(2) किसी रियासत की कानून सभा कानून बनाकर उस रियासत की कानून सभा के सदन या सदनों के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने के लिये लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क्रायदाबन्दी कर सकती है.

(3) जब तक धारा (2) के अधीन रियासत की कानून सभा कोई बन्धान नहीं करती तब तक रियासतपति आमसदन के सभामुख से या खास सदन के मसनदी से, जैसी सूरत हो, सलाह करने के बाद आमसदन के या खाससदन के मंत्रायती अमले में नियोजे जाने वाले लोगों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क्रायदाबन्दी करने वाले नियम बना सकता है, और जो नियम इस तरह बनाए जायेंगे उनका असर उस धारा के अधीन बने हुए कानून के बन्धानों के अधीन होगा.

### काम का संचालन

मेम्बरों का हलफ़  
उठाना या बचन  
भरना

188—हर रियासत के आम सदन और खास सदन का हर मेम्बर अपनी सीट लेने से पहले रियासतपति के सामने या इस काम के लिये रियासतपति के नियोजे हुए किसी आदमी के सामने उस रूप के अनुसार हलफ़ उठायगा या बचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा जो रूप इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया हुआ है.

सदनों में बैठ केना,  
सीटें सूनी होने  
पर भी सदनों को  
काम करने की  
शक्ति और कोरम

189—(1) सिवाय जब कि इस विधान में कुछ और बन्धान किया गया हो, रियासत की कानून सभा के हर सदन की हर बैठक में, सब सवाल, सभामुख की और मसनदी को छोड़ कर, या उस आदमी को छोड़ कर जो सभामुख या मसनदी की जगह काम कर

रहा हो, उस समय मौजूद और वोट देने वाले सब मेम्बरों के वोटों की बढ़ीयत से तय किये जायंगे.

सभामुख या मसनदी या वह आदमी जो इनकी जगह काम कर रहा हो पहले तो वोट नहीं देगा, पर बराबर वोट आने की सूरत में उसको ज़िंताऊ वोट देने का अधिकार होगा और वह उस अधिकार से काम लेगा.

(2) रियासत की क़ानून सभा के हर सदन को यह शक्ति होगी कि उस सदन के मेम्बरों की कुछ सीटें सूनी होने पर भी काम करे, और रियासत की क़ानून सभा की हर कारवाई सरदुरुस्त होगी, भले ही बाद में यह पता चले कि कोई ऐसा आदमी सदन में बैठा, उसने वोट दिया या और किसी तरह कारवाई में भाग लिया जो ऐसा करने का हक़दार नहीं था.

(3) जब तक रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर कोई दूसरा बन्धान नहीं करती तब तक, रियासत की क़ानून सभा के हर सदन की मिलनी के लिये कोरम दस मेम्बरों का होगा या उस सदन के मेम्बरों की कुल गिनती का एक दसवाँ होगा, जो भी अधिक हो.

(4) अगर किसी रियासत के आम सदन या खास सदन की किसी मिलनी के दौरान में किसी समय कोरम न रहे तो सभामुख का या मसनदी का, या उस आदमी का जो उनमें से किसी की जगह काम कर रहा हो, फ़रज़ होगा कि वह या तो सदन को मुलतवी कर दे या उस मिलनी को कोरम पूरा हो जाने तक के लिये रोक दे.

### मेम्बरों की अजोगताएं

190—(1) कोई आदमी किसी रियासत की क़ानून सभा के दोनों सदनों का मेम्बर नहीं होगा, और रियासत की क़ानून सभा क़ानून बना कर इस बात का बन्धान कर देगी कि अगर कोई आदमी दोनों सदनों का मेम्बर चुन लिया जाय तो वह किसी एक सदन में अपनी सीट सूनी कर दे.

सीटों का सूना  
होना

(2) कोई आदमी पहली पट्टी में दर्ज दो या अधिक रियासतों की कानून सभा का मेम्बर नहीं होगा, और अगर कोई आदमी ऐसी दो या अधिक रियासतों की कानून सभाओं का मेम्बर चुन लिया जाय तो उस अरसे के पूरा होने पर जो राजपति के बनाए नियमों में दिया गया हो, उन सब रियासतों की कानून सभाओं में उस आदमी की सीटें सूनी हो जाएंगी, जब तक कि इससे पहले ही उसने एक को छोड़ कर बाकी सब रियासतों की कानून सभाओं में अपनी सीट से इस्तीफा न दे दिया हो।

(3) अगर रियासत की कानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर—

(ए) दफ्ता 191 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अधीन हो जाय; या

(बी) सभामुख या मसनदी के नाम, जैसी सूरत हो, अपनी दसखती लिखत भेजकर अपनी सीट से इस्तीफा दे दे, तो इस पर उसकी सीट सूनी हो जायगी।

(4) अगर किसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर साठ दिन के अरसे तक, सदन की इजाजत बिना, सदन की सब मिलनियों में नामौजूद रहे तो सदन उसकी सीट को सूनी ठहरा सकता है ;

शर्तें कि साठ दिन के इस अरसे के गिनने में वह अरसा नहीं गिना जायगा जब कि सदन बरखास्त रहा हो या लगातार चार दिन से अधिक के लिये मुलतबी कर दिया गया हो।

मेम्बरी के लिये  
अजोगताएँ

191—(1) वह आदमी किसी रियासत के आम सदन का या खास सदन का मेम्बर चुने जाने, और मेम्बर होने, के अजोग होगा—

(ए) जो भारत सरकार के अधीन या पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, सिवाय किसी ऐसे पद के जिसे रियासत की कानून सभा ने कानून बनाकर यह ठहरा दिया हो कि उस पद पर रहने से कोई आदमी अजोग नहीं होगा ;

(बी) जिसका दिमाग ठीक नहीं है और जिसे किसी अधिकारी अदालत ने ना-ठीक दिमाग का ठहरा दिया है ;

(सी) जो ऐसा दिवालिया है जिसे अभी तक बरी नहीं किया गया है ;

(डी) जो भारत का नागर नहीं है, या जो अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज का नागर बन गया है, या जो किसी विदेशी राज की भक्ति या उससे लगाव मान चुका है ;

(ई) जो राजपंचायत के बनाए किसी कानून में या उसके अधीन इसके लिये अजोग ठहराया गया है.

(2) इस दफा के मतलबों के लिये कोई आदमी भारत सरकार के या पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की सरकार के अधीन केवल इसी कारन किसी लाभ के पद पर नहीं सम्म्ला जायगा कि वह यूनियन का या उस रियासत का बच्चीर है.

192—(1) अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि किसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन का कोई मेम्बर दफा 191 की धारा (1) में बताई किसी अजोगता के अन्दर आ गया है या नहीं, तो इस सवाल को रियासतपति के फ़ैसले के लिये भेजा जायगा, और उसका फ़ैसला आखरी होगा.

मेम्बरों की अजोगताओं के बारे में सवालों का फ़ैसला

(2) ऐसे किसी सवाल पर कोई फ़ैसला देने से पहले रियासतपति चुनाव कमीशन से राय लेगा और उस राय के अनुसार काम करेगा.

193—अगर कोई आदमी दफा 188 की जरूरतों को पूरा करने से पहले, या जब वह यह जानता हो कि वह किसी रियासत के आम सदन या खास सदन की मेम्बरी के जोग नहीं है या उसे उसके अजोग ठहराया गया है या राजपंचायत या रियासत की कानून सभा के बनाए किसी कानून के बन्धानों से उसको मेम्बर की तरह बैठने या वोट देने की मनाही की गई है, रियासत के आम सदन या खास सदन में मेम्बर की तरह बैठेगा या वोट देगा तो जितने दिन

दफा 188 के अधीन हलफ़ उठाने या वचन भरने से पहले या जोग न होने या अजोग ठहराए जाने पर सदन में बैठने और वोट देने पर दंड

वह इस तरह बैठेगा या वोट देगा, उस पर हर दिन के लिये पाँच सौ रुपए दंड लगाया जा सकेगा, जो उससे रियासत के करप्ते के रूप में वसूल किया जायगा.

*सुले* *सुले*  
रियासत की कानून सभाओं और उनके मेम्बरों की शक्तियाँ,  
निर्जनियम और बरीयतें

कानून सभाओं के  
सदनों, उनके मेम्बरों  
और उनकी कमे-  
टियों की शक्तियाँ,  
निर्जनियम बगैरा

194—(1) इस विधान के बन्धानों, और कानून सभा के दस्तूर की क़ायदाबन्दी करने वाले नियमों और क़ायमी हुकुमों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की कानून सभा में बोलने की आज़ादी होगी.

(2) किसी रियासत की कानून सभा के किसी मेम्बर ने जो कुछ कानून सभा में या उसकी किसी कमेटी में कहा हो या जिस तरह वोट दिया हो उसके बारे में उस मेम्बर के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी, और ऐसी कानून सभा के किसी सदन की तरफ से या उसके हुकुम से जो कोई रिपोर्ट, कागज़, वोट या कारवाई निकाली जाय, उसके बारे में किसी आदमी के खिलाफ इस तरह की कोई कारवाई नहीं की जा सकेगी.

(3) और बातों में, हर रियासत की कानून सभा के हर सदन की और उस कानून सभा के हर सदन के मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियाँ, निर्जनियम और बरीयतें वह होंगी जो कानून सभा समय समय पर कानून बनाकर तय कर दे, और जब तक इस तरह तय कर दी जाय तब तक वह होंगी जो इस विधान के आरम्भ के समय यूनाइटेड किंगडम (इंगलिस्तान) की पार्लमेंट के हाउस आफ़ कामन्स को और उसके मेम्बरों और कमेटियों को हासिल हों.

(4) धारा (1), (2) और (3) के बन्धान जिस तरह किसी रियासत की कानून सभा के मेम्बरों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, वही तरह उन लोगों के सम्बन्ध में लागू होंगे जिनको इस विधान की रू से उस रियासत की कानून सभा के किसी सदन में या उसकी किसी कमेटी में बोलने का या किसी और तरह कारवाई में भाग लेने का अधिकार है.

195—हर रियासत के आम सदन और खास सदन के मेम्बर वह तनखाहें और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो उस रियासत की कानून सभा समय समय पर कानून बनाकर तय करे, और जब तक इस बारे में इस तरह का बन्धान न किया जाय तब तक वह उसी दर से और उन्हीं शर्तों पर तनखाहें और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे के आमसदन ( लेजिस्लेटिव असेम्बली ) के मेम्बरों के लिये लागू थीं।

कानूनकारी दस्तूर *financial*

196—(1) नकदी बिलों और दूसरे माली बिलों के बारे में दफा 198 और 207 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी भी बिल की पहल जहां रियासत में खास सदन है वहां रियासत की कानून सभा के किसी भी सदन में की जा सकती है।

बिल रखने और पास करने के बारे में बन्धान

(2) दफा 197 और 198 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, कोई बिल जहां रियासत में खास सदन है वहां कानून सभा के सदनों में पास हुआ उस समय तक नहीं समझा जायगा जब तक कि दोनों सदनों ने, या तो बिना सुधार या केवल ऐसे सुधारों के साथ जिन्हें दोनों सदनों ने मान लिया हो, उस बिल को मान न लिया हो।

(3) कोई बिल, जो किसी रियासत की कानून सभा में पेश है, उसके सदन या सदनों के बरखास्त हो जाने के कारन गिर नहीं जायगा।

(4) कोई बिल जो किसी रियासत के खास सदन में पेश है, और जिसे आम सदन ने पास नहीं किया है, आम सदन के भंग होने पर गिर नहीं जायगा।

(5) अगर कोई बिल रियासत के आम सदन में पेश है या आम सदन से पास होकर खास सदन में पेश है, तो वह उस आम सदन के भंग होने पर गिर जायगा।

197—(1) अगर किसी बिल के, किसी ऐसी रियासत के आम सदन से पास होकर जिसमें खास सदन भी है, खास सदन को भेज दिये जाने के बाद—

नकदी बिलों को छोड़कर दूसरे बिलों के सम्बन्ध में खास सदन की शक्तियों पर रूकावट

(ए) खास सदन ने बिल को नामंजूर कर दिया है; या  
 (बी) खास सदन के सामने बिल के रखे जाने की तारीख  
 से तीन महीने से अधिक बीत गए हों और उस  
 सदन ने उसे तबतक पास न किया हो; या  
 (सी) उस सदन ने बिल को ऐसे सुधारों के साथ पास  
 किया हो जिनको आम सदन नहीं मानता,  
 तो आम सदन, अपने दस्तूर की क्रायदाबन्दी करने वाले नियमों  
 के अधीन रहते हुए, अगर कोई ऐसे सुधार हों जिन्हें खास सदन  
 ने किया, सुझाया या मान लिया हो तो ऐसे सुधारों के साथ या बिना  
 ऐसे सुधारों के, उस बिल को, उसी या उसके बादवाले किसी इजलास  
 में, फिर पास कर सकता है, और उसके बाद इस तरह पास हुए  
 बिल को खास सदन को भेज सकता है.

(2) अगर आम सदन से दूसरी बार इस तरह पास  
 होकर खास सदन को भेज दिये जाने के बाद किसी बिल को—

(ए) खास सदन ने नामंजूर कर दिया हो; या  
 (बी) खास सदन के सामने रखे जाने की तारीख  
 से एक महीने से अधिक बीत गया हो, और  
 उस सदन ने पास न किया हो; या  
 (सी) खास सदन ने ऐसे सुधारों के साथ पास  
 किया हो जिनको आम सदन नहीं मानता,  
 तो यह समझा जायगा कि उस बिल को, उस रूप में जिस में  
 वह दूसरी बार आम सदन में पास हुआ था, और उन सुधारों के  
 साथ, अगर कोई ऐसे सुधार हों तो, जिन्हें खास सदन ने किया है  
 या सुझाया है और आम सदन ने मान लिया है, रियासत की  
 कानून सभा के सदनों ने पास कर दिया है.

(3) इस दफा की कोई बात किसी नकदी बिल पर लागू  
 नहीं होगी.

नकदी बिलों के  
 बारे में खास दस्तूर

198—(1) कोई नकदी बिल पहले खास सदन में नहीं रखा  
 जायगा.



(2) जहाँ रियासत में खास सदन है वहाँ नक़दी बिल आम सदन से पास होकर खास सदन को उसकी सिफ़ारिशों के लिये भेजा जायगा, और खास सदन बिल के आने की तारीख़ से चौदह दिन के अरसे के अन्दर अपनी सिफ़ारिशों के साथ बिल आम सदन को लौटा देगा, इस पर आम सदन चाहे तो खास सदन की सारी सिफ़ारिशें या कोई सी सिफ़ारिश मान ले या न माने.

(3) अगर आम सदन खास सदन की सिफ़ारिशों में से किसी को मान लेता है, तो यह समझा जायगा कि उस नक़दी बिल को उन सुधारों के साथ जिनकी खास सदन ने सिफ़ारिश की है और जिन्हें आम सदन ने मान लिया है, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(4) अगर आम सदन खास सदन की सिफ़ारिशों में से किसी को भी नहीं मानता तो यह समझा जायगा कि उस नक़दी बिल को, बिना उन सुधारों में से किसी के जिनकी सिफ़ारिश खास सदन ने की है, उसी रूप में जिसमें उसे आम सदन ने पास किया था, दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

(5) अगर कोई नक़दी बिल आम सदन से पास होकर सिफ़ारिशों के लिये खास सदन को भेजा गया हो और ऊपर कहे चौदह दिन के अरसे के अन्दर आम सदन को न लौटाया गया हो, तो यह समझा जायगा कि इस अरसे के बीत जाने पर उस बिल को उसी रूप में जिसमें आम सदन ने उसे पास किया था दोनों सदनों ने पास कर दिया है.

199—(1) इस खंड के मतलबों के लिये, वह बिल नक़दी बिल "नक़दी बिलों" की परिभाषा. समझा जायगा जिसमें केवल वही बन्धान हों जिनका नीचे लिखे सब मामलों से या उनमें से किसी मामले से सम्बन्ध है, यानी—

(ए) किसी टैक्स का लगाना, अन्त करना, उसमें छूट देना, उसे बदलना या उसकी क़ायदाबन्दी करना ;

(बी) रियासत के रुपया उधार लेने या किसी तरह की गारंटी देने की क़ायदाबन्दी करना या किसी ऐसी माली ज़िम्मेदारियों के बारे में जो रियासत ने

ले रखी हों या जिन्हें वह लेने वाली हो कानून में कोई सुधार करना ;

(सी) रियासत के मूठकोश या जोगाजोग कोश की रखवाली, ऐसे किसी कोश में रुपया जमा करना या उसमें से रुपया निकालना ;

(डी) रियासत के मूठकोश में से रुपए को खर्च की मदों में डालना ;

(ई) किसी खर्च को रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाला खर्च ठहराना, या इस तरह के किसी खर्च की रकम को बढ़ाना ;

(एफ) रियासत के मूठकोश के हिसाब में या रियासत के सरकारी हिसाब में रुपया वसूल करना, या ऐसे रुपए की रखवाली करना, या उसका निकास करना ; या

(जी) (ए) से (एफ) तक की उप-धाराओं में दर्ज मामलों में से किसी के साथ प्रसंग से आया हुआ कोई और मामला.

(2) किसी बिल को केवल इसी कारन नक़दी बिल नहीं समझा जायगा कि वह जुरमाने करने, या रुपए पैसे के दूसरे दंड देने, या लाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएँ की गई हों उनके लिये फ़ीस माँगने या फ़ीस देने का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुक़ामी मतलबों के लिये किसी मुक़ामी अधिकारी या संस्था के कोई टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने, या उसकी क़ायदाबन्दी करने का बन्धान करता है.

(3) अगर किसी ऐसी रियासत में जहाँ खास सदन है किसी ऐसे बिल के बारे में जो रियासत की कानून सभा में रखा गया है यह सवाल उठे कि वह बिल नक़दी बिल है या नहीं तो इस पर उस रियासत के आम सदन के सभामुख का फ़ैसला आख़री होगा.

(4) जब कोई नक़दी बिल दफ़ा 198 के अधीन खास

सदन को भेजा जाय और जब कोई नकदी बिल दफ्ता 200 के अधीन मंजूरी के लिये रियासतपति के सामने रखा जाय, तो हर ऐसे बिल पर आम सदन के सभामुख की दसखती सनद होगी कि वह बिल नकदी बिल है.

200—जब कोई बिल रियासत के आम सदन से, या उस सूरत बिलों पर मंजूरी में जबकि उस रियासत में खास सदन भी है रियासत की क़ानून सभा के दोनों सदनों से, पास हो जाय तो उसे रियासतपति के सामने रखा जायगा, और रियासतपति ऐलान करेगा कि वह उस बिल पर मंजूरी देता है या उससे अपनी मंजूरी रोक लेता है या उस बिल को राजपति के विचार के लिये रख देता है :

शर्तें कि किसी बिल के रियासतपति के सामने मंजूरी के लिये रखे जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके रियासतपति उस बिल को, अगर वह नकदी बिल नहीं है तो, एक ऐसे संदेसे के साथ सदन या सदनों को लौटा सकता है जिसमें यह प्रार्थना की गई हो कि वह बिल पर या उसके किन्हीं बताए हुए बन्धानों पर फिर से विचार करें और खास कर इस बात को सोचें कि अगर रियासतपति ने अपने संदेसे में किन्हीं सुधारों की सिफ़ारिश की है तो ऐसे किन्हीं सुधारों को ले लेना चाहिये या नहीं, और जब कोई बिल इस तरह लौटा दिया जायगा तो उस संदेसे के अनुसार वह सदन या दोनों सदन बिल पर फिर से विचार करेंगे, और अगर सदन या दोनों सदन बिल को फिर बिना सुधार या सुधारों के साथ पास कर देते हैं, और वह मंजूरी के लिये रियासतपति के सामने रखा जाता है, तो रियासतपति उससे अपनी मंजूरी नहीं रोकेगा :

और शर्तें कि रियासतपति हर ऐसे बिल पर, जो उसकी राय में अगर क़ानून बन जाय तो हाईकोर्ट की शक्तियों को इस तरह कम कर देगा कि वह जगह जिसको भरने के लिये इस विधान ने हाईकोर्ट को बनाया है ख़तरे में पड़ जायगी, अपनी मंजूरी नहीं देगा, बल्कि उसे राजपति के सोच विचार के लिये रख देगा.

201—जब रियासतपति किसी बिल को राजपति के विचार के लिये रख दे, तो राजपति ऐलान करेगा कि वह उस बिल पर अपनी विचार के लिये रखे हुए बिल

मंजूरी देता है या उससे अपनी मंजूरी रोक लेता है :

शर्त कि, जहाँ बिल नक़दी बिल नहीं है, राजपति रियासतपति को यह निर्देश दे सकता है कि वह उस बिल को एक ऐसे संदेसे के साथ, जो दफ़ा 200 की पहली शर्त में बताया गया है, रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों को, जैसी सूरत हो, लौटा दे, और जब बिल इस तरह लौटा दिया जाय तो सदन या दोनों सदन, ऐसे संदेसे के मिलने की तारीख़ से छै महीने के अरसे के अन्दर अन्दर, बिल पर उस संदेसे के अनुसार फिर से विचार करेंगे, और अगर उस बिल को, बिना सुधार या सुधारों के साथ, सदन या दोनों सदन फिर पास कर दें तो उसे फिर राजपति के सामने विचार के लिये रखा जायगा.

### माली मामलों में दस्तूर

सालाना  
ब्योरा

202—(1) रियासतपति हर माली साल के बारे में रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के सामने उस साल के लिये रियासत की आमदनी और खर्च के तख़मीने का एक ब्योरा रखवायगा जिसकी चरचा इस भाग में “सालाना माली ब्योरा” कह कर की गई है.

(2) सालाना माली ब्योरे के अन्दर खर्च के जो तख़मीने रहेंगे उनमें यह रक़में अलग अलग दिखाई जायंगी—

(ए) वह रक़में जो उस खर्च के लिये दरकार होंगी जिसे इस विधान में रियासत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाला खर्च बताया गया है; और

(बी) वह रक़में जो उन दूसरे खर्चों के लिये दरकार होंगी जिनके बारे में यह सुझाव है कि वह रियासत के मूठकोश में से किये जायं;

और उसमें मालगुज़ारी खाते खर्च और दूसरे खर्चों में फ़रक़ किया जायगा.

(3) नीचे लिखे खर्च वह खर्च होंगे जो हर रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगे—

(ए) रियासतपति के वेतन और भत्ते, और उसके पद सम्बन्धी दूसरे खर्च;

- (बी) आम सदन के सभामुख और उप-सभामुख की और, जहाँ रियासत में खास सदन है, वहाँ खास सदन के मसनदी और उप-मसनदी की भी तनखाहें और भत्ते;
- (सी) करजा खर्च जिसके लिये रियासत देनदार है, जिसमें सूद-ब्याज, करजा चुकाई कोश खर्च, और भुगतान खर्च, और उधार लेने, करजा जारी रखने और करजा भुगतान के सम्बन्ध में दूसरे खर्च शामिल होंगे;
- (डी) किसी हाईकोर्ट के जजों की तनखाहों और भत्तों के बारे में खर्च;
- (ई) वह रकमों जो किसी अदालत या पंचायती अदालत के किसी फ़ैसले, डिगरी या पंच फ़ैसले को चुकाने के लिये दरकार हों;
- (एफ़) कोई दूसरा खर्च जिसे यह विधान, या रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर ऐसा खर्च ठहरा दे.

203—(1) उतने तख़्मीने जितनों का सम्बन्ध किसी रियासत के मूठकोश के खाते में पड़नेवाले खर्च से है आम सदन के सामने बोट के लिये नहीं रखे जायंगे, पर इस धारा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह क़ानून सभा में उन तख़्मीनों में से किसी पर बहस होने को रोकती है.

तख़्मीनों के बारे में क़ानून सभा का दस्तूर

(2) उतने तख़्मीने जितनों का सम्बन्ध दूसरे खर्च से है देनगियों की मांगों के रूप में आम सदन के सामने रखे जायंगे, और आम सदन को यह शक्ति होगी कि वह किसी मांग को मंज़ूर कर ले या मंज़ूर करने से इनकार कर दे या किसी मांग को उस मांग में दर्ज रकम में कमी करके मंज़ूर कर ले.

(3) रियासतपति की सिफ़ारिश के बिना किसी देनगी की मांग नहीं की जायगी.

204—(1) दफ़ा 203 के अधीन आम सदन के देनगियां पास कर देने के बाद जितनी ज़रूरी हो सकेगा एक बिल रखा जायगा

मह-बटवारा बिल

जिसमें रियासत के मूठकोश में से नीचे लिखे खर्चों के लिये दरकार रुपयों को खर्च की मदों में डालने का बन्धान किया जायगा—

(ए) जो देनगियां आम सदन ने इस तरह पास कर दी हों ; और

(बी) रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले खर्च, पर जो किसी सूरत में भी सदन या सदनों के सामने पहले से रखे हुए व्योरे में दिखाई रकम से अधिक न होंगे.

(2) ऐसे किसी बिल में रियासत की कानून सभा के किसी सदन या सदनों में किसी ऐसे सुधार का सुझाव नहीं रखा जायगा जिससे इस तरह पास की हुई किसी देनगी की रकम घटाई बढ़ाई जा सके, या उसके देनस्थान को बदल दिया जाय, या रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ने वाले किसी खर्च की रकम बदल दी जाय, और सदारत करनेवाले आदमी का यह फ़ैसला, कि इस धारा के अधीन कोई सुधार लिया जा सकता है या नहीं आख़री होगा.

(3) दफ़ा 205 और 206 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, रियासत के मूठकोश में से कोई रुपया नहीं निकाला जायगा सिवाय उस मह बटवारे के अधीन जो इस दफ़ा के बन्धानों के अनुसार पास हुए कानून में कर दिया गया हो.

पूरक, सहायक या  
अधिक देनगियां

205—(1), (ए) अगर दफ़ा 204 के बन्धानों के अनुसार बने हुए किसी कानून से, किसी खास सेवा पर चालू माली साल में खर्च किये जाने के लिये अधिकारी हुई रकम उस बरस के मतलबों के लिये नाकाफी पाई जाय, या जब किसी चालू माली साल में किसी ऐसी नई सेवा पर पूरक या सहायक खर्च की ज़रूरत पैदा हो गई हो, जिसका विचार उस साल के सालाना माली व्योरे में नहीं किया गया था, या

(बी) अगर किसी माली साल की बात किसी सेवा के लिये मंज़ूर रकम से अधिक कोई रुपया उस

सेवा पर उस साल खर्च हो गया है, तो रियासतपति रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के सामने उस खर्च के तख़मीने की रक़म को दिखानेवाला दूसरा ब्योरा रखवायगा, या रियासत के आम सदन के सामने, जैसी सूरत हो, ऐसे अधिक खर्च की मांग रखवायगा.

(2) ऐसे किसी ब्योरे और खर्च या मांग के सम्बन्ध में, और उस खर्च को पूरा करने के लिये या उस मांग के सम्बन्ध की देनगी को पूरा करने के लिये रियासत के मूठकोश में से रुपये को खर्च की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में, दफ़ा 202, 203, और 204 के बन्धानों का वही असर होगा जो असर उनका सालाना माली ब्योरे और उसमें बताए खर्च या किसी देनगी की मांग और उस खर्च या देनगी को पूरा करने के लिये रियासत के मूठकोश में से रुपये को खर्च की मदों में डालने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले क़ानून के सम्बन्ध में होता है

206—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, रियासत के आम सदन को यह शक्ति होगी कि—

हिसाब पर बोट, साख की बोट और अलग देनगियां

(ए) किसी देनगी पर बोट लेने के लिये दफ़ा 203 में जो दस्तूर बताया गया है उसके पूरा होने से पहले, और उस खर्च के बारे में दफ़ा 204 के बन्धानों के अनुसार क़ानून पास होने से पहले, किसी माली साल के किसी भाग के लिये खर्च के तख़मीने की बाबत पहले से कोई देनगी मंज़ूर कर दे ;

(बी) रियासत के साधनों पर किसी अचानक मांग को पूरा करने के लिये, उस सूरत में जब कि उस सेवा के फैलाव या अनिश्चित रूप के कारन वह मांग उन तफ़सीलों के साथ बयान नहीं की जा सकती जो आम तौर पर सालाना माली ब्योरे में दी

जाती हैं, देनगी मंजूर कर दे ;

(बी) कोई ऐसी अलग देनगी, जो किसी माली साल की किसी चालू सेवा का कोई भाग नहीं है, मंजूर कर दे ;

और रियासत की क़ानून सभा को शक्ति होगी कि क़ानून बनाकर वह देनगियां जिन मतलबों के लिये मंजूर की गई हैं उनके लिये रियासत के मूठकोश में से रुपए निकालने का अधिकार दे दे.

(2) धारा (1) के अधीन कोई देनगी मंजूर करने के सम्बन्ध में, और उस धारा के अधीन बनाए जाने वाले किसी क़ानून के सम्बन्ध में, दफ़ा 203 और 204 के बन्धानों का वही असर होगा जो सालाना माली ब्योरे में बताए किसी खर्च के बारे में कोई देनगी मंजूर करने के सम्बन्ध में, और ऐसे खर्च को पूरा करने के लिये रियासत के मूठकोश में से रुपए को खर्च की मदों में बाँटने का अधिकार देने के लिये बनाए जाने वाले क़ानून के सम्बन्ध में, होता है.

माली बिलों के बारे में खास बन्धान

207—(1) दफ़ा 199 की धारा (1) की (ए) से (एफ तक की उप-धाराओं में जो मामले दर्ज हैं उनमें से किसी के लिये बन्धान करने वाला कोई बिल पहले नहीं रखा जा सकेगा, न कोई सुधार पेश किया जा सकेगा, जब तक कि रियासतपति उसकी सिफ़ारिश न करे, और इस तरह का बन्धान करने वाला कोई बिल पहले खास सदन में नहीं रखा जायगा :

शर्तें कि किसी ऐसे सुधार को पेश करने के लिये जो किसी टैक्स को कम करने या उसका अन्त करने का बन्धान करता हो इस धारा के अधीन कोई सिफ़ारिश दरकार न होगी.

(2) कोई बिल या सुधार केवल इसी कारन ऊपर बताए किसी मामले के लिये बन्धान करने वाला नहीं समझा जायगा कि वह ज़ुरमाने करने या रुपए पैसे का कोई दूसरा दंड देने या लाइसेंसों के लिये या जो कोई सेवाएं की गई हों उनके लिये फ़ीस मांगने या फ़ीस देने का बन्धान करता है, या इस कारन कि वह मुक़ामी मतलबों के लिये किसी मुक़ामी अधिकारी या संस्था के कोई



टैक्स लगाने, अन्त करने, उसमें छूट देने, उसको बदलने, या उसकी क्रायदाबन्दी करने का बन्धान करता है.

(3) अगर किसी बिल के कानून बन जाने और उस पर अमल होने से किसी रियासत के मूठकोश से खर्च करना पड़े तो उस बिल को उस रियासत की कानून सभा का कोई सदन पास नहीं करेगा जब तक कि रियासतपति ने उस बिल पर सोच विचार करने की उस सदन से सिफारिश न की हो.

### आम दस्तूर

208—(1) इस विधान के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, हर दस्तूर के नियम रियासत की कानून सभा का हर सदन अपने दस्तूर की और काम के संचालन की क्रायदाबन्दी करने के लिये नियम बना सकता है.

(2) जब तक धारा (1) के अधीन नियम नहीं बनते, तब तक दस्तूर के जो नियम और जो क्रायमी हुकुम इस विधान के जारी होने से ठीक पहले जवाबी सूबे की कानून सभा के बारे में अमल में थे वही उस रियासत की कानून सभा के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, पर आम सदन का सभामुख या खास सदन का मसनदी, जैसी सूरत हो, उनमें अदल बदल और अनुकूलन कर सकता है.

(3) जिस रियासत में खास सदन है वहाँ रियासतपति, आम सदन के सभामुख और खास सदन के मसनदी से सलाह करके, दोनों सदनों के बीच आवाजाई के बारे में दस्तूर के नियम बना सकता है.

209—माली काम को समय के अन्दर पूरा करने के लिये, किसी रियासत की कानून सभा कानून बनाकर किसी माली मामले के सम्बन्ध में, या रियासत के मूठकोश में से रुपये को खर्च की मदों में डालने वाले किसी बिल के सम्बन्ध में, रियासत की कानून सभा के सदन या सदनों के दस्तूर की, और काम के संचालन की, क्रायदाबन्दी कर सकती है, और अगर इस तरह बने किसी कानून का कोई बन्धान, दफ्ता 208 की धारा (1) के अधीन रियासत की कानून सभा के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन के बनाए हुए किसी नियम से, या किसी ऐसे नियम या क्रायमी हुकुम से

माली काम के सम्बन्ध में रियासत की कानून सभा के दस्तूर की कानून से क्रायदाबन्दी

जो उस दफ्ता की धारा (2) के अधीन रियासत की क़ानून सभा के सन्बन्ध में लागू होता हो, मेल नहीं खाता तो उस मेल न खाने की हद तक वह बन्धान ही चलेगा.

क़ानूनसभा में काम  
में आने वाली भाषा

210—(1) भाग सतरह में किसी बात के रहते भी, पर दफ्ता 348 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की क़ानून सभा में काम उस रियासत की दफ्तरारी भाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंगरेज़ी में किया जायगा :

शर्तें कि आम सदन का सभामुख या ख़ास सदन का मसनद या उनकी जगह काम करने वाला कोई आदमी, जैसी सूरत हो, किसी ऐसे मेम्बर को जो ऊपर कही भाषाओं में से किसी में अपने को पूरी तरह अदा न कर सकता हो, सदन में अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है.

(2) जब तक रियासत की क़ानून सभा क़ानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे तब तक इस दफ्ता का इस विधान के आरंभ से पन्द्रह बरस का अरसा बीत जाने के बाद वही असर होगा मानो “या अंगरेज़ी में” ये शब्द इस दफ्ता में से निकाल दिये गये हों.

क़ानून सभा में  
बहस पर रुकवट

211—आला अदालत के या किसी हाईकोर्ट के किसी जज ने अपने फ़रज़ निभारने में जो कुछ किया हो उसके बारे में किसी रियासत की क़ानून सभा में कोई बहस नहीं की जायगी.

क़ानून सभा की  
कारवाइयों के बारे  
में अदालतें पूछताछ  
नहीं करेंगी

212—(1) किसी रियासत की क़ानून सभा की किसी कारवाई की सरदुरुस्ती के बारे में इस बिना पर कोई सवाल नहीं उठाया जायगा कि उसमें दस्तूर की कोई बेक़ायदगी बताई गई है.

(2) किसी रियासत की क़ानून सभा का कोई अफ़सर या मेम्बर, जिसको इस विधान में या इसके अधीन क़ानून सभा के दस्तूर की या काम के संचालन की क़ायदाबन्दी करने के लिये या क़ानून सभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिये शक्तियाँ हासिल हैं, उन शक्तियों से काम लेने के बारे में किसी अदालत की अमलदारी के अधीन न होगा.

## खंड चार—रियासतपति की कानूनकारी शक्ति

213—(1) अगर किसी समय, सिबाय जबकि किसी रियासत के आम सदन का इजलास हो रहा हो, या जहाँ रियासत में खास सदन भी है वहाँ कानून सभा के दोनों सदनों का इजलास हो रहा हो, रियासतपति को यह भरोसा हो जाय कि उस समय कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें उसे तुरंत कारवाई करने की जरूरत है, तो रियासतपति ऐसे राजहुकुम जारी कर सकता है जो उन सूरतों में उसे जरूरी मालूम हों:

कानून सभा को छुटी के दिनों में रियासतपति को राजहुकुम जारी करने की शक्ति

शर्तें कि, रियासतपति, बिना राजपति की हिदायतों के, कोई ऐसा राजहुकुम जारी नहीं करेगा अगर—

(ए) इस विधान के अधीन, उस राजहुकुम के बन्धानों वाले किसी बिल को कानून सभा में रखने के लिये राजपति की पहले से मंजूरी लेना दरकार होता ; या

(बी) वह उन्हीं बन्धानों वाले किसी बिल को राजपति के सोचविचार के लिये रखना जरूरी समझता; या

(सी) उन्हीं बन्धानों वाला रियासत की कानून सभा का कोई एकट इस विधान के अधीन तब तक सर-दुरुस्त न होता जबतक वह राजपति के सोच-विचार के लिये न रखा गया होता और उसे राजपति की मंजूरी न मिल गई होती.

(2) इस दफा के अधीन जो राजहुकुम जारी किया जाय उसका वही बल और असर होगा जो उस रियासत की कानून सभा के किसी ऐसे एकट का होता जिस पर रियासतपति ने मंजूरी दे दी होती ; पर हर ऐसे राजहुकुम को—

(ए) रियासत के आम सदन के सामने या जहाँ रियासत में खास सदन भी है वहाँ दोनों सदनों के सामने रखा जायगा, और कानून सभा के फिर मिलने से छै हफ्ते बीत जाने पर, या अगर इस अरसे के बीत चुकने से पहले ही आम सदन ने उस

राजहुकुम को नापसन्द करने का ठहराव पास कर दिया हो, और जहाँ खास सदन भी है वहाँ खास सदन ने उस ठहराव को मान लिया हो, तो उस ठहराव के पास होने पर, या, जैसी सूरत हो, खास सदन के उस ठहराव को मान लेने पर, वह राजहुकुम आगे अमल में नहीं रहेगा ; और

(बी) रियासतपति कभी भी वापस ले सकता है.

समझाव—जिस रियासत में खास सदन है वहाँ अगर दोनों सदनों को फिर से मिलने के लिये अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया हो तो इस धारा के मतलबों के लिये छै हफ्ते का अरसा उन तारीखों में से पिछड़ी तारीख से गिना जायगा.

(3) अगर इस दफा के अधीन कोई राजहुकुम कोई ऐसा बन्धान करता है जिसे अगर रियासतपति से मंजूरी पाए हुए उस रियासत की कानून सभा के किसी एक्ट में कानून का रूप दिया गया होता तो वह बन्धान सरदुरुस्त न होता, तो उस हद तक वह राजहुकुम रद्द होगा :

शर्तें कि इस विधान के उन बन्धानों के मतलबों के लिये, जिनका सम्बन्ध किसी रियासत की कानून सभा के ऐसे एक्ट के असर से है जो संगचारी तालिका में गिनाए हुए किसी मामले के बारे में किसी मौजूदा कानून के या राजपंचायत के किसी एक्ट के खिलाफ जाता है, राजपति की हिदायतों पर अमल करते हुए, इस दफा के अधीन, जो राजहुकुम जारी किया जाय, वह उस रियासत की कानून सभा का ऐसा एक्ट समझा जायगा जिसे राजपति के खोच विचार के लिये रखा गया हो और राजपति ने उसपर मंजूरी दे दी हो.

### खंड पाँच—रियासतों की हाईकोर्टें

रियासतों के लिये  
हाईकोर्टें

214—(1) हर रियासत के लिये एक हाईकोर्ट होगी.

(2) इस विधान के मतलबों के लिये उस हाईकोर्ट को जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले किसी सूबे के संबंध में

अपनी अमलदारी से काम लेती थी जवाबी रियासत के लिये हाईकोर्ट समझा जायगा.

(3) इस खंड के बन्धान हर उस हाईकोर्ट पर लागू होंगे जिसकी चरचा इस दफा में की गई है.

215—हर हाईकोर्ट नज़ीरी अदालत होगी और उसे अपनी तौहीन के लिये सजा देने की शक्ति समेत ऐसी अदालत की सब शक्तियाँ होंगी. हाईकोर्टें नज़ीरी अदालतें होंगी

216—हर हाईकोर्ट में एक सरजज और ऐसे दूसरे जज होंगे जिन्हें राजपति समय समय पर नियोजना जरूरी समझे : हाईकोर्टों की बनावट

शर्तें कि इस तरह नियोजे हुए जज किसी समय भी उस बड़ी से बड़ी गिनती से ज्यादा नहीं होंगे जो राजपति, समय समय पर, उस अदालत के सम्बन्ध में हुकुम देकर तय करदे.

217—(1) हाईकोर्ट के हर जज का नियोजन राजपति, भारत के सरजज से, उस रियासत के रियासतपति से, और सरजज को छोड़ कर किसी और जज के नियोजन में उस हाईकोर्ट के सरजज से, सलाह कर के, एक ऐसे हुकुमनामे से करेगा जिस पर राजपति के दसखत होंगे और उसकी मुहर रहेगी, और वह जज साठ बरस की उमर पूरी करने तक अपने पद पर रहेगा: हाईकोर्ट के हर जज का नियोजन और उसके पद की शर्तें

शर्तें कि—

(ए) कोई जज राजपति के नाम अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है;

(बी) किसी जज को राजपति उस ढंग पर उसके पद से हटा सकता है जो दफा 124 की धारा (4) में आला अदालत के किसी जज को हटाने के लिये बताया गया है ;

(सी) अगर किसी जज को राजपति आला अदालत का जज नियोज दे या उसकी भारत के भूभाग के अन्दर किसी और हाईकोर्ट को बदली करदे तो उस जज का पहला पद सूना हो जायगा.

(2) कोई आदमी किसी हाईकोर्ट का जज नियोजे जाने

के जोग नहीं होगा जब तक वह भारत का नागर न हो, और—

- (ए) कम से कम दस बरस तक भारत के भूभाग में किसी न्यायी पद पर न रहा हो ; या
- (बी) कम से कम दस बरस तक पहली पट्टी में दर्ज किसी रियासत की हाईकोर्ट में या लगातार दो या अधिक ऐसी हाईकोर्टों में वकील न रह चुका हो.

समझाव—इस धारा के मतलबों के लिये—

- (ए) उस अरसे को गिनने में जिसमें कोई आदमी किसी हाईकोर्ट का वकील रहा है, वह अरसा भी शामिल किया जायगा जब वकील बनने के बाद उसने किसी न्यायी पद पर काम किया हो ;
- (बी) उस अरसे को गनने में जिसमें कोई आदमी भारत के भूभाग में न्यायी पद पर रह चुका है, या किसी हाईकोर्ट का वकील रह चुका है, इस विधान के आरंभ होने से पहले का वह अरसा भी शामिल किया जायगा जिसमें वह आदमी किसी ऐसे क्षेत्र में न्यायी पद पर काम कर चुका है जो 1947 की अगस्त के पन्द्रहवें दिन से पहले उस हिन्द में शामिल था जिसकी परिभाषा हिन्द सरकार एक्ट 1935 में की गई है, या वह ऐसे किसी क्षेत्र में किसी हाईकोर्ट में वकील रह चुका है, जैसी सूरत हो.

आला अदालत से सम्बन्ध रखने वाले कुछ बन्धानों का हाईकोर्टों पर लागू होना

218—दफा 124 की धारा (4) और (5) के बन्धान जिस तरह आला अदालत के सम्बन्ध में लागू होते हैं उसी तरह हर हाईकोर्ट के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, और जहाँ उनमें आला अदालत की चरचा की गई है वहाँ उसकी जगह हाईकोर्ट की चरचा समझी जायगी .

हाईकोर्टों के जजों का हलफ उठाना या बचन भरना

219—हर वह आदमी जो किसी रियासत की हाईकोर्ट का जज नियोजा जाय, अपना पद संभालने से पहले, उस रियासत के रियासतपति के सामने या किसी दूसरे आदमी के सामने जिसे रियासतपति ने इस काम के लिये नियोजा हो, उस रूप में हलफ

उठायगा या वचन भरेगा और उस पर दसखत करेगा, जो इस मतलब के लिये तीसरी पट्टी में दिया गया है.

220—कोई आदमी जो इस विधान के आरम्भ होने के बाद किसी हाईकोर्ट के जज के पद पर रह चुका है भारत के भूभाग के अन्दर किसी अदालत में या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं करेगा, न काम करेगा.

जजों को अदालतों में या किसी अधिकारी के सामने वकालत करने की मनाही

221—(1) हर हाईकोर्ट के जजों को वह तनखाहें दी जायंगी जो दूसरी पट्टी में दर्ज हैं.

जजों की तनखाहें, भगैरा

(2) हर जज वह भत्ते पाने का हकदार होगा और छुट्टी और पेनशन के बारे में उसके वह अधिकार होंगे जो समय समय पर राजपंचायत के बनाए कानून में या उसके अधीन तय कर दिये जायं, और जब तक इस तरह तय नहीं किये जाते तब तक उसको वह भत्ते और अधिकार मिलेंगे जो दूसरी पट्टी में बताए गए हैं :

शर्तें कि किसी जज के नियोजन के बाद उसके भत्तों में या छुट्टी या पेनशन के बारे में उसके अधिकारों में कोई ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.

222—(1) राजपति भारत के सरजज से सलाह करके भारत के भूभाग के अन्दर किसी जज का एक हाईकोर्ट से किसी दूसरी हाईकोर्ट को तबादला कर सकता है.

किसी जज का एक हाईकोर्ट से दूसरी में तबादला

(2) जब किसी जज का इस तरह तबादला किया जाय तो उस अरसे में जब वह दूसरी अदालत के जज की हैखियत से काम कर रहा हो वह अपनी तनखाह के अलावा वह भरपाई भत्ता पाने का हकदार होगा जो राजपंचायत कानून बनाकर तय करे, और जब तक इस तरह तय न हो तब तक वह भरपाई भत्ता पाने का हकदार होगा जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे.

223—जब किसी हाईकोर्ट के सरजज का पद सूना हो, या नामौजूदगी या दूसरे कारन से सरजज अपने पद के फरजों को पूरा न कर सके, तब उस अदालत के दूसरे जजों में से कोई एक, जिसे राजपति इस मतलब के लिये नियोजे, उस पद के फरजों को पूरा करेगा.

कारकर सरजज का नियोजन

हाईकोर्टों की बैठकों में सेवासुक्त जजों का आना

224—इस खंड में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत की हाईकोर्ट का सरजज, किसी समय भी, राजपति की पहले से अनुमति लेकर, किसी ऐसे आदमी से जो कभी उस हाईकोर्ट के या किसी और हाईकोर्ट के जज के पद पर रह चुका है प्रार्थना कर सकता है कि वह उस रियासत की हाईकोर्ट में जज की हैसियत से बैठे और काम करे, और हरवह आदमी जिससे यह प्रार्थना की गई हो, जब तक इस तरह बैठेगा और काम करेगा, उन भत्तों का हकदार होगा जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे, और उसे उस हाईकोर्ट के जज की सारी अमलदारी, शक्तियाँ और निजनियम मिलेंगे, मगर वह किसी और तरह उस अदालत का जज नहीं समझा जायगा :

शर्तें कि इस दफा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि किसी ऐसे आदमी को जिसकी चरचा ऊपर की गई है उस हाईकोर्ट के जज की हैसियत से बैठना और काम करना पड़ेगा, जब तक कि वह ऐसा करने के लिये राजी न हो जाय.

मौजूदा हाईकोर्टों की अमलदारी

225—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, और किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो किसी मुनासिब क़ानून सभा ने उन शक्तियों की रूप से बनाया हो जो इस विधान में उस क़ानून सभा को दी गई हैं, किसी मौजूदा हाईकोर्ट की वही अमलदारी होगी, और उसमें उसी क़ानून पर अमल कराया जायगा, और उस अदालत में न्याय करने के बारे में जजों को अलग अलग वही शक्तियाँ होंगी, जो इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले थीं ; इन शक्तियों में अदालत के नियम बनाने की शक्ति और अदालत और उसके जजों की बैठकों के लिये, चाहे वह अकेले बैठें चाहे डिब्रीज्मन अदालत के रूप में बैठें, क़ायदाबन्दी करने की शक्ति भी शामिल होगी:

शर्तें कि मालगुजारी सम्बन्धी किसी मामले के बारे में, या मालगुजारी की वसूली में जो कोई काम किया जाय या जिसके करने का हुकुम दिया जाय उससे सम्बन्ध रखने वाले किसी मामले के बारे में, किसी हाईकोर्ट के पहली सुनवाई के अधिकार से काम लेने पर इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले अगर कोई रुकावट लगी हुई



थी तो वह रुकावट इसके बाद उस हाईकोर्ट के उस अधिकार से काम लेने पर नहीं रहेगी।

226—(1) दफा 32 में किसी बात के रहते भी, तीसरे भाग में जो अधिकार दिये गए हैं उनमें से किसी पर अमल कराने के लिये या और किसी मतलब के लिये हर हाईकोर्ट को, उन तमाम भूभागों में जिनके सम्बन्ध में उसकी अमलदारी चलती है, उन भूभागों के अन्दर के किसी आदमी या किसी अधिकारी या मुनासिब सूरतों में वहां की किसी सरकार के नाम, निर्देश, हुकुम, या परवाने जारी करने की शक्ति होगी, जिनमें परवाना तनतलबी, परवाना हुकुम, परवाना मनाही, परवाना अधिकार-बताई और परवाना मिसल-मंगाई जैसे या इनमें से कोई परवाने भी हो सकते हैं।

कुछ परवाने जारी करने की हाईकोर्टों की शक्ति

(2) धारा (1) में जो शक्ति हाईकोर्ट को दी गई है, उससे आला अदालत की उस शक्ति में कोई कमी नहीं आयगी जो दफा 32 की धारा (2) में आला अदालत को दी गई है।

227—(1) हर हाईकोर्ट, उन सब भूभागों में जिनके सम्बन्ध में उसकी अमलदारी चलती है, सब अदालतों और पंचायती अदालतों पर निगरानी रखेगी।

हाईकोर्ट को सब अदालतों पर निगरानी रखने की शक्ति

(2) ऊपर के बंधान की आसियत को कम किये बिना, हाईकोर्ट—

(ए) उन अदालतों से व्योरे मांग सकती है;

(बी) उन अदालतों के काम और कारवाइयों की क़ायदाबन्दी करने के लिये आम नियम बना सकती है और जारी कर सकती है और रूप बता सकती है; और

(सी) वह रूप बता सकती है जिनमें ऐसी किसी अदालतों के अफ़सर अपने यहाँ के खाते, दाखले, और हिसाब किताब रखेंगे।

(3) हाईकोर्ट उन फ़ीसों के भी नक़शे तय कर सकती है जो उन अदालतों के शैरिफ़, और सब क़लकों, और अफ़सरों को,

और उन अदालतों में बकायत करने वाले मुख्तारों, वकीलों और प्लीडरों को दी जा सकेंगी :

शर्तें कि धारा (2) या धारा (3) के अधीन जो नियम बनाए जायं, या जो रूप बताए जायं, या नक़्शे तय किये जायं, वह किसी ऐसे क़ानून के बन्धान के ख़िलाफ़ नहीं होंगे जो उस समय अमल में हो, और उन पर पहले से रियासतपति की रज़ामन्दी लेना द़रकार होगा.

(4) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह किसी हाईकोर्ट को ऐसी किसी अदालत या पंचअदालत पर निगरानी रखने की शक्तियाँ देती है जो हथियारबन्द फ़ौजों से संबन्ध रखने वाले किसी क़ानून से या उसके अधीन बनी हो.

कुछ मुक़दमों का हाईकोर्ट में तथा-दला

228—अगर हाईकोर्ट को यह भरोसा हो जाय कि, किसी ऐसे मुक़दमे में जो उसकी किसी मातहत अदालत में पेश है, इस विधान के अर्थ करने के बारे में क़ानून का कोई ऐसा ठोस सवाल उठता है जिसका तय करना उस मुक़दमे को निबटाने के लिये ज़रूरी है, तो वह उस मुक़दमे को उस अदालत से उठा लेगी और—

(ए) या तो आप उस मुक़दमे को निबटा देगी, या

(बी) क़ानून के उस सवाल को तय कर देगी, और उस सवाल पर अपने फ़ैसले की नक़ल के साथ मुक़दमा उस अदालत को वापस कर देगी जिससे वह उठाया गया था, और वह अदालत उसके आने पर उस फ़ैसले के अनुसार उस मुक़दमे को निबटाने की कारवाई करेगी.

हाईकोर्टों के अफ़सर, नौकर और खर्च

229—(1) हाईकोर्ट के अफ़सरों और नौकरों का नियोजन उस अदालत का सरजज करेगा या अदालत का वह दूसरा जज या अफ़सर करेगा जिसे सरजज निर्देश करदे:

शर्तें कि जिस रियासत में उस हाईकोर्ट की खास जगह है उस रियासत का रियासतपति नियम बनाकर यह द़रकार कर सकता है कि, उन सूरतों में जो उस नियम में बताई गई हों, किसी ऐसे आदमी को, जो पहले से उस अदालत से लगा हुआ नहीं है, उस अदालत से सम्बन्ध रखने वाले किसी पद पर रियासत सरकारी

नौकरी कमीशन से संलाह किये बिना नहीं नियोजा जायगा.

(2) रियासत की कानून सभा के बनाए किसी कानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, हाईकोर्ट के अफसरों और नौकरों की नौकरी की शर्तें वह होंगी जो उन नियमों में बताई जायं जिन्हें उस हाईकोर्ट के सरजज ने या उसके किसी ऐसे दूसरे जज या अफसर ने बनाया हो जिसे सरजज ने इस मतलब के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया है :

शर्तें कि इस धारा के अधीन बने नियमों के लिये जहां तक उनका सम्बन्ध तनखाहों, भत्तों, छुट्टी या पेनशनों से है, उस रियासत के रियासतपति की रजामन्दी दरकार होगी जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है.

(3) हाईकोर्ट के शासनी खर्च, जिनमें उस अदालत के अफसरों और नौकरों को या उनके बारे में दी जाने वाली सब तनखाहें, भत्ते और पेनशनें शामिल हैं, रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगे, और वह अदालत जो फीसों या दूसरी रकमों लेगी वे उस कोश का भाग होंगी.

#### 230—राजपंचायत कानून बनाकर—

(ए) किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को पहली पट्टी में दर्ज किसी ऐसी रियासत तक या किसी ऐसे क्षेत्र तक बढ़ा सकती है, या

(बी) किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को पहली पट्टी में दर्ज किसी ऐसी रियासत से या किसी ऐसे क्षेत्र से अलग कर सकती है,

जो वह रियासत नहीं है, या उस रियासत के अन्दर नहीं है, जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है.

231—जहाँ किसी हाईकोर्ट की अमलदारी किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में भी चलती है, जो उस रियासत से बाहर है जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है, वहाँ इस विधान की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि—

(ए) वह उस रियासत की कानून सभा को जिसमें उस

हाईकोर्टों की अमलदारी को बढ़ाना या कम करना

किसी रियासत को किसी ऐसी हाईकोर्ट की अमलदारी के सम्बन्ध में रियासतों की कानून सभाओं की कानून बनाने

को शक्तियों पर  
रुकावटें जिस  
हाईकोर्ट की  
अमलदारी उस  
रियासत के बाहर  
भी हो

हाईकोर्ट की खास जगह है उस अमलदारी को बढ़ाने,  
कम करने या खत्म करने की शक्ति देती है;

(बी) वह पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज  
किसी ऐसी रियासत की कानून सभा को जिसमें कोई  
ऐसा क्षेत्र है, उस अमलदारी को खत्म करने की शक्ति  
देती है; या

(सी) वह उस कानून सभा को जिसे ऐसे किसी क्षेत्र के  
बारे में उस मतलब के लिये कानून बनाने की शक्ति  
है, धारा (बी) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, उस  
क्षेत्र के सम्बन्ध की उस हाईकोर्ट की अमलदारी के  
बारे में ऐसे कानून बनाने से रोकती है, जिन्हें पास  
करने का उस कानून सभा को अधिकार होता अगर  
उस अदालत की खास जगह उसी क्षेत्र में होती।

अथ

232—जहां किसी हाईकोर्ट की अमलदारी पहली पट्टी में दर्ज  
एक से अधिक रियासतों के सम्बन्ध में, या किसी एक रियासत  
और एक ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में चलती है जो उस रियासत का  
भाग नहीं है, वहां—

(ए) इस खंड में जहां किसी हाईकोर्ट के जजों के  
सम्बन्ध में रियासतपति की चरचा की गई है, उससे  
मतलब उस रियासत के रियासतपति से लिया जायगा  
जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है;

(बी) मातहत अदालतों के लिये नियमों, रूपों और नक्शों  
पर रियासतपति की रजामन्दी की जहां चरचा की  
गई है, उससे मतलब उस रियासत के रियासतपति  
या राजप्रमुख की रजामन्दी से लिया जायगा जिसमें  
वह मातहत अदालत है, या अगर वह किसी ऐसे  
क्षेत्र में है जो पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी)  
में दर्ज किसी रियासत का भाग नहीं है, तो उससे मत-  
लब राजपति की रजामन्दी से लिया जायगा; और

(सी) रियासत के मूठकोश की जहां जहां चरचा की गई है

उससे मतलब उस रियासत के मूठकोश की चरचा से लिया जायगा जिसमें उस हाईकोर्ट की खास जगह है.

### खंड छै—मातहत अदालतें

233—(1) किसी रियासत में जिला जज होने वाले लोगों का जिला जजों का नियोजन, उनकी तैनाती और तरक्की उस रियासत का रियासतपति, उस रियासत के संबंध में अमलदारी रखने वाली हाईकोर्ट से सलाह करके करेगा.

(2) कोई आदमी जो पहले से यूनियन की या रियासत की नौकरी में नहीं है केवल तभी जिला जज नियोजे जाने का पात्र होगा जब वह कम से कम सात बरस तक वकील या लीडर रह चुका है और हाईकोर्ट ने उसके नियोजन की सिफारिश की है.

234—किसी रियासत की न्यायी नौकरी में जिला जजों को छोड़कर दूसरे लोगों का नियोजन उस रियासत का रियासतपति इस काम के लिये अपने बनाए हुए उन नियमों के अनुसार करेगा जो उसने रियासत सरकारी नौकरी कमीशन और उस रियासत के संबंध में अमलदारी रखने वाली हाईकोर्ट से सलाह करके बनाए हों.

235—जिला अदालतों और उनकी मातहत अदालतों पर दबान हाईकोर्ट को हासिल होगा, जिसमें किसी रियासत की न्यायी नौकरी में काम करने वाले और जिला जज से नीचे पद पर रहने वाले लोगों की तैनाती और तरक्की और उनकी छुट्टी मंजूर करना शामिल होगा, पर इस दफा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह किसी ऐसे आदमी का अपील करने का वह अधिकार छीन लेती है जो उसको उसकी नौकरी की शर्तों की क्रायदाबन्दी करनेवाले कानून के अधीन मिला हुआ हो, या यह कि वह हाईकोर्ट को यह अधिकार देती है कि वह उस कानून के अधीन बताई उस आदमी की नौकरी की शर्तों के अनुसार न चलकर उसके साथ किसी दूसरी तरह ब्योहार करे.

236—इस खंड में—

(ए) “जिला जज” शब्दों में नगर दीवानी अदालत का जज, अधिक जिला जज, संगी जिला जज, सहायक

जिला जजों का नियोजन

न्यायी नौकरी में जिला जजों को छोड़कर और लोगों की भरती

मातहत अदालतों पर दबान

अर्थ

ज़िला जज, खफ़ीफ़ा अदालत का प्रमुख जज, प्रमुख प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सहायक प्रमुख प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, अधिक सेशन जज और सहायक सेशन जज शामिल होंगे;

(बी) “न्यायी नौकरी” शब्दों के मानी हैं वह नौकरी जिसमें केवल वही लोग होंगे जो ज़िला जज की जगह और ज़िला जज की जगह से नीचे की दूसरी दीवानी न्यायी जगहों को भरने के लिये हैं.

इस खंड के बन्धानों का मजिस्ट्रेटों की किसी खास जमात या जमातों पर लागू होना

237—रियासतपति आम नोटिस निकाल कर यह निर्देश कर सकता है कि, उस नोटिस में बताए हुए अपवादों और अदल बदल के अधीन रहते हुए, इस खंड के ऊपर लिखे बन्धान और उनके अधीन बने नियम, उस तारीख से जो वह इस काम के लिये तय करे, उस रियासत में मजिस्ट्रेटों की किसी जमात या जमातों पर उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे उस रियासत की न्यायी नौकरी में नियोजित हुए लोगों के संबंध में लागू होते हैं.

## भाग सात

### पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतें

238—भाग छै के बन्धान पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज रियासतों के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे उस पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के संबंध में लागू होते हैं, पर नीचे लिखे अदल बदल और छूटों का ध्यान रखते हुए लागू होंगे, यानी :—

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों पर भाग छै के बन्धानों का लागू होना

(1) भाग छै में जहाँ कहीं “रियासतपति” शब्द आया है उसकी जगह, सिवाय जब वह दफा 232 की धारा (बी) में दूसरी बार आया है, “राजप्रमुख” शब्द रख दिया जायगा.

(2) दफा 152 में “भाग (ए)” इस शब्द और अक्षर की जगह “भाग (बी)” यह शब्द और अक्षर रखे जायंगे.

(3) दफा 155, 156 और 157 छोड़ दिये जायंगे.

(4) दफा 158 में—

(एक) धारा (1) में “नियोजा जाय” शब्दों की जगह “हो जाय” शब्द रख दिये जायंगे;

(दो) धारा (3) की जगह नीचे लिखी धारा रख दी जायगी, यानी :—

“(3) राजप्रमुख, जबतक कि रियासत की सरकार की खास जगह में उसका अपना रहने का मकान न हो, बिना किराया दिये सरकारी मकान को काम में लाने का हकदार होगा और वह उन भत्तों और निजनियमों का भी हकदार होगा जो राजपति आम या खास हुकुम देकर तय करदे.”;

(तीन) धारा (4) में “वेतन और” शब्द छोड़ दिये जायंगे.

(5) दफा 159 में “बड़े से बड़े जज के सामने जो मिल सके” शब्दों के बाद “या ऐसे दूसरे ढंग से जो राजपति इस काम के लिये तय करदे” शब्द जोड़ दिये जायंगे.

(6) दफा 164 में धारा (1) की शर्त की जगह नीचे लिखी शर्त रख दी जायगी, यानी :—

“शर्तें कि मध्यभारत की रियासत में एक वजीर ऐसा होगा जिसको कबीलों की भलाई का काम सौंपा जायगा और जिसको इसके अलावा पट्टी दर्ज जातियों और पिछड़ी जमातों की भलाई का काम या कोई और दूसरा काम भी सौंपा जा सकता है।”

(7) दफ्ता 168 में धारा (1) की जगह नीचे लिखी धारा रखी जायगी, यानी :—

“(1) हर रियासत की एक कानून सभा होगी जिसमें राजप्रमुख होगा, और जिस में—

(ए) मैसूर की रियासत में दो सदन होंगे;

(बी) दूसरी रियासतों में एक एक सदन होगा।”

(8) दफ्ता 186 में “जो दूसरी पट्टी में दर्ज है” शब्दों की जगह “जो राजप्रमुख तय कर दे” शब्द रख दिये जायंगे.

(9) दफ्ता 195 में “जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे के आम सदन (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के मेम्बरों के लिये लागू थीं” शब्दों की जगह “जो राजप्रमुख तय कर दे” शब्द रख दिये जायंगे.

(10) दफ्ता 202 की धारा (3) में—

(एक) उप-धारा (ए) की जगह नीचे लिखी उप-धारा रख दी जायगी, यानी :—

“(ए) राजप्रमुख के भत्ते और उसके पद संबंधी दूसरे खर्च जो राजपति आम या खास हुकुम देकर तय करदे;”

(दो) उपधारा (एक) की जगह नीचे लिखी उप धाराएं रखी जायंगी, यानी :—

“(एक) द्रावनकोर-कोचीन रियासत की सूरत में इक्यावन लाख रुपए की वह रकम, जो इस विधान के आरम्भ होने से पहले द्रावनकोर कोचीन की मिली हुई रियासत बनाने के लिये, द्रावनकोर और कोचीन की देसी रियासतों के शासकों ने जो मुआहिदा किया था उसके अधीन हर साल देव-स्वोम कोश को दी जायगी;

(जी) कोई दूसरा खर्च जिसे यह विधान या रियासत की कानून सभा कानून बनाकर ऐसा खर्च ठहरा दे.”



(11) दफ्ता 208 में धारा (2) की जगह नीचे लिखी धारा रख दी जायगी, यानी :—

“(2) जब तक धारा (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तबतक दस्तूर के वह नियम और वह क़ायमी हुकुम जो इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले उस रियासत की क़ानून सभा के बारे में लागू थे, या जहाँ रियासत की क़ानून सभा का कोई सदन नहीं था, वहाँ दस्तूर के वह नियम और वह क़ायमी हुकुम जो इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले उस सूबे के आमसदन (लेजिस्लेटिव असेम्बली) के बारे में लागू थे जिसे उस रियासत का राजप्रमुख इस काम के लिये तय करदे, उस रियासत की क़ानून सभा के संबंध में ऐसे अदल बदल और अनुकूलन के अधीन जो आम सदन का सभामुख या खास सदन का मसनदी, जैसी सूरत हो, उनमें करदे, असर रखेंगे”

(12) दफ्ता 214 की धारा (2) में “सूबे” शब्द की जगह “देसी रियासत” शब्द रख दिये जायंगे.

(13) दफ्ता 221 की जगह नीचे लिखी दफ्ता रखदी जायगी, यानी :—

“221—(1) हर हाईकोर्ट के जजों को वह तनखाहें दी जायंगी जो राजपति राजप्रमुख से सलाह करके तय कर दे.

जजों की तनखाहें वगैरा

(2) हर जज उन भत्तों का और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन अधिकारों का हक़दार होगा जो समय समय पर राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन तय किये जायं, और जब तक वह इस तरह तय नहीं किये जाते तब तक उन भत्तों और अधिकारों का हक़दार होगा जो राजपति राजप्रमुख से सलाह कर के तय करदे:

शर्तें कि किसी जज के भत्तों में या छुट्टी या पेनशन के बारे में उसके अधिकारों में उसके नियोजन के बाद इस तरह की कोई अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.”

## भाग आठ

### पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतें

पहली पट्टी के भाग  
(सी) की रियासतों  
का शासन

239—(1) इस भाग के और बन्धानों के अधीन रहते हुए पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज हर रियासत का शासन राजपति करेगा, और जिस हद तक वह ठीक समझे यह शासन वह एक चीफ कमिश्नर या नायब रियासतपति की मारफत करेगा जिसे वह खुद नियोजेगा या किसी पड़ोसी रियासत की सरकार के मारफत करेगा :

शर्तें कि राजपति किसी पड़ोसी रियासत की सरकार की मारफत उस समय तक यह काम नहीं करेगा जब तक कि—

(ए) उसने उस सरकार से सलाह न कर ली हो; और

(बी) जिस रियासत पर इस तरह शासन करना है वहाँ के लोगों के विचार राजपति ने ऐसे ढंग से मालूम न कर लिये हों जिसे वह सब से अधिक मुनासिब समझे.

(2) इस दफा में किसी रियासत की चरचा में उस रियासत के किसी भाग की चरचा भी शामिल है.

मुकामी क़ानून  
सभाओं या सलाह-  
कार मंडल या  
वज़ीर मंडल का  
बनाना या जारी  
रखना

240—(1) पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी ऐसी रियासत के लिये जिसका शासन चीफ कमिश्नर या नायब रियासतपति की मारफत होता हो, राजपंचायत क़ानून बना कर—

(ए) एक संस्था, चाहे नामज़द की हुई चाहे चुनी हुई, चाहे कुछ नामज़द की हुई और कुछ चुनी हुई, उस रियासत की क़ानून सभा का काम करने के लिये; या

(बी) सलाहकार मंडल या वज़ीर मंडल,  
या दोनों बना सकती है या जारी रख सकती है जिनकी बनावट, शक्तियाँ और काम हर सूरत में वह होंगे जो उस क़ानून में बता दिए गए हों.

(2) धारा (1) में जिस किसी क़ानून की चरचा की गई है उसको दफा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार

नहीं समझा जायगा, भले ही उसमें कोई ऐसा बन्धान हो जो विधान में सुधार करता है या सुधार करने का असर रखता है.

241—(1) राजपंचायत, कानून बनाकर, पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी रियासत के लिये एक हाईकोर्ट बना सकती है, या उस रियासत की किसी अदालत को इस विधान के सब मतलबों या उनमें के किसी मतलब के लिये हाईकोर्ट ठहरा सकती है.

पहली पट्टी के भाग (सी) की रियासतों के लिये हाईकोर्टें

(2) भाग छै के खंड पांच के बन्धान हर उस हाईकोर्ट के संबंध में जिसकी चरचा धारा (1) में की गई है उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वह उस हाईकोर्ट के संबंध में लागू होते हैं जिसकी चरचा दफा 214 में की गई है, पर ऐसी अदल बदल और ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए जिनका राजपंचायत कानून बनाकर बन्धान कर दे.

(3) इस विधान के बन्धानों और मुनासिब कानून सभा के किसी ऐसे कानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो उन शक्तियों की रू से बनाया गया हो जो इस विधान में या इसके अधीन उस कानून सभा को दी गई हों, जिस किसी हाईकोर्ट की अमलदारी पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी रियासत के या उसमें शामिल किसी क्षेत्र के संबंध में इस विधान के आरंभ से ठीक पहले चलती थी उस हाईकोर्ट की वह अमलदारी उस रियासत या उस क्षेत्र के संबंध में विधान के आरंभ के बाद भी चलती रहेगी.

(4) इस दफा की किसी भी बात से राजपंचायत की वह शक्ति कम नहीं होती जो उसे पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को उस पट्टी के भाग (सी) में दर्ज किसी रियासत तक या उस रियासत में शामिल किसी क्षेत्र तक बढ़ा देने की या उससे अलग कर देने की हासिल है.

242—(1) जब तक राजपंचायत कानून बना कर दूसरा बन्धान कुर्ग नहीं करती तब तक कुर्ग के खास सदन की बनावट, उसकी शक्तियाँ और उसके काम वही होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले थे.

कुर्ग में जो मालगुजारी जमा की जाय उसके बारे में

प्रबन्ध और कुर्ग के सम्बन्ध में खर्च बिना बदले जारी रखे जायेंगे जब तक कि राजपति इस काम के लिये हुक्म देकर कोई दूसरा बन्धान न करदे.

---

## भाग नौ

पहली पट्टी के भाग (डी) के भूभाग और वह दूसरे भूभाग जो उस पट्टी में दर्ज नहीं हैं

243—(1) पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज हर भूभाग का शासन और हर ऐसे दूसरे भूभाग का शासन जो भारत के भूभाग में शामिल है पर पहली पट्टी में दर्ज नहीं है, राजपति करेगा, और जिस हद तक वह ठीक समझेगा यह शासन एक चीफ कमिश्नर की मारफत या किसी और ऐसे अधिकारी की मारफत करेगा जिसे वह खुद नियोजेगा.

पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज भूभागों का और उन दूसरे भूभागों का शासन जो उस पट्टी में दर्ज नहीं हैं

(2) राजपति हर ऐसे भूभाग की शान्ति और वहां अच्छी हुकूमत के लिये क़ायदे बना सकता है, और जो क़ायदा इस तरह बनाया जायगा वह राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून को, या किसी ऐसे मौजूदा क़ानून को जो उस समय उस भूभाग पर लागू हो, रद्द कर सकता है या उसमें सुधार कर सकता है, और जब राजपति किसी ऐसे क़ायदे को जारी कर देगा तो उस क़ायदे का वही बल और असर होगा जो राजपंचायत के किसी ऐसे एक्ट का जो उस भूभाग पर लागू हो.

---

## भाग दस

### पट्टी-दर्ज क्षेत्र और कबायली क्षेत्र

पट्टी-दर्ज क्षेत्रों और कबायली क्षेत्रों का शासन. 244—(1) पांचवीं पट्टी के बन्धान, आसाम की रियासत को छोड़ कर, पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज हर दूसरी रियासत के पट्टी दर्ज क्षेत्रों और पट्टी-दर्ज कबीलों के शासन और उनके दबान के सम्बन्ध में लागू होंगे.

(2) छठी पट्टी के बन्धान आसाम की रियासत के कबायली क्षेत्रों के शासन के सम्बन्ध में लागू होंगे.

---

## भाग ग्यारह

### यूनियन और रियासतों के बीच सम्बन्ध

#### खंड एक—कानूनकारी सम्बन्ध

#### कानूनकारी शक्तियों का बटवारा

245—(1) इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत भारत के सारे भूभाग के लिये या उसके किसी भाग के लिये कानून बना सकती है, और हर रियासत की कानून सभा उस सारी रियासत या उसके किसी भाग के लिये कानून बना सकती है.

राजपंचायत के बनाए और रियासतों की कानून सभाओं के बनाए कानूनों का फैलाव

(2) राजपंचायत का बनाया हुआ कोई कानून इस बिना पर नादुरुस्त नहीं समझा जायगा कि उस पर अमल भूभाग-परे भी होगा.

246—(1) धारा (2) और (3) में किसी बात के रहते भी, अकेले राजपंचायत को ही यह शक्ति है कि वह सातवीं पट्टी की तालिका एक में ( जिसकी इस विधान में “यूनियन तालिका” कह कर चरचा की गई है ) गिनाए मामलों में से किसी के बारे में कानून बनाए.

राजपंचायत के बनाए और रियासतों की कानून सभाओं के बनाए कानूनों का विषय

(2) धारा (3) में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को, और धारा (1) के अधीन रहते हुए पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की कानून सभा को भी यह शक्ति है कि वह सातवीं पट्टी की तीसरी तालिका में ( जिसकी इस विधान में “संगचारी तालिका” कह कर चरचा की गई है ) गिनाए मामलों में से किसी के बारे में कानून बनाए.

(3) धारा (1) और (2) के अधीन रहते हुए, पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की कानून सभा को ही अकेले यह शक्ति है कि वह उस रियासत के लिये या उसके किसी भाग के लिये सातवीं पट्टी की तालिका दो में ( जिसकी इस विधान में “रियासत तालिका” कहकर चरचा की गई है ) गिनाए मामलों में से किसी के बारे में कानून बनाए.

(4) राजपंचायत को यह शक्ति है कि वह भारत के भूभाग के किसी ऐसे भाग के लिये जो पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में शामिल नहीं है, किसी मामले के बारे में कानून बनाए, भले ही वह मामला ऐसा मामला हो जो रियासत तालिका में गिनाया गया है.

कुछ अधिक अदालतों को क्रायम करने के लिये बन्धान करने की राजपंचायत को शक्ति

247—इस खंड में किसी बात के रहते भी, “यूनियन तालिका” में गिनाए किसी मामले के बारे में किसी मौजूदा कानून पर, या राजपंचायत के बनाए कानूनों पर, अधिक अच्छी तरह अमल कराने के लिये राजपंचायत कानून बनाकर कोई अधिक अदालतें क्रायम करने का बन्धान कर सकती है.

कानून बनाने की बची शक्तियाँ

248—(1) अकेले राजपंचायत को ही यह शक्ति है कि किसी ऐसे मामले के बारे में कोई कानून बनाए जो न संगचारी तालिका में गिनाया गया है न रियासत तालिका में.

(2) इस शक्ति में कोई ऐसा टैक्स लगाने के लिये कानून बनाने की शक्ति भी शामिल होगी जिसकी चरचा उन तालिकाओं में से किसी में नहीं की गई.

क्रौमी हित के लिये रियासत तालिका के किसी मामले के बारे में राजपंचायत को कानून बनाने की शक्ति

249—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, अगर रियासत सदन ने किसी ऐसे ठहराव से, जिसका उस समय मौजूद और वोट देने वाले मेम्बरों में से कम से कम दो तिहाई ने समर्थन किया हो, यह ठहरा दिया है कि क्रौमी हित में यह जरूरी है या समयोचित है कि “रियासत तालिका” में गिनाए किसी ऐसे मामले के बारे में जिसकी उस ठहराव में चरचा की गई है राजपंचायत कानून बनाए, तो राजपंचायत के लिये यह कानून-संगत होगा कि जब तक वह ठहराव अमल में रहे राजपंचायत भारत के सारे भूभाग या उसके किसी हिस्से के लिये उस मामले के बारे में कानून बनाए.

(2) धारा (1) के अधीन पास हुआ ठहराव उतने अरसे तक अमल में रहेगा जो एक साल से अधिक न हो और जो ठहराव में बता दिया गया हो:

शर्तें कि अगर, और जितनी बार, किसी ऐसे ठहराव को अमल



में रखने की रजामन्दी देने वाला कोई ठहराव धारा (1) में बताए ढंग से पास हो जाय, तो वह पहला ठहराव जिस तारीख से इस धारा के अधीन अमल में न रहता उतनी बार उससे एक बरस के और अधिक अरसे तक अमल में रहेगा।

(3) राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क्रानून का, जिसे बनाने का अधिकार राजपंचायत को न होता अगर धारा (1) के अधीन ठहराव पास न हुआ होता, उस ठहराव के अमल में न रहने से छै महीने का अरसा बीत जाने पर, उस अनधिकार की हद तक, असर न रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो इस अरसे के बीत जाने से पहले की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों।

250—(1) इस खंड में किसी बात के रहते भी, जब कभी अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो, तो राजपंचायत को शक्ति होगी कि वह रियासत तालिका में गिनाए मामलों में से किसी के बारे में भारत के सारे भूभाग या उसके किसी भाग के लिये क्रानून बनाए।

अचानकी का कोई ऐलान अमल में होने की सूरत में रियासत तालिका के किसी भी मामले के बारे में राजपंचायत को क्रानून बनाने की शक्ति

(2) राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क्रानून का, जिसे बनाने का अधिकार राजपंचायत को न होता अगर अचानकी का ऐलान जारी न हुआ होता, ऐलान के अमल में न रहने के बाद छै महीने का अरसा बीत जाने पर, उस अनधिकार की हद तक, असर न रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो इस अरसे के बीत जाने से पहले की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों।

251—दफा 249 और 250 की कोई बात किसी रियासत की क्रानून सभा की इस शक्ति पर कोई रुकावट नहीं लगा सकेगी कि वह कोई ऐसा क्रानून बनाए जिसे इस विधान के अधीन उसको बनाने की शक्ति है, पर अगर किसी रियासत की क्रानून सभा के बनाए किसी क्रानून का कोई बंधन राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क्रानून के किसी बंधन के खिलाफ पड़ता हो, जिसे बनाने की ऊपर बताई हुई दोनों दफाओं में से किसी के अधीन राजपंचायत को शक्ति है, तो राजपंचायत का बनाया क्रानून ही चलेगा, चाहे वह रियासत की क्रानून सभा के बनाए क्रानून से पहले बना हो और

दफा 249 और 250 के अधीन राजपंचायत के बनाए क्रानूनों का रियासतों की क्रानून सभाओं के बनाए क्रानून के साथ अनमेल

चाहे पीछे, और उस खिलाफ पड़ने की हद तक, पर तभी तक जब तक राजपंचायत के बनाए हुए कानून का असर जारी है, रियासत की कानून सभा का बनाया कानून अमल में नहीं रहेगा।

राजपंचायत को दो या अधिक रियासतों के लिये उनकी अनुमति से कानून बनाने की शक्ति और किसी दूसरी रियासत का ऐसे कानूनों को अपनाना

252—(1) अगर दो या अधिक रियासतों की कानून सभाओं को यह बात चाहनी मालूम हो कि राजपंचायत कानून बनाकर उन रियासतों में किसी ऐसे मामले की क्रायदाबन्दी करदे जिस मामले के बारे में उन रियासतों के लिये कानून बनाने की राजपंचायत को शक्ति नहीं है, सिवाय उस सूरत में जिसका बन्धान दफ्ता 249 और 250 में किया गया है, और इस मतलब के ठहराव उन रियासतों की कानून सभाओं के सब सदनों में पास हो जाते हैं, तो राजपंचायत के लिये यह कानून-संगत होगा कि वह इस तरह उस मामले की क्रायदाबन्दी करने के लिये एकट पास कर दे, और कोई एकट जो इस तरह पास हो गया हो उन रियासतों में लागू होगा और किसी ऐसी दूसरी रियासत में भी लागू होगा जिस रियासत ने अपनी कानून सभा के सदन में, या जहां दो सदन हैं वहां उस रियासत की कानून सभा के हर सदन में, इस काम के लिये ठहराव पास करके उस एकट को बाद में अपना लिया हो।

(2) राजपंचायत के इस तरह पास किये हुए किसी एकट में, उसी तरह पास हुए या उसी तरह अपनाए हुए राजपंचायत के ही किसी एकट से, सुधार किया जा सकता है या उसे रद्द किया जा सकता है, पर जहां तक किसी ऐसी रियासत का सम्बन्ध है जिसमें वह एकट लागू होता है उस रियासत की कानून सभा के किसी एकट से न उसमें सुधार किया जा सकेगा न उसे रद्द किया जा सकेगा।

अन्तर-क्रौमी सम-  
झौतों पर अमल  
कराने के लिये  
कानून बनाना

253—इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को शक्ति है कि वह किसी दूसरे देश या देशों के साथ किसी संधिनामे, समझौते या माने हुए रिवाज पर या किसी अन्तर-क्रौमी कानफरेंस, सभा या दूसरी संस्था के किसी फैसले पर अमल कराने के लिये भारत के सारे भूभाग या उसके किसी भाग के लिये कोई कानून बनाए।

254—(1) अगर किसी रियासत की क्रान्ति सभा के बनाए किसी क्रान्ति का कोई बन्धान राजपंचायत के बनाए किसी ऐसे क्रान्ति के किसी बन्धान के खिलाफ पड़ता है जिसे बनाने का राजपंचायत को अधिकार है, या संगचारी तालिका में गिनाए मामलों में से किसी की बाबत किसी मौजूदा क्रान्ति के किसी बन्धान के खिलाफ पड़ता है, तो धारा (2) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत का बनाया क्रान्ति ही, चाहे वह उस रियासत की क्रान्ति सभा के बनाए क्रान्ति से पहले पास हुआ हो या बाद में, या वह मौजूदा क्रान्ति ही, जैसी सूरत हो, चलेगा, और उस रियासत की क्रान्ति सभा का बनाया क्रान्ति, खिलाफ पड़ने की हद तक, रह होगा।

(2) जहां संगचारी तालिका में गिनाए किसी मामले के बारे में पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क्रान्ति सभा के बनाए किसी क्रान्ति में कोई ऐसा बन्धान है जो पहले से बने हुए राजपंचायत के किसी क्रान्ति के बन्धानों के या उस मामले के बारे में किसी मौजूदा क्रान्ति के बन्धानों के खिलाफ पड़ता है, तो उस रियासत में उस रियासत की क्रान्ति सभा का इस तरह बनाया हुआ क्रान्ति ही चलेगा, अगर उसे राजपति के सोच विचार के लिये रखा गया हो और राजपति ने उस पर अपनी मंजूरी दे दी हो :

शर्तें कि इस धारा की कोई बात राजपंचायत को किसी समय भी, उसी मामले के बारे में कोई क्रान्ति बनाने से नहीं रोकेगी, इसमें कोई ऐसा क्रान्ति भी शामिल होगा जो उस रियासत की क्रान्ति सभा के इस तरह बनाए क्रान्ति में कुछ जोड़े, उसमें सुधार करे, उसका रूप बदल दे या उसे रह कर दे.

255—राजपंचायत का या पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क्रान्ति सभा का कोई एक्ट, और ऐसे किसी एक्ट का कोई बन्धान, केवल इसी कारन नादुरुस्त नहीं होगा कि कोई ऐसी सिफारिश या पहले से मंजूरी जो इस विधान के अनुसार दरकार थी उस एक्ट को नहीं मिली थी, अगर—

(ए) जहाँ रियासतपति की सिफारिश दरकार थी, वहाँ

राजपंचायत के बनाए क्रान्ति और रियासतों की क्रान्ति सभाओं के बनाए क्रान्ति में अनमेल

सिफारिशों के और पहले से मंजूरी के के दरकार होने को सिर्फ दस्तूरी मामला समझा जायगा

रियासतपति ने या राजपति ने,  
 (बी) जहाँ राजप्रमुख की सिफारिश दरकार थी, वहाँ  
 राजप्रमुख ने या राजपति ने,  
 (सी) जहाँ राजपति की सिफारिश या पहले से मंजूरी  
 दरकार थी वहाँ राजपति ने,  
 उस ऐक्ट पर अपनी राजामन्दी दे दी हो.

खंड दो

### शासनी संबंध

आम

रियासतों की और  
 यूनियन की जिम्मे-  
 दारी

256—हर रियासत की काजकारी शक्ति से इस तरह काम लिया जायगा जिससे राजपंचायत के बनाए हुए कानूनों और उस रियासत में लागू मौजूदा कानूनों पर अमल होने का भरोसा रहे, और यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी भी रियासत को इस तरह के निर्देश देना शामिल होगा जो भारत सरकार को इस मतलब के लिये जरूरी मालूम हों.

कुछ सूतों में  
 यूनियन का रिया-  
 सतों पर दबान

257—(1) हर रियासत की काजकारी शक्ति से इस तरह काम लिया जायगा जिससे यूनियन की काजकारी शक्ति से काम लेने में रुकावट न पड़े, न उसे नुकसान पहुँचे, और यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को इस तरह के निर्देश देना भी शामिल होगा जो भारत सरकार को इस मतलब के लिये जरूरी मालूम हों.

(2) यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को इस तरह के निर्देश देना भी शामिल होगा जो आवा-जार्ड के उन साधनों को बनाने और बनाए रखने के सम्बन्ध में दिये गए हों जिन्हें उस निर्देश में क़ौमी या फ़ौजी महत्व का ठहराया गया हो :

शर्तें कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह राजपंचायत की इस शक्ति पर कि राजपंचायत किन्हीं थल मार्गों या जल मार्गों को क़ौमी थल मार्ग या क़ौमी जल मार्ग ठहरा दे कोई रुकावट लगाती है, या जिन थल मार्गों या जल मार्गों के

सम्बन्ध में ऐसा ठहरा दिया गया है उनके बारे में यूनियन की शक्ति पर कोई रुकावट लगाती है, या यूनियन की इस शक्ति पर कोई रुकावट लगाती है कि यूनियन आवा-जाई के साधनों को समन्दरी, जमीनी और हवाई फौजों की इमारतों के संबंध में अपने कामों का एक भाग समझ कर बनाए और बनाए रखे.

(3) यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को ऐसे निर्देश देना भी शामिल होगा कि रियासत के अन्दर रेल मार्गों की रक्षा के लिये क्या क्या तरकीबें की जायं.

(4) जहाँ धारा (2) के अधीन आवा-जाई के किन्हीं साधनों को बनाने या बनाए रखने के संबंध में, या धारा (3) के अधीन किसी रेल मार्ग की रक्षा करने के लिये जो तरकीबें की जानेवाली हैं उनके संबंध में किसी रियासत को दिये हुए किसी निर्देश पर अमल करने में उससे ज्यादा खर्च हो गया हो, जो ऐसा निर्देश न दिये जाने की सूरत में रियासत के अपने मामूली फरज पूरे करने में होता, तो भारत सरकार उस रियासत को वह रकम देगी जिस पर दोनों राजी हो जायं, या अगर राजी न हो सकें तो वह रकम देगी जो भारत के सर जज का नियोजा हुआ कोई पंच रियासत के उस अधिक खर्च के बारे में तय कर दे.

258—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपति, किसी रियासत की सरकार की रजामन्दी से, उस सरकार को या उसके अफसरों को, कुछ शर्तों के साथ या बिना शर्त, किसी ऐसे मामले के संबंध में काम सौंप सकता है जो मामला यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में शामिल है.

कुछ सूरतों में  
रियासतों को  
शक्तियां बगैरा देने  
की यूनियन को  
शक्ति

(2) राजपंचायत का बनाया हुआ कोई कानून जो किसी रियासत में लागू होता हो, इस बात के बावजूद कि उसका संबंध किसी ऐसे मामले से है जिसके बारे में उस रियासत की कानून सभा को कानून बनाने की शक्ति नहीं है, उस रियासत को या उसके अफसरों और अधिकारियों को कोई शक्तियां दे सकता है, और उन पर कोई फरज लगा सकता है, या किसी दूसरे को उन्हें शक्तियां देने और उन पर फरज लगाने का अधिकार दे सकता है.

(3) जहां इस दफ्ता की रू से किसी रियासत को या उसके अफसरों या उसके अधिकारियों को कोई शक्तियां दी गई हों और उन पर कोई फरज लगाए गए हों, वहां उन शक्तियों और फरजों से काम लेने के संबंध में रियासत के शासन पर रियासत का जो कुछ अधिक खर्च होगा उसके बारे में भारत सरकार उस रियासत को वह रकम देगी जिस पर दोनों राजी हो जायं या अगर राजी न हो सकें तो वह रकम देगी जो भारत के सरजज का नियोजन हुआ कोई पंच तय कर दे.

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों में हथियारबन्द फौजें

259—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में अगर इस विधान के आरंभ से ठीक पहले कोई हथियार बन्द फौजें थीं तो विधान के आरंभ के बाद, जब तक राजपंचायत कानून बनाकर कुछ और बन्धान न करे तब तक, वह रियासत उन फौजों को रख सकेगी, पर उन आम या खास हुकुमों के अधीन जो राजपति समय समय पर इस काम के लिये जारी करे.

(2) धारा (1) में जिन हथियारबन्द फौजों की चरचा की गई है वह सब यूनियन की हथियारबन्द फौजों का भाग होंगी.

भारत के बाहर भूभागों के संबंध में यूनियन की अमलदारी

260—भारत सरकार किसी ऐसे भूभाग की सरकार से समझौता करके जो भारत के भूभाग का हिस्सा नहीं है कोई ऐसे काजकारी, कानूनकारी या न्यायकारी काम अपने हाथ में ले सकती है जो उस भूभाग की सरकार को मिले हुए हैं, पर हर ऐसा समझौता उस कानून का ध्यान रखते हुए और उस के अधीन होगा जो विदेशी अमलदारी से काम लेने के संबंध में उस समय अमल में हो.

सरकारी काम, लेखे और अदालती कारवाइयां

261—(1) भारत के सारे भूभाग में यूनियन के और हर रियासत के सरकारी कामों, लेखाओं और अदालती कारवाइयों पर पूरा भरोसा किया जायगा और उनकी पूरी साख होगी.

(2) धारा (1) में जिन कामों, लेखाओं और कारवाइयों की चरचा की गई है, उनको जिस ढंग से और जिन शर्तों के अधीन साबित किया जायगा और उनका असर तय किया जायगा वह देखी होंगी जिनका बन्धान राजपंचायत के बनाए कानून में किया गया हो.

(3) भारत के भूभाग के किसी हिस्से में दीवानी अदालतों ने जो आखिरी फैसले सुनाए हों या हुकुम दिये हों उन पर कानून के अनुसार उस भूभाग में कहीं भी अमल कराया जा सकेगा.

### पानी के संबंध में झगड़े

262—(1) राजपंचायत कानून बनाकर किसी ऐसे झगड़े या शिकायत के अदालती-फैसले के लिये बन्धान कर सकती है जिसका संबंध किसी अन्तर-रियासती नदी या नदी की घाटी के पानी के इस्तेमाल, बटवारे या दवान से हो.

अन्तर - रियासती नदियों या उनकी घाटियों के पानी के संबंध में झगड़ों का अदालती फैसला

(2) इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत कानून बनाकर यह बन्धान कर सकती है कि किसी ऐसे झगड़े या शिकायत के बारे में जिसकी चरचा धारा (1) में की गई है, न आला अदालत की अमलदारी चलेगी न किसी दूसरी अदालत की.

### रियासतों के बीच तालमेल

263—अगर किसी समय राजपति को यह मालूम हो कि एक ऐसा मंडल कायम करने से जनता का हित होगा जिसको यह फरज सौंपा जाय कि वह—

अन्तर-रियासती मंडल के बारे में बन्धान

- (ए) रियासतों के बीच जो झगड़े खड़े हो गए हों उनकी पूछताछ करे और उन पर सलाह दे;
- (बी) उन मामलों की जांच करे और उन पर बहस करे जिनमें कुछ या सब रियासतों का, या यूनियन और एक या अधिक रियासतों का मिला जुला हित हो; या
- (सी) ऐसे किसी भी मामले पर सिफारिशें करे, और खास कर उस मामले के बारे में नीति और अमल का अधिक अच्छा तालमेल पैदा करने के लिये सिफारिशें करे,

तो राजपति के लिये यह कानून-संगत होगा कि वह हुकुम देकर एक ऐसा मंडल कायम करदे, और उस मंडल को जिस तरह के फरज पूरे करने हैं उन्हें और मंडल के संगठन और दस्तूर को तय कर दे,

## भाग बारह

### माल, जायदाद, ठेके और नालिशें

#### खंड एक—माल

##### आम

अर्थ

264—इस भाग में जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो—

(ए) “माल कमीशन” के मानी हैं वह माल कमीशन जो दफा 280 के अधीन बनाया गया हो;

(बी) “रियासत” में वह रियासत शामिल नहीं है जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज हो;

(सी) पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों की चरचा में हर उस भूभाग की चरचा भी शामिल होगी जो पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज हो, और किसी दूसरे ऐसे भूभाग की चरचा भी शामिल होगी जो भारत के भूभाग में शामिल है पर उस पट्टी में दर्ज नहीं है.

कानून के अधिकार  
सिवा टैक्स नहीं  
लगाए जायेंगे

265—कानून के अधिकार बिना न कोई टैक्स लगाया जायगा और न जमा किया जायगा.

भारत के और रिया-  
सतों के मूठकोश  
और सरकारी  
हिसाब

266—(1) दफा 267 के बन्धानों के अधीन रहते हुए, और कुछ टैक्सों और महसूलों की असल वसूली के कुल या कुछ भाग को रियासतों के नाम करने के बारे में इस खंड के बन्धानों के अधीन रहते हुए, कुल मालगुजारी जो भारत सरकार को मिले, कुल उधारियां जो भारत सरकार सरकारी हुंडियां जारी करके ले, उधारियां या राहरीत पेशगियां, और वह सब रकमों जो उस सरकार को उधारियों की अदायगी में मिलें, इन सबका मिलकर एक मूठकोश बनेगा जो “भारत का मूठकोश” कहलायगा, और कुल मालगुजारी जो किसी रियासत की सरकार को मिले, कुल उधारियां जो वह सरकार सरकारी हुंडियां जारी करके ले, उधारियां या राहरीत पेशगियां, और वह सब रकमों जो उस सरकार को उधारियों की अदायगी में मिलें



इन सबका मिलकर एक मूठकोश बनेगा जो “उस रियासत का मूठकोश” कहलायगा.

(2) और सब सरकारी रकमों जो भारत सरकार या किसी रियासत की सरकार को मिलें, या जो उनके नाम से मिलें वह भारत के सरकारी हिसाब में या उस रियासत के सरकारी हिसाब में, जैसी सूरत हो, जमा की जायंगी.

(3) भारत के मूठकोश में से या किसी रियासत के मूठकोश में से कोई रकम खर्च की मदों में नहीं ढाली जायंगी सिवाय कानून के अनुसार, और उन मतलबों के लिये, और उस ढंग से जिसका बन्धान इस विधान में किया गया है.

267—(1) राजपंचायत कानून बनाकर पेश-नगदी जैसा एक जोगाजोग कोश कायम कर सकती है जो “भारत का जोगाजोग कोश” कहलायगा, जिसमें समय समय पर वह रकमों जमा की जायंगी जो उस कानून में तय कर दी जायं, और यह कोश राजपति के हाथ में रख दिया जायगा जिससे कि वह तब तक अनसूमे खर्च चलाने के लिये उस कोश में से रुपया पेशगी दे सके जब तक राजपंचायत दफा 115 या 116 के अधीन कानून बनाकर उस खर्च का अधिकार न दे दे.

(2) रियासत की कानून सभा कानून बनाकर पेश-नगदी जैसा एक जोगाजोग कोश कायम कर सकती है जो उस “रियासत का जोगाजोग कोश” कहलायगा, जिसमें समय समय पर वह रकमों जमा की जायंगी जो उस कानून में तय कर दी जायं, और यह कोश उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के हाथ में रख दिया जायगा जिससे कि वह तब तक अनसूमे खर्च चलाने के लिये उस कोश में से रुपया पेशगी दे सके जब तक रियासत की कानून सभा दफा 205 या 206 के अधीन कानून बनाकर उस खर्च का अधिकार न दे दे.

यूनियन और रियासतों के बीच मालगुजारी का बटवारा

268—(1) वह स्टाम्प के महसूल और द्वाइयों और सिंगार के सामान पर वह निकासनी महसूल जो यूनियन तालिका में दिये हुए वह महसूल जिन्हें यूनियन लगाने पर

जिनमें रियासतें  
जमा करें और  
खर्च की मदों में  
डालें

हैं भारत सरकार लगायगी, पर—

- (ए) उस सूरत में जहां यह महसूल किसी ऐसी रियासत में लगने हैं जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज है, उन्हें भारत सरकार जमा करेगी, और
- (बी) दूसरी सूरतों में जिन जिन रियासतों में वह महसूल लगने हैं वह वह रियासतें जमा करेंगी.

(2) किसी माली साल में जो वसूली किसी ऐसे महसूल से हो जो किसी रियासत के अन्दर लगना है, वह भारत के मूठकोश का भाग नहीं होगी, बल्कि उसी रियासत के नाम कर दी जायगी.

वह टैक्स जो  
यूनियन लगाए  
और जमा करे पर  
जो रियासतों के  
नाम कर दिये  
जायें

269—(1) नीचे लिखे हुए महसूल और टैक्स भारत सरकार लगायगी और जमा करेगी, पर धारा (2) में बताए ढंग पर उन्हें रियासतों के नाम कर दिया जायगा, यानी:—

- (ए) खेतीबाड़ी की ज़मीन को छोड़कर दूसरी जायदाद की बिरासत के बारे में महसूल;
- (बी) खेती बाड़ी की ज़मीन को छोड़कर दूसरी जायदाद के बारे में मिलकियत महसूल;
- (सी) रेल मार्ग, समन्दर या हवा से जाने वाले माल या सवारियों पर हदवारी टैक्स;
- (डी) रेल मार्ग की सवारियों के किरायों और माल के भाड़े पर टैक्स;
- (ई) शेयर बाज़ारों और पेश बाज़ारों के सौदों पर स्टाम्प महसूल को छोड़कर दूसरे टैक्स;
- (एफ) अखबारों की बिकरी या खरीद पर और उनमें निकलने वाले जाहिरात पर टैक्स.

(2) किसी माली साल में ऐसे किसी महसूल या टैक्स की असल वसूली, सिवाय जहाँ तक कि वह वसूली ऐसी वसूली हो जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के हिसाब में वसूल हुई हो, भारत के मूठकोश का भाग नहीं होगी, बल्कि उन रियासतों के नाम कर दी जायगी जिनके अन्दर वह महसूल या टैक्स उस साल

में लगाना हो, और उन रियासतों के बीच बटवारे के उन सिद्धांतों के अनुसार बांटी जायगी जिनको राजपंचावत कानून बनाकर रूप दे दे.

270—(1) खेती बाढ़ी की आमदनी को छोड़कर दूसरी आमदनी पर टैक्स भारत सरकार लगायगी और वही जमा करेगी, और उन्हें यूनियन और रियासतों के बीच, उस ढंग से बांटा जायगा जिसका बन्धान धारा (2) में किया गया है.

वह टैक्स जो यूनियन लगाए और जमा करे और जो यूनियन और रियासतों के बीच बंटा जाय

(2) किसी माली साल में ऐसे किसी टैक्स की असल वसूली का वह फ्री सैकड़ा जो बता दिया जाय, सिवाय जिस हद तक कि वह वसूली ऐसी वसूली हो जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के हिसाब में वसूल हुई हो, या उन टैक्सों के हिसाब में वसूल हुई हो जो यूनियन बेतनों के बारे में दिये जाने हों, भारत के मूठकोश का भाग नहीं होगा, बल्कि उन रियासतों के नाम कर दिया जायगा जिनके अन्दर उस साल वह टैक्स लगाना है, और उसको उन रियासतों के बीच उस ढंग से और उस समय से बांटा जायगा जो बता दिया जाय.

(3) धारा (2) के मतलबों के लिये हर माली साल में आमदनी पर टैक्सों से जो असल वसूली हो उस में से, उस भाग को छोड़ कर जो यूनियन बेतनों के बारे में दिये जाने वाले टैक्सों की असल वसूली है, बाक़ी का वह फ्री सैकड़ा जो बता दिया जाय, वह वसूली समझा जायगा जो पहली पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के हिसाब में वसूल हुई है.

(4) इस दफ़ा में—

(ए) “आमदनी पर टैक्सों” में एकतनी टैक्स शामिल नहीं है;

(बी) “बता दिया जाय” के मानी हैं—

(एक) जब तक कोई माल कमीशन न बनाया जाय, तबतक जो कुछ राजपति हुकुम देकर बता दे, और

(दो) माल कमीशन बनाए जाने और माल कमीशन की सिफ़ारिशों पर बिचार करने के बाद राजपति अपने हुकुम से जो बता दे;

(सी) “यूनियन वेतनों” में भारत के मूठकोश में से दिये जाने वाले वह सब वेतन और पेनशन शामिल हैं जिनके ऊपर आमदनी टैक्स लिया जा सकता है.

कुछ महसूलों और टैक्सों पर यूनियन के मतलबों के लिये अधिक-टैक्स

271—दफा 269 और 270 में किसी बात के रहते भी, राज-पंचायत किसी समय भी उन दफाओं में जिन महसूलों या टैक्सों की चरचा की गई है उनमें से किसी को यूनियन के मतलबों के लिये अधिक-टैक्स लगाकर बढ़ा सकती है, और ऐसे हर अधिक-टैक्स की कुल वसूली भारत के मूठकोश का भाग होगी.

वह टैक्स जो यूनियन लगाती है और जमा करती है और जो यूनियन और रियासतों के बीच बांटे जा सकते हैं

272—यूनियन तालिका में बताए हुए दवाइयों और सिंगार के सामान पर निकासनी महसूलों को छोड़कर, यूनियन के दूसरे निकासनी महसूल भारत सरकार लगायगी और जमा करेगी, लेकिन अगर राजपंचायत कानून बनाकर बन्धान कर दे तो भारत के मूठकोश में से उन रियासतों को जो उस महसूल को लगाने वाले कानून के फैलाव में आ जाती हैं, उस महसूल की असल वसूली के कुल या कुछ भाग के बराबर रकमों दी जायंगी, और वह रकमों उन रियासतों में बटवारे के उन सिद्धान्तों के अनुसार बांटी जायंगी जिनको उस कानून में रूप दे दिया जाय.

पटसन और पटसन से बनी चीजों पर निकासी-महसूल के बदले में देनगियाँ

273—(1) आसाम, बिहार, उड़ीसा और पच्छिम बंगाल की रियासतों के नाम, पटसन या पटसन की बनी चीजों पर निकासी-महसूल की हर बरस की असल वसूली का कोई हिस्सा कर देने के बदले में उन रियासतों की मालगुजारी की सहायती देनगियों के रूप में उन्हें वह रकमों हर बरस दी जायंगी जो बता दी जाय, और वह रकमों भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी.

(2) जो रकमों इस तरह बता दी जाय वह तब तक भारत के मूठकोश के खाते में पड़ती रहेंगी जब तक पटसन या पटसन की बनी चीजों पर भारत सरकार कोई निकासी महसूल लगाती रहे या जब तक इस विधान के आरंभ होने के बाद दस बरस न बीत जाय, जो भी इनमें से पहले हो.

(3) इस दफा में “बतादी जाय” शब्दों के वही मानी हैं जो दफा 270 में.

274—(1) कोई ऐसा बिल या सुधार, जो कोई ऐसा टैक्स या महसूल लगाता है या उसमें अदल बदल करता है जिसमें रियासतों का हित है, या जो “खेती-बाड़ी की आमदनी” शब्दों के मानी में, जैसी उसकी परिभाषा भारत आमदनी टैक्स संबंधी कानूनों के मतलबों के लिये की गई है, अदल बदल करता है, या जिसका असर उन सिद्धान्तों पर पड़ता है जिनके अनुसार इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में से किसी के अधीन रियासतों में रकमों बांटी जाती हैं या बांटी जा सकती हैं, या जो यूनियन के मतलबों के लिये ऐसा कोई अधिक-टैक्स लगाता है जो इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में बताया गया है, राजपति की सिफारिश के सिवाय राजपंचायत के किसी सदन में न रखा जायगा न पेश किया जायगा.

जिन टैक्सों में रियासतों का हित हो उन पर असर डालने वाले बिलों पर राजपति को पहले से सिफारिश दरकार

(2) इस दफ्ता में “टैक्स या महसूल जिसमें रियासतों का हित है” शब्दों के मानी हैं—

(ए) कोई टैक्स या महसूल जिसकी असल वसूली का कुल या कुछ भाग किसी रियासत के नाम कर दिया गया हो; या

(बी) कोई टैक्स या महसूल जिसकी असल वसूली का हवाला देकर उस समय भारत के मूठकोश में से रकमों किसी रियासत को दी जानी हों.

275—(1) हर साल वह रकमों जिनका राजपंचायत कानून बनाकर बंधान करे और जो उन रियासतों को उनकी मालगुजारी की सहायती देनगियों के रूप में दी जायंगी, जिनके संबंध में राजपंचायत यह तय करे कि उनको मदद की जरूरत है, भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी, और अलग अलग रियासतों के लिये अलग अलग रकमों तय की जा सकती हैं :

यूनियन की तरफ से कुछ रियासतों को देनगियां

शर्त कि किसी रियासत को भारत के मूठकोश में से, उस रियासत की सरकारी मालगुजारी की सहायती देनगियों के रूप में, वह पूँजी और वह फिराती रकमों दी जायँगी जो इस बात के लिये जरूरी हों कि वह रियासत विकास की उन योजनाओं का खर्च उठा सके जो उस रियासत ने भारत सरकार की रजामन्दी से उस रिया-

सत के पट्टीदर्ज कबीलों की भलाई के कामों को बढ़ाने के लिये या उस रियासत के पट्टीदर्ज छेत्रों के शासन-तल को रियासत के बाक़ी छेत्रों के शासन-तल तक ऊँचा ले जाने के लिये हाथ में ली हों :

और शर्तें कि आसाम को भारत के मूठकोश में से रियासत की मालगुजारी की सहायती देनगियों के रूप में, वह पूँजी की रक़म और वह फिराली रक़म दी जायगी जो—

(ए) छटी पट्टी के बीसवें पैरे के साथ दिये हुए नक़शे के भाग (ए) में दर्ज क़बाइली छेत्रों के शासन के सम्बन्ध में, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले दो साल तक आमदनी से खर्च जितना ब्यादा रहा हो उसकी औसत के बराबर हों; और

(बी) वह रियासत, भारत सरकार की रज़ामन्दी से, ऊपर कहे छेत्रों के शासन तल को उस रियासत के बाक़ी छेत्रों के शासन-तल तक ऊँचा उठाने के लिये विकास की जो योजनाएँ हाथ में ले, उनके खर्च के बराबर हों.

(2) जब तक राजपंचायत धारा (1) के अधीन बन्धान नहीं करती तब तक उस धारा के अधीन जो शक्तियाँ राजपंचायत को दी गई हैं उन शक्तियों से राजपति हुकुम जारी करके काम ले सकेगा, और उस धारा के अधीन राजपति जो हुकुम जारी करे उसका असर राजपंचायत के इस तरह बनाए बन्धान के अधीन होगा :

शर्तें कि माल कमीशन के बनाए जाने के बाद उस माल कमीशन की सिफ़ारिशों पर विचार किये बिना राजपति इस धारा के अधीन कोई हुकुम जारी नहीं करेगा.

पेशों, ब्योपारों,  
रोज़गारों और  
कामगारियों पर  
टैक्स

276—(1) दफ़ा 246 में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत की क़ानून सभा का कोई क़ानून जिसका संबंध उस रियासत के लाभ के लिये या उसको किसी नगरायत, ज़िला बोर्ड, मुक़ामी बोर्ड, या किसी दूसरे मुक़ामी अधिकारी के लाभ के लिये, पेशों, ब्योपारों, रोज़गारों या कामगारियों के बारे में लगाए जाने वाले किन्हीं टैक्सों से है, इस बिना पर नादुरुस्त नहीं

होगा कि उसका संबंध आमदनी पर लगने वाले टैक्स से है.

(2) वह कुल रकम जो किसी एक आदमी के बारे में, पेशों, ब्योपारों, रोजगारों और कामगारियों पर टैक्सों के रूप में, उस रियासत को या उसकी किसी एक नगरायत, जिला बोर्ड, मुकामी बोर्ड, या किसी एक दूसरे मुकामी अधिकारी को दी जायगी, दो सौ पचास रुपए सालाना से अधिक न होगी :

शर्तें कि अगर इस विधान के आरंभ से ठीक पहले के माली साल में, किसी रियासत में या ऐसी किसी नगरायत, बोर्ड या अधिकारी संस्था में पेशों, ब्योपारों, रोजगारों या कामगारियों पर कोई ऐसा टैक्स जारी था, जिसकी दर, या जिसकी ज्यादा से ज्यादा दर दो सौ पचास रुपए सालाना से अधिक थी, तो वह टैक्स आगे भी तब तक लगाया जा सकेगा जब तक कि राजपंचायत कानून बना कर इसके खिलाफ बंधान न करदे, और राजपंचायत इस तरह का जो कानून बनाए वह या तो एक आम कानून हो सकता है या किन्हीं खास बताई हुई रियासतों, नगरायतों, बोर्डों या अधिकारियों के सम्बन्ध में हो सकता है.

(3) पेशों, ब्योपारों, रोजगारों और कामगारियों पर टैक्स के बारे में ऊपर बताए हुए कानून बनाने की किसी रियासत की कानून सभा को जो शक्ति है, उसका यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह राजपंचायत की कानून बनाने की उस शक्ति को किसी तरह सिमियाती है जो राजपंचायत को पेशों, ब्योपारों, रोजगारों और कामगारियों से होने वाली या मिलने वाली आमदनी पर टैक्स लगाने के बारे में है.

277—जो कोई टैक्स, महसूल, मुकामी टैक्स, या फीस, इस बचावे विधान के आरंभ से ठीक पहले, किसी रियासत की सरकार या कोई नगरायत या कोई दूसरा मुकामी अधिकारी या संस्था उस रियासत, नगरायत, जिले या दूसरे मुकामी क्षेत्र के मतलबों के लिये कानून के अनुसार लगाती थी, वह इस बात के रहते भी कि उन टैक्सों, महसूलों, मुकामी टैक्सों या फीसों का यूनियन तालिका में जिक्र आया है, आगे भी लगाया जा सकेगा, और उन्हीं मतलबों के

लिये काम में लाया जा सकेगा, जब तक कि राजपंचायत कानून बना कर इसके खिलाफ कोई बन्धान न करे.

कुछ माली मामलों के संबंध में पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों से समझौता.

278—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, भारत सरकार, धारा (2) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की सरकार के साथ नीचे लिखी बातों के बारे में समझौता कर सकती है:—

(ए) किसी ऐसे टैक्स या महसूल का लगाना या जमा करना जो भारत सरकार उस रियासत में लगा सकती हो, और उसकी वसूली को इस खंड के बन्धानों के अनुसार न चलते हुए किसी और तरह बांटना;

(बी) भारत सरकार का ऐसी रियासत को उस रियासत की उस मालगुजारी में घाटे के कारन कोई माली मदद मंजूर करना जो मालगुजारी उस रियासत को किसी ऐसे टैक्स या महसूल से मिलती रही हो जिसे इस विधान के अधीन भारत सरकार लगा सकती है, या जो उसे किसी और जरिये से मिलती रही हो;

(सी) किसी ऐसी रकम का जो भारत सरकार दफा 291 की धारा (1) के अधीन दे, वह हिस्सा जो वह रियासत देगी,

और जब इस तरह कोई समझौता हो जाय तो इस खंड के बन्धानों का असर उस रियासत के संबंध में उस समझौते की शर्तों के अधीन होगा.

(2) धारा (1) के अधीन जो समझौता किया जाय वह इस विधान के आरंभ से अधिक से अधिक दस बरस के अरसे तक अमल में रहेगा :

शर्तें कि राजपति विधान के आरंभ से पांच बरस बीत जाने के बाद किसी समय भी ऐसे किसी समझौते को खतम कर सकता है या उसमें अदल बदल कर सकता है, अगर माल कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह ऐसा करना जरूरी समझे.



279—(1) इस खंड के ऊपर लिखे बन्धानों में किसी टैक्स या महसूल के सम्बन्ध में “असल वसूली” के मानी हैं उस टैक्स या महसूल की वसूली में से उसे जमा करने का खर्च निकाल कर जो बचे वह, और उन बंधानों के मतलबों के लिये किसी टैक्स या महसूल की, या किसी टैक्स या महसूल के किसी भाग की असल वसूली जो किसी क्षेत्र से वसूल हो या जो किसी क्षेत्र के हिसाब में वसूल हो, उसका हिसाब भारत का सरपड़तालिया और दाबअफसर लगायगा और उस हिसाब की सनद करेगा और उसकी यह सनद आखिरी होगी.

“असल वसूली” का हिसाब लगाना, वगैरा

(2) ऊपर जो कहा गया है उसके और इस खंड के किसी और साफ साफ बन्धान के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सूरत में जिसमें किसी महसूल या टैक्स की वसूली रकम इस भाग के अधीन किसी रियासत के नाम की गई है या की जा सकती है, राजपंचायत का बनाया हुआ कोई कानून या राजपति का कोई हुकुम इस बात का बन्धान कर सकता है कि उस वसूली का हिसाब किस ढंग से किया जायगा, और उसकी कोई रकम किस समय से कब और किस ढंग से अदा की जायगी, और एक माली साल और दूसरे माली साल में बैठ बिठाव किस तरह होगा, ऐसा कानून या हुकुम किन्हीं और प्रसंगी या सहायक मामलों का भी बन्धान कर सकता है.

280—(1) इस विधान के आरंभ से दो साल के अन्दर माल कमीशन अन्दर, और उसके बाद हर पांचवे साल के बीत जाने पर, या उससे पहले किसी और समय जब राजपति जरूरी समझे, राजपति हुकुम जारी करके एक माल कमीशन बनायगा जिसमें एक मसनदी और चार दूसरे मेम्बर होंगे जिनको राजपति नियोजेगा.

(2) राजपंचायत कानून बनाकर तय कर सकती है कि कमीशन के मेम्बर नियोजे जाने के लिये क्या क्या जोगताएँ दरकार होंगी और मेम्बर किस ढंग पर छांटे जायंगे.

(3) कमीशन का फरज होगा कि वह राजपति से इन बातों के बारे में सिफारिशें करे —

(ए) टैक्सों की जो असल वसूली इस खंड के अधीन

यूनियन और रियासतों के बीच बांटी जानी है या बांटी जा सकती है उसका बंटवारा और उस वसूली में से रियासतों के अलग अलग हिस्सों का तय किया जाना;

(बी) वह सिद्धान्त जिनके अधीन भारत के मूठकोश में से रियासतों की मालगुजारी की सहायती देनगियां की जायेंगी;

(सी) भारत सरकार ने दफा 278 की धारा (1) के अधीन या दफा 306 के अधीन, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की सरकार के साथ जो समझौता किया हो उसकी शर्तों का जारी रखना या बदलना; और

(डी) कोई दूसरा मामला जो राजपति ने माल को पक्का रखने के हित में कमीशन को राय के लिये भेजा हो.

(4) कमीशन अपना दस्तूर तय करेगा, और उसको अपने कामों के करने में वह शक्तियां होंगी जो राजपंचायत उसे कानून बनाकर सौंपे.

माल कमीशन की सिफारिशें

281— इस विधान के बन्धानों के अधीन माल कमीशन जो भी सिफारिश करेगा उसे राजपति, एक ऐसी यादी के साथ जिसमें यह समझाया गया होगा कि उस सिफारिश पर क्या कारवाई की गई है, राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

### फुटकर माली बन्धान

खर्चा जो यूनियन या कोई रियासत अपनी मालगुजारी में से कर सकती है

मूठकोश, जोगा-जोग कोश और सरकारी हिसाबों में जमा हुई रकमों की रखवाली वगैरा

282— यूनियन या कोई रियासत जनता के किसी मतलब के लिये कोई देनगी कर सकती है, भले ही वह मतलब ऐसा न हो जिसके बारे में राजपंचायत या उस रियासत की कानून सभा, जैसी सूरत हो, कानून बना सकती है.

283—(1) भारत के मूठकोश और भारत के जोगाजोग कोश की रखवाली, उन कोशों में रकमों जमा करना, उनमें से रकमों निकासना, उन सरकारी रकमों की रखवाली जो भारत सरकार को मिली हों या जो उसके नाम से ली गई हों और जो इन कोशों में जमा न की गई हों उन रकमों का भारत के सरकारी हिसाब में

जमा करना और उस हिसाब में से रकमों निकालना, और दूसरे सब मामले जिन का ऊपर कहे मामलों से संबंध हो या जो उनके सहायक हों, इन सबकी क्रायदाबन्दी राजपंचायत कानून बनाकर करेगी, और जब तक इस काम के लिये इस तरह बन्धान न किया जाय तब तक उनकी क्रायदाबन्दी राजपति के बनाए नियमों से होगी.

(2) किसी रियासत के मूठकोश और उसके जोगाजोग कोश की रखवाली, उन कोशों में रकमों जमा करना, उनमें से रकमों निकालना, उन सरकारी रकमों की रखवाली जो रियासत की सरकार को मिली हों या उसके नाम से ली गई हों और जो इन कोशों में जमा न की गई हों, उन रकमों का रियासत के सरकारी हिसाब में जमा करना और उस हिसाब में से रकमों निकालना, और दूसरे सब मामले जिनका ऊपर कहे मामलों से संबंध हो या जो उनके सहायक हों, इन सब की क्रायदाबन्दी रियासत की कानून सभा कानून बना कर करेगी, और जब तक इस काम के लिये इस तरह बन्धान न किया जाय तब तक उनकी क्रायदाबन्दी उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के बनाए नियमों से होगी.

284—वह सब रकमों जो—

(ए) यूनियन के या किसी रियासत के मामलों के संबंध में काम पर लगे हुए किसी अफसर को उसकी उस हैसियत से मिलें या जो उसके पास जमा की जायं, सिवाय उस मालगुजारी या सरकारी रकमों के जो भारत सरकार या उस रियासत की सरकार, जैसी सूरत हो, ले या उसे मिलें, या

सायलों की जमा की हुई रकमों और उन दूसरी रकमों की रखवाली जो सरकारी नौकरों और अदालतों को मिलें

(बी) भारत के भूभाग के अन्दर किसी अदालत को किसी मुकदमें, मामले, हिसाब या किन्हीं आदमियों के नाम से मिलें या जो उसके पास जमा की जायं,

भारत के सरकारी हिसाब में या उस रियासत के सरकारी हिसाब में, जैसी सूरत हो, जमा की जायंगी.

माल की खरीद या बिकरी पर कोई टैक्स जो इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले किसी रियासत की सरकार कानून के अनुसार लगा रही थी मार्च सन् 1951 के इकतीसवें दिन तक लगता रहेगा, भले ही ऐसे टैक्स का लगाना इस धारा के बन्धानों के खिलाफ हो.

(3) किसी रियासत की कानून सभा का बनाया हुआ कोई कानून जो किसी ऐसे माल की बिकरी या खरीद पर कोई टैक्स लगाता है या किसी को लगाने का अधिकार देता है जिस माल को राजपंचायत ने कानून बनाकर समाज के जीवन के लिये जरूरी ठहरा दिया हो, कोई असर नहीं रखेगा जब तक कि उसे राजपति के विचार के लिये न रखा गया हो और उसको राजपति की मंजूरी न मिल गई हो.

287—सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपंचायत बिजली के टैक्सों से बरी होना कानून बनाकर कोई और बंधान कर दे, किसी रियासत का कोई कानून उस बिजली की ( चाहे उसे सरकार पैदा करे या कोई दूसरे आदमी ) खपत या बिकरी पर न कोई टैक्स लगायगा न किसी को लगाने का अधिकार देगा, जिसकी—

(ए) भारत सरकार खपत करे या जो भारत सरकार के खपाने के लिये उस सरकार को बेची जाय; या

(बी) किसी रेल मार्ग के बनाने, बनाए रखने या चलाने में भारत सरकार खपत करे, या उस रेल मार्ग को चलाने वाली कोई रेल मार्ग कम्पनी खपत करे, या जो भारत सरकार को या ऐसी किसी रेल मार्ग कम्पनी को किसी रेल मार्ग के बनाने, बनाए रखने या चलाने में खपत के लिये बेची गई हो,

और हर ऐसे कानून में जो बिजली की बिकरी पर कोई टैक्स लगाता हो या लगाने का अधिकार देता हो, इस बात का पक्का प्रबन्ध रहेगा कि भारत सरकार के खपाने के लिये भारत सरकार को जो बिजली बेची जाय, या जो बिजली ऊपर बताई हुई किसी रेल मार्ग कम्पनी को, किसी रेल मार्ग के बनाने, बनाए रखने या चलाने में खपत करने के लिये बेची जाय, उसकी कीमत, काफ़ी बिजली खपत

करने वाले दूसरे गाइकों से जो क्रीमत ली जाती है, उससे टैक्स की रकम घटा कर ली जायगी.

कुछ सूरतों में पानी या बिजली के बारे में रियासतों के टैक्सों से बरी होना

288—(1) सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपति हुकुम दे कर कोई और बन्धान कर दे, किसी रियासत का कोई कानून, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में हो, किसी ऐसे पानी या बिजली के बारे में कोई टैक्स नहीं लगायगा न लगाने का किसी को अधिकार देगा जिसे कोई ऐसी अधिकारी संस्था जमा करे, पैदा करे, खपाए, बांटे या बेचे, जो किसी मौजूदा कानून से या राजपंचायत के बनाए किसी कानून से किसी अन्तर-रियासती नदी या नदी-घाटी का विकास या कायदाबन्दी करने के लिये कायम की गई हो.

समझाव—इस धारा में “किसी रियासत का कोई कानून जो अमल में हो” शब्दों में किसी रियासत का वह कानून भी शामिल होगा जो इस विधान के आरंभ होने से पहले पास किया गया हो या बनाया गया हो और जो इससे पहले रद्द न कर दिया गया हो, भले ही वह कुल कानून या इसके कुछ भाग उस समय बिल्कुल ही या कुछ खास क्षेत्रों के अन्दर अमल में न हों.

(2) किसी रियासत की कानून सभा कानून बनाकर ऐसा कोई टैक्स जो धारा (1) में बताया गया है लगा सकती है या लगाने का अधिकार दे सकती है, पर ऐसे किसी कानून का कोई असर नहीं होगा जब तक कि उसको राजपति के विचार के लिये रखे जाने के बाद राजपति की मंजूरी न मिल गई हो; और अगर कोई ऐसा कानून ऐसे टैक्स की दरों और दूसरी प्रसंगी बातों को, ऐसे नियमों और हुकमों से तय कराने का बन्धान करता है जिन्हें उस कानून के अधीन कोई अधिकारी बनाए या दे तो वह कानून ऐसे किसी नियम या हुकुम के बनाए जाने या दिये जाने के लिये राजपति की पहले से अनुमति लिये जाने का बन्धान करेगा.

रियासत की जाय-  
दाद और आमदनी  
का यूनियन के  
टैक्सों से बरी  
होना

289—(1) रियासत की जायदाद और आमदनी यूनियन के टैक्सों से बरी होगी.

(2) धारा (1) की कोई बात यूनियन को उस हद तक,

अगर कोई ऐसी हद हो तो, किसी टैक्स के लगाने या लगाने का अधिकार देने से नहीं रोकेगी, जिस हद तक, राजपंचायत, किसी तरह के किसी व्योपार या कारबार की बाबत, जिसे रियासत की सरकार चलाती हो या जो रियासत की सरकार के नाम से चलाया जाता हो, या उससे संबंध रखने वाले किन्हीं कामों की बाबत, या किसी ऐसी जायदाद की बाबत जिसे ऐसे व्योपार या कारबार के मतलबों के लिये इस्तेमाल किया जाता हो, या जिस पर उन मतलबों के लिये कब्जा किया गया हो, या उसके संबंध में होने वाली या मिलने वाली किसी आमदनी की बाबत, कानून बनाकर कोई बन्धान कर दे.

(3) धारा (2) की कोई बात किसी ऐसे व्योपार या कारबार पर या किसी ऐसी तरह के व्योपारों या कारबार पर लागू नहीं होगी जिनकी बाबत राजपंचायत कानून बनाकर यह ठहरा दे कि वह सरकार के मामूली कामों के साथ कुदरती संबंध रखते हैं.

290—जहाँ इस विधान के बन्धानों के अधीन, किसी अदालत या कमीशन का खर्च, या किसी ऐसे आदमी को या उसके बारे में दी जाने वाली पेनशन, जो इस विधान के आरंभ होने से पहले सम्राट के अधीन हिन्द में नौकरी कर चुका है, या जो विधान के आरंभ होने के बाद यूनियन या किसी रियासत के मामलों के संबंध में नौकरी कर चुका है, भारत के मूठकोश या किसी रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ती हैं, वहाँ—

कुछ खर्चों और पेनशनों के बारे में बैठ-बिठाव

(ए) अगर वह भारत के मूठकोश के खाते में पड़ता है, और वह अदालत या कमीशन, किसी रियासत की अलग जरूरतों में से किसी को पूरा करे, या उस आदमी ने बिलकुल या कुछ हद तक किसी रियासत के मामलों के सम्बन्ध में नौकरी की है; या

(बी) अगर वह किसी रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ता है, और वह अदालत या कमीशन यूनियन की या किसी दूसरी रियासत की अलग जरूरतों को पूरा करे, या उस आदमी ने बिलकुल या कुछ हद तक

यूनियन या किसी दूसरी रियासत के मामलों के सम्बन्ध में नौकरी की है, तो

उन खर्चों या उस पेनशन का वह हिस्सा जिस पर सब राजी हों या अगर कोई राजी न हो तो जो भारत के सरजज का नियोजन हुआ कोई पंच तय कर दे, उस रियासत के मूठकोश के खाते में डाला जायगा और उस कोश में से दिया जायगा या, जैसी सूरत हो, भारत के मूठकोश के खाते में, या उस दूसरी रियासत के मूठकोश के खाते में, डाला जायगा और उसमें से दिया जायगा.

शासकों की निजी  
थलियों की रकमें

291—(1) जहाँ किसी ऐसे मुआहदे या समझौते के अधीन जो इस विधान के आरंभ से पहले किसी देसी रियासत के शासक ने किया हो, टैक्स से बरी किन्हीं रकमों का उस रियासत के शासक को उसकी निजी थैली के रूप में दिया जाना हिन्द डोमिनियन की सरकार ने गारंटी कर दिया हो या उसका भरोसा दिलाया हो, वहाँ—

(ए) वह रकमें भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी और उसमें से दी जायंगी; और

(बी) किसी शासक को जो रकमें इस तरह दी जायंगी उन पर कोई आमदनी टैक्स नहीं लिया जायगा.

(2) जहाँ ऊपर कही किसी देसी रियासत के भूभाग पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत के अन्दर आ जाते हैं, वहाँ धारा (1) के अधीन भारत सरकार जो रकमें देगी उनका वह हिस्सा, अगर कोई हो, और उस अरसे के लिये जो दफा 278 की धारा (1) के अधीन इस बारे में किसी समझौते का ध्यान रखते हुए राजपति हुकुम देकर तय करदे, उस रियासत के मूठकोश के खाते में पड़ेगा और उसमें से दिया जायगा.

### खंड दो—उधार लेना

भारत सरकार का  
उधार लेना

292—यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में, भारत के मूठकोश की जमानत पर, उन सीमाओं के अन्दर अगर कोई ऐसी सीमाएं हों तो जो राजपंजायत समय समय पर कानून बनाकर तय करदे, उधार लेना, और उन्हीं सीमाओं के अन्दर अगर कोई

ऐसी सीमाएं हों तो जो इस तरह तय कर दी गई हों, गारंटिया देना शामिल है।

293—(1) इस दफ्ता के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी रियासत की काजकारी शक्ति के फैलाव में, भारत के भूभाग के अन्दर, रियासत के मूठकोश की ज़मानत पर, उन सीमाओं के अन्दर अगर कोई ऐसी सीमाएं हों तो जो उस रियासत की क़ानून सभा समय समय पर क़ानून बनाकर तय कर दे, उधार लेना, और उन्हीं सीमाओं के अन्दर अगर कोई ऐसी सीमाएं हों तो जो इस तरह तय कर दी जायं, गारंटियां देना शामिल होगा।

रियासतों का उधार लेना

(2) भारत सरकार, उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो राजपंजायत के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन बता दी जायं, किसी रियासत को उधारियां दे सकता है, या किसी रियासत ने जो उधारियां ली हों उनके बारे में, दफ्ता 292 के अधीन तय की हुई सीमाओं के बाहर न जाते हुए, गारंटियां दे सकती है, और जो रकमों इस तरह उधारियां देने के लिये दरकार होंगी वह भारत के मूठकोश के खाते में पड़ेंगी।

(3) कोई रियासत भारत सरकार की अनुमति बिना कोई उधारी नहीं ले सकेगी, जब तक किसी ऐसी उधारी का कोई हिस्सा अदा करना बाक़ी है जो भारत सरकार ने या इससे पहले की सरकार ने उस रियासत को दी हो, या जिसके बारे में भारत सरकार ने या इससे पहले की सरकार ने कोई गारंटी दी हो।

(4) धारा (3) के अधीन अनुमति उन शर्तों का ध्यान रखते हुए ही दी जा सकती है, अगर ऐसी कोई शर्तें हों तो, जिन्हें भारत सरकार लगाना ठीक समझे।

**खंड तीन—जायदाद, ठेके, अधिकार, देनदारियाँ,**

**ज़िम्मेदारियाँ और नालिशें**

294—इस विधान के आरंभ होने के समय से—

(ए) सब जायदाद और देनदारियाँ जो विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्दू डोमिनियन की सरकार के मतलबों के लिये सम्राट को हासिल थीं, और वह सब जाय-

कुछ शर्तों में जायदाद, देनदारियाँ, अधिकारों, देनदारियाँ और ज़िम्मेदारियों का विरसा



दाद और लेनदारियां जो विधान के आरंभ से ठीक पहले हर गवरनरी सूबे की सरकार के मतलबों के लिये सम्राट को हासिल थीं, अब अलग अलग यूनियन को और जवाबी रियासत को हासिल होंगी, और

(बी) हिन्द डोमिनियन सरकार के और हर गवरनरी सूबे की सरकार के सब अधिकार, देनदारियां और ज़िम्मेदारियां, चाहे वह किसी ठेके के कारन पैदा हुई हों या दूसरी तरह पैदा हुई हों, अब अलग अलग भारत सरकार और हर जवाबी रियासत सरकार के अधिकार, देनदारियां और ज़िम्मेदारियां होंगी,

पर उस बैठविठाव के अधीन रहते हुए जो इस विधान के आरंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन के, या पच्छिमी बंगाल और पूरबी बंगाल और पच्छिमी पंजाब और पूरबी पंजाब के सूबों के, बनने के कारन किया गया हो या किया जाने वाला हो.

दूसरी सूतों में  
जायदाद, लेन  
दारियों, अधिका-  
रों, देनदारियों  
और ज़िम्मेदारियों  
का बिरसा

295—(1) इस विधान के आरंभ होने के समय से—

(ए) वह सब जायदाद और लेनदारियां जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत को हासिल थीं अब यूनियन को हासिल होंगी अगर वह मतलब, जिनके लिये वह जायदाद और लेनदारियां विधान के आरंभ से ठीक पहले रखी गई थीं, विधान के आरंभके बाद यूनियन तालिका में गिनाए मामलों में से किसी के संबंध में यूनियन के मतलब हो जायंगे, और

(बी) वह सब अधिकार, देनदारियां और ज़िम्मेदारियां, जो पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत की सरकार की थीं, चाहे वह किसी ठेके से पैदा हुई हों चाहे किसी दूसरी तरह पैदा हुई हों, भारत सरकार के अधिकार, देनदारियां और ज़िम्मेदारियां हो जायंगी, अगर वह मतलब,

जिन मतलबों के लिये विधान आरंभ होने से पहले वह अधिकार हासिल किये गए थे या वह देनदारियाँ या जिम्मेदारियाँ ली गई थीं, विधान के आरंभ के बाद, यूनियन तालिका में गिनाए मामलों में से किसी के संबंध में, भारत सरकार के मतलब हो जायेंगे,

पर ऐसे किसी समझौते का ध्यान रखते हुए जो इस काम के लिये भारत सरकार ने उस रियासत की सरकार के साथ किया हो.

(2) ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज हर रियासत की सरकार, इस विधान के आरंभ होने के समय से, धारा (1) में जिनकी चरचा की गई है उन्हें छोड़कर और सब जायदादों और लेनदारियों और सब अधिकारों, देनदारियों और जिम्मेदारियों के संबंध में, चाहे वह किसी ठेके से पैदा हुई हों या दूसरी तरह पैदा हुई हों, अपनी जवाबी देसीरियासत की वारिस होगी.

296—आगे जो कुछ बन्धान किया गया है उसके अधीन रहते हुए, भारत के भूभाग में जो कोई जायदाद, अगर यह विधान अमल में न आया होता तो, सरकारी ज़ब्ती, या हक़दार का हक़ खतम हो जाने, या कोई हक़दार मालिक न होने से लावारसी होने के कारन सम्राट को, या जैसी सूरत हो, किसी देसी रियासत के शासक को मिल गई होती, वह जायदाद अगर किसी रियासत में है, तो उस रियासत को हासिल हो जायगी और हर दूसरी सूरत में यूनियन को हासिल हो जायगी :

शर्त कि जो कोई जायदाद, उस तारीख को जिस दिन वह इस तरह सम्राट को या किसी देसी रियासत के शासक को मिल जाती, भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के कब्जे या दबान में थी, वह जायदाद, अगर जिन मतलबों के लिये उस समय उस का इस्तेमाल होता था या जिन मतलबों के लिये उस पर कब्जा था, वह मतलब यूनियन के मतलब थे तो यूनियन को या अगर वह मतलब किसी रियासत के मतलब थे तो उस रियासत को, हासिल हो जायगी.

सरकारी ज़ब्ती, या हक़ खतम हो जाने, या वारिस न रहने के कारन मिलने वाली जायदाद

समझाव : इस दफा में “शासक” और “देशी रियासत” शब्दों के वही मानी हैं जो दफा 363 में हैं.

भूभागी जल में  
जो क्रीमती चीजें  
हों वह यूनियन को  
हासिल होंगी

297—भारत के भूभागी जल की सीमा के अन्दर समन्दर के नीचे की सारी धरती, खनिज और दूसरी क्रीमती चीजें यूनियन को हासिल होंगी और यूनियन के मतलबों के लिये उसके कब्जे में रहेंगी.

जायदाद हासिल  
करने की शक्ति

298—(1) किसी ऐसे क़ानून का ध्यान रखते हुए जिसे मुनासिब क़ानून सभा ने बनाया हो, यूनियन की और हर रियासत की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी ऐसी जायदाद की देनगी करना, उसे बेच देना, किसी को दे डालना, या रहन रखना शामिल होगा जिस जायदाद पर यूनियन के या, जैसी सूरत हो, उस रियासत के मतलबों के लिये कब्जा हो, और उस शक्ति के फैलाव में उन अपने अपने मतलबों के लिये जायदाद खरीदना या हासिल करना भी शामिल होगा, और ठेके करना भी शामिल होगा.

(2) यूनियन के या किसी रियासत के मतलबों के लिये जो जायदाद हासिल की जायगी वह सब यूनियन को या उस रियासत को, जैसी सूरत हो, हासिल होगी.

ठेके

299—(1) यूनियन की या किसी रियासत की काजकारी शक्ति से काम लेते हुए जो ठेके किये जाँय वह सब राजपति के किये हुए या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के किये हुए, जैसी सूरत हो, कहे जायंगे, और उसी शक्ति से काम लेते हुए इस तरह के जो ठेके किये जायँ, और जायदाद के बारे में जो भरोसे दिलाए जायँ उन सब को राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख की तरफ से वह लोग उस ढंग पर करेंगे या देंगे जिन्हें और जिस ढंग के लिये राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, निर्देश दे या अधिकार दे.

(2) इस विधान के मतलबों के लिये या भारत सरकार से संबंध रखने वाले किसी ऐसे क़ानून के मतलबों के लिये जो अब तक अमल में हो, राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख किसी ठेके के बारे में जो वह करे या किसी भरोसे के बारे में जो वह

दिलाए, निजी तौर पर देनदार नहीं होगा, और न कोई आदमी जिसमें उनमें से किसी की तरफ से ऐसा ठेका किया हो या भरोसा दिलाया हो उसके बारे में निजी तौर पर देनदार होगा।

300—(1) भारत सरकार भारत की यूनियन के नाम से नालिश कर सकती है या उस पर नालिश की जा सकती है, और किसी रियासत की सरकार उस रियासत के नाम से नालिश कर सकती है या उस पर नालिश की जा सकती है, और राजपंचायत के किसी ऐसे एक्ट या उस रियासत की कानून सभा के किसी ऐसे एक्ट के बन्धानों के अधीन रहते हुए जो इस विधान में दी हुई शक्तियों की रू से बनाया गया हो, दोनों अपने अपने मामलों के सम्बन्ध में वन्हीं सूरतों में नालिश कर सकती हैं या उन पर नालिश की जा सकती है, जिन सूरतों में अगर यह विधान न बना होता तो हिन्द डोमीनियन या जवाबी सूबे या जवाबी देसी रियासतें नालिश कर सकती थीं या उन पर नालिशें की जा सकती थीं।

नालिशें और  
कारवाइयाँ

(2) अगर विधान के आरंभ होने के समय—

(ए) कोई ऐसी कानूनी कारवाइयाँ चल रही हों जिनमें एक फरीक हिन्द डोमीनियन है तो उन कारवाइयों में हिन्द डोमीनियन के नाम की जगह भारत की यूनियन का नाम समझा जायगा; और

(बी) कोई ऐसी कानूनी कारवाइयाँ चल रही हों जिनमें कोई सूबा या कोई देसी रियासत एक फरीक है, तो उन कारवाइयों में उस सूबे के या उस देसी रियासत के नाम की जगह उस सूबे की या उस देसी रियासत की जवाबी रियासत का नाम समझा जायगा।

## भाग तेरह

भारत के भूभाग के अन्दर व्यापार, •

### तिजारत और अन्तर-व्योहार

व्यापार, तिजारत  
और अन्तर-व्योहार  
की आज्ञादी

व्यापार, तिजारत  
और अन्तर-व्योहार  
पर रुकावटें लगाने  
की राजपंचायत  
को शक्ति

व्यापार और तिजा-  
रत के बारे में  
यूनियन और रिया-  
सतों की कानून-  
कारी शक्तियों पर  
रुकावटें

301—इस भाग के दूसरे बन्धानों के अधीन रहते हुए, भारत के तमाम भूभाग में व्यापार, तिजारत और अन्तर-व्योहार खुला होगा.

302—राजपंचायत कानून बनाकर एक रियासत और दूसरी रियासत के बीच या भारत के भूभाग के किसी हिस्से के अन्दर व्यापार, तिजारत और अन्तर-व्योहार की आज्ञादी पर ऐसी रुकावटें लगा सकती है जो जनता के हित में दरकार हों.

303—(1) दफ्ता 302 में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को या किसी रियासत की कानून सभा को, सातवीं पट्टी की तालिकाओं में से किसी में व्यापार और तिजारत संबंधी किसी अन्तरी की रू से, कोई ऐसा कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक रियासत को दूसरी पर कोई तरजीह देता हो, या तरजीह देने का अधिकार देता हो, या एक रियासत और दूसरी रियासत के बीच कोई भेदभाव करता हो या करने का अधिकार देता हो.

(2) धारा (1) की कोई बात राजपंचायत को कोई ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेंगी जो किसी तरह की तरजीह देता हो या देने का अधिकार देता हो, या कोई भेदभाव करता हो या करने का अधिकार देता हो, अगर ऐसे कानून में यह ऐलान कर दिया गया है कि भारत के भूभाग के किसी हिस्से में माल की कमी से पैदा हुई हालत को संभालने के लिये ऐसा करना जरूरी है.

रियासतों के बीच  
व्यापार, तिजारत  
और अन्तर-व्योहार  
पर रुकावटें

304—दफ्ता 301 या दफ्ता 303 में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत की कानून सभा कानून बनाकर—

(ए) दूसरी रियासतों से आप्र माल पर कोई ऐसा टैक्स लगा सकती है जो उस रियासत में बने या पैदा हुए उसी तरह के माल पर लगता हो, पर इस तरह कि ऐसे आप्र

माल और इस तरह बने या पैदा हुए माल के बीच कोई भेदभाव न किया जाय; और

(बी) उस रियासत के साथ या उसके अन्दर, ब्योपार, तिजारत या अन्तर-ब्योहार की आजादी पर ऐसी उचित रुकावटें लगा सकती हैं जो जनता के हित के लिये दरकार हों:

शर्तें कि धारा (बी) के मतलबों के लिये राजपति की पहले से मंजूरी लिये बिना किसी रियासत की कानून सभा में न कोई बिल रखा जायगा न कोई सुधार पेश किया जायगा.

305—दफ़ा 301 और 303 की किसी बात का किसी मौजूदा कानून के बन्धानों पर कोई असर नहीं होगा सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि राजपति हुकुम जारी करके कोई दूसरा बन्धान कर दे.

दफ़ा 301 और 303 का मौजूदा कानूनों पर असर

306—इस भाग के ऊपर-लिखे बन्धानों में या इस विधान के किन्हीं दूसरे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत, जो इस विधान के आरम्भ से पहले दूसरी रियासतों से उस रियासत में आने वाले माल पर या उस रियासत से दूसरी रियासतों में जाने वाले माल पर कोई टैक्स या महसूल लगाती थी, अगर इस काम के लिये भारत सरकार और उस रियासत की सरकार के बीच कोई समझौता हो गया हो तो उस समझौते की शर्तों के अधीन रहते हुए, और उस अरसे के लिये जो उस समझौते में बताया गया हो पर जो इस विधान के आरंभ से लेकर दस साल से अधिक नहीं होगा, उस टैक्स या महसूल को लगाना और जमा करना जारी रख सकती है :

पहली पट्टी के भाग (बी) की कुछ रियासतों को ब्योपार और तिजारत पर रुकावटें लगाने की शक्ति

शर्तें कि राजपति विधान के आरंभ से पांच साल बीत जाने पर किसी समय भी ऐसे किसी समझौते को खतम कर सकता है या उसमें अदल बदल कर सकता है, अगर दफ़ा 280 के अधीन बने माल कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद वह ऐसा करना जरूरी समझे.

दफ्ता 301 से  
304 तक के मत-  
लबों पर अमल  
कराने के लिये  
अधिकारी का  
नियोजन

307—राजपंचायत कानून बनाकर किसी ऐसे अधिकारी का नियोजन कर सकती है जिसे वह दफ्ता 301, 302, 303 और 304 के मतलबों पर अमल कराने के लिये मुनासिब समझे, और इस तरह नियोजे हुए अधिकारी को वह शक्तियाँ और फरज सौंप सकती है जिन्हें वह जरूरी समझे.

---

## भाग चौदह

### यूनियन और रियासतों के अधीन नौकरियाँ

खंड एक—नौकरियाँ

308—अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तो इस भाग में “रियासत” शब्द के मानी हैं पहली पट्टी के भाग (प) या भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत.

अर्थ

309—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, यूनियन के या किसी रियासत के मामलों से सम्बन्ध रखने वाली सरकारी नौकरियों और जगहों पर जो लोग नियोजे जायेंगे उनकी भरती की और उनकी नौकरी की शर्तों की, मुनासिब क़ानून सभा के एक्टों से क़ायदाबन्दी की जा सकती है :

यूनियन की या किसी रियासत की नौकरी करने वाले लोगों की भरती और नौकरी की शर्तें

शर्तें कि यूनियन के मामलों से संबंध रखने वाली नौकरियों और जगहों की सूची में राजपति या कोई ऐसा आदमी जिसे राजपति निर्देश दे, और किसी रियासत के मामलों से संबंध रखने वाली नौकरियों और जगहों के संबंध में उस रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख या कोई ऐसा आदमी जिसे रियासतपति या राजप्रमुख निर्देश दे, तब तक के लिये इस बात का अधिकारी होगा कि वह ऐसी नौकरियों और जगहों पर नियोजे जाने वाले आदमियों की भरती और उनकी नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी करने के लिये नियम बनाए, जब तक कि इस काम के लिये इस दफ़ा के अधीन किसी मुनासिब क़ानून सभा के किसी एक्ट में या उसके अधीन बन्धान नहीं किया जाता, और इस तरह बनाए हुए किन्हीं नियमों का असर ऐसे एक्ट के बन्धानों के अधीन होगा.

310—(1) सिवाय जब कि इस विधान में साफ़ साफ़ कुछ और बन्धान किया गया हो, हर वह आदमी, जो यूनियन की किसी बचाव नौकरी में या किसी नागरी नौकरी में नौकर है या किसी कुल-भारत नौकरी में नौकर है या यूनियन के अधीन बचाव संबंधी किसी जगह पर या किसी नागरी जगह पर है, राजपति के इच्छा-क़ात्त तक

यूनियन या किसी रियासत की नौकरी करने वाले आदमियों की पद-पियाद



अपने पद पर रहेगा, और हर वह आदमी जो किसी रियासत की किसी नागरी नौकरी में नौकर है या किसी रियासत के अधीन किसी नागरी जगह पर है उस रियासत के रियासतपति के या, जैसी सूरत हो, राजप्रमुख के इच्छा-काल तक अपने पद पर रहेगा.

(2) इस बात के रहते भी कि कोई आदमी जो यूनियन के या किसी रियासत के अधीन किसी नागरी जगह पर है राजपति के या, जैसी सूरत हो, उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के इच्छा-काल तक ही अपने पद पर रह सकता है, अगर किसी ठेके के अधीन कोई आदमी, जो किसी बचाव नौकरी या किसी कुल-भारत नौकरी या यूनियन की या किसी रियासत की किसी नागरी नौकरी में नौकर नहीं है, इस विधान के अधीन किसी ऐसी जगह पर नियोजा जाय, और अगर राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, विशेष जोगताएँ रखने वाले किसी आदमी की सेवाएँ पाने के लिये यह जरूरी समझे, तो उस ठेके में यह बन्धान किया जा सकता है कि अगर उस अरसे के बीतने से पहले जिस पर समझौता था वह जगह तोड़ दी जाय या उस आदमी से, ऐसे कारनों से जिनका संबंध उसके किसी बुरे चलन से नहीं है, वह जगह खाली कराना दरकार हो, तो उसको नुकसान भरपाई दी जायगी.

यूनियन या किसी रियासत के अधीन नागरी हैसियत से नौकरी करने वालों का बरखास्त कि या जाना, हटायाजाना या रुतबा घटाया जाना

311—(1) किसी आदमी को जो यूनियन की किसी नागरी नौकरी में या किसी कुल-भारत नौकरी में या किसी रियासत की नागरी नौकरी में नौकर है, या यूनियन के या किसी रियासत के अधीन किसी नागरी जगह पर है, कोई ऐसा अधिकारी जो उसके नियोजन के वाले अधिकारी से मातहत दर्जे का है न बरखास्त करेगा और न हटायागा.

(2) ऊपर बताए किसी आदमी को न बरखास्त किया जायगा, न हटाया जायगा और न उसका रुतबा घटाया जायगा, जबतक कि उसके बारे में तजवीज की हुई कारवाई के खिलाफ कारन दिखाने का उचित मौक़ा उसे न दिया गया हो :

शर्तें कि यह धारा वहां लागू नहीं होगी—

(ए) जहां किसी आदमी को किसी ऐसे चलन की बिना पर

जिसके कारन वह किसी कौजदारी जुर्म का दोशी ठहराया जा चुका है, बरखास्त किया गया हो या हटाया गया हो या उसका रुतबा घटाया गया हो;

(बी) जहाँ किसी आदमी को बरखास्त करने, हटाने या उसका रुतबा कम करने की शक्ति रखने वाले किसी अधिकारी को इतमीनान हो जाय कि, किसी ऐसी वजह से जिसे वह अधिकारी लिख रखेगा, उस आदमी को कारन बताने का मौक़ा देना समझदारी के खयाल से अमली नहीं है; या

(सी) जहाँ राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख को, जैसी सूरत हो, यह इतमीनान हो जाय कि राज की सुरक्षा के हित में उस आदमी को ऐसा मौक़ा देना समयोचित नहीं है.

(3) अगर कोई ऐसा सवाल उठे कि किसी आदमी को धारा (2) के अधीन कारन बताने का मौक़ा देना समझदारी के खयाल से अमली है या नहीं, तो ऐसे आदमी को बरखास्त करने या हटाने या उसका रुतबा घटाने की, जैसी सूरत हो, शक्ति रखने वाले अधिकारी का इस बात पर फैसला आखिरी होगा.

312—(1) भाग ग्यारह में किसी बात के रहते भी, अगर रियासत सदन ने, किसी ऐसे ठहराव से जिसका मौजूद और बोट देने वाले मेम्बरों में से कम से कम दो तिहाई ने समर्थन किया हो, यह ऐलान कर दिया हो कि कौमी हितमें ऐसा करना जरूरी या समयोचित है तो राजपंचायत क़ानून बनाकर यूनियन और रियासत के लिये एक या एक से अधिक शामिलती कुल-भारत नौकरियाँ खोलने का बन्धान कर सकती है, और, इस खंड के दूसरे बन्धानों के अधीन रहते हुए, ऐसी किसी नौकरी में नियोजे जाने वाले लोगों की भरती और नौकरी की शर्तों की क़ायदाबन्दी कर सकती है.

कुल भारत  
नौकरियाँ.

(2) इस बिधान के आरम्भ होने पर जो नौकरियाँ हिन्द शासनी नौकरी (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) और हिन्द पुलिस नौकरी (इंडियन पुलिस सर्विस) कहलाती थीं वह इस दफ़्ता के अधीन राज-

पंचायत की खोली हुई नौकरियां समझी जायंगी.

बिचवकी बन्धान

313—जब तक इस विधान के अधीन इस के लिये कोई दूसरा बन्धान नहीं किया जाता, तब तक वह सब क़ानून, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में थे, और जो किसी ऐसी सरकारी नौकरी या किसी जगह के लिये लागू थे जो इस विधान के आरंभ के बाद कुल-भारत नौकरी के रूप में या यूनियन के या किसी रियासत के अधीन नौकरी या जगह के रूप में जारी है, जहां तक इस विधान के बन्धानों से मेल रखते होंगे, अमल में रहेंगे.

कुछ नौकरियों के मौजूदा अफ़सरों की रक्षा के लिये बन्धान

314—सिवाय जब कि इस विधान में साफ़-साफ़ कुछ और बन्धान किया गया हो, हर वह आदमी, जिसे स्टेट सेक्रेटरी या कौंसिल समेत स्टेट सेक्रेटरी ने हिन्दू सम्राट की किसी नागरी नौकरी में नियोजन हो और जो इस विधान के आरंभ होने के समय और उसके बाद भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के अधीन नौकरी करता रहता है, भारत सरकार से और उस रियासत की सरकार से, जिसकी नौकरी वह समय समय पर करता रहता है, मेहनताने, छुट्टी और पेनशन के बारे में नौकरी की वही शर्तें, और क़ायदादारी के मामलों के बारे में वही अधिकार, या उनसे इतने मिलते जुलते अधिकार, जितने बदली हुई हालतें इजाज़त दें, पाने का हक़दार होगा जिनके पाने का वह इस विधान के आरम्भ से ठीक पहले हक़दार था.

### खंड दो—सरकारी नौकरी कमीशन

यूनियन के लिये और रियासतों के लिये सरकारी नौकरी कमीशन

315—(1) इस दफ़ा के बन्धानों के अधीन रहते हुए, यूनियन के लिये एक सरकारी नौकरी कमीशन होगा और हर रियासत के लिये एक सरकारी नौकरी कमीशन होगा.

(2) दो या अधिक रियासतें यह समझौता कर सकती हैं कि रियासतों के उस गुट के लिये एक ही सरकारी नौकरी कमीशन होगा, और अगर इस मतलब का कोई ठहराव उन रियासतों में से हर एक की क़ानून सभा के सदन में या, जहाँ दो सदन हैं वहाँ, हर सदन में पास हो जाता है, तो राजपंचायत क़ानून बना कर उन रियासतों की ज़रूरतें पूरी करने के लिये एक मिला-जुला रियासत

सरकारी नौकरी कमीशन (जिसकी इस खंड में मिला-जुला कमीशन कह कर चर्चा की गई है) नियोजे जाने के लिये बन्धान कर सकती है.

(3) ऊपर कहे हर कानून में ऐसे प्रसंगी और परिनामी बन्धान रह सकते हैं जो उस कानून के मतलबों पर अमल कराने के लिये जरूरी या चाहनी हों.

(4) यूनियन के सरकारी नौकरी कमीशन से अगर किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख ऐसा करने की प्रार्थना करे तो वह कमीशन, राजपति की राजामन्दी से, उस रियासत की सब या किन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिये राजी हो सकता है.

(5) जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तब तक, इस विधान में यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन की या रियासत सरकारी नौकरी कमीशन की जहाँ जहाँ चर्चा की गई है, वहाँ उस कमीशन से मतलब लिया जायगा जो उस खास मामले के बारे में जिस पर सवाल उठा है यूनियन की या उस रियासत की, जैसी सूरत हो, जरूरतें पूरी करता है.

316—(1) किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी और दूसरे मेम्बरों को, यूनियन कमीशन या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में, राजपति और, किसी रियासत कमीशन की सूरत में, उस रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख नियोजेगा :

मेम्बरों का निर्बो-  
जन और पद-  
मियाद

शर्तें कि हर सरकारी नौकरी कमीशन के आधे के जितने करीब हो सकें उतने मेम्बर ऐसे लोग होंगे जो अपने अपने नियोजन की तारीखों पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन कम से कम दस बरस तक किसी ओहदे पर रह चुके हैं, और इस दस बरस के अरसे को गिनने में इस विधान के आरंभ से पहले का वह अरसा भी शामिल कर लिया जायगा जिसमें वह आदमी हिन्द सम्राट के अधीन या किसी देसी रियासत की सरकार के अधीन किसी ओहदे पर रह चुका है.

(2) सरकारी नौकरी कमीशन का हर मेम्बर अपना पद संभालने की तारीख से छै बरस की मियाद तक या, यूनियन

कमीशन की सूरत में, पैंसठ बरस की उमर का होने तक और, किसी रियासत कमीशन की या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में, साठ बरस की उमर का होने तक, जो भी पहले हो जाय, अपने पद पर रहेगा :

शर्तें कि—

(ए) किसी सरकारी नौकरी कमीशन का कोई मेम्बर, यूनि-यन कमीशन और मिले-जुले कमीशन की सूरत में, राजपति को और, किसी रियासत कमीशन की सूरत में, उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख को, अपनी दसखती लिखत भेज कर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है;

(बी) किसी सरकारी नौकरी कमीशन का कोई मेम्बर दफ्ता 317 की धारा (1) या धारा (3) में बन्धान किये ढँग से अपने पद से हटाया जा सकता है.

(3) कोई आदमी जो किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर के पद पर है, अपनी पद-मियाद के बीत जाने पर, उस पद पर फिर नियोजे जाने का पात्र न होगा.

किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर का हटाया जाना और मुअत्तल किया जाना

317—(1) धारा (3) के बन्धानों के अधीन रहते हुए, किसी सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या कोई दूसरा मेम्बर अपने पद से केवल राजपति के हुकुम से और बद्-ब्योहार की बिना पर ही हटाया जा सकेगा, और वह तब जब आला अदालत ने, राजपति के उस अदालत की राय मांगने पर, दफ्ता 145 के अधीन इस काम के लिये बताए दस्तूर के अनुसार पूछ ताछ करने के बाद, यह रिपोर्ट दे दी हो कि वह मसनदी या दूसरा मेम्बर, जैसी सूरत हो, ऐसी किसी बिना पर हटाया जाना चाहिये.

(2) यूनिशन कमीशन या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में राजपति, और किसी रियासत कमीशन की सूरत में रियासतपति या राजप्रमुख, उस कमीशन के मसनदी या ऐसे किसी दूसरे मेम्बर को, जिसके बारे में धारा (1) के अधीन आला अदालत की राय मांगी गई है, उसके पद से तब तक के लिये मुअत्तल कर

सकता है जब तक इस तरह मांगी हुई राय पर आला अदालत की रिपोर्ट मिलने के बाद राजपति हुकुम न दे दे.

(3) धारा (1) में किसी बात के रहते भी, राजपति किसी सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी या दूसरे किसी मेम्बर को उसके पद से हटा सकता है अगर वह मसनदी या दूसरा मेम्बर, जैसी सूरत हो,—

(ए) अदालत से दिवालिया ठहरा दिया जाय; या

(बी) अपनी पद-मियाद के अन्दर अपने पद के फ़रजों के बाहर कोई और वेतनी काम करने लगे; या

(सी) राजपति की राय में, दिमाग या शरीर की कमजोरी के कारन, अपने पद पर बने रहने के अजोग हो.

(4) अगर किसी सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या कोई दूसरा मेम्बर भारत सरकार के किये हुए या किसी रियासत की सरकार के किये हुए या उनमें से किसी की तरफ़ से किये हुए किसी ठेके या समझौते से किसी तरह का संबंध या उसमें अपना कोई हित रखे या रखने लगे, या किसी तरह उसके लाभ में या उससे पैदा होने वाले किसी फ़ायदे या वेतन में हिस्सा लेने लगे, सिवाय जबकि वह किसी एकतनी कम्पनी के मेम्बर की हैसियत से उस कम्पनी के दूसरे मेम्बरों के साथ साथ, ऐसा करे, तो धारा (1) के मतलबों के लिये वह बद्-व्योहारी का अपराधी समझा जायगा.

318—यूनियन कमीशन या किसी मिले-जुले कमीशन की सूरत में राजपति, और किसी रियासत कमीशन की सूरत में उस रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, क़ायदे बनाकर—

(ए) कमीशन के मेम्बरों की गिनती और उनकी नौकरी की शर्तें तय कर सकता है; और

(बी) कमीशन के अमले के मेम्बरों की गिनती और उनकी नौकरी की शर्तों के बारे में बन्धान कर सकता है :

शर्तेकि किसी सरकारी नौकरी कमीशन के किसी मेम्बर के नियोजन के बाद उसकी नौकरी की शर्तों में ऐसी अदल बदल नहीं की जायगी जिससे वह घाटे में रहे.

कमीशन के मेम्बरों और अमले की नौकरी की शर्तों के बारे में क़ायदा-बन्दी करने की शक्ति

कमीशन के मेम्बरों को मेम्बर न रहने के बाद पदों पर रहने के बारे में मनाही

319—अपने पद पर न रहने के बाद—

(ए) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन आगे कोई नौकरी करने का पात्र न होगा;

(बी) किसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी, यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या उसका दूसरा मेम्बर या किसी दूसरे रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी नियोजे जाने का पात्र होगा, पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत सरकार के अधीन किसी दूसरी नौकरी के लिये पात्र न होगा;

(सी) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी को छोड़कर उसका कोई और मेम्बर यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या किसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी नियोजे जाने का पात्र होगा, पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन किसी और नौकरी के लिये पात्र न होगा;

(डी) किसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन के मसनदी को छोड़कर उसका कोई और मेम्बर यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी या कोई दूसरा मेम्बर या उसी रियासत सरकारी नौकरी कमीशन या किसी दूसरे रियासत सरकारी नौकरी कमीशन का मसनदी नियोजे जाने का पात्र होगा, पर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत सरकार के अधीन किसी दूसरी नौकरी के लिये पात्र न होगा.

सरकारी नौकरी कमीशनों के काम

320—(1) यूनियन के और रियासतों के सरकारी नौकरी कमीशनों का यह फ़रज़ होगा कि वह यूनियन की नौकरियों और उस रियासत की नौकरियों पर अलग अलग नियोजनों के लिये परीक्षाएं चलाएँ

(2) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन का यह भी फ़रज़ होगा कि अगर कोई दो या अधिक रियासतें उससे ऐसा करने की प्रार्थना करें तो उन रियासतों को, ऐसी नौकरियों के लिये जिन के लिये खास जोगताएँ रखने वाले उम्मीदवार दरकार हों, मिली जुली भरती की योजनाएँ बनाने और चलाने में मदद दे.

(3) यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन से या रियासत सरकारी नौकरी कमीशन से, जैसी सूरत हो, नीचे लिखे मामलों में सलाह लेनी होगी:—

(ए) वह सब मामले जिन का सम्बन्ध नागरी नौकरियों और नागरी जगहों के लिये भरती करने के तरीकों से है ;

(बी) वह सिद्धान्त जिन पर चल कर नागरी नौकरियों और जगहों पर नियोजन किये जायेंगे, और एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर तरक्कियाँ दी जायेंगी और तबादले किये जायेंगे, और इस बात पर कि इस तरह के नियोजनों, तरक्कियों या तबादलों के लिये कौन उम्मीदवार ठीक होंगे ;

(सी) क़ायदादारी के वह सब मामले जिनका असर भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन नागरी हैसियत में नौकरी करने वाले किसी आदमी पर पड़ता हो, जिसमें ऐसे मामलों से सम्बन्ध रखने वाले आवेदनपत्र या प्रार्थनापत्र भी शामिल होंगे ;

(डी) किसी ऐसे आदमी का जो भारत सरकार के अधीन या किसी रियासत की सरकार के अधीन या हिन्द सम्राट के अधीन या किसी देसी रियासत की सरकार के अधीन नागरी हैसियत में नौकरी कर रहा है या कर चुका है, यह दावा, या उसकी तरफ से किया हुआ यह दावा, कि अपना फ़रज़ पूरा करने के दौरान में जो काम उसने किये या उसके किये माने गए, उनके बारे



में अगर कोई कानूनी कारवाई उसके खिलाफ चलाई गई हो तो उसकी जवाबदेही करने में उसका जो खर्च हुआ हो वह भारत के या उस रियासत के, जैसी सूरत हो, मूठकोश में से दिया जाय;

- (ई) भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के या हिन्दु सम्राट के या किसी देसी रियासत की सरकार के अधीन नागरी हैसियत में नौकरी करते हुए किसी आदमी को अगर कोई आघात पहुँचे हों तो उनके बारे में उसका यह दावा कि उसको उनके लिये पेनशन दी जाय, और इस तरह जो पेनशन दी जाय उसकी रकम के बारे में कोई सवाल,

और सरकारी नौकरी कमीशन का फ़रज होगा कि जिस किसी मामले पर इस तरह उसकी राय मांगी गई हो और किसी दूसरे ऐसे मामले पर जिस पर राजपति या, जैसी सूरत हो, उस रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख उसकी राय मांगे उस पर सलाह दे:

शर्तें कि कुल-भारत नौकरियों के बारे में और यूनियन के मामलों के संबंध की दूसरी नौकरियों और जगहों के बारे में भी राजपति, और किसी रियासत के मामलों के संबंध की दूसरी नौकरियों और जगहों के बारे में, रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, क़ायदे बना सकता है जिन में वह मामले बता दिये जायं जिन पर या आम तौर पर, या किसी खास तरह की सूरतों में, या किन्हीं खास हालातों में, सरकारी नौकरी कमीशन से सलाह लेना ज़रूरी नहीं होगा.

(4) धारा (3) की किसी बात से यह दरकार नहीं होगा कि किसी सरकारी नौकरी कमीशन से इस बात के बारे में सलाह ली जाय कि दफ़ा 16 की धारा (4) में जिस बन्धान की चर्चा की गई है वह किस ढंग से किया जाय या दफ़ा 335 के बन्धानों पर किस ढंग से असर कराया जाय.

(5) धारा (3) की शर्त के अधीन राजपति या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख जो क़ायदे बनाए उन सब

को उनके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके कम से कम चौदह दिन के लिये राजपंचायत के हर सदन के सामने या उस रियासत की कानून सभा के सदन या हर सदन के सामने, जैसी सूरत हो, रखा जायगा, और उन क्रायदों में ऐसे अदल बदल किये जा सकेंगे, चाहे वह अदल बदल किसी क्रायदे को रद्द करने के रूप में हों या सुधारने के रूप में, जिन्हें राजपंचायत के दोनों सदन या उस रियासत की कानून सभा का सदन या दोनों सदन उस इजलास में कर दें जिसमें कि वह क्रायदे इस तरह रखे गए हों।

321—राजपंचायत का बनाया हुआ कोई एक्ट या जैसी सूरत हो, किसी रियासत की कानून सभा का बनाया हुआ कोई एक्ट इस बात का बन्धान कर सकता है कि यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन या उस रियासत का सरकारी नौकरी कमीशन, यूनियन की नौकरियों के बारे में, या उस रियासत की नौकरियों के बारे में, और किसी मुकामी अधिकारी की, या कानून से बनी किसी और एक-तन संस्था की, या जनता की किसी संस्था की नौकरियों के बारे में भी, और अधिक काम अपने हाथ में ले।

सरकारी नौकरी  
कमीशनों के कामों  
को बढ़ाने की शक्ति

322—यूनियन के या किसी रियासत के सरकारी नौकरी कमीशन के खर्च, जिनमें उस कमीशन के मेम्बरों को या उसके अमले के लोगों को या उनके बारे में दी जाने वाली तनखाहें, भत्ते और पेनशनें शामिल होंगी, भारत के या उस रियासत के, जैसी सूरत हो, मूठकोश के खाते में पड़ेंगे।

सरकारी नौकरी  
कमीशनों के खर्च

32 —(1) यूनियन कमीशन का फ़रज होगा कि वह हर बरस अपने कामों की राजपति को रिपोर्ट दे, और उस रिपोर्ट के मिलने पर राजपति, उन मामलों के बारे में, अगर कोई ऐसे मामले हों तो, जिनमें कमीशन की सलाह नहीं मानी गई, न मानने के कारणों को समझाने वाले याद-पत्र के साथ, उस रिपोर्ट की एक नक़ल राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा।

सरकारी नौकरी  
कमीशनों की  
रिपोर्टें

(2) रियासत कमीशन का फ़रज होगा कि वह हर बरस, अपने कामों की रियासतपति या राजप्रमुख को रिपोर्ट दे, और मिले जुले कमीशन का यह फ़रज होगा कि वह हर बरस उन

रियासतों में से हर एक के रियासतपति या राजप्रमुख को, जिनकी ज़रूरतें वह मिलाजुला कमीशन पूरी करता है, उस रियासत के संबंध में अपने कामों की रिपोर्ट दे, और हर सूरत में रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, उस रिपोर्ट के मिलने पर उन मामलों के बारे में, अगर कोई ऐसे मामले हों तो, जिनमें कमीशन की सलाह नहीं मानी गई, न मानने के कारणों को समझाने वाले याद-पत्र के साथ उस रिपोर्ट की एक नक़ल उस रियासत की क़ानून सभा के सामने रखवायगा.

---

## भाग पंद्रह

### चुनाव

324—(1) इस विधान के अधीन, राजपंचायत के लिये और हर रियासत की कानून सभा के लिये, और राजपति और उप-राजपति के पदों के लिये, जो चुनाव होंगे उन सब के लिये चुनाव-चिट्ठे तैयार कराने की निगरानी, निर्देशन और दबान, और उन सब चुनावों का संचालन, जिसमें उन शंकाओं और झगड़ों का फ़ैसला करने के लिये चुनाव अदालतों का नियोजन भी शामिल होगा जो राजपंचायत और रियासतों की कानून सभाओं के चुनावों में या उनके सम्बन्ध में पैदा हों, एक कमीशन के हाथ में रहेगा (जिसकी चरचा इस विधान में चुनाव कमीशन कह कर की गई है).

चुनावों की निगरानी, निर्देशन और दबान एक चुनाव कमीशन के हाथ में रहेगा

(2) चुनाव कमीशन में एक प्रमुख चुनाव कमिशनर और, अगर हों तो, इतने और चुनाव कमिशनर होंगे जितने राजपति समय समय पर तय करे, और प्रमुख चुनाव कमिशनर का और दूसरे चुनाव कमिशनरों का नियोजन, इस काम के लिये बने राजपंचायत के किसी कानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपति करेगा.

(3) जब कोई और चुनाव कमिशनर भी इस तरह नियोजा जाय तो प्रमुख चुनाव कमिशनर चुनाव कमीशन के मसनदों का काम करेगा.

(4) लोक सदन के और हर रियासत के आम सदन के हर आम चुनाव से पहले, और खास सदन वाली हर रियासत के खास सदन के पहले आम चुनाव और उसके बाद हर दुबरासी चुनाव से पहले, राजपति चुनाव कमीशन से सलाह करके धारा (1) से चुनाव कमीशन को मिले कामों को पूरा करने में चुनाव कमीशन

की मदद करने के लिये ऐसे इलाका कमिश्नर भी नियोजन सकता है जिन्हे वह जरूरी समझे.

(5) राजपंचायत के बनाए किसी कानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, चुनाव कमिश्नरों और इलाका कमिश्नरों की नौकरी की शर्तें और उनकी पद-मिथाद वह होंगी जो राजपति नियम बना कर तय कर दे :

शर्तें कि जिस ढंग और जिन बिनाओं पर आला अदालत के किसी जज को उसके पद से हटाया जा सकता है उस ढंग और उन बिनाओं के सिवा और किसी ढंग या बिना पर प्रमुख चुनाव कमिश्नर अपने पद से न हटाया जायगा, और प्रमुख चुनाव कमिश्नर के नियोजन के बाद उसकी नौकरी की शर्तों में कोई ऐसी अदल बदल न की जायगी जिससे वह घाटे में रहे :

और शर्तें कि किसी दूसरे चुनाव कमिश्नर या इलाका कमिश्नर को प्रमुख चुनाव कमिश्नर की सिफारिश के बिना पद से न हटाया जायगा.

(6) राजपति या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, जब चुनाव कमीशन उससे ऐसी प्रार्थना करे तब, चुनाव कमीशन या किसी इलाका कमिश्नर को वह अमला मिलने का सुभीता कर देगा जो धारा (1) से चुनाव कमीशन को मिले कामों को निभारने के लिये जरूरी हो.

धर्म, नसल, जात या जिन्स की बिना पर कोई आदमी किसी खास चुनाव चिट्ठे में शामिल होने का अपात्र न होगा और न शामिल किये जाने का दावा करेगा

325—राजपंचायत के किसी सदन या किसी रियासत की कानून सभा के सदन या सदनों के चुनाव के लिये हर भूभागी चुनाव हलके का एक आम चुनाव चिट्ठा होगा, और केवल धर्म, नसल, जात, जिन्स या इनमें से किसी की बिना पर, कोई आदमी न ऐसे किसी चुनाव चिट्ठे में शामिल किये जाने का अपात्र होगा, और न ऐसे किसी चुनाव-हलके के लिये किसी खास चुनाव-चिट्ठे में शामिल किये जाने का दावा करेगा.

लोक सदन के लिये और रिया-

326—लोकसदन का और हर रियासत के आम सदन का चुनाव बालिग वोट के आधार पर होगा; यानी हर आदमी जो

भारत का नागर है और जो उस तारीख पर, जो मुनासिब क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून में या उसके अधीन इस काम के लिये तय कर दी जाय, इक्कीस बरस से कम उमर का न हो, और जो इस विधान के अधीन या मुनासिब क़ानून सभा के बनाए किसी क़ानून के अधीन, ना-निवास, दिमाग़ ठीक न होने, जुर्म, घूसखोरी या ग़ैर क़ानूनी आचार की बिना पर अजोग नहीं हो गया है, ऐसे किसी चुनाव के लिये वोटरों में अपना नाम रजिस्टर कराने का हक़दार होगा.

सनों के आम सदनों के लिये चुनाव बालिग़ वोट के आधार पर होंगे

327—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपंचायत समय समय पर, क़ानून बनाकर, उन सब मामलों के बारे में बंधान कर सकती है जिनका वास्ता या सम्बन्ध राजपंचायत के किसी भी सदन के या किसी रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के चुनावों से है, जिनमें चुनाव चिट्ठों की तैयारी, चुनाव-हलकों की हद्बन्दी और वह दूसरे सब मामले भी शामिल होंगे जो ऐसे सदन या सदनों के, क़ायदे से बनने के लिये ज़रूरी हों.

क़ानून सभाओं के चुनावों के बारे में राजपंचायत को बंधान करने की शक्ति

328—इस विधान के बन्धानों के अधीन रहते हुए, और जहाँ तक कि राजपंचायत ने इस काम के लिये कोई बन्धान न किया हो, किसी रियासत की क़ानून सभा, समय समय पर, क़ानून बना कर, उन सब मामलों के बारे में बन्धान कर सकती है जिनका वास्ता या सम्बन्ध उस रियासत की क़ानून सभा के सदन या सदनों के चुनावों से है और जिनमें चुनाव चिट्ठों की तैयारी और वह सब मामले शामिल होंगे जो उस सदन या उन सदनों के, क़ायदे से बनने के लिये ज़रूरी हों.

किसी रियासत की क़ानून सभा की उस क़ानून सभा के चुनावों के बारे में बंधान करने की शक्ति

329—इस विधान में किसी बात के रहते भी—

चुनाव के मामलों में अदालतों के दखल देने पर रोक

(ए) दफ़ा 327 या दफ़ा 328 के अधीन बने या बने माने जाने वाले किसी ऐसे क़ानून की सरदुरुस्ती पर किसी अदालत में सवाल नहीं उठाया जायगा जिसका वास्ता चुनाव हलकों की हद्बन्दी से या ऐसे चुनाव हलकों को सीटें बांटने से हो.

- (बी) राजपंचायत के किसी सदन के या किसी रियासत की कानून सभा के सदन या सदनों के चुनाव पर सिवाय एक ऐसी चुनाव अरज़ी के जो उस अधिकारी को, और ऐसे ढंग से, दी गई हो जिसका बन्धान मुनासिब कानून सभा के बनाए किसी कानून में या उसके अधीन किया गया है, और किसी ढंग से कोई सवाल नहीं उठाया जायगा.
-

## भाग सोलह

### कुछ जमातों से संबंध रखने वाले खास बन्धान

330—(1) लोक सदन में—

(ए) पट्टी दर्ज जातों के लिये,

(बी) आसाम के कबाइली क्षेत्रों के पट्टी-दर्ज कबीलों को छोड़ कर दूसरे पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये, और

(सी) आसाम के स्वाधीन जिलों के पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये,

सीटें अलग रखी जायंगी.

(2) किसी रियासत की पट्टी-दर्ज जातों या उसके पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये धारा (1) के अधीन अलग रखी सीटों की गिनती और लोक सदन में उस रियासत को मिली कुल सीटों की गिनती में जितने करीब से करीब हो सके बड़ी निश्चय होगी जो उस रियासत की उन पट्टी-दर्ज जातों की, या उस रियासत के या उसके किसी भाग के, जैसी सूरत हो, उन पट्टी-दर्ज कबीलों की, जिनके बारे में सीटें इस तरह अलग रखी गई हैं, आबादी और उस रियासत की कुल आबादी में है.

331—दफ़ा 81 में किसी बात के रहते भी, अगर राजपति की यह राय हो कि लोक सदन में ऐंग्लो इंडियन समाज का काफी प्रतिनिधान नहीं है, तो वह उस समाज के अधिक से अधिक दो मेम्बरों को लोक सदन में नामजद कर सकेगा.

लोक सदन में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये सीटें अलग रखना

लोक सदन में ऐंग्लो इंडियन समाज का प्रतिनिधान

332—(1) पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत के आम सदन में, आसाम के कबाइली क्षेत्रों के पट्टी-दर्ज कबीलों को छोड़ कर, सब पट्टी दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये सीटें अलग रखी जायंगी.

रियासतों के आम सदन में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये सीटों का अलग रखा जाना

(2) आसाम की रियासत के आम सदन में स्वाधीन जिलों के लिये भी सीटें अलग रखी जायंगी.

(3) धारा (1) के अधीन किसी रियासत के आम सदन में पट्टी-दर्ज जातों या पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये अलग रखी सीटों



की गिनती और आम सदन की सीटों की कुल गिनती में, जितने करीब से करीब हो सके, वही निश्चित होगी जो उस रियासत की उन पट्टी-दर्ज जातों की या उस रियासत या उसके किसी भाग के, जैसी सूरत हो, उन पट्टी-दर्ज कबीलों की, जिनके बारे में सीटें इस तरह अलग रखी गई हैं, आबादी और उस रियासत की कुल आबादी में है।

(4) आसाम की रियासत के आम सदन में किसी स्वाधीन जिले के लिये अलग रखी सीटों की गिनती और उस आम सदन में सीटों की कुल गिनती में जो निश्चित होगी वह उससे कम न होगी जो उस जिले की आबादी और उस रियासत की कुल आबादी में है।

(5) आसाम के किसी स्वाधीन जिले के लिये अलग रखी सीटों के चुनाव हलकों में उस जिले से बाहर का कोई क्षेत्र शामिल नहीं होगा, सिवाय उस चुनाव हलके के जिसमें शिलांग की छावनी और नगरायत शामिल हैं।

(6) कोई आदमी जो आसाम की रियासत के किसी स्वाधीन जिले के किसी पट्टी-दर्ज कबीले का मेम्बर नहीं है उस जिले के किसी चुनाव हलके से, सिवाय उस चुनाव हलके के जिसमें शिलांग की छावनी और नगरायत शामिल हैं, रियासत के आम सदन में चुने जाने का पात्र नहीं होगा।

रियासतों के आम सदन में ऐंग्लो इन्डियन समाज का प्रतिनिधान

333—दफा 170 में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, अगर उसकी यह राय है कि उस रियासत के आम सदन में ऐंग्लो इन्डियन समाज को प्रतिनिधान की जरूरत है और उसमें उसका काफी प्रतिनिधान नहीं है, आम सदन में उस समाज के उतने मेम्बर नामजद कर सकता है जितने वह मुनासिब समझे।

सीटों का अलग रखा जाना और खास प्रतिनिधान दस साल बाद बन्द

334—इस भाग में ऊपर-लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, इस विधान के वह बन्धान जिनका सम्बन्ध—

(ए) लोक सदन में और रियासतों के आम सदन में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये सीटें अलग रखने से है; और

(बी) लोक सदन में और रियासतों के आम सदन में नाम-जदगी के जरिये ऐंग्लो-इन्डियन समाज के प्रतिनिधान से है,

इस विधान के आरंभ से दस साल का अरसा बीत जाने पर बेअसर हो जायेंगे :

शर्तें कि इस दफा की किसी बात का लोक सदन में या किसी रियासत के आम सदन में किसी प्रतिनिधान पर कोई असर नहीं होगा जब तक कि उस समय का लोक सदन या आम सदन, जैसी सूरत हो, भंग न हो जाय.

335—यूनियन के या किसी रियासत के मामलों के संबंध की नौकरियों या जगहों पर नियोजन करने में, शासन की कुशलता बनाए रखने का खयाल रखते हुए, पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के मेम्बरों के दावों का ध्यान रखना होगा.

नौकरियों और जगहों के लिये पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के दावे

336—(1) इस विधान के आरम्भ के बाद पहले दो बरस तक यूनियन की रेल मार्ग, विदेसनी महसूल, डाक और तार की नौकरियों की जगहों पर ऐंग्लो इन्डियन समाज के मेम्बरों का नियोजन उसी आधार पर होगा जिस पर अगस्त, 1947 के पंद्रहवें दिन से ठीक पहले होता था.

कुछ नौकरियों में ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये खास बन्धान

हर अगले दो साल के अन्दर जितनी जगहें ऊपर लिखी नौकरियों में उस समाज के मेम्बरों के लिये अलग रखी जायेंगी उनकी गिनती, उससे ठीक पहले के दो साल के अन्दर जितनी जगहें इस तरह अलग रखी गई थीं उनसे, दस फी सैकड़ा के जितने करीब से करीब हो सके कम होंगी :

शर्तें कि इस विधान के आरम्भ से दस बरस खतम हो जाने पर जगहों का इस तरह अलग रखा जाना सब बन्द हो जायगा.

(2) धारा (1) की कोई बात, उस धारा के अधीन जो जगहें ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये अलग रखी गई हैं उनके अलावा या, उनसे ज्यादा, और दूसरी जगहों पर उस समाज के लोगों के नियोजन को नहीं रोकेगी, अगर दूसरे समाजों के लोगों के मुक़ाबले

में ऐंग्लो इन्डियन समाज के लोग अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर नियोजित जाने के जोग पाए जायें.

ऐंग्लो इन्डियन समाज के फायदे के लिये तालीमी देनगियों के बारे में खास बन्धान

337—इस विधान के आरम्भ के बाद पहले तीन माली सालों में, यूनिट और पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत तालीमी के बारे में ऐंग्लो इन्डियन समाज के फायदे के लिये वही देनगियां करेगी, अगर ऐसी कोई देनगियां हों तो, जो मार्च, 1948 के इक्तीसवें दिन खतम होने वाले माली साल में की गई थीं.

हर अगले तीन साल में यह देनगियां उससे ठीक पहले के तीन साल में जो देनगियां की गई थीं उनसे दस फी सैकड़ा कम की जा सकेंगी :

शर्तें कि इस विधान के आरम्भ से दस साल खतम हो जाने पर, ऐंग्लो इन्डियन समाज के लिये खास रियायत होने की हद तक, इस तरह की देनगियां बन्द हो जायेंगी :

और शर्तें कि इस दफा के अधीन कोई तालीमी संस्था कोई देनगी पाने की हकदार नहीं होगी जब तक कि उस संस्था के सलाना दाखलों का कम से कम चालीस फी सैकड़ा ऐंग्लो इन्डियन समाज को छोड़ कर दूसरे समाजों के लोगों के लिये खुला न रखा जाय.

पट्टी-दर्ज जातों, पट्टी-दर्ज कबीलों वगैरा के लिये खास अफसर

338—(1) पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये एक खास अफसर होगा जिसको राजपति नियोजेगा.

(2) खास अफसर का फरज होगा कि इस विधान के अधीन पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों के लिये जिन बचावनियों का बन्धान किया गया है उनसे सम्बन्ध रखने वाले सब मामलों की जांच करे, और, हर इतने दिनों के बाद जिनका राजपति निर्देश दे, उन बचावनियों के अमल पर राजपति को रिपोर्ट दे, और राजपति ऐसी सब रिपोर्टों को राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

(3) इस दफा में पट्टी-दर्ज जातों और पट्टी-दर्ज कबीलों की जहां जहां चरचा की गई है उससे यह मतलब लिया जायगा कि उसमें उन दूसरी बिछड़ी हुई जमातों की चरचा भी शामिल है जिनको, दफा 340 की धारा (1) के अधीन नियोजे हुए किसी

कमीशन की रिपोर्ट मिलने पर, राजपति हुकुम देकर बता दे, और उसमें ऐंग्लो इन्डियन समाज की चरचा भी शामिल समझी जायगी.

339—(1) राजपति किसी समय भी हुकुम दे कर पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी) में दर्ज रियासतों के पट्टी-दर्ज क्षेत्रों के शासन पर, और पट्टी-दर्ज कबीलों की भलाई के कामों पर, रिपोर्ट देने के लिये, एक कमीशन का नियोजन कर सकता है, और इस विधान के आरम्भ से दस साल बीत जाने पर उसे ऐसे एक कमीशन का नियोजन करना होगा.

पट्टी-दर्ज क्षेत्रों के शासन और पट्टी-दर्ज कबीलों की भलाई पर यूनियन का दबान

ऐसे हुकुम में कमीशन की रचना, शक्तियां और दस्तूर सब तय किये जा सकते हैं, और उसमें ऐसे प्रसंगो या सहायक बन्धान भी रह सकते हैं जिन्हें राजपति जरूरी या चाहनी समझे.

(2) यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में ऐसी किसी रियासत को इस तरह की योजनाएं बनाने और उन पर अमल करने के बारे में निर्देश देना भी शामिल होगा, जिन योजनाओं को उस निर्देश में रियासत के पट्टी-दर्ज कबीलों की भलाई के लिये जरूरी बताया गया हो.

340—(1) राजपति हुकुम दे कर एक ऐसे कमीशन का नियोजन कर सकता है जिसमें वह आदमी होंगे जिन्हें राजपति ठीक समझे, और जो भारत के भूभाग में समाजी और तालीमी निगाह से पिछड़ी हुई जमातों की हालत की, और जो कठिनाइयां उन्हें मिलनी पड़ती हैं उनकी, जांच करेगा, और सिफारिशें करेगा कि उन कठिनाइयों को दूर करने और उन लोगों की हालत सुधारने के लिये यूनियन को या किसी रियासत को क्या क्या कदम उठाने चाहियें, और इस मतलब के लिये यूनियन को या किसी रियासत को क्या क्या देनगियां किन किन शर्तों पर करनी चाहियें, और जिस हुकुम से इस तरह के कमीशन का नियोजन किया जायगा उसमें कमीशन जिस दस्तूर पर चलेगा वह भी तय कर दिया जायगा.

पिछड़ी हुई जमातों की हालत की जांच करने के लिये कमीशन का नियोजन

(2) जिस कमीशन का इस तरह नियोजन किया जायगा वह जिन जिन मामलों के लिये उससे कहा गया हो उनकी जांच

करेगा और राजपति को एक रिपोर्ट देगा जिसमें वह सब बातें दी होंगी जिनका कमीशन को पता चले और वह सब सिफारिशों की गई होंगी जिन्हें कमीशन ठीक समझे.

(3) जो रिपोर्ट इस तरह राजपति को दी जायगी उसकी एक नकल, एक याद-पत्र के साथ जिसमें यह समझाया गया होगा कि उस रिपोर्ट पर क्या कारवाई की गई है, राजपति राजपंचायत के हर सदन के सामने रखवायगा.

पट्टी-दर्ज जातें

341—(1) राजपति, किसी रियासत के रियासतपति या राज-प्रमुख से सलाह करके, एक आम नोटिस निकाल कर, वह जातें, नसलें या कबीले, या जातों, नसलों या कबीलों के भाग, या उनके अन्दर के गिरोह, तय कर सकता है जो इस विधान के मतलबों के लिये उस रियासत के संबंध में पट्टी-दर्ज जातें समझी जायंगी.

(2) राजपंचायत कानून बनाकर, धारा (1) के अधीन जो नोटिस निकाला गया हो उसमें बताई पट्टी-दर्ज जातों की तालिका में, किसी जात, नसल या कबीले को या किसी जात, नसल या कबीले के किसी भाग को या उनके अन्दर के किसी गिरोह को शामिल कर सकती है या उसमें से निकाल सकती है, पर सिवाय जिस तरह कि यहां कहा गया है ऊपर की धारा के अधीन जो नोटिस निकाला जाय उसमें बाद के किसी नोटिस से कोई अदल बदल नहीं की जायगी.

पट्टी-दर्ज कबीले

342—(1) राजपति, किसी रियासत के रियासतपति या राज-प्रमुख से सलाह करके, एक आम नोटिस निकाल कर, वह कबीले या कबाइली समाज, या उन कबीलों या कबाइली समाजों के भाग, या उनके अन्दर के गिरोह तय कर सकता है जो इस विधान के मतलबों के लिये उस रियासत के संबंध में पट्टी-दर्ज कबीले समझे जायंगे.

(2) राजपंचायत, कानून बनाकर, धारा (1) के अधीन जो नोटिस निकाला गया हो उसमें बताई पट्टी-दर्ज कबीलों की तालिका

में, किसी कबीले या कबायली समाज को या किसी कबीले या कबायली समाज के किसी भाग को या उनके अन्दर के किसी गिरोह को शामिल कर सकती है या उसमें से निकाल सकती है, पर सिवाय जिस तरह कि यहां कहा गया है ऊपर की धारा के अधीन जो नोटिस निकाला जाय उस में बाद के किसी नोटिस से कोई अदल बदल नहीं की जायगी.

---

## भाग सतरह

### दफ्तरी भाषा

खंड एक—यूनियन की भाषा

यूनियन की दफ्तरी  
भाषा

343—(1) यूनियन की दफ्तरी भाषा देव नागरी लिखाबट में हिन्दी होगी.

यूनियन के दफ्तरी मतलबों के लिये हिन्दुसों का जो रूप काम में लाया जायगा वह हिन्दुस्तानी हिन्दुसों का अन्तर-क्रौमी रूप होगा.

(2) धारा (1) में किसी बात के रहते भी, इस विधान के आरंभ से पंद्रह बरस के अरसे तक अँगरेजी भाषा यूनियन के उन सब दफ्तरी मतलबों के लिये काम में आती रहेगी जिनके लिये वह विधान के आरंभ से ठीक पहले काम में आती थी :

शर्तेकि राजपति, उस अरसे के दौरान में, हुकुम देकर, अँगरेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा के, और हिन्दुस्तानी हिन्दुसों के अन्तर-क्रौमी रूप के साथ साथ हिन्दुसों के देव नागरी रूप के, यूनियन के दफ्तरी मतलबों में से किसी के लिये काम में लाए जाने का अधिकार दे सकता है.

(3) इस दफ्ता में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत क़ानून बनाकर पन्द्रह बरस के उस अरसे के बाद—

(ए) अँगरेजी भाषा के, या

(बी) हिन्दुसों के देवनागरी रूप के,

उन मतलबों के लिये जो उस क़ानून में बताए जायं, काम में लाए जाने का बंधान कर सकती है.

344—(1) राजपति, इस विधान के आरंभ से पांच बरस बीत जाने पर, और उसके बाद विधान के आरंभ से दस बरस बीत जाने पर, हुकुम दे कर, एक कमीशन बनायगा जिसमें एक मसनदी और वह दूसरे मेम्बर होंगे जो आठवीं पट्टी में बताई अलग अलग भाषाओं के प्रतिनिधि हों और जिन्हें राजपति नियोजे, और उस हुकुम में, वह दस्तूर तय कर दिया जायगा जिस पर कमीशन चलेगा.

दफ्तरी भाषा पर  
कमीशन और  
राजपंचायत की  
कमेटी

(2) कमीशन का यह फरज होगा कि वह इन बातों के बारे में राजपति से सिफारिशें करे—

(ए) यूनियन के दफ्तरी मतलबों के लिये हिन्दी भाषा का बढ़ता हुआ इस्तेमाल;

(बी) यूनियन के दफ्तरी मतलबों में से सब या किसी के लिये अंगरेजी भाषा के इस्तेमाल पर रुकावटें;

(सी) दफ्ता 348 में बताए मतलबों में से सब या किसी के लिये इस्तेमाल की जाने वाली भाषा;

(डी) यूनियन के किसी एक या अधिक ऐसे मतलबों के लिये जो बता दिये जायं इस्तेमाल किये जाने वाले हिन्दुओं का रूप;

(ई) यूनियन की दफ्तरी भाषा, और यूनियन और किसी रियासत के बीच या एक रियासत और दूसरी के बीच आपसी ब्योहार की भाषा, और इन भाषाओं के इस्तेमाल, के संबंध में कोई और मामला जिसे राजपति ने कमीशन के पास राय के लिये भेजा हो.

(3) धारा (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करते समय कमीशन भारत की उद्योगी, कलचरी और साइंसी तरक्की का, और सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में गैर-हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लोगों के उचित दावों और हितों का, मुनासिब खयाल रखेगा.

(4) तीस मेम्बरों की एक कमेटी बनाई जायगी जिनमें से बीस लोक सदन के मेम्बर होंगे और दस रियासत सदन के, और जिनको, निसबती प्रतिनिधान के ढंग के अनुसार इकहरे बदलते बोट



भाषा होनी चाहिये तो उनके आपसी ब्यौहार के लिये वह भाषा काम में आ सकती है.

347—इस बात के लिये मांग होने पर, राजपति को अगर यह इतमीनान हो जाय कि किसी रियासत की आबादी का काफी हिस्सा अपने बोलने की किसी भाषा के इस्तेमाल को उस रियासत से मनवाना चाहता है, तो राजपति यह निर्देश दे सकता है कि वह भाषा भी उस सारी रियासत में या उसके किसी भाग में जिस मतलब के लिये राजपति तय कर दे सरकारी तौर पर मान ली जायगी.

किसी रियासत की आबादी की किसी टुकड़ी में बोली जाने वाली भाषा के बारे में खास बन्धान

### खंड तीन—आला अदालत, हाईकोर्टों वगैरा की भाषा

348—(1) इस भाग में ऊपर लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, जब तक राजपंचायत कानून बनाकर कुछ और बन्धान न कर दे तब तक—

आला अदालत में और हाईकोर्टों में और एक्टों, बिलों वगैरा के लिये काम में आने वाली भाषा

(ए) आला अदालत में और हर हाईकोर्ट में सब कार-वाइयां,

(बी) (एक) राजपंचायत के किसी सदन में या किसी रियासत की कानून सभा के सदन या किसी सदन में रखे जाने वाले सब बिलों की और उनपर पेश किये जाने वाले सब सुधारों की प्रमान लिखत,

(दो) राजपंचायत के या किसी रियासत की कानून सभा के पास किये हुए सब एक्टों की और राजपति के या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के जारी किये हुए सब राजहुकुमों की, प्रमान लिखतें, और

(तीन) उन सब हुकुमों, नियमों, क्रायदों और छुट-कानूनों की प्रमान लिखतें जो इस विधान के अधीन या राजपंचायत के या किसी रियासत की कानून सभा के बनाए किसी कानून के अधीन जारी किये गये हों,

अँगरेजी भाषा में होंगी.

(2) धारा (1) की उप-धारा (ए) में किसी बात के रहते भी, किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, राजपति की पहले से अनुमति लेकर, हिन्दी भाषा या किसी दूसरी भाषा को जो उस रियासत के किन्हीं दफ्तरी मतलबों के लिये काम में आती हो, उस हाईकोर्ट की कारवाइयों में काम में लाए जाने का अधिकार दे सकता है जिसकी खास जगह उस रियासत में है :

शर्तें कि इस धारा की कोई बात उस हाईकोर्ट के दिये हुए या किये हुए किसी फ़ैसले, डिगरी या हुकुम पर लागू नहीं होगी.

(3) धारा (1) की उपधारा (बी) में किसी बात के रहते भी, जहाँ किसी रियासत की कानूनसभा ने उस रियासत की कानूनसभा में रखे जाने वाले बिलों या पास होने वाले एक्टों में, या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के जारी किये राजहुकुमों में, या उस उप-धारा के पैरा (3) में जिस किसी हुकुम, नियम, कायदे या छुट-कानून की चरचा की गई है उनमें, अँगरेज़ी भाषा को छोड़ कर किसी दूसरी भाषा का काम में लाया जाना तय कर दिया है, वहाँ उसका अँगरेज़ी भाषा में अनुवाद, जो उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के अधिकार से उस रियासत के दफ्तरी गज़ट में निकाला जायगा, इस दफ्ता के अधीन अँगरेज़ी भाषा में उसकी प्रमान लिखत माना जायगा.

भाषा के संबंध में कुछ कानूनों के बनाए जाने के लिये खास दस्तूर

349—इस विधान के आरंभ से पन्द्रह बरस के अरसे के अन्दर, दफ्ता 348 की धारा (1) में बताए मतलबों में से किसी के लिये काम में आने वाली भाषा का बन्धान करने वाला कोई बिल या सुधार राजपति की पहले से मंजूरी लिये बिना राजपंचायत के किसी सदन में न रखा जायगा, न पेश किया जायगा, और राजपति ऐसे किसी बिल के रखे जाने की या ऐसे किसी सुधार के पेश किये जाने की मंजूरी नहीं देगा सिवाय इसके कि वह दफ्ता 344 की धारा (1) के अधीन बने कमीशन की सिफारिशों पर और उस दफ्ता की धारा (4) के अधीन बनी कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद मंजूरी दे.

## खंड चार—खास निर्देश

350—किसी तकलीफ को दूर कराने के लिये, यूनियन के या किसी रियासत के किसी अफसर या अधिकारी को, यूनियन में या, जैसी सूरत हो, उस रियासत में काम में आने वाली किसी भी भाशा में, अरजी पत्र देने का हर आदमी को हक्क होगा.

तकलीफों के दूर कराने के लिये अरजी पत्रों में काम आने वाली भाशा

351—यूनियन का फरज होगा कि, हिन्दी भाशा के फैलाव को बढ़ाए, और उसका इस तरह विकास करे कि वह भारत की मिली जुली कलचर के सब अंगों को जाहिर करने का साधन बन सके, और, उसकी आत्मा को छेड़े बिना, जो जो रूप, जो शैली और जो मुहावरे हिन्दुस्तानी में और आठवीं पट्टी में दर्ज भारत की दूसरी भाशाओं में काम में आते हैं उनको उसमें रचा पचा कर, और, जहाँ कहीं जरूरी या चाहनी हो, उसकी शब्दावली के लिये पहले संस्कृत से और फिर दूसरी भाशाओं से शब्द लेकर, उसे मालामाल करे.

हिन्दी भाशा के विकास के लिये निर्देश

अ

## भाग अठारह

### अचानकी बन्धान

अचानकी  
ऐलान का

352—(1) अगर राजपति को इतमीनान हो जाय कि कोई गहरी अचानकी मौजूद है जिससे, चाहे जंग के कारन या बाहरी हमले के कारन या भीतरी गड़बड़ी के कारन भारत की या उसके भूभाग के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है, तो वह ऐलान निकाल कर इस बात को जाहिर कर सकता है.

(2) धारा (1) के अधीन जो ऐलान निकाला जाय—

(ए) उसे बाद के किसी ऐलान से मंसूख किया जा सकता है;

(बी) उसे राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा;

(सी) वह दो महीने बीत जाने पर अमल में नहीं रहेगा, जब तक कि उस अरसे के बीत जाने से पहले राजपंचायत के दोनों सदनों ने ठहराव पास करके उस पर रजामन्दी न दे दी हो :

शर्तें कि अगर इस तरह का कोई ऐलान ऐसे समय निकले, जब लोक सदन भंग हो चुका हो, या अगर उप-धारा (सी) में जिस दो महीने के अरसे की चरचा की गई है, उसके अन्दर लोक सदन भंग हो जाय, और रियासत सदन ने ऐलान पर रजामन्दी का ठहराव पास कर दिया हो, पर उस अरसे के बीतने से पहले लोक सदन ने उस ऐलान के बारे में कोई ठहराव पास न किया हो, तो उस तारीख से तीस दिन बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं रहेगा, जिस तारीख को लोक सदन के दुबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक हो, जब तक कि उस तीस दिन के अरसे के बीत जाने से पहले ही लोक सदन ने भी उस ऐलान पर रजामन्दी का ठहराव पास न कर दिया हो.

(3) अचानकी का कोई ऐलान, जिसमें यह जाहिर किया गया हो कि जंग या बाहरी हमले या भीतरी गड़बड़ी के कारन भारत की या उसके भूभाग के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है,

जंग या उस तरह के किसी हमले या गड़बड़ी के सचमुच शुरु होने से पहले ही निकाला जा सकता है, अगर राजपति को यह इतमीनान हो जाय कि उसका खतरा बिल्कुल सामने है.

353—जब अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो तब—

अचानकी के  
ऐलान का अमल

(ए) इस विधान में किसी बात के रहते भी, यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में किसी रियासत को यह निर्देश देना शामिल होगा कि उस रियासत की काजकारी शक्ति से किस ढंग से काम लिया जाय;

(बी) किसी मामले के बारे में राजपंचायत की कानून बनाने की शक्ति में ऐसे कानूनों के बनाने की शक्ति शामिल होगी जिन से उस मामले के बारे में यूनियन को या यूनियन के अफसरों और अधिकारियों को कोई शक्तियाँ सौंपी जाय और उन पर कोई फ़रज़ लगाय जाय या उन्हें शक्तियाँ सौंपने और उन पर फ़रज़ लगाने का किसी को अधिकार दिया जाय, भले ही वह मामला ऐसा हो जो यूनियन तालिका में नहीं गिनाया गया है.

354—(1) जिस समय अचानकी का कोई ऐलान अमल में हो उस समय राजपति हुकुम जारी करके यह निर्देश दे सकता है कि दफ़ा 268 से 279 तक की दफ़ाओं के बन्धानों में से सब का या किसी का असर उतने अरसे के लिये जो उस हुकुम में बता दिया गया हो, पर जो किसी सूरत में भी उस मास्ती साल के खतम होने से आगे नहीं बढ़ेगा जिसमें उस ऐलान पर अमल बन्द हो जाय, उन अपवादों या अदल बदल के अधीन होगा जिन्हें राजपति ठीक समझे.

जब अचानकी का  
कोई ऐलान अमल  
में हो तब माल-  
गुजारी के बटवारे के  
सम्बन्ध के बन्धानों  
का लागू होना

(2) धारा (1) के अधीन दिया हुआ हर हुकुम दिये जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा.

५

355—यूनियन का फ़रज़ होगा कि हर रियासत की बाहरी हमले और भीतरी गड़बड़ी से रक्षा करे, और इस बात को पक्का

रियासतों की बाहरी  
हमले और भीतरी

गड़बड़ी से रक्षा  
करना यूनियन का  
फरज़

रियासतों में विधानी  
मशीन के फेक हो  
जाने की सूरत में  
बन्धान

करे कि हर रियासत की हुकूमत इस विधान के बन्धानों के अनुसार चलाई जाय.

356—(1) अगर राजपति को किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख से रिपोर्ट मिलने पर, या किसी दूसरी तरह, यह इतमीनान हो जाय कि ऐसी हालत पैदा हो गई है जिसमें इस विधान के बन्धानों के अनुसार उस रियासत की हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, तो राजपति ऐलान निकाल कर—

(ए) उस रियासत की सरकार के सब या कुछ काम, और उसकी सब या कुछ शक्तियाँ जो रियासतपति या राजप्रमुख को, जैसी सूरत हो, हासिल हैं, या जिनसे वह काम ले सकता है, या जो उस रियासत में, रियासत की क़ानून सभा को छोड़ कर, दूसरी किसी संस्था या अधिकारी को हासिल हैं, या जिनसे वह संस्था या अधिकारी काम ले सकता है, अपने हाथ में ले सकेगा;

(बी) यह जाहिर कर सकता है कि उस रियासत की क़ानून सभा की शक्तियों से राजपंचायत काम ले सकेगी या राजपंचायत के अधिकार के अधीन उन शक्तियों से काम लिया जा सकेगा;

(सी) ऐसे प्रसंगी और परिनामी बन्धान कर सकता है जो उस ऐलान के उद्देशों पर अमल कराने के लिये राजपति को ज़रूरी या चाहनी मालूम हों; इन में ऐसे बन्धान भी शामिल होंगे जो उस रियासत की किसी संस्था या अधिकारी से सम्बन्ध रखने वाले इस विधान के किन्हीं बन्धानों के अमल को पूरे तौर पर या कुछ हद तक मुअत्तल करते हों:

शर्तें कि इस धारा की किसी बात से राजपति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उन शक्तियों में से किसी को अपने हाथ में ले ले जो किसी हाईकोर्ट को हासिल हैं या जिनसे हाईकोर्ट काम ले सकती है, या हाईकोर्टों से सम्बन्ध रखने वाले इस विधान के किसी बन्धान

के अमल को पूरे तौर पर या कुछ हद तक मुअत्तल कर दे.

(2) हर ऐसा ऐलान बाद के किसी ऐलान से मंसूख किया जा सकता है या बदला जा सकता है.

(3) इस दफा के अधीन हर ऐलान को राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा, और सिवाय उस सूरत में जब कि वह कोई ऐसा ऐलान हो जो किसी पहले ऐलान को मंसूख करता हो, दो महीने बीत जाने पर वह अमल में नहीं रहेगा, जब तक कि उस अरसे के बीत जाने से पहले राजपंचायत के दोनों सदनों ने ठहराव पास करके उस पर रजामन्दी न दे दी हो :

शर्तें कि अगर इस तरह का कोई ऐलान (जो किसी पहले ऐलान को मंसूख करने वाला ऐलान न हो) ऐसे समय निकले जब लोक सदन भंग हो चुका हो, या अगर इस धारा में जिस दो महीने के अरसे की चरचा की गई है, उसके अन्दर लोक सदन भंग हो जाय, और रियासत सदन ने ऐलान पर रजामन्दी का ठहराव पास कर दिया हो, पर उस अरसे के बीतने से पहले लोक सदन ने उस ऐलान के बारे में कोई ठहराव पास न किया हो, तो उस तारीख से तीस दिन बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं रहेगा, जिस तारीख को लोक सदन के दुबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक हो, जब तक कि उस तीस दिन के अरसे के बीतने से पहले ही लोक सदन ने भी उस ऐलान पर रजामन्दी का ठहराव पास न कर दिया हो.

(4) जिस ऐलान पर इस तरह रजामन्दी दे दी गई हो, वह, जब तक मंसूख न कर दिया जाय, धारा (3) के अधीन ऐलान पर रजामन्दी देने वाले ठहरावों में से दूसरे ठहराव के पास होने की तारीख से छै महीने का अरसा बीत जाने पर, अमल में नहीं रहेगा :

शर्तें कि अगर और जितनी बार, ऐसे किसी ऐलान के अमल को जारी रखने की रजामन्दी का कोई ठहराव राजपंचायत के दोनों सदनों में पास हो जाय, तो वह ऐलान, जब तक मंसूख न कर दिया जाय, उस तारीख से लेकर जिस से इस धारा के अधीन ठहराव पास न होने की सूरत में वह अमल में न रहता, उतनी ही बार और छै महीने के अरसे तक अमल में रहेगा, पर किसी सूरत में भी

ऐसा कोई ऐलान तीन बरस से ज्यादा अमल में नहीं रहेगा :

और शर्तें कि अगर ऐसे किसी छै महीने के अरसे के अन्दर लोक सदन भंग हो जाय और ऐलान को जारी रखने की रजामन्दी देने वाला ठहराव उस अरसे के अन्दर रियासत सदन में पास हो जाय, पर उस ऐलान के अमल को जारी रखने के बारे में कोई ठहराव उस अरसे के अन्दर लोक सदन में पास न हो, तो लोक सदन के दुबारा बनने के बाद उसकी पहली बैठक की तारीख से तीस दिन बीत जाने पर वह ऐलान अमल में नहीं रहेगा, जब तक कि तीस दिन के उस अरसे के बीतने से पहले ही उस ऐलान के अमल को जारी रखने की रजामन्दी देने वाला ठहराव लोक सदन ने भी पास न कर दिया हो.

दफा 356 के अधीन जारी हुए ऐलान के अधीन कानूनकारी शक्तियों से काम लेना

357—(1) जहां दफा 356 की धारा (1) के अधीन जारी होने वाले किसी ऐलान में यह ठहरा दिया गया है कि उस रियासत की कानून सभा की शक्तियों से राजपंचायत काम ले सकेगी या राजपंचायत के अधिकार के अधीन उन शक्तियों से काम लिया जा सकेगा वहां—

(ए) राजपंचायत को यह अधिकार होगा कि उस रियासत की कानून सभा की कानून बनाने की शक्ति राजपति को सौंप दे, और राजपति को यह अधिकार दे दे कि जो शक्ति इस तरह उसे सौंपी गई है उसे वह, उन शर्तों के अधीन जिन्हें राजपति लगाना ठीक समझे, अपनी तरफ से किसी ऐसे दूसरे अधिकारी को दे दे जिसे वह इस काम के लिये तय करे;

(बी) राजपंचायत को, या राजपति को, या उस दूसरे अधिकारी को जिसे उप-धारा (ए) के अधीन कानून बनाने की इस तरह की शक्ति हासिल हुई है, यह अधिकार होगा कि यूनियन को या उसके अफसरों और अधिकारियों को शक्तियां सौंपने और उन पर फरज लगाने के लिये, या उनको शक्तियां सौंपने और उन पर फरज लगाने का किसी को अधिकार देने के लिये, कानून बनाए;



(सी) राजपति को यह अधिकार होगा कि, उन दिनों जब लोक सदन का इजलास न हो रहा हो, रियासत के मूठकोश में से खर्च किये जाने का उस समय तक के लिये अधिकार दे दे जब तक कि राजपंचायत उस खर्च पर अपनी मंजूरी न दे दे.

(2) जिस किसी कानून को राजपंचायत या राजपति या कोई दूसरा अधिकारी जिसकी चरचा धारा (1) की उपधारा (ए) में की गई है, रियासत की कानून सभा की शक्ति से काम लेते हुए बनाए, और जिसको दफ्ता 356 के अधीन अगर कोई ऐलान जारी न किया गया होता तो राजपंचायत को या राजपति को या ऐसे किसी अधिकारी को बनाने का अधिकार न होता, उसका अधिकार न होने की हद तक, ऐलान के अमल में न रहने के बाद एक बरस का अरसा बीत जाने पर, कोई असर नहीं रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो उस अरसे के बीत जाने से पहले ही की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों, जब तक कि वह बंधान जिनका असर इस तरह खतम हो जायगा पहले ही मुनासिब कानून सभा के एकट के जरिये रह न कर दिये गए हों या अदल बदल के साथ या बिना अदल बदल फिर से कानून न बना दिये गए हों.

358—उन दिनों जब कि अधानकी का कोई ऐलान अमल में हो, दफ्ता 19 की कोई बात, उस राज की जिसकी परिभाषा भाग तीन में की गई है, इस शक्ति में रुकावट नहीं डालेगी कि वह कोई ऐसा कानून बनाए या कोई ऐसा काजकारी काम करे जिसे, अगर भाग तीन के बन्धान न होते, तो उस राज को बनाने या करने का अधिकार होता, लेकिन इस तरह बने किसी कानून का अधिकार न होने की उस हद तक, ऐलान का अमल खतम होते ही कोई असर नहीं रहेगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो उस कानून के इस तरह असर न रहने से पहले ही की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों.

अधानकी के दौरान में दफ्ता 19 के बंधानों का मुअतल रहना

359—(1) जहां अधानकी का कोई ऐलान अमल में हो, वहां राजपति हुकुम दे कर यह जाहिर कर सकता है कि भाग तीन

अधानकियों के दौरान में भाग तीन

में दिये अधिकारों पर अमल का मुअत्तल रहना

में दिये अधिकारों में से उन पर अमल कराने के लिये जो उस हुकुम में बता दिये जायं, किसी अदालत से फरियाद करने का अधिकार उस अरसे तक मुअत्तल रहेगा, और इस तरह बताए अधिकारों पर अमल कराने के लिये किसी अदालत में जो कारवाइयां चल रही होंगी वह सब उस अरसे तक मुअत्तल रहेंगी जिस अरसे तक कि वह ऐलान अमल में रहे, या उस कम अरसे तक जो उस हुकुम में बताया जाय.

(2) ऊपर कहे अनुसार जो हुकुम दिया गया हो उसका फैज़ाव भारत के सारे भूभाग तक या उस भूभाग के किसी हिस्से तक हो सकता है.

(3) धारा (1) के अधीन दिया हुआ हर हुकुम, दिये जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राजपंचायत के हर सदन के सामने रखा जायगा.

माली अचानकी के बारे में बन्धान

360—(1) अगर राजपति को यह इतमीनान हो जाय कि ऐसी हालत पैदा हो गई है जिससे भारत का या उसके भूभाग के किसी हिस्से का माली टिकाव या उसकी साख खतरे में है, तो वह एक ऐलान निकाल कर इस बात को जाहिर कर सकता है.

(2) दफा 352 की धारा (2) के बन्धान इस धारा के अधीन निकले हुए किसी ऐलान के संबंध में उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वह दफा 352 के अधीन जारी हुए अचानकी के किसी ऐलान के संबंध में लागू होते हैं.

(3) उस अरसे के दौरान में जिसमें धारा (1) में बताया कोई ऐलान अमल में हो, यूनियन की काजकारी शक्ति के फैज़ाव में किसी रियासत को यह निर्देश देना शामिल होगा कि वह उचित माली ब्योहार के उन असूलों का ध्यान रखे जो उन निर्देशों में बताये गए हों, और ऐसे दूसरे निर्देश देना भी शामिल होगा जिन्हें राजपति इस मतलब के लिये जरूरी और काफ़ी समझे.

(4) इस विधान में किसी बात के रहते भी—

(ए) ऐसे किसी निर्देश में—

(एक) ऐसा बन्धान भी हो सकता है जिससे किसी रियासत

के मामलों के संबंध में नौकरी करनेवाले सब आदमियों या उनकी किसी जमात की तनखाहें और भत्ते घटाना दरकार हो;

(दो) ऐसा बन्धान भी हो सकता है जिससे उन सब नकदी बिलों या दूसरे बिलों को, जिन पर दफा 207 के बन्धान लागू होते हैं, रियासत की क्रानून सभा से पास होने के बाद राजपति के विचार के लिये अलग रखा जाना दरकार हो;

(बी) राजपति को यह अधिकार होगा, कि उस अरसे के दौरान में जब इस दफा के अधीन निकला हुआ कोई ऐलान अमल में हो वह यूनियन के मामलों के संबंध में नौकरी करनेवाले सब लोगों की या उनकी किसी जमात की, जिसमें आला अदालत और हाईकोर्टों के जज भी शामिल हो सकते हैं, तनखाहें और भत्ते घटाने के लिये निर्देश जारी करे.

---

## भाग उन्नीस

### फुटकर

राजपति और  
रियासतपतियों और  
राजप्रमुखों की  
रक्षा

361—(1) राजपति, या किसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख, अपने पद की शक्तियों से काम लेने और उस पद के फरजों को पूरा करने के लिये, या उन शक्तियों से काम लेने और उन फरजों को पूरा करने में जो कोई काम उसने किया हो या उसका किया माना जाता हो उसके लिये, किसी अदालत को जवाबदेह नहीं होगा:

शर्तें कि कोई ऐसी अदालत, पंच अदालत या संस्था, जिसे दफ्ता 61 के अधीन किसी दोशलेखे की जांच के लिये राजपंचायत के किसी सदन ने नियोजित हो या नामजद किया हो, राजपति के चलन की जाँच पड़ताल कर सकेगी :

और शर्तें कि इस धारा की किसी बात का यह मतलब नहीं समझा जायगा कि वह भारत सरकार के या किसी रियासत की सरकार के खिलाफ मुनासिब कारवाई करने के किसी आदमी के अधिकार पर रुकावट लगाती है.

(2) राजपति के, या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख के, खिलाफ उसकी पद-मियाद के अन्दर, किसी अदालत में किसी भी तरह की फौजदारी कारवाई न शुरू की जा सकेगी और न जारी रखी जा सकेगी.

(3) राजपति को, या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख को गिरफ्तार करने या कैद करने के लिये कोई हुकुमनामा उसकी पद-मियाद के अन्दर किसी अदालत से जारी नहीं किया जायगा.

(4) राजपति की या किसी रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख की पद-मियाद के अन्दर किसी अदालत में कोई ऐसी दीवानी कारवाई नहीं की जा सकेगी जिसमें राजपति से या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख से किसी ऐसे काम के बारे में

भरपाई का दावा किया गया हो जो काम राजपति या उस रियासत के रियासतपति या राजप्रमुख ने अपना पद संभालने से चाहे पहले या उसके बाद अपनी निजी हैसियत से किया हो, या जो उसका किया माना जाता हो, जब तक कि एक ऐसे लिखे हुए नोटिस को दिये दो महीने न बीत चुके हों जो राजपति या रियासतपति या राजप्रमुख को, जैसी सूरत हो, दिया गया हो, या उसके दफ्तर में छोड़ दिया गया हो, और जिसमें उस कारवाई की कैफियत, उसके किये जाने का कारन, जो फरीक कारवाई शुरू करने वाला है उसका नाम, ब्यौरा और रिहाइश की जगह और जिस भरपाई का वह दावा करता है वह सब बताए गए हों।

362—राजपंचायत की या किसी रियासत की कानून सभा की कानून बनाने की शक्ति से काम लेने में, या यूनियन या किसी रियासत की काजकारी शक्ति से काम लेने में, उस गारंटी या भरोसे का उचित लिहाज रखना होगा जो किसी देसी रियासत के शासक के निजी अधिकारों, निजनियमों और सम्मानों के बारे में किसी ऐसे मुआहदे या समझौते के अधीन दिया गया हो जिसकी चरचा दफा 291 की धारा (1) में की गई है।

363—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, पर दफा 143 के बन्धानों का ध्यान रखते हुए, किसी ऋगड़े में जो किसी ऐसे सन्धिनामे, समझौते, मुआहदे, इकरारनामे, सनद या दूसरे इसी तरह के पट्टे के किसी बन्धान से पैदा हुआ हो, जिसे किसी देसी रियासत के शासक ने इस विधान के आरंभ से पहले किया हो या लिखा हो, और जिसमें हिन्द डोमिनियन की सरकार या उसी जगह पर उससे पहले की कोई सरकार एक फरीक रही हो, और जो विधान के आरंभ होने के बाद भी अमल में रहा हो या रखा गया हो, या इसी तरह के किसी संधिनामे, समझौते, मुआहदे, इकरारनामे, सनद या इसी तरह के दूसरे पट्टे से संबंध रखने वाले इस विधान के बन्धानों में से किसी के अधीन मिलने वाले किसी अधिकार के बारे में या उस बन्धान से पैदा होने वाली किसी देनदारी या ज़िम्मेदारी के बारे में किसी तरह के ऋगड़े

देसी रियासतों के शासकों के अधिकार और निजनियम

कुछ सन्धिनामों, समझौतों वगैरा से पैदा होनेवाले ऋगड़ों में अदालतों के दखल देने पर रोक

में, न आला अदालत की अमलदारी चलेगी, न किसी दूसरी अदालत की.

(2) इस दफा में—

(ए) “देसी रियासत” के मानी हैं कोई भूभाग जिसे इस विधान के आरम्भ से पहले सम्राट ने या हिन्द डोमिनियन की सरकार ने इस तरह की रियासत मान लिया हो; और

(बी) “शासक” शब्द में वह नरेश, सरदार या दूसरा आदमी शामिल है जिसको विधान के आरम्भ से पहले सम्राट ने या हिन्द डोमिनियन की सरकार ने किसी देसी रियासत का शासक मान लिया हो.

बड़े बन्दरगाहों और  
हवाई अड्डों के  
लिये खास बंधान

364—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपति आम नोटिस निकालकर यह निर्देश कर सकता है कि उस तारीख से जो उस नोटिस में बताई गई हो—

(ए) राजपंचायत का या किसी रियासत की कानून सभा का बनाया कोई कानून किसी बड़े बन्दरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों या अदल बदल के साथ लागू होगा जो उस नोटिस में बता दिये जायं, या

(बी) किसी मौजूदा कानून का किसी बड़े बन्दरगाह या हवाई अड्डे में असर नहीं रहेगा सिवाय उन कामों के बारे में जो उस तारीख से पहले किये जा चुके हों या करने से छोड़ दिये गए हों, या ऐसे बन्दरगाह या हवाई अड्डे पर उस कानून का असर ऐसे अपवादों या अदल बदल के साथ होगा जो उस नोटिस में बता दिये जायं.

(2) इस दफा में—

(ए) “बड़ा बन्दरगाह” के मानी हैं वह बन्दरगाह जो राज-पंचायत के बनाए किसी कानून में या किसी मौजूदा कानून में या ऐसे किसी कानून के अधीन बड़ा

बन्दरगाह ठहरा दिया गया है, और उसमें वह सब क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय उस बन्दरगाह की सीमाओं के अन्दर शामिल हों;

(बी) “हवाई अड्डे” के मानी हैं वह हवाई अड्डा जिसकी परिभाषा हवा मार्गों, हवाई जहाजों और हवाई जहाजरानी से संबंध रखनेवाले कानूनों के मतलबों के लिये की गई है.

365—जहां कोई रियासत ऐसे किसी निर्देशों पर न चल सकी हो या अमल न करा सकी हो जो इस विधान के बन्धानों में से किसी के अधीन यूनियन की काजकारी शक्ति से काम लेते हुए दिये गए हों, तो राजपति के लिये यह क्रार देना कानून-संगत होगा कि ऐसी हालत पैदा हो गई है जिसमें उस रियासत की हुकूमत इस विधान के बन्धानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती.

यूनियन के दिये निर्देशों पर न चल सकने या उन पर अमल न कर सकने का असर

366—इस विधान में, जब तक कि प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, नीचे लिखे शब्दों के वह मानी हैं जो यहां उनमें से हर एक के अलग अलग दिये गए हैं, यानी यह कि—

परिभाषाएँ

(1) “खेती बाड़ी की आमदनी” के मानी हैं वह खेती बाड़ी की आमदनी जिसकी परिभाषा भारत आमदनी-टैक्स से संबंध रखनेवाले कानूनों के मतलबों के लिये की गई है;

(2) “ऐंग्लो इन्डियन” के मानी हैं वह आदमी जिसका बाप या जिसके बाप की लाइन में कोई और जनक पुरुष यूरोपियन नसल का है या था, पर जो भारत के भूभाग का निवासी बन गया है, और उस भूभाग के अन्दर ऐसे मां बाप से पैदा हुआ है या पैदा हुआ था जो केवल आरज़ी मतलबों के लिये यहाँ नहीं रहते थे बल्कि आदतन यहाँ के बासी थे;

(3) “दफ़ा” के मानी हैं इस विधान की कोई दफ़ा;

(4) “उधार लेने” में सालाना क्रिस्तों में अदायगी मंज़ूर करके रुपया जुटाना शामिल है, और “उधारी” के भी इसी तरह मानी किये जायेंगे;

(5) “धारा” के मानी हैं उस दफा की कोई धारा जिसमें यह शब्द आया हो;

(6) “एकतनी टैक्स” के मानी हैं आमदनी पर कोई टैक्स जहां तक कि वह टैक्स कम्पनियों को भरना है और जो ऐसा टैक्स है जिसमें नीचे लिखी शर्तें पूरी होती हैं :—

(ए) यह कि वह टैक्स खेती बाड़ी की आमदनी के बारे में नहीं लिया जा सकता;

(बी) यह कि उस टैक्स पर लागू होने वाले किसी कानून के जरिये किसी को यह अधिकार न हो कि कम्पनियां जो टैक्स दें उसके बारे में उन लाभ-बटावों में से रुपया काटा जाय जो कम्पनियां लोगों को देती हैं;

(सी) यह कि भारत आमदनी टैक्स के मतलब के लिये इस तरह के लाभ-बटावे पाने वाले लोगों की कुल आमदनी का हिसाब लगाने में, या उस भारत आमदनी टैक्स का हिसाब लगाने में जो इस तरह के लोगों को भरना है या जो उन्हें वापस मिलना है, इस तरह दिये हुए टैक्स को हिसाब में लेने के लिये कोई बन्धान नहीं है;

(7) “जवाबी सूबा”, “जवाबी देसी रियासत”, या “जवाबी रियासत” के मानी हैं, जहां शक हो, वह सूबा, देसी रियासत या रियासत जिसको राजपति उस खास मतलब के लिये जिसका सवाल उठा हो “जवाबी सूबा”, “जवाबी देसी रियासत” या “जवाबी रियासत”, जैसी सूरत हो, तय कर दे;

(8) “कर्जे” में पूँजी की रकमों को सालाना क्रिस्तों में अदा करने की किसी ज़िम्मेदारी के बारे में हर देनदारी और किसी गारंटी के अधीन हर देनदारी शामिल है, और “कर्जा खर्च” के मानी भी इसी तरह किये जायंगे ;

(9) “मिलकियत महसूल” के मानी हैं वह महसूल जो उस सब जायदाद की असल क्रीमत पर या असल क्रीमत के हिसाब से आंका जाय जो जायदाद किसी के मरने पर मिलकियत महसूल सम्बन्धी राजपंचायत के बताए कानूनों या किसी रियासत की कानून



सभा के बनाए कानूनों के बन्धानों के अधीन किसी को मिले या मिली समझी जाय; यह असल क्रीमत उन नियमों के अनुसार तय की जायगी जो ऊपर-लिखे कानूनों में या उनके अधीन बताए गए हों.

(10) "मौजूदा कानून" के मानी हैं कोई कानून, राज-हुकुम, हुकुम, छुट-कानून, नियम या क़ायदा जो इस विधान के आरंभ से पहले किसी ऐसी कानून सभा, किसी ऐसे अधिकारी या किसी ऐसे आदमी ने पास किया हो या बनाया हो जिसे ऐसा कानून, राज-हुकुम, हुकुम, छुट-कानून, नियम या क़ायदा बनाने की शक्ति है;

(11) "संघ अदालत" के मानी हैं वह संघ अदालत जो हिन्दू सरकार ऐक्ट 1935 के अधीन बनी थी ;

(12) "माल" में सब सामान, विज़ारती माल और चीज़ें शामिल हैं ;

(13) "गारंटी" में अदायगियां करने की हर वह ज़िम्मेदारी शामिल है जो इस विधान के जारी होने से पहले, किसी कार-बार में, किसी तय की हुई रकम से कम मुनाफ़े होने की सूरत में, अपने ऊपर ली गई हो;

(14) "हाईकोर्ट" के मानी हैं कोई अदालत जो इस विधान के मतलबों के लिये किसी रियासत की हाईकोर्ट समझी जाय, और उसमें—

(ए) भारत के भूभाग की हर वह अदालत शामिल होगी जो इस विधान के अधीन हाईकोर्ट बनाई गई हो, या फिर से हाईकोर्ट बनाई गई हो, और

(बी) भारत के भूभाग की हर वह दूसरी अदालत शामिल होगी जिसे राजपंचायत कानून बनाकर इस विधान के मतलबों में से सब या किसी के लिये हाईकोर्ट ठहरा दे.

(15) "देसी रियासत" के मानी हैं कोई भूभाग जिसे हिन्दू डोमिनियन की सरकार ने देसी रियासत माना हो.

(16) "भाग" के मानी हैं इस विधान का कोई भाग.

(17) "पेंशन" के मानी हैं हर तरह की पेंशन, चाहे

वह हिस्सेवारी हो या न हो, जो किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी है, और उसमें सेवा मुक्त लोगों की तनखाह जो किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी है, इनामी रकम जो किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी है, और कोई रकम या रकमों जो प्रोविडेंट फंड की जमा रकमों की वापसी के तौर पर, सूद समेत या बिना सूद या उसमें कुछ और रकम जोड़ कर या न जोड़ कर, किसी आदमी को या उसके बारे में दी जानी हैं, सब शामिल हैं;

(18) “अचानकी का ऐलान” के मानी हैं दफा 352 की धारा (1) के अधीन जारी हुआ कोई ऐलान;

(19) “ग्राम नोटिस” के मानी हैं भारत के गजट में या किसी रियासत के दफ्तरी गजट में, जैसी सूरत हो, निकला नोटिस;

(20) “रेल मार्ग” में—

(ए) वह ट्राम मार्ग शामिल नहीं है जो कुल किसी नगरायत क्षेत्र में हो, या

(बी) आवाजाई की कोई और ऐसी लाइन शामिल नहीं है जो कुल किसी एक रियासत में हो और जिसे राजपंचायत ने कानून बनाकर यह ठहरा दिया हो कि वह रेल मार्ग नहीं है;

(21) “राजप्रमुख” के मानी हैं—

(ए) हैदराबाद रियासत के संबंध में, वह आदमी जिसे उस समय राजपति ने हैदराबाद का निजाम मान लिया हो;

(बी) जम्मू और काश्मीर रियासत या मैसूर रियासत के संबंध में, वह आदमी जिसे उस समय राजपति ने उस रियासत का महाराजा मान लिया हो; और

(सी) पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी और रियासत के संबंध में, वह आदमी जिसे उस समय राजपति ने उस रियासत का राजप्रमुख मान लिया हो,

और इसमें उन रियासतों में से किसी के संबंध में वह आदमी भी

शामिल है जिसे उस समय राजपति ने उस रियासत के संबंध में राजप्रमुख की शक्तियों से काम लेने का अधिकारी मान लिया हो;

(22) "शासक" के किसी देसी रियासत के संबंध में मानी हैं वह नरेश, सरदार या दूसरा आदमी जिसने ऐसा कोई मुआहदा या समझौता किया हो जिसकी चरचा दफा 291 की धारा (1) में की गई है और जिसको राजपति ने उस समय उस रियासत का शासक मान लिया हो, और इसमें वह आदमी भी शामिल है जिसको उस समय राजपति ने उस शासक का वरिष्ठ मान लिया हो ;

(23) "पट्टी" के मानी हैं इस विधान के आख्यार की कोई पट्टी;

(24) "पट्टी-दर्ज जातों" के मानी हैं वे जातें, नसलें या कबीले, या उन जातों, नसलों या कबीलों के भाग, या उनमें के गिरोह, जिनको दफा 341 के अधीन इस विधान के मतलबों के लिये पट्टी-दर्ज जातें समझा गया है;

(25) "पट्टी-दर्ज कबीलों" के मानी हैं वह कबीले या कबायली समाज, या उन कबीलों या कबायली समाजों के भाग, या उनमें के गिरोह, जिनको दफा 342 के अधीन इस विधान के मतलबों के लिये पट्टी-दर्ज कबीले समझा गया है;

(26) "हुन्डियों" में पत्ती पूँजी शामिल है;

(27) "उप-धारा" के मानी हैं उस धारा की कोई उप-धारा जिसमें यह शब्द आया हो;

(28) "टैक्स लगाने" में हर टैक्स या महसूल का लगाना शामिल है, चाहे वह आम हो या मुकामी या खास, और "टैक्स" के भी इसी तरह मानी किये जायेंगे;

(29) "आमदनी पर टैक्स" में बढ़ती नफा टैक्स जैसा टैक्स शामिल है;

(30) "उप-राजप्रमुख" के, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत के संबंध में, मानी हैं वह आदमी जिसको उस समय राजपति ने उस रियासत का उप-राजप्रमुख मान लिया हो.

367—(1) जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, तब तक आम धारा एक्ट (जनरल क्लॉजेज़ एक्ट) 1897, ऐसे किन्हीं अनु-कूलनों और अदल बदल का ध्यान रखते हुए जो दफ़ा 372 के अधीन उसमें किये जायं, इस विधान के अर्थ करने में उसी तरह लागू होगा जिस तरह वह हिन्द डोमिनियन की क़ानून सभा के किसी एक्ट के अर्थ करने में लागू होता है.

(2) इस विधान में राजपंचायत के एक्टों या उसके बनाए हुए क़ानूनों की, या पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की क़ानून सभा के एक्टों या उसके बनाए हुए क़ानूनों की, किसी चरचा का यह मतलब लिया जायगा कि उसमें राजपति के दिये राजहुकुम की, या किसी रियासत-पति या राजप्रमुख के दिये राज हुकुम की, जैसी सूरत हो, चरचा शामिल है.

(3) इस विधान के मतलबों के लिये, “विदेशी राज” के मानी हैं भारत को छोड़ कर कोई और राज :

शर्तें कि, राजपंचायत के बनाए किसी क़ानून के बन्धानों के अधीन रहते हुए, राजपति हुकुम देकर, उन मतलबों के लिये जो उस हुकुम में बता दिये जायं, किसी राज की बाबत यह ठहरा सकता है कि वह विदेशी राज नहीं है.

---

## भाग बीस

### विधान में सुधार

368—इस विधान में किसी सुधार की शुरुआत केवल राज-पंचायत के किसी सदन में इस मतलब के लिये एक बिल रख कर ही की जा सकती है, और जब वह बिल हर सदन में, उस सदन के कुल मेम्बरों की बड़ीयत से, और सदन में उस समय मौजूद और वोट देने वाले मेम्बरों की कम से कम दो तिहाई की बड़ीयत से, पास हो जाय, तो उसे मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखा जायगा, और जब बिल पर इस तरह की मंजूरी मिल जाय तब उस बिल की शर्तों के अनुसार विधान में सुधार हो जायगा :

विधान में सुधार  
के लिये दस्तूर

शर्तें कि अगर उस सुधार से—

(ए) दफा 54, दफा 55, दफा 73, दफा 162, या दफा 241 में, या

(बी) भाग पांच के खंड चार, भाग छै के खंड पांच या भाग ग्यारह के खंड एक में, या

(सी) सातवीं पट्टी की किसी तालिका में, या

(डी) राजपंचायत में रियासतों के प्रतिनिधान में, या

(ई) इस दफा के बन्धानों में,

कोई तबदीली होती हो, तो यह भी दरकार होगा कि, उस सुधार के लिये बंधान करने वाले बिल को मंजूरी के लिये राजपति के सामने रखने से पहले, पहली पट्टी के भाग (ए) और (बी) में दर्ज रियासतों में से कम से कम आधी रियासतों को कानून सभाएँ, उस मतलब के ठहराव पास करके, उस सुधार की तसदीक कर दें.

## भाग इक्कीस

### आरज़ी और विचवक्ती बंधान

रियासत तालिका के कुछ मामलों के बारे में राज-पंचायत को क़ानून बनाने की आरज़ी शक्ति, मानो वह मामले संगचारी तालिका में हों

369—इस विधान में किसी बात के रहते भी, राजपंचायत को, इस विधान के आरंभ से पांच बरस के अरसे तक, नीचे लिखे मामलों के बारे में, उसी तरह क़ानून बनाने की शक्ति होगी मानो वह मामले संगचारी तालिका में गिनाए गए हों, यानी—

(ए) सूती और ऊनी कपड़ों, कच्ची रुई ( जिसमें ओटी और अनओटी रुई यानी कपास शामिल हैं), बिनौले, कागज (जिसमें न्यूज प्रिन्ट शामिल है), खाने की चीजें (जिसमें खाने के तिलहन और तेल शामिल हैं), ढोरों का चारा (जिसमें खली और दूसरे सार-चारे शामिल हैं), कोयला ( जिसमें कोक और कोयले से निकली चीजें शामिल हैं ), लोहा, फौलाद, और अबरक का किसी रियासत के अन्दर ब्योपार और तिज़ारत, और इन चीजों का पैदा करना, मुहय्या करना और बाँटना ;

(बी) धारा (ए) में बताए मामलों में से किसी से सम्बन्ध रखने वाले क़ानूनों के ख़िलाफ़ जुर्म, उन मामलों में से किसी के सम्बन्ध में आला अदालत को छोड़कर सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां, और उन मामलों में से किसी के सम्बन्ध में फ़ीसों, जिनमें किसी अदालत में ली जाने वाली फ़ीसें शामिल नहीं होंगी;

पर राजपंचायत का बनाया हुआ कोई क़ानून, जिसे इस दफ़ा के बन्धानों के न होने पर राजपंचायत बनाने की अधिकारी न होती, उस अधिकार न होने की हद तक, उस अरसे के बीत जाने पर बेअसर हो जायगा, सिवाय उन बातों के बारे में जो उस अरसे के बीत जाने से पहले ही की जा चुकी हों या करने से छोड़ दी गई हों.

370—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी,—

जम्मू और काश्मीर  
रियासत के संबंध  
में आरज़ी बंधान

(ए) दफ़ा 238 के बन्धान जम्मू और काश्मीर रियासत के संबंध में लागू नहीं होंगे ;

(बी) ऊपर कही रियासत के लिये क़ानून बनाने की राजपंचायत की शक्ति केवल—

(एक) यूनियन तालिका और संगचारी तालिका के उन मामलों तक होगी जिनकी बाबत, उस रियासत की सरकार से सलाह करके, राजपति यह ठहरा दे कि यह मामले उन मामलों से मेल रखने वाले मामले हैं जो उस मिलन-पट्टे में दर्ज हैं जिसके अधीन वह रियासत हिन्द डोमिनियन में मिली, और जिन्हें उस मिलन-पट्टे में वह मामले बताया गया है जिनके बारे में डोमिनियन क़ानून सभा उस रियासत के लिये क़ानून बना सकती है; और

(दो) उन तालिकाओं के उन दूसरे मामलों तक होगी जो राजपति, उस रियासत के सरकार की सहमती से, हुकुम जारी करके, बता दे.

समझाव—इस दफ़ा के मतलबों के लिये रियासत की सरकार के मानी हैं वह आदमी जिसको उस समय राजपति ने जम्मू और काश्मीर का महाराजा मान रखा हो और जो उस बज़ीर मंडल की सलाह से काम करता हो जो महाराजा के पांच मार्च सन् 1948 वाले ऐलान के अधीन उस समय पद पर हो.

(सी) दफ़ा (1) के और इस दफ़ा के बन्धान उस रियासत के संबंध में लागू होंगे;

(डी) इस विधान के दूसरे बन्धानों में से वह बन्धान उन अपवादों और अदल बदल के साथ उस रियासत के संबंध में लागू होंगे जो राजपति हुकुम देकर बता दे :

शर्तें कि कोई ऐसा हुकुम जिसका संबंध उस रियासत के उस मिलन-पट्टे में बताए मामलों से है, जिसकी चरचा उप-धारा (बी) के पैरा (एक) में की गई है, उस रियासत की सरकार से सलाह लिये बिना जारी नहीं किया जायगा :

और शर्तें कि कोई ऐसा हुकुम, जिसका संबंध उन मामलों को

छोड़कर जिनकी चरचा पिछली आखिरी शर्त में की गई है, किन्हीं और मामलों से है, उस रियासत की सहमती के बिना जारी नहीं किया जायगा.

(2) अगर रियासत की सरकार की वह सहमती, जिसकी चरचा धारा (1) की उप-धारा (बी) के पैरा (दो) में या उस धारा की उप-धारा (डी) की दूसरी शर्त में की गई है, उस रियासत का विधान बनाने के मतलब के लिये विधान सभा बुलाए जाने से पहले दे दी जाय, तो वह सहमती उस विधान सभा के सामने ऐसे फ़ैसले के लिये रखी जायगी जो फ़ैसला वह सभा उस पर करे.

(3) इस दफ़ा के उपर-लिखे बन्धानों में किसी बात के रहते भी, राजपति आम नोटिस निकाल कर यह ज़ाहिर कर सकता है कि यह दफ़ा अमल में नहीं रहेगी, या यह कि वह उस तारीख से केवल उन अपवादों और उन अदल बदल के साथ अमल में रहेगी जो राजपति बता दे:

शर्तें कि राजपति के ऐसा नोटिस निकालने से पहले उस रियासत की उस विधान सभा की सिफ़ारिश ज़रूरी होगी जिसकी चरचा धारा (2) में की गई है.

पहली पट्टी के भाग  
(बी) की रियासतों  
के बारे में भारती  
बन्धान

371—इस विधान में किसी बात के रहते भी, विधान के आरंभ से दस बरस के अरसे के अन्दर, या इससे अधिक या इससे कम उस अरसे के अन्दर जिसका राजपंचायत किसी रियासत के बारे में क़ानून बनाकर बन्धान करदे, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज हर रियासत की सरकार राजपति के आम दवान में रहेगी और उन खास निर्देशों पर चलेगी, अगर कोई ऐसे निर्देश हों तो, जो राजपति समय समय पर दे :

शर्तें कि राजपति हुकुम देकर निर्देश कर सकता है कि इस धारा के बन्धान उस हुकुम में बताई किसी खास रियासत पर लागू नहीं होंगे.

मौजूदा क़ानूनों का  
अमल जारी रहना  
और उनका अनु-  
कूलन

372—(1) दफ़ा 395 में जिन क़ानूनों की चरचा की गई है, इस विधान के ज़रिये उनके रद्द कर दिये जाने पर भी, पर इस विधान के दूसरे बन्धानों के अधीन रहते हुए, इस विधान के



आरंभ से ठीक पहले भारत के भूभाग में जितने क़ानून अमल में थे वह सब तब तक उस भूभाग में अमल में रहेंगे जब तक कोई अधिकारी क़ानून सभा या दूसरा हक़दार अधिकारी उन्हें बदल न दे या रह न कर दे या उनमें सुधार न कर दे.

(2) किसी ऐसे क़ानून के बन्धानों का जो भारत के भूभाग में अमल में हो इस विधान के बन्धानों के साथ मेल बिठाने के लिये, राजपति हुकुम देकर, उस क़ानून में, चाहे कुछ रद्द कर के, चाहे सुधार करके, ऐसे अनुकूलन और अदल बदल कर सकता है जो ज़रूरी या समयोचित हों, और यह बन्धान कर सकता है कि उस क़ानून का असर, उस तारीख़ से जो उस हुकुम में बताई जाय, उन अनुकूलनों और अदल बदल के अधीन होगा, और ऐसे किसी अनुकूलन या अदल बदल पर किसी अदालत में कोई सवाल नहीं उठाया जायगा.

(3) धारा (2) की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह—

(ए) राजपति को इस विधान के आरंभ होने से दो बरस बीत जाने के बाद किसी क़ानून में कोई अनुकूलन या अदल बदल करने की शक्ति देती है; या

(बी) किसी अधिकारी क़ानून सभा या किसी दूसरे हक़दार अधिकारी को उस क़ानून के रद्द करने या उसमें सुधार करने से रोकती है जिसमें उस धारा के अधीन राजपति ने अनुकूलन या अदल बदल किये हों.

**समझाव (1)**—इस दफ़ा में “अमल में क़ानून” शब्दों में वह क़ानून शामिल होगा जिसे इस विधान के आरंभ से पहले भारत के भूभाग के अन्दर किसी क़ानून सभा या दूसरे हक़दार अधिकारी ने पास किया हो या बनाया हो और जो इससे पहले रद्द न कर दिया गया हो, भले ही वह क़ानून या उसके कुछ भाग उस समय बिलकुल या किन्हीं खास क्षेत्रों में अमल में न हों.

**समझाव (2)**—भारत के भूभाग की किसी क़ानून सभा के या किसी दूसरे हक़दार अधिकारी के पास किये हुए या बनाए हुए ऐसे किसी क़ानून का जिसका इस विधान के आरंभ से ठीक पहले भारत

के भूभाग में असर था और भूभाग-परे भी असर था, उपर कहे किन्हीं अनुकूलनों और अदल बदल के अधीन, वह भूभाग-परे असर जारी रहेगा.

समझाव (3)—इस दफा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह किसी ऐसे आरज़ी क़ानून को जो अमल में हो उस तारीख के बाद भी जारी रखती है जो उसके अन्त होने के लिये तय है, या जिस तारीख पर वह क़ानून अन्त हो जाता अगर यह विधान अमल में न आया होता.

समझाव (4)—कोई राजहुकुम जो हिन्द सरकार एक्ट 1935 की दफा 88 के अधीन किसी सूबे के गवर्नर ने जारी किया हो, और जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में हो, अगर पहले ही जवाबी रियासत के रियासतपति ने उसे लौटा न लिया हो, तो विधान आरंभ होने के बाद दफा 382 की धारा (1) के अधीन काम करने वाले उस रियासत के आम सदन की पहली मिलनी से छै हफ्ते बीत जाने पर अमल में नहीं रहेगा, और इस दफा की किसी बात का यह मतलब नहीं लिया जायगा कि वह ऐसे किसी राजहुकुम को उस अरसे के बाद भी अमल में रखती है.

कुछ सूत्रों में उन लोगों के बारे में जो रोकथामी नजर-बन्दी में हैं हुकुम देने की राजपति को शक्ति

373—दफा 22 की धारा (7) के अधीन राजपंचायत के कोई बन्धान करने तक, या इस विधान के आरंभ से एक बरस बीत जाने तक, जो भी पहले हो, उस दफा का इस तरह असर होगा मानों उस दफा की धारा (4) और धारा (7) में राजपंचायत की चरचा की जगह राजपति की चरचा की गई है और उन धाराओं में राजपंचायत के बनाए क़ानून की चरचा की जगह राजपति के दिये हुकुम की चरचा की गई है.

सब अदालत के जजों के बारे में और सब अदालत में या कौंसिल समेत सम्राट के सामने चालू कार-वाइयों के बारे में बन्धान

374—(1) संघ अदालत के वह जज जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर, आला अदालत के जज हो जायंगे, और उसके बाद वह वही तनखाहें और भत्ते पाने के और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन्ही अधिकारों के हक़दार होंगे जिनका बन्धान दफा 125 में आला अदालत के जजों

के बारे में किया गया है.

(2) इस विधान के आरंभ के समय संघ अदालत में दीवानी या फौजदारी जो नालिशों, अपीलें और कारवाइयाँ, चालू हों वह सब वहाँ से उठ कर आला अदालत में आ जायंगी, और उन्हें सुनने और तय करने की अमलदारी आला अदालत को होगी, और इस विधान के आरंभ से पहले संघ अदालत ने जो फैसले सुना दिये हों या हुकुम दिये हों उनका बल और असर वही होगा मानो वह फैसले या हुकुम आला अदालत ने सुनाए या दिये हों.

(3) इस विधान की किसी बात का यह असर नहीं होगा कि वह कौंसिल समेत सम्राट के उस अमलदारी से काम लेने को ना-सरदुस्त ठहरा दे जो कौंसिल समेत सम्राट को भारत के भूभाग के अन्दर की किसी अदालत के किसी फैसले, डिगरी या हुकुम के खिलाफ अपीलें और उनके बारे में प्रार्थनापत्र निपटाने की हासिल है, जहां तक कि कानून उस अमलदारी से काम लेने का अधिकार देता है, और ऐसे किसी अपील या प्रार्थनापत्र पर इस विधान के आरंभ के बाद कौंसिल समेत सम्राट जो कोई हुकुम दे उसका सब मतलबों के लिये वही असर होगा मानो इस विधान से आला अदालत को जो अमलदारी सौंपी गई है उससे काम लेते हुए आला अदालत ने वह हुकुम दिया है या वह डिगरी की है.

(4) इस विधान के आरंभ होने पर और उसके बाद से, पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में प्रीवी कौंसिल की हैसियत से काम करने वाली किसी अधिकारी संस्था की वह अमलदारी नहीं रहेगी जो उसे उस रियासत के अन्दर किसी अदालत के किसी फैसले, डिगरी या हुकुम के खिलाफ अपीलें या उनके बारे में प्रार्थनापत्र लेने और निपटाने की रही हो, और विधान आरंभ होने पर उस अधिकारी संस्था के सामने जो अपीलें और दूसरी कारवाइयाँ चालू होंगी वह सब आला अदालत को तबदील कर दी जायंगी और वही उन्हें निपटायगी.

(5) इस दफा के बंधनों पर अमल कराने के लिये राज-पंचायत कानून बनाकर और भी बंधन कर सकती है.

इस विधान के बंधानों के अधीन रहते हुए अदायतों, अधिकारियों और अफसरों का काम करते रहना

हाईकोर्ट के जजों के बारे में बंधान

375—भारत के सारे भूभाग में, दीवानी, फौजदारी और माली अमलदारी वाली सब अदालतें, और सब न्यायी, काजकारी और बज्जीरायती अधिकारी और अफसर इस विधान के बंधानों के अधीन रहते हुए अपने अपने काम करते रहेंगे.

376—(1) दफा 217 की धारा (2) में किसी बात के रहते भी, किसी सूबे की हाईकोर्ट के वह जज जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर, जवाबी रियासत की हाईकोर्ट के जज हो जायेंगे, और इसके बाद वह वही तनखाहें और भत्ते पाने के और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन्हीं अधिकारों के हक़दार होंगे जिनका बंधान उस हाईकोर्ट के जजों के बारे में दफा 221 में किया गया है.

(2) पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत की हाईकोर्ट के जो जज इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुके हों, विधान आरंभ होने पर, इस तरह दर्ज रियासत की हाईकोर्ट के जज हो जायेंगे, और दफा 217 की धारा (1) और (2) में किसी बात के रहते भी, पर उस दफा की धारा (1) की शर्त के अधीन रहते हुए, वह उस अरसे के बीत जाने तक पद पर रहेंगे जो राजपति हुकुम देकर तय कर दे.

(3) इस दफा में “जज” शब्द में कारकर जज या अधिक जज शामिल नहीं हैं.

भारत के दाब अफसर और सरपड़-तालिया के बारे में बन्धान

377—हिन्द का वह सरपड़तालिया जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पद पर हो, जबतक कि वह खुद कोई दूसरा फ़ैसला न कर चुका हो, विधान के आरंभ होने पर भारत का दाब अफसर और सरपड़तालिया हो जायगा, और उसके बाद वह वही तनखाहें पाने का और छुट्टी और पेनशन के बारे में उन्ही अधिकारों का हक़दार होगा जिनका बन्धान दफा 148 की धारा (3) में भारत के दाब अफसर और सरपड़तालिया के बारे में किया गया है, और वह अपनी उस पद-मियाद के बीत

जाने तक पद पर रहने का हक्कदार होगा, जो पद-मियाद उन बन्धानों के अधीन तय की गई हो जो विधान के आरंभ से ठीक पहले उस पर लागू होते थे.

378—(1) हिन्द डोमिनियन के सरकारी नौकरी कमीशन के वह मेम्बर जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर यूनियन के सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर हो जायेंगे, और दफ्ता 316 की धारा (1) और (2) में किसी बात के रहते भी, पर उस दफ्ता की धारा (2) की शर्त के अधीन रहते हुए, अपनी उस पद-मियाद के बीत जाने तक पद पर रहेंगे जो पद-मियाद उन नियमों के अधीन तय की गई हो जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले उन मेम्बरों पर लागू होते थे.

सरकारी नौकरी  
कमीशन के बारे  
में बंधान

(2) किसी सूबे के सरकारी नौकरी कमीशन के वह मेम्बर या सूबों के किसी गुट की ज़रूरतें पूरी करने वाले सरकारी नौकरी कमीशन के वह मेम्बर जो, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, अपने पदों पर हों, जब तक कि वह खुद कोई दूसरा फैसला न कर चुके हों, विधान के आरंभ होने पर जवाबी रियासत के सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर या जवाबी रियासतों की ज़रूरतें पूरी करने वाले मिले-जुले रियासत सरकारी नौकरी कमीशन के मेम्बर, जैसी सूरत हो, हो जायेंगे, और दफ्ता 316 की धारा (1) और (2) में किसी बात के रहते भी, पर उस दफ्ता की धारा (2) की शर्त के अधीन रहते हुए, अपनी उस पद-मियाद के बीत जाने तक पद पर रहेंगे जो पद-मियाद उन नियमों के अधीन तय की गई हो जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले उन मेम्बरों पर लागू होते थे.

379—(1) जब तक इस विधान के बंधानों के अधीन राज-पंचायत के दोनों सदन क्रायदे से न बन जायें और उन्हें पहले इज-लास के लिये मिलने को न बुलाया जाय, तब तक वह संस्था जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा की हैसियत से काम कर रही थी कामचलाऊ राजपंचायत हो जायगी, और उन सब शक्तियों से काम लेगी, और उन सब

कामचलाऊ राज-  
पंचायत के और  
उसके सभामुख और  
उप-सभामुख के बारे  
में बंधान

फरजों को पूरा करेगी, जो इस विधान के बंधानों से राजपंचायत को सौंपे गए हैं.

**समझाव—**इस धारा के मतलबों के लिये हिन्द डोमिनियन की विधान सभा में—

(एक) वह मेम्बर जो किसी ऐसी रियासत या दूसरे भूभाग का प्रतिनिधान करने के लिये चुने गए हैं जिसके प्रतिनिधान का बन्धान धारा (2) में किया गया है, और

(दो) वह मेम्बर जो उस सभा में औसरी सूनियां भरने के लिये चुने गए हैं,

शामिल हैं.

(2) राजपति नियम बनाकर—

(ए) धारा (1) के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत में, किसी ऐसी रियासत या दूसरे भूभाग के प्रतिनिधान का, जिसका इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की विधान सभा में कोई प्रतिनिधि नहीं था,

(बी) उस ढंग का जिस ढंग पर कामचलाऊ राजपंचायत में ऐसी रियासतों या दूसरे भूभागों के प्रतिनिधि चुने जायंगे, और

(सी) उन जोगताओं का जो ऐसे प्रतिनिधियों में होनी चाहियें, बन्धान कर सकता है.

(3) अगर हिन्द डोमिनियन की विधान सभा का कोई मेम्बर, अक्टूबर सन् 1949 के छठे दिन या उसके बाद इस विधान के आरंभ से पहले किसी समय भी, किसी गवरनरी सूबे की कानून सभा के किसी सदन का, या पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की जवाबी देसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन का, मेम्बर था, या ऐसी किसी रियासत का कोई वजीर था, तो इस विधान के आरंभ होने के बाद से ही विधान सभा में उस मेम्बर की सीट सूनी हो जायगी, जब तक कि इससे पहले ही विधान सभा की उसकी मेम्बरी खतम न हो गई हो, और हर ऐसी

सूनी को औसरी सूनी समझा जायगा.

(4) इस बात के होते भी कि हिन्द डोमिनियन की विधान सभा में ऐसी कोई सूनी जो धारा (3) में बताई गई है उस धारा के अधीन अभी पैदा नहीं हुई है, उस सूनी को भरने के लिये इस विधान के आरंभ से पहले ही क्रम उठाए जा सकते हैं, पर ऐसी सूनी को भरने के लिये विधान के आरंभ से पहले जो आदमी चुना जायगा वह उस सभा में अपनी सीट लेने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह सूनी इस तरह पैदा न हो गई हो.

(5) कोई आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले विधान सभा के सभामुख या उप-सभामुख के पद पर हो, उस समय जब कि विधान सभा हिन्द सरकार एक्ट 1935 के अधीन डोमिनियन कानून सभा की हैसियत से काम कर रही थी, विधान आरंभ होने पर, धारा (1) के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत का सभामुख या उप-सभामुख, जैसी सूरत हो, हो जायगा.

380—(1) वह आदमी जिसको हिन्द डोमिनियन की विधान सभा ने इस काम के लिये चुना होगा उस समय तक के लिये भारत का राजपति होगा जब तक कि भाग पांच के खंड एक में दिये बंधानों के अनुसार कोई राजपति न चुना जाय और वह अपना पद न संभाल ले.

राजपति के बारे में  
बंधान

(2) हिन्द डोमिनियन की विधान सभा ने जिस आदमी को इस तरह राजपति चुना हो, उसके मर जाने, इस्तीफा देने या हटाए जाने या किसी दूसरे कारण से उसका पद सूना हो जाने की सूरत में, उस सूनी को वह आदमी भरेगा जिसको दफ्ता 379 के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत इस काम के लिये चुने, और जब तक कोई आदमी इस तरह नहीं चुना जाता तब तक भारत का सर जज राजपति का काम करेगा.

381—वह आदमी जिनको राजपति इस काम के लिये नियोजे, इस विधान के अधीन राजपति के वज़ीर मंडल के मेम्बर हो जायंगे और जब तक इस तरह के नियोजन नहीं किये जाते तब तक वह

राजपति का वज़ीर  
मंडल

सब आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनि-यन के वज्जीरों की हैसियत से अपने पद पर थे, विधान आरंभ होने पर, विधान के अधीन राजपति के वज्जीर मंडल के मेम्बर हो जायेंगे और अपने पदों पर बने रहेंगे.

पहली पट्टी के भाग (ए) की रियासतों के लिये काम चलाऊ कानून सभाओं के बारे में बंधान

382—(1) पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज हर रियासत की कानून सभा का सदन या उसके दोनों सदन जब तक इस विधान के बंधानों के अधीन क्रायदे से न बन जायें और उस सदन को या उन सदनों को पहले इजलास के लिये मिलने को न बुलाया जाय, तब तक जवाबी सूबे की कानून सभा का वह सदन या उसके वह सदन जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले काम कर रहा था या कर रहे थे, उन शक्तियों से काम लेगा या लेंगे और उन फ़रजों को पूरा करेगा या करेंगे जो इस विधान के बंधानों से उस रियासत की कानून सभा के सदन या सदनों को सौंपे गए हैं.

(2) धारा (1) में किसी बात के रहते भी, जहाँ कहीं इस विधान के आरंभ से पहले किसी सूबे के आम सदन (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के फिर से बनने के लिये आम चुनाव का हुकुम दिया जा चुका है, वहाँ विधान के आरंभ के बाद वह चुनाव इस तरह पूरा किया जा सकता है मानो यह विधान अमल में आया ही न हो, और जो आम सदन इस तरह फिर से बने वह उस धारा के मतलबों के लिये उस सूबे का आम सदन समझा जायगा.

(3) कोई आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले किसी सूबे के आमसदन (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के सभामुख या उप-सभामुख या खास सदन (लेजिस्लेटिव कौंसिल) के सदर या नायब सदर के पद पर हो, इस विधान के आरंभ पर, पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज जवाबी रियासत के आम सदन का सभामुख या उप-सभामुख या खास सदन का मसनदी या उप-मसनदी, जैसी सूरत हो, होगा, जब तक कि वह आम सदन या खास सदन धारा (1) के अधीन काम करे:

शर्तें कि जहाँ इस विधान के आरंभ से पहले किसी सूबे के आम सदन के फिर से बनने के लिये आम चुनाव का हुकुम दे दिया गया



है और इस तरह फिर से बने आम सदन की पहली मिलनी विधान आरंभ होने के बाद होती है तो इस धारा के बंधन लागू नहीं होंगे, और इस तरह फिर से बना आम सदन अपने दो मेम्बरों को अलग अलग सदन का सभामुख और उप-सभामुख चुन लेगा.

383—कोई आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले किसी सूबे के गवर्नर के पद पर हो, विधान आरंभ होने पर पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज जवाबी रियासत का रियासतपति होगा, जब तक कि भाग छै के खंड दो के बंधनों के अनुसार नए रियासतपति का नियोजन न हो जाय और वह अपना पद न संभाल ले.

384—वह आदमी जिनको किसी रियासत का रियासतपति इस काम के लिये नियोजे इस विधान के अधीन रियासतपति के वजीर मंडल के मेम्बर हो जायेंगे और जब तक इस तरह नियोजन नहीं किये जाते तब तक वह सब आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे के वजीरों के पद पर थे, विधान आरंभ होने पर इस विधान के अधीन उस रियासत के रियासतपति के वजीर मंडल के मेम्बर हो जायेंगे और अपने पदों पर बने रहेंगे.

385—जब तक पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत की कानून सभा का सदन या दोनों सदन इस विधान के बन्धानों के अधीन क्रायदे से न बन जायें और पहले इजलास के लिये मिलने को न बुलाए जायें, तब तक वह संस्था या अधिकारी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत की कानून सभा की हैसियत से काम कर रही थी या कर रहा था उन शक्तियों से काम लेगी या लेगा और वह फरज पूरे करेगी या करेगा जो इस तरह दर्ज रियासत की कानून सभा के सदन या सदनों को इस विधान के बन्धानों से सौंपे गए हैं.

386—वह आदमी, जिनको पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत का राजप्रमुख इस काम के लिये नियोजे, इस विधान के अधीन उस राजप्रमुख के वजीर मंडल के मेम्बर हो जायेंगे, और जब तक इस तरह के नियोजन नहीं किये जाते तब तक वह सब

सूबों के गवर्नरों के बारे में बंधन

रियासतपतियों के वजीर मंडल

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों में काम-चलाऊ कानून सभाओं के बारे में बन्धान

पहली पट्टी के भाग (बी) की रियासतों के लिये वजीर मंडल

आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत के वज्जीरों के पद पर थे, विधान आरंभ होने पर, इस विधान के अधीन, उस राजप्रमुख के वज्जीर मंडल के मेम्बर हो जायेंगे और अपने पदों पर बने रहेंगे.

कुछ चुनावों के मतलबों के लिये आबादी तय करने के बारे में खास बन्धान

387—इस विधान के आरंभ से तीन बरस के अरसे के अन्दर, इस विधान के बंधानों में से किसी के अधीन होने वाले चुनावों के मतलबों के लिये, भारत की या उसके किसी भाग की आबादी, इस विधान में किसी बात के रहते भी, उस ढंग से तय की जा सकती है जिसका राजपति हुक्म दे कर निर्देश करे, और ऐसे हुक्म में अलग अलग रियासतों के लिये और अलग अलग मतलबों के लिये अलग अलग बंधान किये जा सकते हैं.

कामचलाऊ राज-पंचायत में और रियासतों की काम-चलाऊ कानून सभाओं में औसरी सूनियों को भरने के बारे में बन्धान

388—(1) दफा 379 की धारा (1) के अधीन काम करने वाली कामचलाऊ राजपंचायत के मेम्बरों की सीटों में औसरी सूनियों का भरा जाना, जिनमें उस दफा की धारा (3) और (4) में जिन सूनियों की चरचा की गई है वह शामिल होंगी, और उन सूनियों को भरने के संबंध में सब मामलों की कायदाबन्दी ( जिनमें ऐसी सूनियों को भरने के चुनावों से पैदा होने वाली या उनके संबंध में शंकाओं और फगड़ों का फैसला शामिल है )—

(ए) उन नियमों के अनुसार होगी जो राजपति इस काम के लिये बनाए, और

(बी) जब तक इस तरह नियम नहीं बनते तब तक उन नियमों के अनुसार होगी जो, हिन्दू डोमिनियन की विधान सभा में, औसरी सूनियों को भरने और उससे संबंध रखने वाले मामलों के बारे में, इन सूनियों को भरने के समय या इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, जैसी सूरत हो, अमल में हों, उन नियमों में ऐसे अपवादों और अदल बदल का ध्यान रखते हुए जो विधान के आरंभ से पहले विधान सभा का सदर और उसके बाद भारत का राजपति उन में कर दे :

शर्तें कि जहाँ ऐसी किसी सीट पर, जिसकी चरचा इस धारा में

की गई है, सूनी होने से ठीक पहले, किसी सूबे का या जैसी सूरत हो पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियासत का कोई प्रतिनिधि किसी पट्टी-दर्ज जाति का या मुसलिम समाज का या सिख समाज का हो वहां जब तक विधान सभा का सदर या भारत का राजपति, जैसी सूरत हो, दूसरी तरफ का बन्धान करना जरूरी या समयोचित न समझे तब तक उस सीट को भरने वाला आदमी उसी समाज का होगा :

और शर्तें कि पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज किसी रियासत के या किसी सूबे के प्रतिनिधि की सीट की ऐसी किसी सूनी को भरने के लिये जो चुनाव किया जाय उसमें उस सूबे के, या उस जवाबी रियासत के, या उस रियासत के, जैसी सूरत हो, आम सदन का हर मेम्बर भाग लेने और वोट देने का हकदार होगा;

समझाव—इस धारा के मतलबों के लिये—

(ए) उन सब जातों, नसलों या कबीलों को, या उन जातों, नसलों या कबीलों के भागों को, या उनके अन्दर के गिरोहों को, जिनको हिन्द सरकार (पट्टी दर्ज जातें) हुकुम, 1936, में, किसी सूबे के संबंध में पट्टी-दर्ज जातें बताया गया है, उस सूबे के या उसकी जवाबी रियासत के संबंध में तब तक पट्टी-दर्ज जातें समझा जायगा जब तक कि राजपति ने दफा 341 की धारा (1) के अधीन एक नोटिस जारी न कर दिया हो जिसमें उस जवाबी रियासत के संबंध की पट्टी-दर्ज जातें बता दी गई हों;

(बी) किसी सूबे या रियासत में सारी पट्टी दर्ज जातों को एक समाज समझा जायगा.

(2) दफा 382 या दफा 385 के अधीन काम करने वाली किसी रियासत की कानून सभा के किसी सदन के मेम्बरों की सीटों में औसरी सूनियों को उन बंधानों के अनुसार भरा जायगा और ऐसी सूनियों को भरने के संबंध के सब मामलों की (जिनमें ऐसी सूनियों को भरने के चुनावों से पैदा होने वाली या उनके संबंध में शंकाओं और झगड़ों का फैसला शामिल है) कायदाबन्दी

उन बन्धानों के अनुसार की जायगी जिनके अधीन ऐसी सूनियां भरी जाती थीं और जिनसे ऐसे मामलों की क्रायदाबन्दी होती थी, और जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले अमल में थे, पर उन अपवादों और अदल बदल का ध्यान रखते हुए जिनका राजपदि हुकुम दे कर निर्देश कर दे.

डोमिनियन कानून सभा में और सबों और देसी रियासतों की कानून सभाओं में पेश बिलों के बारे में बन्धान

389—कोई बिल जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द डोमिनियन की कानून सभा में या किसी सूबे या देसी रियासत की कानून सभा में पेश था, इस बात के खिलाफ किसी ऐसे बन्धान का ध्यान रखते हुए जो इस विधान के अधीन राजपंचायत के या जवाबी रियासत की कानून सभा के बनाए नियमों में शामिल हो, राजपंचायत में या जवाबी रियासत की कानून सभा में, जैसी सूरत हो, उसी तरह चालू रह सकता है मानो हिन्द डोमिनियन की कानून सभा में या उस सूबे या उस देसी रियासत की कानून सभा में उस बिल के सम्बन्ध में जो कारबाइयां की गई थीं वह राजपंचायत में या जवाबी रियासत की कानून सभा में की गई हों.

विधान के आरंभ और 31 मार्च सन् 1950 के बीच जो रकमें मिलें या जुटाई जाय या जो खर्च किया जाय

390—इस विधान के जो बन्धान भारत के मूठकोश या किसी रियासत के मूठकोश से संबंध रखते हैं, और जो इनमें से किसी कोश से रकमों को खर्च की मदों में डालने से संबंध रखते हैं वह उन रकमों के या उस खर्च के संबंध में नहीं लागू होंगे जो रकमों भारत सरकार को या किसी रियासत की सरकार को इस विधान के आरंभ और मार्च सन् 1950 के इकतीसवें दिन के बीच, इन दोनों दिनों को लेकर, मिलें, या जिन्हें वह जुटावे, या जो खर्च वह करे, और इस अरसे में जो खर्च किया जायगा वह क्रायदे से अधिका हुआ समझा जायगा अगर वह खर्चा अधिकारे खर्च की किसी ऐसी पट्टी में दर्ज था जिसको हिन्द सरकार एक्ट, 1935, के बंधानों के अनुसार हिन्द डोमिनियन के गवरनर जनरल ने या जवाबी सूबे के गवरनर ने सही कर दिया था, या ऐसा खर्चा है जिसे उस रियासत के राजप्रमुख ने उन नियमों के अनुसार अधिकारा है जो नियम इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत

की मालगुजारी में से खर्चा अधिकार जाने पर लागू थे.

391—(1) अगर इस विधान के पास होने और उसके आरंभ होने के बीच किसी समय, हिन्द सरकार एक्ट, 1935, के बंधानों के अधीन कोई ऐसी कारवाई की जाय जिससे राजपति की राय में पहली पट्टी और चौथी पट्टी में कोई सुधार दरकार हो, तो राजपति, इस विधान में किसी बात के रहते भी, हुकुम देकर उन पट्टियों में इस तरह के सुधार कर सकता है जो उस कारवाई पर अमल कराने के लिये जरूरी हों, और ऐसे किसी हुकुम में ऐसे पूरक, प्रसंगी और परिनामी बंधान भी हो सकते हैं जिन्हें राजपति जरूरी समझे.

(2) जब पहली पट्टी या चौथी पट्टी में इस तरह सुधार हो जाय, तो इस विधान में उस पट्टी की जहां कहीं चरचा की गई है उससे यह मतलब लिया जायगा कि वह इस तरह सुधारी हुई पट्टी की ही चरचा है.

392—(1) राजपति किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के मतलब से, खासकर उन कठिनाइयों को जो हिन्द सरकार एक्ट 1935 के बन्धानों से हटकर इस विधान के बन्धानों तक आने से संबंध रखती हैं, हुकुम देकर निर्देश कर सकता है कि उस अरसे के दौरान में, जो उस हुकुम में बताया जाय, इस विधान पर उन अनुकूलनों के अधीन अमल होगा जिन्हें राजपति जरूरी या समयोचित समझे, चाहे उन अनुकूलनों के जरिये इस विधान में कुछ अदल बदल की गई हो, या जोड़ा गया हो, या छोड़ दिया गया हो:

शर्तें कि भाग पाँच के खंड दो के अधीन क़ायदे से बनी राजपंचायत की पहली मिलनी के बाद इस तरह का कोई हुकुम नहीं दिया जायगा.

(2) हर हुकुम जो धारा (1) के अधीन दिया जाय राज-पंचायत के सामने रखा जायगा.

(3) इस दफ़ा से, दफ़ा 324 से, दफ़ा 367 की धारा (3) से और दफ़ा 391 से जो शक्तियां राजपति को सौंपी गई हैं उनसे इस विधान के आरंभ से पहले हिन्द डोमिनियन का गवरनर जनरल काम ले सकेगा.

कुछ जोगाजोगों में राजपति को पहली और चौथी पट्टियों में सुधार करने की शक्ति

कठिनाइयों को दूर करने की राजपति की शक्ति

## भाग बाईस

### छोटा सरनामा, आरंभ, और रद्द

छोटा सरनामा  
आरम्भ

393—इस विधान को भारत का विधान कहा जाय

394—यह दफा और दफा 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 फौरन अमल में आ जायंगी, और इस विधान के बाकी बंधान जनवरी सन 1950 के छब्बीसवें दिन अमल में आयंगे; उस दिन की, इस विधान में, इस विधान का आरंभ कह कर चरचा की गई है.

रद्द

395—हिन्दू आज़ादी एक्ट 1947, और हिन्दू सरकार एक्ट 1935, उन सब क़ानूनों के साथ जो हिन्दू सरकार एक्ट 1935 में सुधार करते हैं, या उसके पूरक हैं, इस दफा से रद्द किये जाते हैं, पर उन क़ानूनों में प्रीवी कौंसिल अमलदारी अन्त एक्ट, 1949, शामिल नहीं है.

---

## पहली पट्टी

( दफा 1, 4 और 391 )

भारत की रियासतें और उसके भूभाग

भाग ( ए )

रियासतों के नाम	जवाबी सूबों के नाम
1. आसाम	आसाम
2. बिहार	बिहार
3. बम्बई	बम्बई
4. मध्यप्रदेश	मध्य प्रान्त और बरार
5. मद्रास	मद्रास
6. उड़ीसा	उड़ीसा
7. पंजाब	पूरब पंजाब
8. युक्त प्रान्त	युक्त प्रान्त
9. पच्छिम बंगाल	पच्छिम बंगाल

### रियासतों के भूभाग

आसाम रियासत के भूभाग में वह भूभाग शामिल होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले आसाम के सूबे, खासी रियासतों और आसाम क्वायली क्षेत्रों में शामिल थे.

पच्छिम बंगाल की रियासत के भूभाग में वह भूभाग शामिल होगा जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले पच्छिम बंगाल के सूबे में शामिल था.

इस भाग की दूसरी रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह भूभाग शामिल होंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे में और उन भूभागों में शामिल थे जिनका शासन हिन्द सरकार एक्ट 1935 की दफा 290 (ए) के अधीन बने हुकुम की रू से विधान के आरंभ से ठीक पहले इस तरह किया जाता था मानो वह उस सूबे के भाग हैं.

## भाग ( बी )

## रियासतों के नाम

1. हैदराबाद
2. जम्मू और काश्मीर
3. मध्य भारत
4. मैसूर
5. पटियाला और पूरब पंजाब रियासत यूनियन
6. राजस्थान
7. सौराष्ट्र
8. द्रावन्कोर - कोचीन
9. विन्ध्य प्रदेश

## रियासतों के भूभाग

इस भाग की रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह भूभाग शामिल होगा जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत में शामिल था, और—

(ए) राजस्थान और सौराष्ट्र रियासतों में से हर एक की सूरत में उनमें वह भूभाग भी शामिल होंगे जिनका शासन विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी देसी रियासत की सरकार, चाहे सूबा-परे अमलदारी एक्ट 1947 के बन्धानों के अधीन, या दूसरी तरह, करती थी ; और

(बी) मध्यभारत रियासत की सूरत में उसमें वह भूभाग भी शामिल होगा जो विधान के आरंभ से ठीक पहले चीफ कमिश्नर के सूबे पंथ पिपलोदा में शामिल था.

## भाग ( सी )

## रियासतों के नाम

1. अजमेर
2. भोपाल
3. बिलासपुर



4. कूच बिहार
5. कुर्ग
6. दिल्ली
7. हिमाचल प्रदेश
8. कच्छ
9. मनीपुर
10. त्रिपुरा

### रियासतों के भूभाग

अजमेर, कुर्ग और दिल्ली रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह वह भूभाग शामिल होगा जो, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और दिल्ली के चीफ कमिशनरी सूबों में अलग अलग शामिल था।

इस भाग की दूसरी रियासतों में से हर एक के भूभाग में वह वह भूभाग शामिल होगा जिनका शासन, हिन्द सरकार एक्ट 1935 की दफा 290 (ए) के अधीन बने हुकुम की रू से, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, इस तरह किया जाता था मानो वह भूभाग उसी नाम का चीफ कमिशनरी सूबा हैं।

भाग (डी)

अन्दमान और निकोबार टापू.

## दूसरी पट्टी

[ दफ्ता 59 (3), 65 (3), 75 (6), 97, 125, 148 (3), 158 (3), 164 (5), 186 और 221 ] .

भाग (ए)

### राजपति के और पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के रियासतपतियों के बारे में बंधान

1—राजपति को और पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के रियासतपतियों को हर महीने नीचे लिखे वेतन दिये जायेंगे, यानी—

राजपति ..... 10,000 रुपए

रियासत का रियासतपति ..... 5,500 रुपए

2—राजपति को और इस तरह दर्ज रियासतों के रियासतपतियों को वह भत्ते भी दिये जायेंगे जो, इस विधान के आरंभ से ठीक पहले, हिन्दू डोमिनियन के गवर्नर जनरल को और जवाबी सूबों के गवर्नरों को अलग अलग देने होते थे.

3—राजपति और ऐसी रियासतों के रियासतपति अपनी अपनी पद-मियाद भर में उन्हें निजनियमों के हकदार होंगे जिनके गवर्नर जनरल और जवाबी सूबों के गवर्नर अलग अलग इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हकदार थे.

4—जब उप-राजपति या कोई दूसरा आदमी राजपति के कामों को निभार रहा हो, या राजपति की जगह काम कर रहा हो, या कोई आदमी रियासतपति के कामों को निभार रहा हो, तो वह उन्हीं वेतनों, भत्तों और निजनियमों का हकदार होगा जिनका वह राजपति या वह रियासतपति हकदार था जिसके कामों को वह निभार रहा है या जिसकी जगह वह काम कर रहा है, जैसी सूरत हो.

भाग (बी)

**यूनियन के और पहली पट्टी के भाग (ए) और भाग (बी)  
की रियासतों के वज्जियों के बारे में बंधान**

5—यूनियन के प्रधान वज्जीर को और दूसरे वज्जीरों में से हर एक को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्दू डोमिनियन के प्रधान वज्जीर को और दूसरे वज्जीरों में से हर एक को अलग अलग देने होते थे.

6—पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज हर रियासत के वज्जीरों को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे या जवाबी देशी रियासत के वज्जीरों को, जैसी सूरत हो, देने होते थे.

भाग (सी)

**लोक सदन के सभामुख और उप-सभामुख, रियासतसदन  
के मसनदी और उप-मसनदी, पहली पट्टी के भाग  
(ए) की हर रियासत के आमसदन के सभामुख और  
उप-सभामुख, और ऐसी हर रियासत के खास सदन  
के मसनदी और उप-मसनदी के बारे में बंधान**

7—लोक सदन के सभामुख और रियासत सदन के मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्दू डोमिनियन की विधानसभा के सभामुख को देने होते थे, और लोक सदन के उप-सभामुख और रियासत सदन के उप-मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो विधान आरंभ होने से ठीक पहले हिन्दू डोमिनियन की विधान सभा के उप-सभामुख को देने होते थे.

8—पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज हर रियासत के आम सदन के सभामुख और उप-सभामुख को और उस रियासत के खास सदन के मसनदी और उप-मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे के आम सदन (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) के सभामुख और उप-सभा-

मुख को और खाससदन (लेजिस्लेटिव कौंसिल) के सदर और नायब सदर को अलग अलग देने होते थे, और जहाँ विधान आरंभ होने से ठीक पहले जवाबी सूबे में लेजिस्लेटिव कौंसिल नहीं थी वहाँ उस रियासत के खास सदन के मसनदी और उप-मसनदी को वह तनखाहें और भत्ते दिये जायेंगे जो उस रियासत का रियासतपति तय करे.

भाग (डी)

**आला अदालत के जजों के बारे में और पहली पट्टीके  
भाग (ए) की रियासतों की हाईकोर्टों के जजों के  
बारे में बंधान**

9—(1) आला अदालत के जजों को, जितने दिनों वह असल नौकरी पर रहें उतने दिनों के बारे में, हर महीने नीचे लिखी दर से तनखाह दी जायगी, यानी —

सरजज ..... 5, 000 रुपए

हर दूसरा जज ..... 4, 000 रुपए

शर्तें कि अगर आला अदालत के किसी जज को उसके नियोजन के समय, हिन्द सरकार के अधीन, या उस जगह उससे पहले की सरकारों में से किसी के अधीन, या किसी रियासत की सरकार के अधीन, या उस जगह उससे पहले की सरकारों में से किसी के अधीन, किसी पहले की नौकरी के बारे में, (अपाहिजी पेनशन या घायल पेनशन को छोड़ कर) कोई पेनशन मिलती हो तो आला अदालत की नौकरी की उसकी तनखाह में से उस पेनशन की रकम के बराबर रकम कम कर दी जायगी.

(2) आला अदालत का हर जज, बिना किराया दिये, सरकारी मकान के इस्तेमाल का हकदार होगा.

(3) इस पैरा के उप-पैरा (2) की कोई बात किसी ऐसे जज पर, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले,—

(ए) संघ अदालत के सरजज के पद पर था और विधान आरंभ होने पर दफ्ता 374 की धारा (1) के अधीन आला अदालत का सरजज हो गया है, या

(बी) संघ अदालत के किसी दूसरे जज की हैसियत से पद पर

था और विधान आरंभ होने पर उस धारा के अधीन आला अदालत का (सर जज को छोड़कर कोई दूसरा) जज हो गया है,

उस अरसे के दौरान में जब वह इस तरह के सरजज या दूसरे जज की हैसियत से पद पर रहे, लागू न होगी, और हर वह जज, जो इस तरह आला अदालत का सरजज या दूसरा जज हो जाय, उतने दिनों के बारे में जितने दिन वह सरजज या दूसरे जज की हैसियत से, जैसी सूरत हो, जितने दिन वह असल नौकरी पर रहे, इस पैरा के उप-पैरा (1) में बताई तनखाह के अलावा एक खास तनखाह के रूप में वह रकम पाने का हकदार होगा जो इस तरह बताई तनखाह और इस विधान के आरंभ से ठीक पहले उसे मिलने वाली तनखाह के फरक के बराबर है.

(4) आला अदालत का हर जज भारत के भूभाग के अन्दर सरकारी काम पर सफर करने में जो खर्च करेगा उसको पूरा करने के लिये उसे वह उचित भत्ते मिलेंगे और सफर के संबंध में उसे वह उचित सुविधाएँ दी जायंगी जो राजपति समय समय पर तय करे.

(5) आला अदालत के जजों को छुट्टी ( छुट्टी के भत्तों समेत ) और पेनशन के बारे में अधिकार उन बंधानों के अधीन रहेंगे जो इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले संघ अदालत के जजों पर लागू थे.

10—(1) पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज हर रियासत की हाई-कोर्ट के जजों को जितने दिनों वह असल नौकरी पर रहें, उतने दिनों के बारे में हर महीने नीचे लिखी दर से तनखाहें दी जायंगी यानी —

सरजज	...	...	...	4,000 रुपए
हर दूसरा जज	...	...	...	3,000 रुपए

(2) हर वह आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले—

(ए) किसी सूबे में किसी हाईकोर्ट के सरजज के

पद पर था और विधान आरंभ होने पर दफ्ता 376 की धारा (1) के अधीन जवाबी रियासत की हाईकोर्ट का सरजज हो गया है, या

(बी) किसी सूबे में किसी हाईकोर्ट के किसी दूसरे जज के पद पर था और विधान आरंभ होने पर उस धारा के अधीन जवाबी रियासत में हाईकोर्ट का (सरजज को छोड़कर) कोई जज हो गया है,

अगर विधान आरंभ होने से ठीक पहले वह इस पैरा के उप-पैरा (1) में बताई दर से अधिक तनखाह पा रहा था तो, सरजज की या किसी दूसरे जज की हैसियत से, जैसी सूरत हो, जितने दिनों वह असल नौकरी पर रहे उतने दिनों के बारे में, उस उप-पैरा में बताई तनखाह के अलावा खास तनखाह के रूप में वह रकम पाने का हकदार होगा जो इस तरह बताई तनखाह और विधान आरंभ होने से ठीक पहले उसे मिलने वाली तनखाह के फरक के बराबर है.

(3) हाईकोर्ट का हर जज भारत के भूभाग के अन्दर सरकारी काम पर सफर करने में जो खर्च करेगा उसको पूरा करने के लिये उसे वह उचित भत्ते मिलेंगे और सफर के संबंध में उसे वह उचित सुविधाएँ दी जायंगी जो राजपति समय समय पर तय करे.

(4) किसी रियासत की हाईकोर्ट के जजों को छुट्टी (छुट्टी के भत्तों समेत) और पेनशन के बारे में अधिकार उन बंधानों के अधीन रहेंगे जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले जवाबी सूबे में हाईकोर्ट के जजों पर लागू थे.

11—अगर प्रसंग से कुछ और दरकार न हो तो इस भाग में—

(ए) “सरजज” शब्द में कारकर सरजज, और “जज” में जरूरती जज शामिल हैं;

(बी) “असल नौकरी” में—

(एक) वह समय शामिल है जो किसी जज ने जज का फरज पूरा करने में या ऐसे दूसरे काम करने में बिताया हो जिन्हें निभारना राजपति की प्रार्थना पर उसने अपने जिम्मे ले लिया है;

(दो) तावीलों का समय शामिल है, उस समय को छोड़कर जिसमें जज ने छुट्टी ले रखी हो; और

(तीन) वह समय शामिल है जो किसी हाईकोर्ट से आला अदालत को या किसी एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट को तबादला होने पर जाने और काम संभालने में खर्च हो.

भाग (ई)

### भारत के दाब अफसर और सरपड़तालिया के बारे में बंधान

12—(1) भारत के दाब अफसर और सरपड़तालिया को चार हजार रुपए माहवार की दर से तनखाह दी जायगी.

(2) वह आदमी जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द के सरपड़तालिया के पद पर था और विधान आरंभ होने पर दफा 377 के अधीन भारत का दाब अफसर और सरपड़तालिया हो गया है, इस पैरा के उप-पैरा (1) में बताई तनखाह के अलावा खास तनखाह के रूप में वह रकम पाने का हकदार होगा जो इस तरह बताई तनखाह और विधान आरंभ होने से ठीक पहले उसे हिन्द के सरपड़तालिया की हैसियत से मिलने वाली तनखाह के फरक के बराबर है.

(3) भारत के दाब अफसर और सरपड़तालिया की छुट्टी और पेनशन के बारे में अधिकार और उसकी नौकरी की दूसरी शर्तें उन बंधानों के अधीन रहेंगी या अधीन जारी रहेंगी, जैसी सूरत हो, जो इस विधान के आरंभ से ठीक पहले हिन्द के ऑडीटर-जनरल पर लागू थीं, और उन बंधानों में जहाँ जहाँ गवरनर जनरल की चरचा की गई है उस से यह मतलब लिया जायगा मानो वह राजपति की चरचा है.

## तीसरी पट्टी

[ दफ्ता 75 (4), 99, 124 (6), 148 (2), 164 (3), 188 और 219 ]

### हलफ़ या वचन के रूप

#### एक

यूनियन के वज़ीर के पद के हलफ़ का रूप :—

“मैं,.....(नाम).....ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के गंभीरता से वचन भरता हूँ

उस विधान का जो क़ानून से क़ायम हुआ है सचाई से वफ़ादार और भक्त रहूँगा, वफ़ादारी के साथ और अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ पर चलते हुए यूनियन के एक वज़ीर की हैसियत से अपने फ़रज़ों को निभाऊँगा और विधान और क़ानून के अनुसार सब तरह के लोगों के साथ बिना डर या तरफ़दारी, बिना लगाव या बैर ठीक ठीक बरताव करूँगा.”

#### दो

यूनियन के वज़ीर के लिये राज़दारी के हलफ़ का रूप :—

“मैं,.....(नाम).....ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं, कोई भीरता से वचन भरता हूँ

मामला जो मेरे विचार के लिये लाया जायगा, या जो यूनियन के वज़ीर की हैसियत से मुझे मालूम होगा, किसी आदमी या आदमियों तक, सीधे या नासीधे, न पहुँचाऊँगा न किसी को बताऊँगा, सिवाय जब कि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़रज़ क़ायदे से निभारने के लिये मुझे ऐसा करना दरकार हो”.

#### तीन

राजपंचायत के मेम्बर के लिये हलफ़ या वचन का रूप :—

“मैं,•• (नाम)•• जो रियासत सदन (या लोक सदन) का मेम्बर



चुना गया हूँ (या नामजद किया गया हूँ), ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ  
गंभीरता से वचन भरता हूँ  
 कि मैं भारत के उस विधान का जो कानून से कायम हुआ है सचाई  
 से वफादार और भक्त रहूँगा, और जो फरज में अब संभालने वाला  
 हूँ उसे वफादारी के साथ निभाऊँगा।”

### चार

आला अदालत के जजों के लिये और भारत के दाब अफसर  
 और सरपड़तालिया के लिये हलफ या वचन का रूप :—

“मैं,...(नाम), जो भारत की आला अदालत का सरजज (या जज)  
 (या भारत का दाब अफसर और सरपड़तालिया) नियोजा गया हूँ,  
ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ  
गंभीरता से वचन भरता हूँ कि मैं भारत के उस विधान का जो  
 कानून से कायम हुआ है सचाई से वफादार और भक्त रहूँगा, अपनी  
 पूरी सकत, जानकारी और विवेक से, बिना डर या तरफदारी, बिना  
 लगाव या बैर, कायदे से और वफादारी के साथ, अपने पद के फरज  
 पूरे करूँगा, और विधान और कानूनों की मान-मर्यादा को बनाए  
 रखूँगा।”

### पाँच

रियासत के वजीर के लिये पद के हलफ का रूप :—

“मैं,.....(नाम)....., ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ  
गंभीरता से वचन भरता हूँ कि मैं भारत  
 के उस विधान का जो कानून से कायम हुआ है सचाई से वफादार  
 और भक्त रहूँगा, वफादारी के साथ और अपनी अन्तरात्मा की आवाज  
 पर चलते हुए,.....रियासत के एक वजीर की हैसियत से, अपने  
 फरजों को निभाऊँगा, और विधान और कानून के अनुसार, सब  
 तरह के लोगों के साथ, बिना डर या तरफदारी, बिना लगाव या बैर,  
 ठीक ठीक बरताव करूँगा।”

### छै

रियासत के वजीर के लिये राजदारी के हलफ का रूप :—

“मैं,.....(नाम)....., ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं, कोई गंभीरता से वचन भरता हूँ

मामला जो मेरे विचार के लिये लाया जायगा, या जो.....रियासत के वजीर की हैसियत से मुझे मालूम होगा, किसी आदमी या आदमियों तक, सीधे या नासीधे, न पहुँचाऊँगा न किसी को बताऊँगा, सिवाय जब कि वजीर की हैसियत से अपने फरज कायदे से निभारने के लिये मुझे ऐसा करना दरकार हो.”

### सात

रियासत की कानून सभा के मेम्बर के लिये हलफ या वचन का रूप:—

“मैं,...(नाम), जो आम सदन (या खास सदन) का मेम्बर चुना गया हूँ (या नामजद किया गया हूँ), ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि गंभीरता से वचन भरता हूँ मैं भारत के उस विधान का जो कानून से कायम हुआ है सचाई से वफादार और भक्त रहूँगा, और जो फरज मैं अब संभालने वाला हूँ उसे वफादारी के साथ निभाऊँगा.”

### आठ

हाईकोर्ट के जजों के लिये हलफ या वचन का रूप :—

“मैं...(नाम)..., जो.....की हाईकोर्ट का सर जज ( या जज ) नियोजा गया हूँ, ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के उस गंभीरता से वचन भरता हूँ

विधान का जो कानून से कायम हुआ है सचाई से वफादार और भक्त रहूँगा, अपनी पूरी सकत, जानकारी और विवेक से, बिना डर या तरफदारी, बिना लगाव या बैर, कायदे से और वफादारी के साथ, अपने पद के फरज पूरे करूँगा, और विधान और कानूनों की मान-मर्यादा को बनाए रखूँगा.”

## चौथी पट्टी

[क्लॉ 4 (1), 80(2), और 391]

### रियासत सदन की सीटों का बटवारा

इस पट्टी के साथ दिये सीटों के नक्शे के पहले कालम में दर्ज हर रियासत या रियासत गुट को उतनी सीटें दी जायँगी जितनी इस नक्शे के दूसरे कालम में उस रियासत या रियासत गुट के नाम के सामने, जैसी सूरत हो, दर्ज हैं.

### सीटों का नक्शा

#### रियासत सदन

पहली पट्टी के भाग (ए) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि

1	2
रियासतें	कुल सीटें
1. आसाम	6
2. बिहार	21
3. बम्बई	17
4. मध्यप्रदेश	12
5. मदरास	27
6. उड़ीसा	9
7. पंजाब	8
8. युक्तप्रान्त	31
9. पच्छिम बंगाल	14
	कुल 145

## पहली पट्टी के भाग (बी) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि

1	2
रियासतें	कुल सीटें
1. हैदराबाद	11
2. जम्मू और काश्मीर	4
3. मध्यभारत	6
4. मैसूर	6
5. पटियाला और पूरब पंजाब रियासत यूनियन	3
6. राजस्थान	9
7. सौराष्ट्र	4
8. ट्रावनकोर-कोचीन	6
9. विन्ध्य-प्रदेश	4
	कुल 53

## पहला पट्टी के भाग (सी) में दर्ज रियासतों के प्रतिनिधि

1	2
रियासतें और रियासत गुट	कुल सीटें
1. अजमेर } 2. कुर्ग }	1
3. भोपाल	1
4. बिलासपुर } 5. हिमाचल प्रदेश }	1
6. कूच-बिहार	1
7. दिल्ली	1
8. कच्छ	1
9. मनीपुर } 10. त्रिपुरा }	1
	कुल 7

सब सीटों की कुल गिनती 205

## पांचवी पट्टी

[ दफा 244 (1) ]

### पट्टी-दर्ज क्षेत्रों और पट्टी-दर्ज कबीलों के शासन और दबान के बारे में बंधान

भाग (ए)

आम

1—अर्थ—इस पट्टी में, जब तक प्रसंग से कुछ और दरकार न हो, “रियासत” शब्द के मानी हैं पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज कोई रियासत, पर इसमें आसाम की रियासत शामिल नहीं है.

2—पट्टी-दर्ज क्षेत्रों में रियासत की काजकारी शक्ति—  
इस पट्टी के बंधानों के अधीन रहते हुए, हर रियासत की काजकारी शक्ति के फैलाव में उसके अन्दर के पट्टी-दर्ज क्षेत्र शामिल हैं.

3—पट्टी-दर्ज क्षेत्रों के शासन के बारे में रियासतपति या राजप्रमुख की राजपति को रिपोर्ट—हर ऐसी रियासत का रियासतपति या राजप्रमुख जिसमें पट्टी-दर्ज क्षेत्र हैं, हर साल या जब कभी राजपति मांगे, उस रियासत के पट्टी-दर्ज क्षेत्रों के शासन के बारे में राजपति को रिपोर्ट देगा, और यूनियन की काजकारी शक्ति के फैलाव में उन क्षेत्रों के शासन के बारे में उस रियासत को निर्देश देना शामिल होगा.

भाग (बी)

### पट्टी-दर्ज क्षेत्रों और पट्टी-दर्ज कबीलों का शासन और दबान

4—कबीला सलाहकार मंडल—(1) हर उस रियासत में जिसमें पट्टी-दर्ज क्षेत्र हैं, और अगर राजपति इस तरह निर्देश करे तो किसी ऐसी रियासत में भी जिसमें पट्टी-दर्ज कबीले हैं पर पट्टी-

दर्ज क्षेत्र नहीं हैं, एक कबीला सलाहकार मंडल कायम किया जायगा, जिसमें बीस से अधिक मेम्बर नहीं होंगे जिनमें से तीन चौथाई के जितने करीब हो सके वह होंगे जो उस रियासत के आम सदन में पट्टी-दर्ज कबीलों के प्रतिनिधि हैं :

शर्तें कि अगर उस रियासत के आम सदन में पट्टी-दर्ज कबीलों के प्रतिनिधियों की गिनती, कबीला सलाहकार मंडल में जो सीटें ऐसे प्रतिनिधियों से भरी जानी हैं उन की गिनती से कम है तो बाक़ी सीटें उन कबीलों के दूसरे मेम्बरों से भरी जायंगी.

(2) कबीला सलाहकार मंडल का फ़रज़ होगा कि वह उन मामलों पर सलाह दे जिनका सम्बन्ध उस रियासत में पट्टी-दर्ज कबीलों की भलाई और बढ़ोतरी से है और जिन्हें रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, उसके पास राय के लिये भेजे.

(3) रियासतपति या राजप्रमुख—

(ए) मंडल के मेम्बरों की गिनती, उनके नियोजन का ढंग और मंडल के मसनदी और अफ़सरों और नौकरों के नियोजन का ढंग,

(बी) मंडल की मिलनियों का संचालन और उनका आम दस्तूर, और

(सी) प्रसंग से आए हुए दूसरे सब मामले, तय करने या उनकी कायदाबन्दी करने के लिये, जैसी सूरत हो, नियम बना सकता है.

5—पट्टी-दर्ज क्षेत्रों में लागू क़ानून—(1) इस विधान में किसी बात के रहते भी, रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, आम नोटिस निकाल कर निर्देश दे सकता है कि राजपंचायत का या उस रियासत की क़ानून सभा का कोई खास पक़ट उस रियासत में किसी पट्टी-दर्ज क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा, या उस रियासत में किसी पट्टी-दर्ज क्षेत्र या उसके किसी भाग पर उन अपवादों और अदल बदल के अधीन लागू होगा जो वह उस नोटिस में बतादे, और इस उप-पैरा के अधीन जो निर्देश दिया जाय वह इस तरह दिया जा सकता है कि उसका पिछ-लगता असर हो.

(2) रियासतपति या राजप्रमुख, जैसी सूरत हो, रियासत के किसी ऐसे क्षेत्र की शान्ति और अच्छी हुकूमत के लिये, जो उस समय पट्टी-दर्ज क्षेत्र है, क़ायदे बना सकता है।

ऐसे क़ायदे, खास कर, और ऊपर-लिखी शक्ति की आमियत को कम किये बिना, —

(ए) उस क्षेत्र में पट्टी-दर्ज क़बीलों के लोगों के, बाहर वालों को या एक दूसरे को, ज़मीन दे डालने पर रोक लगा सकते हैं या उसकी मनाही कर सकते हैं;

(बी) उस क्षेत्र में पट्टी दर्ज क़बीलों के लोगों को ज़मीने बांटे जाने की क़ायदाबन्दी कर सकते हैं;

(सी) उस क्षेत्र में पट्टी-दर्ज क़बीलों के लोगों को जो लोग रुपया उधार देते हैं उनके इस साहूकारे के काम की क़ायदाबन्दी कर सकते हैं।

(3) ऐसा कोई क़ायदा बनाने में जिसकी चरचा इस पैरा के उप-पैरा (2) में की गई है रियासतपति या राजप्रमुख राजपंचायत के या उस रियासत की क़ानून सभा के किसी ऐसे एक्ट को या किसी ऐसे मौजूदा क़ानून को, जो उस क्षेत्र पर, जिसका सवाल है, उस समय लागू हो, रद्द कर सकता है या सुधार सकता है।

(4) इस पैरा के अधीन बने सब क़ायदे उसी समय राजपति के सामने रखे जायंगे और जब तक राजपति उन पर मंजूरी न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा।

(5) इस पैरा के अधीन कोई क़ायदा नहीं बनाया जायगा जब तक उस क़ायदे को बनाने वाले रियासतपति या राजप्रमुख ने, उस सूरत में जब कि उस रियासत के लिये कोई क़बीला सलाहकार मंडल है, उस मंडल से सलाह न करली हो।

भाग (सी)

### पट्टी-दर्ज क्षेत्र

6—पट्टी-दर्ज क्षेत्र—(1) इस विधान में “पट्टी-दर्ज क्षेत्र” शब्दों के मानी हैं वह क्षेत्र जिन्हें राजपति हुकूम देकर पट्टी-दर्ज क्षेत्र ठहरा दे।

(2) राजपति किसी भी समय हुकुम दे कर—

- (ए) यह निर्देश दे सकता है कि कोई पट्टी-दर्ज क्षेत्र पूरा या उसका कोई खास भाग, पट्टी-दर्ज क्षेत्र नहीं रहेगा या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा;
- (बी) किसी पट्टी-दर्ज क्षेत्र को बदल सकता है, पर केवल उसकी सीमाओं को ठीक करने के रूप में ही;
- (सी) किसी रियासत की सीमाओं के बदले जाने पर, या यूनि-यन में किसी नई रियासत के दाखिल किये जाने पर, या नई रियासत के क़ायम किये जाने पर, किसी ऐसे भूभाग को जो पहले किसी रियासत में शामिल नहीं था पट्टी-दर्ज क्षेत्र या किसी पट्टी-दर्ज क्षेत्र का भाग ऐलान कर सकता है;

और ऐसे किसी हुकुम में वह प्रसंगी और परिनामी बंधान रह सकते हैं जो राजपति को ज़रूरी और उचित मालूम हों, पर सिवाय जैसा ऊपर कहा गया है इस पैरा के उप पैरा (1) के अधीन दिये हुए हुकुम को किसी बाद के हुकुम से नहीं बदला जायगा.

भाग (डी)

### इस पट्टी में सुधार

7—इस पट्टी में सुधार—(1) राजपंचायत समय समय पर क़ानून बना कर इस पट्टी के बंधानों में से किसी में कुछ जोड़ कर, अदल बदल कर, या रद्द कर के, पट्टी में सुधार कर सकती है, और जब किसी पट्टी में इस तरह सुधार हो जाय, तब इस विधान में इस पट्टी की चरचा का मतलब यह लिया जायगा मानो वह इस तरह सुधारी हुई पट्टी की चरचा है.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) में जिस क़ानून की बात आई है उस को दफ़ा 368 के मतलबों के लिये इस विधान का सुधार नहीं समझा जायगा.



## छटी पट्टी

[ दफा 244(2) और 275 (1) ]

### आसाम के कबाइली क्षेत्रों के शासन के बारे में बंधान

1—स्वाधीन जिले और स्वाधीन इलाक़े—(1) इस पट्टी के पैरा 20 के साथ जो नक्शा दिया गया है उसके भाग (ए) की हर मद के कबाइली क्षेत्र, इस पैरा के बंधानों का ध्यान रखते हुए, एक स्वाधीन जिला होंगे.

(2) अगर किसी स्वाधीन जिले में अलग अलग पट्टी दर्ज कबीले हैं तो रियासतपति आम नोटिस निकालकर उस क्षेत्र या उन क्षेत्रों को, जिनमें वह कबीले बसते हैं, स्वाधीन इलाक़ों में बांट सकता है.

(3) रियासतपति आम नोटिस निकाल कर—

(ए) किसी क्षेत्र को उस नक्शे के भाग (ए) में शामिल कर सकता है;

(बी) किसी क्षेत्र को उस नक्शे के भाग (ए) से अलग कर सकता है;

(सी) एक नया स्वाधीन जिला बना सकता है;

(डी) किसी स्वाधीन जिले का क्षेत्र बढ़ा सकता है;

(ई) किसी स्वाधीन जिले का क्षेत्र घटा सकता है;

(एफ़) दो या अधिक स्वाधीन जिलों को या उनके भागों को मिलाकर एक स्वाधीन जिला बना सकता है;

(जी) किसी स्वाधीन जिले की सीमाएँ तय कर सकता है:

शर्तें कि इस उप-पैरा की धारा (सी), (डी), (ई), और (एफ़) के अधीन रियासतपति कोई हुकूम नहीं देगा जब तक कि वह इस पट्टी के पैरा 14 के उप-पैरा (1) के अधीन नियोजे हुए कमीशन की रिपोर्ट पर विचार न कर चुका हो.

2—जिला मंडलों और इलाक़ा मंडलों की बनावट—

(1) हर स्वाधीन जिले के लिये एक जिला मंडल होगा जिसमें अधिक

से अधिक चौबीस मेम्बर होंगे, जिनमें से कम से कम तीन चौथाई बालिग वोट के आधार पर चुने जायेंगे.

(2) इस पट्टी के पैरा 1 के उप-पैरा (2) के अधीन स्वाधीन इलाका बने हर क्षेत्र के लिये एक अलग इलाका मंडल होगा.

(3) हर जिला मंडल और हर इलाका मंडल एकतन संस्था होगा जो अलग अलग “....(जिले का नाम) का जिला मंडल” और “... (इलाके का नाम) का इलाका मंडल” कहलायगा, जो लगातार बनता और चलता रहेगा, जिसकी एक ही मोहर होगी, और जो इस नाम से नालिश कर सकेगा और उस पर नालिश की जा सकेगी.

(4) इस पट्टी के बंधानों के अधीन रहते हुए, हर स्वाधीन जिले का शासन, जहां तक वह इस पट्टी के अधीन उस जिले के अन्दर किसी इलाका मंडल के हाथ में नहीं दिया गया है, उस जिले के जिला मंडल के हाथ में रहेगा, और हर स्वाधीन इलाके का शासन उस इलाके के इलाका मंडल के हाथ में रहेगा.

(5) हर ऐसे स्वाधीन जिले में, जहाँ इलाका मंडल हैं, इलाका मंडल के अधिकार के अधीन क्षेत्रों के बारे में जिला मंडल को उन शक्तियों के अलावा जो उन क्षेत्रों के बारे में इस पट्टी में जिला मंडल को सौंपी गई हैं, केवल वह शक्तियाँ और होंगी जो इलाका मंडल उसे अपनी तरफ से दे दे.

(6) रियासतपति, जिला मंडलों और इलाका मंडलों के पहली बार बनाए जाने के लिये, जिन स्वाधीन जिलों या इलाकों से इस बात का सम्बन्ध होगा उनके मौजूदा कबाइली मंडलों से या कबीलों का प्रतिनिधान करने वाली दूसरी संस्थाओं से सलाह लेकर, नियम बनायगा और उन नियमों में नीचे लिखी बातों का बन्धान किया जायगा:—

(ए) जिला मंडलों और इलाका मंडलों की रचना और उनमें सीटों का बटवारा;

(बी) इन मंडलों के चुनावों के मतलब के लिये भूभागी चुनाव हलकों की हद्दबन्दी;

(सी) ऐसे चुनावों में वोट देने वालों की जोगताएँ और उनके लिये चुनाव-चिट्ठों का तैयार किया जाना;

(डी) उन चुनावों में उन मंडलों के मेम्बर चुने जाने वालों की जोगताएँ;

(ई) उन मंडलों के मेम्बरों की पद-मियाद;

(एफ) उन मंडलों के चुनावों या उनके लिये नामजदगी के बारे में या उन से सम्बन्ध रखने वाला कोई और मामला;

(जी) जिला और इलाका मंडलों के दस्तूर और उनके काम का संचालन;

(एच) जिला और इलाका मंडलों के अफसरों और अमलों का नियोजन.

(7) पहली बार बन जाने के बाद जिला या इलाका मंडल इस पैरा के उप-पैरा (6) में जो मामले दर्ज हैं, उनके लिये नियम बना सकते हैं; और नीचे लिखे मामलों की क्रायदाबन्दी करने के लिये भी नियम बना सकते हैं:—

(ए) मातहत मुकामी मंडलों या बोर्डों का बनाना और उनके दस्तूर और उनके काम का संचालन;

(बी) उस जिले या इलाके के, जैसी सूरत हो, शासन से सम्बन्ध रखने वाले काम चलाने के बारे में आम तौर पर सब मामले:

शर्तें कि जब तक जिला या इलाका मंडल इस उप-पैरा के अधीन नियम नहीं बनाता, तब तक हर ऐसे मंडल के चुनावों के बारे में, उसके अफसरों और अमले के बारे में, और उसके दस्तूर और काम के संचालन के बारे में, इस पैरा के उप-पैरा (6) के अधीन रियासत-पति के बनाए नियम अमल में रहेंगे :

और शर्तें कि उत्तर कछार पहाड़ियों और मिकिर पहाड़ियों का डिप्टी कमिश्नर या सब-डिविजनल अफसर, जैसी सूरत हो, अपने पद-नाते, इस पट्टी के पैरा 20 के साथ वाले नक्शे के भाग (ए) की मद 5 और मद 6 के अलग अलग भूभागों के लिये बने हुए जिला मंडल

का मसनदी होगा, और जिला मंडल के पहली बार बनने के बाद छै बरस के अरसे के लिये, उसको, रियासतपति के दवान के अधीन रहते हुए, यह शक्ति होगी कि वह जिला मंडल के किसी ठहराव या फैसले को मंसूख कर दे, या उसमें अदल बदल कर दे, या जिला मंडल को ऐसी हिदायतें दे जो वह मुनासिब समझे, और जिला मंडल को हर इस तरह दी हुई हिदायत पर अमल करना होगा।

**3—जिला मंडलों और इलाका मंडलों की कानून बनाने की शक्तियाँ—**(1) हर स्वाधीन इलाके के इलाका मंडल को उस इलाके के अन्दर के सब छेत्रों के बारे में, और हर स्वाधीन जिले के जिला मंडल को उस जिले के अन्दर के सब छेत्रों के बारे में, सिवाय उस जिले के अन्दर के उन छेत्रों के जो इलाका मंडलों के अधिकार में हैं, अगर उस जिले में कोई इलाका मंडल हों तो, नीचे लिखे मामलों के बारे में कानून बनाने की शक्ति होगी:—

(ए) रखाए हुए जंगल की जमीन को छोड़ कर और कोई जमीन, खेती बाड़ी के या ढोर चराने के मतलबों के लिये, या रिहाइश के या दूसरे गैर-खेती बाड़ी मतलबों के लिये, या किसी और ऐसे मतलब के लिये जिससे किसी गाँव या कस्बे के रहने वालों के हितों के बढ़ने की संभावना हो, किसी के नाम कर देना, उस पर कब्जा, उसका इस्तेमाल, या उसे अलग कर देना :

शर्त कि इन कानूनों की कोई बात आसाम की सरकार को, सरकारी मतलबों के लिये, किसी ऐसे कानून के अनुसार जो उस समय अमल में हो और जो जमीन को इस तरह हासिल करने का अधिकार देता हो, किसी जमीन को, चाहे उस पर किसी का कब्जा हो या न हो, जबरन हासिल करने से नहीं रोक सकेगी;

(बी) किसी ऐसे जंगल का प्रबन्ध जो रखाया हुआ जंगल नहीं है;

(सी) खेती बाड़ी के मतलब के लिये किसी नहर या जल-मार्ग का इस्तेमाल;

- (डी) भूम के रिवाज या बदलती जुताई के दूसरे रूपों के लिये क्रायदाबन्दी;
- (ई) गाँव या कस्बा कमेटियों या मंडलों का कायम करना और उनकी शक्तियाँ;
- (एफ) गाँव या कस्बों के शासन के सम्बन्ध में कोई दूसरा मामला, जिसमें गाँव या कस्बों की पुलिस, जन तन-दुरुस्ती और सफाई शामिल है;
- (जी) सरदारों या मुखियों का नियोजन और उनके बाद उनका पदगाहन;
- (एच) जायदाद की विरासत;
- (आई) शादी-ब्याह;
- (जे) समाजी रीति-रिवाज.

(2) इस पैरा में “रखाए हुए जंगल” के मानी हैं कोई ऐसा क्षेत्र जो ‘आसाम जंगल क्रायदाबन्दी 1891’ के अधीन या किसी दूसरे कानून के अधीन, जो, जिस क्षेत्र का सवाल है उसमें उस समय अमल में हो, रखाया हुआ जंगल है.

(3) इस पैरा के अधीन बने सब कानून उसी समय रियासतपति के सामने रखे जायेंगे और जब तक रियासतपति उन पर अपनी मंजूरी न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा.

#### 4—स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाकों में न्याय शासन—

(1) हर स्वाधीन इलाके का इलाका मंडल उस इलाके के अन्दर के क्षेत्रों के बारे में, और हर स्वाधीन जिले का जिला मंडल उस जिले के अन्दर के क्षेत्रों के बारे में, सिवाय उस जिले के अन्दर के उन क्षेत्रों के जो इलाका मंडल के अधिकार में हैं, अगर उस जिले में कोई इलाका मंडल हों तो, उन फरीकों के बीच नालिशों और मुकदमों की जांच के लिये जो सबके सब उन क्षेत्रों के अन्दर पट्टी-दर्ज कबीलों के आदमी हैं, पर उन नालिशों और मुकदमों को छोड़ कर जिन पर इस पट्टी के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के बन्धान लागू होते हैं, गाँव मंडल या गाँव अदालतें बना सकते हैं, जिनके अलावा रियासत की किसी और अदा-

तब में उन नालिशों या मुकदमों की जांच नहीं हो सकेगी, और उन गाँव मंडलों की मेम्बरी के लिये या उन गाँव अदालतों की सदरत के लिये उचित आदमियों का नियोजन कर सकते हैं, और इस पट्टी के पैरा 3 के अधीन बने कानूनों को अमल में लाने के लिये जरूरी अफसरों का भी नियोजन कर सकते हैं

(2) इस विधान में किसी बात के रहते भी, किसी स्वाधीन इलाके के लिये इलाका मंडल या कोई अदालत जो इस काम के लिये इलाका मंडल ने बनाई हो, या अगर किसी स्वाधीन जिले के किसी छेत्र का कोई इलाका मंडल नहीं है, तो उस जिले का जिला मंडल, या कोई अदालत जो इस काम के लिये जिला मंडल ने बनाई हो, उन सब नालिशों और मुकदमों के बारे में अपीली अदालत की शक्तियों से काम लेगी जो ऐसे इलाके या छेत्र के अन्दर, जैसी सूरत हो, इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन बने गाँव मंडल या गाँव अदालत के सामने सुने जा सकते हों, पर उन नालिशों और मुकदमों को छोड़ कर जिन पर इस पट्टी के पैरा 5 के उप पैरा (1) के बन्धान लागू होते हैं, और ऐसी नालिशों और मुकदमों पर हाइकोर्ट या आला अदालत को छोड़ कर और किसी दूसरी अदालत की अमलदारी नहीं होगी.

(3) उन नालिशों और मुकदमों पर जिन पर इस पैरा के उप-पैरा (2) के बन्धान लागू होते हैं आसाम की हाइकोर्ट को वह अमलदारी हासिल होगी और वह उससे काम लेगी जो रियासत-पति समय समय पर हुकुम दे कर बताए.

(4) कोई इलाका मंडल या जिला मंडल, जैसी सूरत हो, पहले से रियासतपति की राजामन्दी लेकर नीचे लिखे मामलों की क्रायदाबन्दी के लिये नियम बना सकता है:—

(ए) गाँव मंडलों और गाँव अदालतों की बनावट और वह शक्तियाँ जिनसे इस पैरा के अधीन गाँव मंडल और गाँव अदालत काम लेंगे;

(बी) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन नालिशों और मुकदमों की जाँच करने में गाँव मंडलों या गाँव अदालतों को जिस दस्तूर पर चलना है वह दस्तूर;

(सी) इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन अपीलों और दूसरी कारवाइयों में इलाका या जिला मंडल को या ऐसे मंडल की बनाई किसी अदालत को जिस दस्तूर पर चलना है वह दस्तूर;

(डी) ऐसे मंडलों और अदालतों के फैसलों और हुकुमों पर अमल कराना;

(ई) इस पैरा के उप-पैरा (1) और (2) के बन्धानों पर अमल कराने के लिये और सब सहायक मामले.

5—जाबता दीवानी 1908 और जाबता फौजदारी 1898 के अधीन, कुछ नालिशों, मुकदमों और जुर्मों की जांच के लिये इलाका और जिला मंडलों को, और कुछ अदालतों और अफसरों को शक्तियाँ सौंपना—(1) रियासतपति, ऐसी नालिशों या ऐसे मुकदमों की जांच के लिये, जो किसी ऐसे कानून से पैदा हों जो किसी स्वाधीन जिले या इलाके में अमल में हो और जिसको इस काम के लिये रियासतपति ने बताया हो, या ऐसे जुर्मों की जांच के लिये जिनकी सच्चा ताजीरात हिन्द के अधीन या किसी दूसरे कानून के अधीन जो उस समय उस जिले या इलाके पर लागू हो, मौत, आजीवन काला पानी या कम से कम पांच साल की कैद हो, उस जिला मंडल या उस इलाका मंडल को जिसका उस जिले या उस इलाके पर अधिकार है, या उन अदालतों को जिन्हें ऐसे किसी जिला मंडल ने बनाया है, या किसी अफसर को जिसको इस काम के लिये रियासतपति ने नियोजा हो, जाबता दीवानी 1908 के या जाबता फौजदारी 1898 के अधीन, जैसी सूरत हो, ऐसी शक्तियाँ सौंप सकता है जिन्हें वह मुनासिब समझे, और उसके ऐसा करने पर वह मंडल, अदालत या अफसर, उन शक्तियों से काम लेते हुए, जो इस तरह सौंपी जायं, उन नालिशों, मुकदमों या जुर्मों की जांच करेगा.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन किसी जिला मंडल, इलाका मंडल, अदालत या अफसर को जो शक्तियाँ सौंपी

जायं उनमें से किसी को रियासतपति वापिस ले सकता है या उनमें अदल बदल कर सकता है.

(3) सिवाय इसके कि इस पैरा में कोई साफ साफ बन्धान किया गया हो, ज़ाबता दीवानी 1908 और ज़ाबता फौजदारी 1898, किसी स्वाधीन ज़िले या किसी स्वाधीन इलाक़े में, जिन पर इस पैरा के बन्धान लागू होते हैं, किसी नालिश, मुक़दमें या जुर्म की जांच पर लागू नहीं होंगे.

6—ज़िला मंडल को प्राइमरी स्कूल वगैरा कायम करने की शक्तियाँ—किसी स्वाधीन ज़िले का ज़िला मंडल ज़िले में प्राइमरी स्कूल, दवाख़ाने, मंडियाँ, कांजी हौज़, उतराई घाट, मछिया-रियाँ, सड़कें और जल मार्ग कायम कर सकता है, बना सकता है या उनका प्रबन्ध कर सकता है और खास कर यह बता सकता है कि ज़िले के प्राइमरी स्कूलों में किस भाशा में और किस ढंग से प्राइमरी तालीम दी जायगी.

7—ज़िला और इलाक़ा कोश—(1) हर स्वाधीन ज़िले के लिये एक ज़िला कोश और हर स्वाधीन इलाक़े के लिये एक इलाक़ा कोश बनाया जायगा, जिसमें वह सब रक़में जमा की जायंगी, जो इस विधान के बन्धानों के अनुसार, उस ज़िले या जैसी सूरत हो उस इलाक़े के शासन के दौरान में उस ज़िले के लिये ज़िला मंडल को और उस इलाक़े के लिये उस इलाक़ा मंडल को मिलें.

(2) रियासतपति की रज़ामंदी से, ज़िला मंडल और इलाक़ा मंडल ज़िला कोश या, जैसी सूरत हो, इलाक़ा कोश के प्रबन्ध के लिये नियम बना सकते हैं, और जो नियम इस तरह बनाए जायं वह उस कोश में रक़में जमा कराने, उसमें से रक़में निकालने, उस में रक़मों की रखवाली करने, और इन मामलों से सम्बन्ध रखने वाले या इनके सहायक किसी और मामले, में जो दस्तूर बरता जायगा उसे तय कर सकते हैं.

8—ज़मीन की मालगुजारी तय करने और जमा करने और टैक्स लगाने की शक्तियाँ—(1) हर स्वाधीन इलाक़े के इलाक़ा



मंडल को उस इलाक़े के अन्दर की सब ज़मीनों के बारे में, और हर स्वाधीन ज़िले के ज़िला मंडल को उस ज़िले के अन्दर, ऐसी ज़मीनों को छोड़ कर जो उन छेत्रों के अन्दर हैं जो इलाक़ा मंडलों के अधिकार में हैं, अगर वहाँ कोई इलाक़ा मंडल हों तो, बाक़ी सब ज़मीनों के बारे में, शक्ति होगी कि वह उन सिद्धान्तों के अनुसार, उन ज़मीनों की मालगुज़ारी तय करें और जमा करें जिन सिद्धान्तों पर उस समय आसाम सरकार आसाम की रियासत में आम तौर पर मालगुज़ारी के मतलबों के लिये ज़मीनों को आंकने में चलती है.

(2) हर स्वाधीन इलाक़े के इलाक़ा मंडल को उस इलाक़े के अन्दर के छेत्रों के बारे में, और हर स्वाधीन ज़िले के ज़िला मंडल को उस ज़िले के अन्दर, उन छेत्रों को छोड़ कर जो इलाक़ा मंडलों के अधिकार में हों, अगर वहाँ कोई इलाक़ा मंडल हों तो, बाक़ी सब छेत्रों के बारे में, ज़मीनों और इमारतों पर टैक्स लगाने और जमा करने, और उन छेत्रों में बसने वाले लोगों पर टोल टैक्स लगाने की शक्ति होगी.

(3) हर स्वाधीन ज़िले के ज़िला मंडल को उस ज़िले के अन्दर नीचे लिखे सब टैक्स या उन में से कोई टैक्स लगाने और जमा करने की शक्ति होगी, यानी—

- (ए) पेशों, ब्योपारों, रोज़गारों और कामगारियों पर टैक्स;
- (बी) जानवरों, गाड़ियों और नावों पर टैक्स;
- (सी) किसी मंडी में बिकरी के लिये माल आने पर टैक्स, और सवारियों और माल पर घाट उतराई टोल; और
- (डी) स्कूलों, दवाखानों या सड़कों को बनाए रखने के लिये टैक्स.

(4) कोई इलाक़ा मंडल या ज़िला मंडल, जैसी सूरत हो, इस पैरा के उप-पैरा (2) और (3) में जो टैक्स बताए गए हैं उनके लगाने और जमा करने का बंधान करने के लिये क़ायदे बना सकता है.

9—खनिजों की खोज करने या उनको निकालने के लिये लाइसेंस या पट्टे—(1) किसी स्वाधीन ज़िले के किसी

क्षेत्र में खनिजों की खोज करने या उनको निकालने के लिये आसाम सरकार जो लाइसेंस या पट्टे दे उनसे हर साल जो रायलटियां मिलें उनका वह हिस्सा जिस पर उस जिले का जिला मंडल और आसाम सरकार दोनों राजी हो जायं जिला मंडल को दे दिया जायगा.

(2) किसी जिला मंडल को ऐसी रायलटियों का जो हिस्सा दिया जाना है उसके बारे में अगर कोई झगड़ा उठे तो वह झगड़ा तय करने के लिये रियासतपति के पास भेज दिया जायगा, और रियासतपति अपनी समझ से जो रकम तय कर दे वह वह रकम समझी जायगी जो इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन जिला मंडल को दी जानी है, और रियासतपति का फैसला आखरी होगा.

10—गैर-क्रबाइली लोगों के रुपया उधार देने और ब्योपार करने पर दबान रखने के लिये क़ायदाबन्दी करने की ज़िला मंडल की शक्ति—(1) हर स्वाधीन जिले का जिला मंडल उस जिले में बसने वाले पट्टी-दर्ज क़बीलों को छोड़ कर उस जिले के अन्दर दूसरे लोगों के रुपया उधार देने या ब्योपार करने पर दबान रखने और इन कामों की क़ायदाबन्दी करने के लिये क़ायदे बना सकता है.

(2) ऐसे क़ायदों में, खास कर, और ऊपर लिखी शक्ति की आमियत को कम किये बिना—

(ए) यह बताया जा सकता है कि रुपया उधार देने का कार-बार उस आदमी के सिवा जिसके पास इस काम के लिये जारी हुआ लाइसेंस है, और कोई आदमी नहीं करेगा;

(बी) यह बताया जा सकता है कि साहूकार सूद की अधिक से अधिक क्या दर लगा सकता है या वसूल कर सकता है;

(सी) साहूकारों के हिसाब रखने का, और ऐसे अफसरों से जिन्हें इस काम के लिये जिला मंडल नियोजे उस हिसाब की जांच कराने का, बंधान किया जा सकता है;

(डी) यह बताया जा सकता है कि कोई आदमी, जो उस ज़िले में बसने वाले पट्टी दर्ज क़बीलों का मेम्बर नहीं है, किसी विज़ारती माल का थोक या फुटकर कारबार नहीं करेगा, सिवाय ऐसे लाइसेंस के अधीन जिसे इस काम के लिये ज़िला मंडल ने जारी किया हो:

शर्तें कि इस पैरा के अधीन कोई क़ायदे नहीं बनाए जा सकेंगे जब तक कि वह उस ज़िला मंडल के कुल मेम्बरों के कम से कम तीन चौथाई की बढ़ीयत से पास न हों :

और शर्तें कि ऐसे किन्हीं क़ायदों के अधीन किसी ऐसे साहूकार या व्यापारी को जो उस ज़िले में उन क़ायदों के बनने के पहले से कारबार कर रहा है, लाइसेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा.

(3) इस पैरा के अधीन बने सब क़ायदे उसी समय रियासतपति के सामने रखे जायेंगे और जब तक वह मंजूरी न दे, उन का कोई असर नहीं होगा.

11—इस पट्टी के अधीन बने क़ानूनों, नियमों और क़ायदों का निकालना—वह सब क़ानून, नियम और क़ायदे जो इस पट्टी के अधीन कोई ज़िला मंडल या इलाक़ा मंडल बनाए उसी समय रियासत के दफ़्तरी गज़ट में निकाले जायेंगे, और इस तरह निकलने पर वह क़ानून का असर रखेंगे.

12—स्वाधीन ज़िलों और स्वाधीन इलाक़ों पर राज-पंचायत के और उस रियासत की क़ानून सभा के एक्टों का लागू होना—(1) इस बिधान में किसी बात के रहते भी—

(ए) इस पट्टी के पैरा 3 में जिन मामलों को ऐसे मामले बताया गया है जिनके बारे में कोई ज़िला मंडल या इलाक़ा मंडल क़ानून बना सकता है, उनके बारे में उस रियासत की क़ानून सभा का कोई एक्ट और उस रियासत की क़ानून सभा का कोई ऐसा एक्ट जो किसी बिना-खिंचे अलकोहोली तरल की खपत की मनाही

करता है या उस पर रुकावटें लगाता है, किसी स्वाधीन ज़िले या स्वाधीन इलाक़े पर लागू नहीं होगा जब तक कि, दोनों सूरतों में, उस ज़िले का या उस इलाक़े पर अमलदारी रखने वाला ज़िला मंडल आम नोटिस निकाल कर यह निर्देश न दे दे, और किसी एक्ट के बारे में इस तरह का निर्देश देने में ज़िला-मंडल यह भी निर्देश दे सकता है कि उस ज़िले या इलाक़े पर या उसके किसी भाग पर उस एक्ट का असर उन अपवादों और अदल बदल के अधीन होगा जिन्हें वह ज़िला मंडल ठीक समझे;

(बी) रियासतपति आम नोटिस निकाल कर यह निर्देश दे सकता है कि राजपंचायत का या उस रियासत की क़ानून सभा का कोई एक्ट, जिस पर इस उप-पैरा की धारा (ए) के बंधन लागू नहीं होते, किसी स्वाधीन ज़िले या स्वाधीन इलाक़े पर लागू नहीं होगा, या किसी ऐसे ज़िले या इलाक़े या उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों या अदल बदल के साथ लागू होगा जो रियासतपति उस नोटिस में बतावे.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन कोई निर्देश इस तरह भी दिया जा सकता है कि उसका पिछ-लगता असर हो.

**13—स्वाधीन ज़िलों की आमदनी और खर्च के तख़मीनों का सालाना माली ब्योरे में अलग दिखाया जाना—**  
हर स्वाधीन ज़िले के सम्बन्ध की उस आमदनी के तख़मीने को जो आसाम की रियासत के मूठकोश में जमा होनी है, और उस ज़िले के सम्बन्ध के उस खर्च के तख़मीने को जो उस मूठकोश में से किया जाना है, पहले वहस के लिये ज़िला मंडल के सामने रखा जायगा, और उस वहस के बाद उन तख़मीनों को रियासत के उस सालाना माली ब्योरे में अलग दिखाया जायगा जो दफ़ा 202 के अधीन रियासत की क़ानून सभा के सामने रखा जाना है.

14—स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाकों के शासन की बाबत पूछताछ करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिये कमीशन का नियोजन—( 1 ) रियासतपति किसी समय भी रियासत के स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाकों के शासन के संबंध में किसी ऐसे मामले की जो वह बता दे, जिसमें इस पट्टी के पैरा 1 के उप-पैरा (3) की धारा (सी), (डी), (ई) और (एफ) में बताए मामले शामिल हैं, जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिये एक कमीशन का नियोजन कर सकता है, या रियासत के स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाकों के आम शासन की और खास तौर पर नीचे लिखी बातों की समय समय पर पूछताछ करने और उन पर रिपोर्ट देने के लिये एक कमीशन का नियोजन कर सकता है :—

(ए) ऐसे जिलों और इलाकों में तालीम और दवादारु की सुविधाओं और आवाजाई का इंतजाम;

(बी) ऐसे जिलों और इलाकों के बारे में किसी नए या खास कानून के बनाने की जरूरत; और

(सी) जो कानून, नियम और क़ायदे जिला और इलाका मंडल बनाएं, उनको अमल में लाना;

और रियासतपति उस दस्तूर को तय कर सकता है जिस पर वह कमीशन चलेगा.

(2) ऐसे हर कमीशन की रिपोर्ट को, उसके बारे में रियासतपति की सिफारिशों के साथ और एक ऐसे यादपत्र के साथ जिसमें यह समझाया गया हो कि आसाम सरकार उस पर क्या कारवाई करने की तजवीज़ करती है, उस महकमे का वज़ीर रियासत की कानून सभा के सामने रखेगा.

(3) रियासतपति, रियासत की सरकार का काम अपने वज़ीरों में बांटते समय, अपने किसी वज़ीर को, खास तौर पर रियासत के स्वाधीन जिलों और स्वाधीन इलाकों की भलाई का काम सौंप सकता है.

**15—ज़िला और इलाका मंडलों के कामों और ठहरावों को मंजूर करना या मुअत्तल करना—**(1) अगर किसी समय रियासतपति को इस बात का इतमीनान हो जाय कि किसी ज़िला मंडल या इलाका मंडल के किसी काम या ठहराव से भारत की रक्षा को कोई खतरा पैदा हो सकता है तो वह ऐसे काम या ठहराव को मंजूर कर सकता है या मुअत्तल कर सकता है, और ऐसे क़दम उठा सकता है (जिसमें उस मंडल का मुअत्तल किया जाना और मंडल को जो शक्तियाँ हासिल थीं या जिन से वह मंडल काम ले सकता था उन सबको या उनमें से किसी को अपने हाथ में ले लेना भी शामिल है) जिन्हें वह उस काम को न होने देने या उसके जारी न रहने देने, या उस ठहराव पर अमल न होने देने के लिये ज़रूरी समझे.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन रियासतपति जो हुकुम देगा वह हुकुम और उसके दिये जाने के कारन जितनी जल्दी हो सकेगा रियासत की क़ानून सभा के सामने रखे जायेंगे, और जब तक उसे उस रियासत की क़ानून सभा मंजूर न कर दे तब तक वह हुकुम जिस तारीख को दिया गया था उससे बारह महीने के अरसे तक अमल में रहेगा :

शर्तें कि अगर और जितनी बार रियासत की क़ानून सभा ऐसे किसी हुकुम को अमल में रखने के लिये अपनी राजामन्दी का ठहराव पास कर दे, उतनी बार वह हुकुम, उस तारीख से लेकर जिस पर वह इस पैरा के अधीन ठहराव पास न होने की सूरत में अमल में न रहता, बारह महीने के एक और अरसे तक अमल में रहेगा, जब तक कि रियासतपति उसे रद्द न कर दे.

**16—किसी ज़िला या इलाका मंडल का भंग किया जाना—**रियासतपति, इस पट्टी के पैरा 14 के अधीन नियोजे हुए किसी कमीशन की सिफ़ारिश पर, आम नोटिस निकाल कर, किसी ज़िला या इलाका मंडल के भंग किये जाने का हुकुम दे सकता है, और—

- (ए) यह निर्देश दे सकता है कि मंडल के फिर बनाए जाने के लिये कौरन नया आम चुनाव किया जायगा, या
- (बी) रियासत की कानून सभा की पहले से राजामन्दी लेकर, अधिक से अधिक बारह महीने के अरसे के लिये उस मंडल के अधिकार के अधीन वाले क्षेत्र का शासन अपने हाथ में ले सकता है, या उस क्षेत्र का शासन उस पैरा के अधीन नियोजित हुए कमीशन के हाथों में, या किसी दूसरी संस्था के हाथों में जिसे वह ठीक समझे दे सकता है :

शर्तें कि जब इस पैरा की धारा (ए) के अधीन कोई हुकुम दिया जा चुका हो तो रियासतपति नया आम चुनाव होने पर मंडल के फिर से बनने तक, जिस क्षेत्र का सवाल है उसके शासन के संबंध में वह कारवाई कर सकता है जिसकी चरचा इस पैरा की धारा (बी) में की गई है :

और शर्तें कि, जिला मंडल या इलाका मंडल को, जैसी सूरत हो, रियासत की कानून सभा के सामने अपने विचार रखने का मौका दिये बिना, इस पैरा की धारा (बी) के अधीन कोई कारवाई नहीं की जायगी.

**17—स्वाधीन जिलों में चुनाव हलके बनाने के लिये उन जिलों में से क्षेत्रों का अलग करना—**आसाम के आम सदन के चुनावों के मतलबों के लिये रियासतपति हुकुम देकर जाहिर कर सकता है कि किसी स्वाधीन जिले के अन्दर का कोई क्षेत्र आम सदन में उस जिले के लिये अलग रखी किसी सीट या सीटों को भरने के लिये बने किसी चुनाव हलके का भाग नहीं होगा, बल्कि किसी ऐसे चुनाव हलके का भाग होगा जो उस हुकुम में बता दिया जाय और जो उस सदन में किसी ऐसी सीट या सीटों को भरने के लिये हो, जो इस तरह अलग नहीं रखी गई हैं.

**18—पैरा २० के साथ के नक्शे के भाग (बी) में दर्ज क्षेत्रों पर इस पट्टी के बंधानों का लागू होना—**  
(1) रियासतपति—

(ए) राजपति की पहले से रज़ामन्दी लेकर और आम नोटिस निकालकर इस पट्टी के ऊपर-लिखे सब बंधानों या उन में से किसी को, इस पट्टी के पैरा 20 के साथ के नक्शे के भाग (बी) में दर्ज किसी क़बाइली छेत्र पर या ऐसे छेत्र के किसी भाग पर लागू कर सकता है, और ऐसा होने पर उस छेत्र का या उस भाग का शासन उन बंधानों के अनुसार किया जायगा, और

(बी) इसी तरह की रज़ामन्दी लेकर और आम नोटिस निकालकर, ऊपर बताए नक्शे के भाग (बी) में दर्ज किसी क़बाइली छेत्र को या उस छेत्र के किसी भाग को उस नक्शे में से अलग कर सकता है.

(2) जब तक ऊपर बताए नक्शे के भाग (बी) में दिये हुए किसी क़बाइली छेत्र के बारे में या उस छेत्र के किसी भाग के बारे में इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन कोई नोटिस न निकाला जाय तबतक उस छेत्र का या उसके उस भाग का शासन, जैसी सूरत हो, राजपति आसाम के रियासतपति की मारफ़त उसे अपना एजेंट मान कर चलायगा, और भाग नौ के बंधान उस छेत्र या उसके उस भाग पर उसी तरह लागू होंगे मानो वह छेत्र या उसका वह भाग पहली पट्टी के भाग (डी) में दर्ज कोई भूभाग है.

(3) इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन राजपति के एजेंट की हैसियत से अपने काम निभारने में रियासतपति अपनी समझ से काम करेगा.

**19—बिच-वक्ती बंधान—**(1) इस विधान के आरंभ होने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा, रियासतपति इस पट्टी के अधीन रियासत के हर स्वाधीन ज़िले के लिये एक एक ज़िला मंडल बनाने के लिये क़दम उठायगा, और जब तक किसी स्वाधीन ज़िले के लिये इस तरह ज़िला मंडल न बन जाय तब तक उस ज़िले का शासन रियासतपति के हाथों में रहेगा, और उस ज़िले के अन्दर के छेत्रों के शासन पर, इस पट्टी में ऊपर-लिखे बंधानों की जगह नीचे लिखे बंधान लागू होंगे, यानी :—



(ए) राजपंचायत का या उस रियासत की कानून सभा का कोई एक्ट ऐसे किसी क्षेत्र पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि रियासतपति आम नोटिस निकाल कर इसका निर्देश न दे दे; और किसी एक्ट के बारे में ऐसा निर्देश देते समय रियासतपति यह निर्देश दे सकता है कि उस क्षेत्र पर या उसके किसी बताए हुए भाग पर लागू होने में उस एक्ट का असर उन अपवादों या अदल बदल के अधीन होगा जो रियासतपति ठीक समझे;

(बी) रियासतपति ऐसे किसी क्षेत्र की शान्ति और अच्छी हुकूमत के लिये क्रायदे बना सकता है और जो क्रायदे इस तरह बनाए जायं वह राजपंचायत के या रियासत की कानून सभा के ऐसे किसी एक्ट को या ऐसे किसी मौजूदा कानून को जो उस समय उस क्षेत्र पर लागू होता हो, रद्द कर सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं.

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) की धारा (ए) के अधीन रियासतपति जो निर्देश दे वह इस तरह दिया जा सकता है कि उसका पिछ-लगता असर हो.

(3) इस पैरा के उप-पैरा (1) की धारा (बी) के अधीन बने हुए सब क्रायदे उसी समय राजपति के सामने रखे जायेंगे, और जब तक राजपति उन पर मंजूरी न दे दे उनका कोई असर नहीं होगा.

20—कबाइली क्षेत्र—(1) जो क्षेत्र नीचे दिये हुए नक्शे के भाग (ए) और (बी) में दर्ज हैं वह आसाम की रियासत के अन्दर कबाइली क्षेत्र होंगे.

(2) युक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ी जिले में वह भूभाग शामिल होंगे जो इस विधान के आरंभ से पहले खासी रियासत और खासी और जैन्तिया पहाड़ी जिला कहलाते थे; इनमें वह क्षेत्र शामिल नहीं होंगे जो उस समय शिलांग की छावनी और नगरायत में शामिल हों,

पर शिलांग की नगरायत के अन्दर के क्षेत्र का उतना भाग शामिल होगा जो मिज़िएम की खासी रियासत का भाग था :

शर्तें कि इस पट्टी के पैरा 3 के उप-पैरा (1) की धारा (ई) और (एफ), पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6, पैरा 8 के उप-पैरा (2), उप-पैरा (3) की धारा (ए), (बी) और (डी), और उप-पैरा (4), और पैरा 10 के उप-पैरा (2) की धारा (डी) के मतलबों के लिये शिलांग की नगरायत के अन्दर के क्षेत्र का कोई भाग युक्त खासी जैन्तिया पहाड़ी जिले में नहीं समझा जायगा।

(3) नीचे दिये नक्शे में किसी जिले (युक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ी जिले को छोड़ कर) या शासनी क्षेत्र की चरचा से उस जिले या क्षेत्र की चरचा समझी जायगी जैसा वह इस विधान के आरंभ के समय था :

शर्तें कि नीचे दिये नक्शे के भाग (बी) में दर्ज क्वाइली क्षेत्रों में मैदानों के कोई ऐसे क्षेत्र शामिल नहीं होंगे जिनकी बाबत, पहले से राजपति की रज़ामंदी लेकर, आसाम का रियासतपति इस तरह का नोटिस निकाल दे।

### नक्शा

#### भाग (ए)

1. युक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ी जिला.
2. गारो पहाड़ी जिला.
3. लुसाई पहाड़ी जिला.
4. नागा पहाड़ी जिला.
5. उत्तर कछार पहाड़ियां.
6. मिक्किर पहाड़ियां.

#### भाग (बी)

1. उत्तर पूरब सरहदी खित्ता जिसमें बालीपारा सरहदी खित्ता, तिराप सरहदी खित्ता, अबोर पहाड़ी जिला और मिसिमी पहाड़ी जिला शामिल हैं.
2. नागा क्वाइली क्षेत्र.

## सातवीं पट्टी

[ दफा 246 ]

### तालिका एक—यूनियन तालिका

1. भारत का और भारत के हर भाग का बचाव, जिसमें बचाव की तैयारी और वह सब काम शामिल हैं जिनसे जंग के समय जंग चलाने में और जंग खतम होने के बाद असरदार ढंग से लाम तोड़ने में मदद मिले.

2. समन्दरी, जमीनी और हवाई फौजें; यूनियन की कोई और हथियार-बन्द फौजें.

3. छावनी छेत्रों की हद्दबन्दी, उन छेत्रों में मुकामी स्वराज, उन छेत्रों में छावनी अधिकारियों की बनावट और शक्तियां, और उन छेत्रों में मकानी गुंजाइश की क़ायदाबन्दी ( जिसमें किरायों पर दबान शामिल है ).

4. समन्दरी, जमीनी और हवाई फौजों की इमारतें.

5. हथियार, आग-हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक.

6. ऐटम शक्ति और उसे पैदा करने के लिये ज़रूरी खनिज साधन.

7. वह उद्योग जिन्हें राजपंचायत क़ानून बना कर बचाव के मतलब के लिये या जंग चलाने के लिये ज़रूरी ठहरा दे.

8. जानकारी और जांच का मरकज़ी महकमा.

9. बचाव, बिदेशी मामलों, या भारत की सुरक्षा से संबंध रखने वाले कारनों से रोकथामी नज़रबन्दी, इस तरह नज़रबन्द किये हुए लोग.

10. बिदेशी मामले; वह सब मामले जिनसे यूनियन का किसी बिदेशी मुल्क से संबंध होता है.

11. राजदूती, बनिजदूती और ब्योपारी प्रतिनिधान.

12. संयुक्त क़ौमी संगठन (यू एन ओ )

13. अन्तर-क़ौमी कानफ़रेन्सों, सभाओं और दूसरी संस्थाओं में भाग लेना और वहाँ जो फ़ैसले किये जाय उन पर काम कराना.

14. विदेशी मुल्कों के साथ संधिनामे और समझौते करना और विदेशी मुल्कों के साथ जो संधिनामे, समझौते और माने हुए रिवाज हों उन पर काम कराना.

15. जंग और सुलह.

16. विदेशी अमलदारी.

17. नागरता, देखीकरन और विदेशी लोग.

18. परसौपनी.

19. भारत में दाखिल होना, और भारत से बाहर जा बसना और भारत से निकाला जाना; पासपोर्ट और बीसा.

20. भारत से बाहर जगहों की तीर्थ यात्रा.

21. समन्दरी डकैतियां और जुर्म जो बीच समन्दर पर या हवा में किये जायं; क्रौमी के कानून के खिलाफ जुर्म जो जमीन पर या बीच समन्दर पर या हवा में किये जायं.

22. रेलमार्ग.

23. थल मार्ग जिन्हें राजपंचायत के बनाए किसी कानून में या ऐसे किसी कानून के अधीन क्रौमी थल मार्ग ठहरा दिया गया है.

24. देश के अन्दर के उन जल मार्गों पर, जिन्हें राजपंचायत ने कानून बना कर क्रौमी जल मार्ग ठहरा दिया हो, मशीनों से चलने वाले जहाजों के जरिये जहाजबानी और जहाजरानी; ऐसे जल-मार्गों पर मार्ग नियम.

25. समन्दरी जहाजबानी और जहाजरानी, जिसमें उबार-जल पर की जहाजबानी और जहाजरानी शामिल हैं; तिजारती बेड़े के लिये तालीम और ट्रेनिंग का प्रबन्ध, और इस तरह की तालीम और ट्रेनिंग का रियासतें और दूसरी एजेन्सियां जो प्रबन्ध करें उसकी क्रायदाबन्दी.

26. दीप-घर, जिसमें दीप जहाज, मार्ग-संकेत, और जहाजों और हवा जहाजों की सलाहती के लिये दूसरे प्रबन्ध शामिल हैं.

27. वह बन्दरगाह जो राजपंचायत के बनाए किसी कानून में या किसी मौजूदा कानून में या उनके अधीन 'बड़े बन्दरगाह' ठहरा

दिये गए हैं, जिनमें उनकी हृदयबन्दी, और उन बन्दरगाहों के अधिकारियों का बनाना और उनकी शक्तियां शामिल हैं।

28. बन्दरगाह चालीसिया, जिसमें उस संबंध के अस्पताल शामिल हैं; मल्लाही और समन्दरी अस्पताल।

29. हवा मार्ग; हवा जहाज और हवा-जहाजरानी; हवाई अड्डों का प्रबन्ध; हवा व्यापार और हवाई अड्डों की क्रायदाबन्दी और संगठन; हवा विद्या की तालीम और ट्रेनिंग का प्रबन्ध, और इस तरह की तालीम और ट्रेनिंग का रियासतें और दूसरी एजेन्सियां जो प्रबन्ध करें उसकी क्रायदाबन्दी।

30. सवारियों और माल का रेल मार्ग, समन्दर या हवा के रास्ते, या मशीनों से चलने वाले जहाजों में क्रौमी जल मार्गों से लाना, ले जाना।

31. डाक और तार; टेलीफोन, बेतार, धुनपसार और आवा-जाई के ऐसे ही दूसरे रूप।

32. यूनियन की जायदाद और उससे मालगुजारी, पर जो जायदाद पहली पट्टी के भाग (ए) या भाग (बी) में दर्ज किसी रियासत में है उस के बारे में उस रियासत के कानूनों के अधीन रहते हुए, सिवाय जहाँ तक कि राजपंचायत कानून बना कर कुछ और बंधान कर दे।

33. यूनियन के मतलबों के लिये जायदाद का हासिल करना या मंगैनी ले लेना।

34. देसी रियासतों के शासकों की मिलकियतों के लिये कोर्ट-कचहरियां।

35. यूनियन का सरकारी क्ररजा।

36. सिक्का चलन, सिक्का-गढ़न और कानूनी सिक्का; विदेशी सिक्का-बदलाव।

37. विदेशी उधारियां।

38. भारत का रिज़र्व बैंक।

39. डाकघर बचत बैंक।

40. भारत सरकार की या रियासत की सरकार की चलाई लाटरियां।

41. विदेशी मुल्कों से ब्योपार और तिजारत; बिदेसनी महसूल की सीमा के पार आयासी और निकासी; बिदेसनी महसूल की सीमाओं की परिभाशा.

42. अन्तर-रियासती ब्योपार और तिजारत.

43. ब्योपारी एकतनियों को एकतन करना, उनकी क्रायदाबन्दी और उनका समेटना, इसमें बंकदारी, बीमा और माली एकतनियां शामिल हैं पर सहकारी समितियां शामिल नहीं हैं.

44. ऐसी एकतनियों को एकतन करना, उनकी क्रायदाबन्दी और उनका समेटना, चाहे वह ब्योपारी हों या न हों, जिनके उद्देश एक रियासत तक महदूद नहीं हैं, पर इनमें बिद्यापीठें शामिल नहीं हैं.

45. बंकदारी.

46. बदलाव-हुंडियाँ, चेक, प्रामिसरी नोट और इसी तरह के दूसरे पट्टे.

47. बीमा.

48. शेयर बाजार और पेश बाजार.

49. पेटेंट, ईजादें और डिजाइन; कापी राइट; ब्योपार-छाप और सौदागरी-माल-छाप.

50. तोल और माप के मान क्रायम करना.

51. भारत से बाहर भेजे जाने वाले और एक रियासत से दूसरी रियासत में जाने वाले माल के गुन-मान क्रायम करना.

52. वह उद्योग जिन का यूनियन के दवान में रहना राजपंचायत ने क़ानून बना कर जनता के हित में समयोचित ठहरा दिया है.

53. तेल-छेत्रों और खनिज तेल के स्रोतों की क्रायदाबन्दी और उनका विकास; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बनी चीजें; दूसरे वह तरल और वह चीजें जिन्हें राजपंचायत ने क़ानून बनाकर भयानक आग-पकड़ ठहरा दिया है.

54. उस हद तक खदानों की क्रायदाबन्दी और खनिजों का विकास जिस हद तक कि इस तरह की क्रायदाबन्दी और विकास को

यूनियन के दबान में रखना राजपंचायत ने कानून बना कर जनता के हित में समयोचित ठहरा दिया है.

55. खदानों और तेल-क्षेत्रों में मजदूरी की क्रायदाबन्दी और सलामती .

56. उस हद तक अन्तर-रियासती नदियों और नदी-घाटियों की क्रायदाबन्दी और विकास जिस हद तक कि इस तरह की क्रायदाबन्दी और विकास को यूनियन के दबान में रखना राज-पंचायत ने कानून बनाकर जनता के हित में समयोचित ठहरा दिया है.

57. भूभागी समन्दर से परे मछली पकड़ना और मछियारी.

58. यूनियन की एजेंसियों का नमक बनाना, मोहय्या करना और बांटना; दूसरी एजेंसियाँ जो नमक बनाएं, मोहय्या करें और बांटें उसकी क्रायदाबन्दी और उस पर दबान.

59. अफीम की खेती, उसका बनाना और देश-बाहर निर्यात के लिये उसकी बिक्री.

60. सिनेमा फिल्मों को दिखाने की मंजूरी.

61. यूनियन के कामगारों संबंधी उद्योगी क़गड़े.

62. वह संस्थाएँ जो इस विधान के आरंभ के समय नेशनल लाइब्रेरी, इन्डियन म्यूजियम, इम्पीरियल वार म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल और इन्डियन वार मेमोरियल कहलाती थीं और ऐसी कोई और संस्था जिसमें कुल या कुछ रुपया हिन्द सरकार का लगा हो और जिसे राजपंचायत कानून बना कर क़ौमी महत्व की संस्था ठहरा दे.

63. वह संस्थाएँ जो इस विधान के आरंभ के समय बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी कहलाती थीं और कोई और संस्था जिसे राजपंचायत कानून बनाकर क़ौमी महत्व की संस्था ठहरा दे.

64. साइंसी या तकनीकी तालीम के लिये वह संस्थाएँ जिन में कुल या कुछ रुपया हिन्द सरकार का लगा हो और जिन्हें राज-पंचायत कानून बना कर क़ौमी महत्व की संस्था ठहरा दे.

65. नीचे लिखे मामलों के लिये यूनियन की एजेंसियां और संस्थाएं:—

- (ए) पेशाई, रोजगारी या तकनीकी ट्रेनिंग, जिसमें पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग शामिल है; या
- (बी) खास पढ़ाईयों या खोज को बढ़ाना; या
- (सी) जुर्म की जांच या पता लगाने में साइंसी या तकनीकी मदद.

66. ऊँची तालीम या खोज की संस्थाओं और साइंसी और तकनीकी संस्थाओं में स्तर तय करना और उनमें तालमेल.

67. प्राचीन और इतिहासी यादगारें और लेखे और पुरातत्त्वी स्थान और खंडहर जिन्हें राजपंचायत क़ानून बनाकर क़ौमी महत्व का ठहरा दे.

68. भारत की सरवे, भारत की भू-विद्या, वनस्पति-विद्या, जन्तु-विद्या और नर-विद्या संबंधी अलग अलग सरवे; खगोल-विद्या संबंधी संस्थाएं.

69. गिनाबा.

70. यूनियन सरकारी नौकरियां; कुल-भारत नौकरियां; यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन.

71. यूनियन पेनशनें, यानी वह पेनशनें जो भारत सरकार को देनी हैं या भारत के मूठकोश में से दी जानी हैं.

72. राजपंचायत के, रियासतों की क़ानून सभाओं के और राजपति और उप-राजपति के पदों के चुनाव; चुनाव कमीशन.

73. राजपंचायत के मेम्बरों की, रियासत सदन के मसनदी और उप-मसनदी की और लोक सदन के सभामुख और उप-सभामुख की तनखाहें और भत्ते.

74. राजपंचायत के हर सदन की और हर सदन के मेम्बरों और कमेटियों की शक्तियां, निजनियम और बरीयतें; राजपंचायत की कमेटियों या राजपंचायत के नियोजे कमीशनों के सम्मने गवाही देने या दस्तावेजों पेश करने के लिये लोगों की हाज़िरी लाज़मी कराना.

75. राजपति और रियासतपतियों के बेतन, भत्ते, निजनियम



और छुट्टी के बारे में अधिकार; यूनियन के वज्जीरों की तनखाहें और भत्ते; दाब अफसर और सरपड़तालिया की तनखाहें, भत्ते और छुट्टी के बारे में अधिकार और नौकरी की दूसरी शर्तें.

76. यूनियन के और रियासतों के हिसाब किताब की पड़ताल.

77. आला अदालत की बनावट, संगठन, अमलदारी और शक्तियां ( जिसमें उस अदालत की तौहीन शामिल है ), और उस अदालत में जो फीसें ली जायं; वह लोग जो आला अदालत में बकालत करने के हकदार हैं.

78. हाईकोर्टों के अफसरों और नौकरों के बारे में बंधानों को छोड़कर हाईकोर्टों की बनावट और संगठन; वह लोग जो हाईकोर्टों में बकालत करने के हकदार हैं.

79. किसी ऐसी हाईकोर्ट की अमलदारी को जिसकी खास जगह किसी रियासत में है उस रियासत से बाहर किसी क्षेत्र तक बढ़ा देना, और उस रियासत से बाहर के किसी क्षेत्र से ऐसी किसी हाईकोर्ट की अमलदारी को अलग कर देना.

80. किसी रियासत के पुलिस बल के मेम्बरों की शक्तियों और अमलदारी को उस रियासत से बाहर के किसी क्षेत्र तक बढ़ा देना, पर इस तरह नहीं कि एक रियासत की पुलिस उस रियासत से बाहर के किसी क्षेत्र में, उस रियासत की सरकार की अनुमति बिना जिसके अन्दर वह क्षेत्र है, अपनी शक्तियों और अमलदारी से काम ले सके; किसी रियासत के पुलिस बल के मेम्बरों की शक्तियों और अमलदारी को उस रियासत से बाहर के रेल मार्ग क्षेत्रों तक बढ़ा देना.

81. एक रियासत से दूसरी रियासत में जा बसना; अन्तर-रियासती चालीसिया.

82. खेती-बाड़ी की आमदनी को छोड़ दूसरी आमदनी पर टैक्स.

83. बिदेसनी महसूल जिनमें निकासी महसूल शामिल हैं.

84. लम्बाकू पर और भारत में बने या पैदा हुए सिवाय नीचे लिखे मालों के, दूसरे माल पर निकासनी महसूल :—

(ए) लोगों में खपत के लिये अलकोहोली तरल;

(बी) अफीम, गांजा और दूसरी पीनक वाली जड़ी-बूटियाँ

और पीनक वाली चीजें,

पर दवा और सिंगार की वह तैयार की हुई चीजें इसमें शामिल हैं जिनमें अलकोहल या इस अन्तरी के उप-पैरा (बी) में आई हुई कोई चीज है.

85. एकतनी टैक्स.

86. खेती बाड़ी की जमीन को छोड़कर, अलग अलग आदमियों और कम्पनियों की लेनदारियों की कुल मालियत पर टैक्स; कम्पनियों की पूंजी पर टैक्स.

87. खेती बाड़ी की जमीन को छोड़कर दूसरी जायदाद के बारे में मिलकियत महसूल.

88. खेती बाड़ी की जमीन को छोड़ कर दूसरी जायदाद की विरासत के बारे में महसूल.

89. रेल मार्ग, समन्दर या हवा से जाने वाले माल या सवारियों पर हदबारी टैक्स; रेल मार्ग के किरायों और भाड़ों पर टैक्स.

90. शेयर बाजारों और पेश बाजारों के सौदों पर स्टाम्प महसूल को छोड़कर दूसरे टैक्स.

91. बदलाव हुंडियों, चेकों, प्रामिसरी नोटों, लदाई बिलटियों, साख-पत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों के तबादलों, करज-पत्रों, एवज़ियों और रसीदों के बारे में स्टाम्प महसूल की दरें.

92. अखबारों की बिकरी या खरीद पर और उनमें निकलने वाले जाहिरात पर टैक्स.

93. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में कानूनों के खिलाफ जुर्म.

94. इस तालिका के मामलों में से किसी के मतलब के लिये पूछताछ, सरवे और आंकड़े.

95. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में आला-अदालत को छोड़ कर और सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियाँ; समन्दरी विभाग की अमलदारी.

96. किसी अदालत में जो फीसें ली जाती हैं उनको शामिल न

करते हुए, इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में कीसैं.

97. कोई दूसरा मामला, जो तालिका दो या तालिका तीन में नहीं गिनाया गया, जिसमें ऐसा टैक्स शामिल है जिसका जिक्र उन तालिकाओं में से किसी में नहीं आया.

### तालिका दो-रियासत तालिका

1. जन-व्यवस्था (लेकिन नागरी शक्ति की मदद के लिये यूनि-यन की समन्दरी, जमीनी या हवाई फौजों या और किसी हथियार-बंद फौजों का इस्तेमाल इसमें शामिल नहीं है).

2. पुलिस, जिसमें रेल मार्ग और गांव पुलिस शामिल है.

3. न्याय-शासन; आला अदालत और हाईकोर्ट के सिवा सब अदालतों की बनावट और उनका संगठन; हाईकोर्ट के अफसर और नौकर; लगान और मालगुजारी की अदालतों का दस्तूर; आला अदालत के सिवा सब अदालतों में ली जाने वाली फीसें.

4. जेलखानें, सुधार-घर, बोरस्टली संस्थाएँ और इसी तरह की दूसरी संस्थाएँ, और वह लोग जो उनमें रोक कर रखे जायें; जेल-खानों और दूसरी संस्थाओं के इस्तेमाल के लिये दूसरी रियासतों के साथ प्रबन्ध.

5. मुकामी हकूमत, यानी नगर एकतनियों, नगर सुधार ट्रस्टों, जिला बोर्डों, खदान आबादी अधिकारियों, और मुकामी स्वराज या गांव शासन के मतलब के लिये दूसरे मुकामी अधिकारियों, की बनावट और उनकी शक्तियां.

6. जन-तन्दुरुस्ती और सफाई; अस्पताल और दवाखाने.

7. तीर्थ यात्राएँ, भारत से बाहर जगहों की तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर.

8. नशीले तरल, यानी नशीले तरलों का पैदा करना, बनाना, रखना, लाना ले जाना, खरीदना और बेचना.

9. अपाहिजों और काम न कर सकने वालों की मदद.

10. दफन और दफन-भूमियां; दाह और दाह-भूमियां.

11. तालीम जिसमें विद्यापीठ शामिल हैं पर तालिका एक की अन्तरी 63, 64, 65 और 66 और तालिका तीन की

अन्तरी 25 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

12. वह किताबघर, अजायबघर, और इस तरह की दूसरी संस्थाएँ जो रियासत के दवान में हों या रियासत के रूप से चलती हों; प्राचीन और इतिहासी यादगारें और लेखे, उन्हें छोड़ कर जिन्हें राजपंचायत कानून बना कर कौमी महत्व का ठहरा दे.

13. आवा-जाई के साधन यानी सड़कें, पुल, उतराई घाट, और आवा-जाई के ऐसे दूसरे साधन जो तालिका एक में दर्ज नहीं हैं; नगर ट्राम मार्ग; रस्सा मार्ग; देश अन्दर के जल मार्ग और ऐसे जल मार्गों के बारे में तालिका एक और तालिका तीन के बंधानों का ध्यान रखते हुए उन पर का व्यापार; मशीन से चलने वाली गाड़ियों को छोड़ कर दूसरी गाड़ियां.

14. खेती बाड़ी, जिसमें खेती बाड़ी की तालीम और खोज, महामारी से रक्षा और पौदों की बीमारियों की रोकथाम शामिल है.

15. मवेशियों को बनाए रखना, बचाए रखना, और उनकी नसल सुधारना, और जानवरों की बीमारियों की रोकथाम; पशु-इलाज की ट्रेनिंग और उसका ब्योहार.

16. कांजी हौज और मवेशियों के हृद लांघने की रोकथाम.

17. पानी, यानी पानी पहुँचाना, सिंचाई और नहरें, पानी का निकास और बांध, पानी इकट्ठा करना और पन-शक्ति, तालिका एक की अन्तरी 56 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

18. ज़मीन, यानी ज़मीन में या ज़मीन पर अधिकार, भूमि-दारियां जिनमें ज़मींदार और किसान का संबंध शामिल है, और लगान जमा करना; खेती बाड़ी की ज़मीन का दाखिल-खारिज और दूसरों को दे डालना; ज़मीन को सुधारना और खेती बाड़ी के लिये उधारियां; बस्तियां बसाना.

19. जंगल्लात.

20. जंगली जानवरों और परिन्दों की रक्षा.

21. मछियारियां.

22. तालिका एक की अन्तरी 34 के बंधानों का ध्यान रखते हुए कोरट कचहरियां; करजा-दबी और कुर्क मिलकियतें.

23. यूनियन के दवान में खदानों की क्रायदाबन्दी और खनिजों के विकास की बाबत तालिका एक के बंधानों का ध्यान रखते हुए खदानों की क्रायदाबन्दी और खनिजों का विकास.

24. तालिका एक की अन्तरी 52 के बंधानों का ध्यान रखते हुए उद्योग.

25. गैस और गैस के कारखाने.

26. रियासत के अन्दर ब्योपार और तिजारत, तालिका तीन की अन्तरी 33 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

27. माल का पैदा करना, मोहय्या करना और बांटना, तालिका तीन की अन्तरी 33 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

28. मंडियां और मेले.

29. तोलने के बाट और माप, सिवाय उनके मान क्रायम करने के.

30. रुपया उधार देना और साहूकार; खेतिहरों की कर्जदारी को हल्का करना.

31. सराय और सराय रखने वाले.

32. तालिका एक में दर्ज एकतनियों को छोड़ कर एकतनियों और विद्यापीठों को एकतन करना, उनकी क्रायदाबन्दी, और उनको समेटना; ऐसी ब्योपारी, अदबी, साइंसी, धार्मिक और दूसरी सोसाइटियां और सभाएँ जो एकतन नहीं हैं; सहकारी समितियां.

33. थेटर और नाटक के खेल; तालिका एक की अन्तरी 60 के बंधानों का ध्यान रखते हुए सिनेमा; खेल, मनोरंजन और तमाशे.

34. शर्त बदना और जुभा खेलना.

35. कारखाने, जमीनें और इमारतें जो रियासत को हासिल हैं या जो रियासत के कब्जे में हैं.

36. तालिका तीन की अन्तरी 42 के बंधानों का ध्यान रखते हुए, जायदाद का हासिल कर लेना या मंगैनी ले लेना, सिवाय यूनियन के मतलबों के लिये.

37. राजपंचायत के बनावे किसी कानून के बंधानों का ध्यान रखते हुए रियासत की कानून सभा के चुनाव.

38. रियासत की कानून सभा के मेम्बरों की, आम सदन के

सभामुख और उप-सभामुख की, और अगर खास सदन हो तो उसके मसनदी और उप-मसनदी की तनखाहें और भत्ते.

39. आम सदन की, और उसके मेम्बरों और उसकी कमेटियों की, और अगर खास सदन है तो उस सदन की और उसके मेम्बरों और उसकी कमेटियों की, शक्तियां, निजनियम और बरीयतें; रियासत की कानून सभा की कमेटियों के सामने गवाही देने या दस्तावेजों पेश करने के लिये लोगों की हाजिरी लाजमी कराना.

40. रियासत के वज्जीरों की तनखाहें और भत्ते.

41. रियासत सरकारी नौकरियां; रियासत सरकारी नौकरी कमीशन.

42. रियासत पेनशनें, यानी वह पेनशनें जो रियासत को देनी हैं या रियासत के मूठकोश में से दी जानी हैं.

43. रियासत का सरकारी करखा.

44. गढ़े और लावारसी खजाने.

45. जमीन की मालगुजारी, जिसमें मालगुजारी का तय करना और जमा करना, जमीन के लेखे रखना, मालगुजारी के मतलबों के लिये सरवे और अधिकारों के लेखे, और मालगुजारी दूसरों के नाम करना, सब शामिल हैं.

46. खेती बाड़ी की आमदनी पर टैक्स.

47. खेती बाड़ी की जमीन की विरासत के बारे में महसूल.

48. खेती बाड़ी की जमीन के बारे में मिलकियत महसूल.

49. जमीनों और इमारतों पर टैक्स.

50. उन सीमाओं के अन्दर रहते हुए जो राजपंचायत कानून बना कर खनिजों के विकास के संबंध में तय कर दे, खनिजों के अधिकारों पर टैक्स.

51. नीचे लिखे मालों पर जो उस रियासत में बने हों या पैदा हुए हों निकासनी महसूल, और उसी तरह के मालों पर जो भारत में कहीं और बने हों या पैदा हुए हों उसी दर से या कम दर से पाखंगी महसूल :—

(ए) लोगों में खपत के लिये अलकोहोली तरल;

(बी) अफीम, गांजा और दूसरी पीनक वाली जड़ी बूटियां और पीनक वाली चीजें;  
पर दवा और सिंगार की वह तैयार की हुई चीजें इनमें शामिल नहीं होंगी जिनमें अलकोहल या इस अन्तरी के उप-पैरा (बी) में आई हुई कोई चीज है.

52. किसी मुकामी क्षेत्र में खपत, इस्तेमाल या बिकरी के लिये माल की आमद पर टैक्स.

53. बिजली की खपत या बिकरी पर टैक्स.

54. अखबारों को छोड़ कर दूसरे मालों की बिकरी या खरीद पर टैक्स.

55. अखबारों में निकलने वाले जाहिरात को छोड़ कर दूसरे जाहिरात पर टैक्स.

56. सड़कों से या देश-अन्दर के जलमार्गों से जाने वाले माल और सवारियों पर टैक्स.

57. ऐसी गाड़ियों पर टैक्स, चाहे वह मशीन से चलती हों या नहीं, जो सड़कों पर इस्तेमाल के काबिल हों, जिनमें ट्राम-गाड़ियां शामिल हैं, पर तालिका तीन की अन्तरी 35 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.

58. जानवरों और किशतियों पर टैक्स.

59. टोल टैक्स.

60. पेशों, व्यापारों, रोजगारों और कामगारियों पर टैक्स.

61. आदमीवार टैक्स.

62. ऐश की चीजों पर टैक्स, जिनमें मनोरंजनों, तमाशों, शर्त बंदने और जूए पर टैक्स शामिल हैं.

63. स्टाम्प महसूल की दरों के बारे में तालिका एक के बंधानों में जो दस्तावेजों बताई गई हैं उनको छोड़कर दूसरी दस्तावेजों के बारे में स्टाम्प महसूल की दरें.

64. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में कानूनों के खिलाफ जुर्म.

65. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में आला-

अदालत के सिवा सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां,

66. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में फीसें, लेकिन किसी अदालत में ली जाने वाली फीसें इसमें शामिल नहीं हैं.

### तालिका तीन—संगचारी तालिका

1. फौजदारी कानून, जिस में वह सब मामले शामिल हैं जो इस विधान के आरंभ के समय ताजीरात हिन्द में शामिल हों, पर तालिका एक या तालिका दो में दर्ज मामलों में से किसी के बारे में कानूनों के खिलाफ जुर्म इसमें शामिल नहीं है और न नागरी शक्ति की मदद के लिये यूनियन की समन्दरी, जमीनी या हवाई फौजों या दूसरी किसी हथियार-बन्द फौजों का इस्तेमाल इसमें शामिल है.

2. फौजदारी दस्तूर, जिसमें वह सब मामले शामिल हैं जो इस विधान के आरम्भ के समय ज्ञान्ता फौजदारी में शामिल हों.

3. किसी रियासत की सुरक्षा से, जन-व्यवस्था को बनाए रखने से, या समाज के लिये जरूरी रसद और नौकरियों को बनाए रखने से संबंध रखने वाले कारनों से रोकथामी नज़रबन्दी; वह लोग जो इस तरह नज़रबंद रखे जायें.

4. क़ैदियों का, मुलजिमों का और इस तालिका की अन्तरी 3 में दर्ज कारनों से रोकथामी नज़रबन्दी में रखे लोगों का एक रियासत से दूसरी रियासत को हटाया जाना.

5. ब्याह-शादी और तलाक़; दुधमुँह बच्चे और नाबालिग; गोद लेना; बसीयतें, बेवसीयती और विरासत; मिला-जुला परिवार और बटवारा; वह सब मामले जिनके बारे में इस विधान के आरंभ होने से ठीक पहले अदालती कारवाइयों के फ़रीक़ अपने अपने निजी कानून के अधीन थे.

6. खेती बाड़ी की ज़मीन को छोड़ कर दूसरी जायदाद का तबादला; तमस्सुकों और इस्तावेजों की रजिस्ट्री.

7. ठेके, जिसमें सामेदारी, एजेंसी, माल ढोने के ठेके, और ठेकों के दूसरे खास रूप शामिल हैं, पर जिनमें खेती बाड़ी की ज़मीन के बारे में ठेके शामिल नहीं हैं.

8. कानूनी कारवाई के क़ाबिल ग़लत काम.



9. नादार हो जाना और दिवाला.
10. ट्रस्ट और ट्रस्टी.
11. सर प्रबन्धक और सरकारी ट्रस्टी.
12. गवाही और हलफ; कानूनों, सरकारी कामों और सरकारी लेखों, और अदालती कारवाइयों का माना जाना.
13. दीवानी दस्तूर, जिसमें वह सब मामले शामिल हैं जो इस विधान के आरंभ के समय ज्ञात्ता दीवानी में शामिल हों, मियाद-बन्दी और पंचनामा.
14. अदालत की तौहीन, पर जिसमें आला अदालत की तौहीन शामिल नहीं है.
15. आबारागरदी; खानाबदोश और मौसमी कबीले.
16. पागलपन और दिमागी कमी, जिसमें वह जगहें शामिल हैं जहां पागलों और दिमागी कमी वालों को लिया जाय या उनका इलाज किया जाय.
17. जानवरों पर बेरहमी की रोकथाम.
18. खाने की चीजों और दूसरे माल में मिलावट.
19. जड़ी बूटियां और जहर, अफीम के बारे में तालिका एक की अन्तरी 59 के बंधानों का ध्यान रखते हुए.
20. आर्थिक और समाजी योजना.
21. तिजारती और उद्योगी इजारे, ब्योपारी गुट और ट्रस्ट.
22. ट्रेड यूनियन; उद्योगी और मजदूरी मगड़े.
23. समाजी सुरक्षा और समाजी बीमा; कामगारी और बेकामगारी.
24. मजदूरों की भलाई, जिसमें काम की शर्तें, प्राविडेन्ट फण्ड, मालिकों की देनदारी, कामगारों की नुकसान-भरपाई, निबल और बुढ़ापा पेनशनें और जापा रियायतें शामिल हैं.
25. मजदूरों की रोजगारी और तकनीकी ट्रेनिंग.
26. कानूनी, डाक्टरी और दूसरे पेशे.
27. हिन्दू और पाकिस्तान डोमिनियनों के क्रायम होने के कारन अपनी पहली रहने की जगह से उखड़े हुए लोगों की मदद और उनका फिर-बसाव.

28. खैरात और खैराती संस्थाएँ, खैराती और धार्मिक देन और धार्मिक संस्थाएँ.

29. उड़नी बीमारियों या छूत की बीमारियों या आदमियों, जानवरों या पौधों पर असर करने वाली महामारियों, के एक रियासत से दूसरी रियासत में फैलने की रोकथाम.

30. जीवन आंकड़े, जिसमें जनम और मौत की रजिस्ट्री शामिल है.

31. बन्दरगाह, उन बन्दरगाहों को छोड़ कर जिनको राज-पंचायत के बनाए कानून में या मौजूदा कानून में या उनके अधीन बड़े बन्दरगाह ठहरा दिया गया हो.

32. देश-अन्दर के जलमार्गों पर, जहां तक मशीन से चलने वाले जहाजों का सम्बन्ध है, जहाजबानी और जहाजरानी, ऐसे जलमार्गों पर मार्ग नियम, और क्रौमी जल मार्गों के बारे में तालिका एक के बंधानों का ध्यान रखते हुए, देश-अन्दर के जलमार्गों पर सवारियों और माल का लाना लेजाना.

33. जहां कुछ उद्योगों को यूनियन के दबान में रखना राज-पंचायत ने कानून बनाकर जनता के हित में समयोचित ठहरा दिया हो, वहां उन उद्योगों की पैदावार का ब्योपार और तिजारत, और उनका पैदा करना, मोहय्या करना और बांटना.

34. दाम कंट्रोल.

35. मशीनों से चलने वाली गाड़ियां, जिसमें वह सिद्धान्त शामिल हैं जिनके अनुसार ऐसी गाड़ियों पर टैक्स लगाये जायंगे.

36. फैक्टरियां.

37. बायलर.

38. बिजली.

39. अखबार, किताबें और द्वापेखाने.

40. पुरातत्त्वी स्थान और खंडहर, उनको छोड़ कर जिन्हें राज-पंचायत कानून बना कर क्रौमी महत्व का ठहरा दे.

41. उस जायदाद की रखवाली, प्रबन्ध और निपटारा ( जिसमें खेती बाड़ी की ज़मीन शामिल है ), जिसे कानून ने घर छुट-जायदाद ठहरा दिया हो.

42. वह सिद्धान्त जिन पर यूनियन के या किसी रियासत के मतलबों के लिये या किसी दूसरे सरकारी मतलब के लिये जो जायदाद हासिल कर ली जाय या मंगैनी ले ली जाय उसकी नुक़सान भरपाई तय की जानी है, और जिस रूप में और जिस ढंग से वह भरपाई दी जानी है.

43. किसी रियासत में टैक्सों और दूसरी सरकारी मांगों के बारे में, जिनमें ज़मीन की मालगुजारी की बक्राया और ऐसी बक्राया के रूप में जो रकम में वसूल करनी हैं वह शामिल हैं, उन दावों की वसूली जो उस रियासत के बाहर पैदा हुए हों.

44. अदालती स्टाम्पों से जो महसूल या फ़ीस जमा की जाय उनको छोड़ कर दूसरे स्टाम्प महसूल, पर इसमें स्टाम्प महसूल की दरें शामिल नहीं हैं.

45. तालिका दो या तालिका तीन में दर्ज मामलों में से किसी के मतलबों के लिये पूछताछ और आंकड़े.

46. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में, आला अदालत के सिवा, सब अदालतों की अमलदारी और शक्तियां.

47. इस तालिका के मामलों में से किसी के बारे में फ़ीस, लेकिन किसी अदालत में ली जाने वाली फ़ीस इसमें शामिल नहीं हैं.

## आठवीं पट्टी

[ दफ्ता 344 (1) और 351 ]

भाषाएँ

1. आसामी.
  2. बंगला.
  3. गुजराती.
  4. हिन्दी.
  5. कन्नड.
  6. कश्मीरी.
  7. मलयालम.
  8. मराठी.
  9. उड़िया.
  10. पंजाबी.
  11. संस्कृत.
  12. तामिल.
  13. तेलगू.
  14. उर्दू.
-



भारत के विधान  
की  
शब्द-माला



# शब्दमाला

## हिन्दी से अंगरेज़ी

हिन्दी के कुछ शब्द जो इस अनुवाद में बरते गए हैं और

उनके सामने मूल अंगरेज़ी के जवाबी शब्द

अ	अदालती क्रैसला—Adjudication
अचल—Immoveable	अदालती स्टाम्प—Judicial stamp
अचानक मांग—Unexpected demand	अधिक अदालत—Additional court
अचानक—Emergency	अधिक खर्च—Excess expenditure
अचानकी का ऐलान—Proclamation of emergency	अधिक ज़िला जज—Additional District Judge
अचानकी बन्धान—Emergency provision	अधिक देनगी—Excess grant
अछूतपन—Untouchability	अधिक सेशन जज—Additional Sessions Judge
अजायबघर—Museum	अधिकार—Right
अजोगता—Disqualification	अधिकारना—To authorise
अदब साहित्य—Literature	अधिकारी—Authority
अदबी—Literary	अधिकारी अदालत—Competent Court
अदल बदल—Modification	अधिकारी क़ानून सभा—Competent Legislature
अदल बदल करना—To modify	अन-ओटी रुई—Unginned cotton
अदा करना—To make payment, to repay	अनकरी ज़रूरत—Undeserved want
अदा करना, अपने को—To express oneself	अनधिकार—Incompetency
अदायगी—Payment	अनमिल क्रैसला—Dissenting judgment
अदालत—Court	
अदालती कारवाई—Judicial proceeding	



## भारत का विधान

अनमिल राय—Dissenting Opinion	अफसर—Office
अनसह्ये खर्च—Unforeseen expenditure	अवरक—Mica
अनिश्चित रूप—Indefinite character	अमलदारी—Jurisdiction
अनुकूलन—Adaptation	अमला—Staff
अनुपात—Ratio	अमली—Practicable, practical
अनुमति—Consent	अमली तजुर्बा—Practical experience
अनुवाद—Translation	अरज़ी पत्र—Representation
अन्तरक्रौषी—International	अर्थ—Interpretation
अन्तरव्योहार—Intercourse	अर्थ व्यवस्था—Economic system
अन्तररियासती—Inter-state	अलकोहल—Alcohol
अन्तरात्मा—Conscience	अलकोहोली तरल—Alcoholic liquor
अन्तरी—Entry	अलग देनगी—Exceptional grant
अपनाना—To adopt	अलग रखना—Reservation
अपमानलेख—Libel	अलग रखी सीट—Reserved seat
अपमानवचन—Slander	अलावा—In addition to
अपवाद—Exception	असक्त—Disability
अपात्र—Ineligible	असर—Effect
अपाहज—Disabled	असरदार—Effective
अपाहजी पेनशन—Disability pension	असरदार ढंग से—Effectively
अपील—Appeal	असल क्रीमत—Principal value
अपील की बिना—Ground of appeal	असल नौकरी—Actual service
अपीली अदालत—Court of appeal	असल वसूली—Net proceeds
अपीली अमलदारी—Appellate jurisdiction	आ
	आंकड़ा—Figure
	आंकड़े—Statistics
	आंकना—To assess

## शब्दमाला

आग-इथियार—Fire-arms	आर्थिक—Economic
आज़ादी—Liberty, freedom	आर्थिक सकत—Economic capacity
आजीवन काछापानी—Transportation for life	आर्थिक संगठन—Economic organisation
आदतन—Habitually	आर्थिक हित—Economic interest
आदमीवार टैक्स—Capitation tax	आला अदालत—Supreme Court
आधार—Basis	आला कमान—Supreme command
आम—General, public	आवाजाई—Communication
आम क़ानून—General law	आवाजाई के साधन—Means of communication
आम चुनाव—General election	आवारागरदी—Vagrancy
आम चुनाव चिदठा—General electoral roll	आवेदन पत्र—Memorial
आम टैक्स—General tax	आसाम जंगल क़ायदाबन्दी, 1891—Assam Forest Regulation, 1891
आमदनी टैक्स—Income tax	
आम दस्तूर—Procedure in general	इ
आम धारा एक्ट, 1897—General Clauses Act, 1897	इकरारनामा—Engagement
आम नोटिस—Public notification	इकहरा बदलता वोट—Single transferable vote
आम सदन—Legislative Assembly	इकाई—Unit
आम हुकुम—General order	इबलास—Session
आमियत—Generality	इजारा—Monopoly
आयासी—Import	इनामी रक़म—Gratuity
आरज़ी—Temporary	इलाक़ा—Region
आरज़ी बन्धान—Temporary provision	इलाक़ा कमिशनर—Regional Commissioner
आरम्भ—Commencement	

## भारत का विधान

इलाका कोश—Regional fund	एकतनी—Corporation
इलाका भाषा—Regional language	एकतनी कम्पनी—Incorporated company
इलाका मंडल—Regional council	एकतनी टैक्स—Corporation tax
इस्तीफा—Resignation	एकता—Unity
इ	एकरूपता—Uniformity
ईजाद—Invention	एक्ट—Act
उ	एजेंट—Agent
उठावा—Issue	एजेंसी—Agency
उड़नी बीमारी—Infectious disease	एटम शक्ति—Atomic energy
उ	एवजी—Proxy
उतराई घाट—Ferry	ऐ
उद्योग—Industry	ऐलान—Proclamation
उद्योगी—Industrial	ऐलान करना—To proclaim, to declare
उद्योगी कारबार—Industrial undetraking	ऐलान निकालना—To issue proclamation
उद्योगी झगड़ा—Industrial dispute	ऐश—Luxury
उधार लेना—Borrowing	ओ
उधारी—Loan	ओटी रुई—Ginned cotton
उधारी लेना—To raise loan	ओहदा—Office
उप-धारा—Sub-clause	औ
उप-राजपति—Vice-President	औसत—Average
उपराजप्रमुख—Uprajpramukh	औसरी सुनी—Casual vacancy
उपाधि—Distinction	क
उम्मीदवार—Candidate	कच्ची उमर—Tender age
ए	कबाइली क्षेत्र—Tribal area
एकतन करना—To incorporate	कबाइली मंडल—Tribal Council
एकतन संस्था—Body corporate	

## शब्दमाला

क्रबाइली समाज—Tribal comm-	क्रानूनकारी—Legislative
unity	क्रानूनकारी काम—Legislative
क्रबीला—Tribe	function
क्रबीला सलाहकार मंडल—Tribes	क्रानूनकारी शक्ति—Legislative
Advisory Council	power
कमीयत—Minority	क्रानूनकारी संबंध—Legislative
कमीशन—Commission	relation
कमेटी—Committee	क्रानून तोड़ना—Violation of law
कम्पनी—Company	क्रानून बनाना—To legislate,
करजपत्र—Debenture	to enact
करजा—Debt	क्रानून शास्त्री—Jurist
करजा खर्च—Debt charges	क्रानूनसभा—Legislature
करजा चुकाई कोश—Sinking fund	क्रानूनसंगत—Lawful
करजा चुकाना, करजा भुगतान—	क्रानूनी कारवाई—Legal pro-
Redemption of debt	ceedings
करजादबी—Encumbered	क्रानूनी मामला—Legal matter
कलचर—Culture	क्रानूनी सवाल—Question of law
कलचरी—Cultural	क्रानूनी सिक्का—Legal tender
कला—Art	कपीराइट—Copyright
कसबा कमेटी—Town com-	काम का संचालन—Conduct of
mittee	business
काजकारी—Executive	कामगार—Employee, work-
काजकारी काम—Executive	man, worker
action, executive function	कामगारी—Employment
काजकारी शक्ति—Executive	कामचलाक—Provisional
power	कामचलाक क्रानूनसभा—Provisi-
कानफ्रेंस—Conference	onal Legislature
क्रानून—Law	कामचलाक राजपंचायत—Provi-
क्रानून का ठोस सवाल—Substan-	sional Parliament
tial question of law	काम निभारना—To discharge
	function

## भारत का विधान

क्रायदा, क्रायदाबन्दी—Regulation	खदान—Mine
क्रायदादारी—Discipline	खदान आबादी अधिकारी—Mining Settlement Authority
क्रायमी हुकुम—Standing order	खनिज—Mineral
कारकर—Acting	खनिज तेल—Mineral oil
कारकर सरजज—Acting Chief Justice	खनिज साधन—Mineral resources
कारबार—Business	खनिजों का विकास—Mineral development
कारवाई रोक देना—Stay of proceedings	खपत—Consumption
कालम—Column	खफ़ीफ़ा अदालत—Small Cause Court
कांजी हौज़ - Cattle pound, pound	खर्च—Expenditure, expense
किताब घर—Library	खर्च की मद में डालना—To appropriate
की रू से—By virtue of	खानाबदोश—Nomadic
कुरकी—Attachment	खास चुनाव चिह्न—Special electoral roll
कुल मालियत—Capital value	खास जानकारी—Special knowledge
कुल वसूली—Whole proceeds	खास टैक्स—Special tax
के इच्छाकाल तक—During the pleasure of	खास दस्तूर—Special procedure
कोर्ट कचहरी—Court of Wards	खास निर्देश—Special directive
कोरम—Quorum	खास पढ़ाई—Special study
क्रौम—Nation	खास प्रतिनिधान—Special representation
क्रौमी जलमार्ग—National waterway	खास बन्धान—Special provision
क्रौमी थलमार्ग—National highway	
क्रौमी हित—National interest	
क्रांसिल समेत सम्राट—His Majesty in Council	
क्लक—Clerk	
ख	
खगोलविद्या—Meteorology	

शब्दमाला

खास रियायत—Special concession	गवरनरी सुबा—Governor's province
खास रूप—Special form	गहरी अचानकी—Grave emergency
खास सदन—Legislative Council	गांव अदालत—Village court
खास सरबचन—Special address	गांव कमेटी—Village committee
खिताब—Title	गांव पुलिस—Village police
खित्ता—Tract	गांव पंचायत—Village panchayat
खुद-मालिक—Sovereign	गांव मंडल—Village council
खुला इजलास—Open court	गांव शासन—Village administration
खेतिहर—Agricultural worker	गारंटी—Guarantee
खेतीबाड़ी—Agriculture	गिनावा—Census
खेतीबाड़ी की आमदनी—Agricultural income	गुन मान—Standard of quality
खेती बाड़ी की ज़मीन—Agricultural land	गुना—Multiple
खैरात—Charity	गैरक़ानूनी—Illegal
ख राती संस्था—Charitable institution	गैर-हिन्दी-भाषी क्षेत्र—Non-Hindi speaking area
खोज—Research	गैस—Gas
खोज निकालना—Discovery	गोद लेना—Adoption
खंड—Chapter	गोला बारूद—Ammunition
खंडहर—Remains	घ
ग	घरछुट—Evacuee
गम्भीरता के साथ—Solemnly	घरछुट जायदाद—Evacuee property
गवरनर—Governor	घरेलू उद्योग—Cottage industry
गवरनर जनरल—Governor General	घाटी—Valle

## भारत का विधान

घायली पेनशन—Wound pension	छावनी अधिकारी—Cantonment authority
<b>च</b>	छावनी क्षेत्र—Cantonment area
चल—Moveable	छुट-क़ानून—Bye-law
चालीसिया—Quarantine	छुट्टी—Leave, leave of absence
चाहनी—Desirable	छूत की बीमारी—Contagious disease
चीफ़ कमिशनर—Chief Com- missioner	क्षेत्र—Area
चीफ़ कमिशनरी सूबा—Chief Commissioner's Province	छोटा सरनामा—Short title
चुनायत—Electorate	<b>ज</b>
चुनाव—Election	जज—Judge
चुनाव अदालत—Election tribunal	जड़ी बूटी—Drug
चुनाव अरज़ी—Election petition	जनक पुरुष—Male progenitor
चुनाव कमिशनर—Election Commissioner	जन-तन्दुस्ती—Public health
चुनाव कमीशन—Election Com- mission	जनता—Public
चुनाव का संचालन—Conduct of election	जनता की संस्था—Public insti- tution
चुनाव चिट्ठा—Electoral roll	जनराज—Republic
चुनाव मंडल—Electoral college	जन-व्यवस्था—Public order
चुनाव हलक़ा—Constituency	जन्तु विद्या—Zoology
चेक—Cheque	जन्मस्थान—Place of birth
<b>छ</b>	जबरन हासिल करना—Compul- sory acquisition
छांटना—To select	जबरी मज़दूरी—Forced labour
छपाख़ाना—Printing press	जबरी सेवा—Compulsory service
छावनी—Cantonment	ज़बती—Forfeiture
	ज़मानत—Security, bail

## शब्दमाला

ज़मीन—Land	जायदाद—Property
ज़मीन का बटवारा—Allotment of land	जाहिरात—Advertisement
ज़मीनी फ़ौज—Military force	बिताऊ वोट—Casting vote
ज़रूरी जज—Ad hoc Judge	जिन्स—Sex
जलपान घर—Restaurant	ज़िला—District
जलमार्ग—Waterway	ज़िला अदालत—District Court
जवाबदेह—Answerable	ज़िला कोश—District fund
जवाबदेही करना—To defend	ज़िला जज—District Judge
जवाबी देसी रियासत—Corres- ponding Indian State	ज़िला बोर्ड—District Board
जवाबी रियासत—Correspond- ing State	ज़िला मंडल—District Council
जवाबी सूबा—Corresponding Province	जीवन आंकड़े—Vital Statistics
जहाज़—Vessel, shipping	जीवन स्तर—Standard of living
जहाज़बानी—Shipping	जुर्म लगाना—To accuse
जहाज़ रानी—Navigation	जोखम का काम—Hazardous employment
जात—Caste	जोग—Qualified
जानकारी और जांच का मरकज़ी महकमा—Central Bureau of Intelligence and Investi- gation	जोगता—Qualification
जापा—Maternity	जोगाजोग—Contingency
जापा मदद—Maternity relief	जोगाजोग कोश—Contingency Fund
जापा रियायत—Maternity benefit	जंग खतम होना—Termination of war
जा बसना—Migration	जंग चलाना—Prosecution of war
ज़ान्ता दीवानी—Code of Civil Procedure	ज्वार जल—Tidal waters
ज़ान्ता फ़ौजदारी—Code of Criminal Procedure	झ
	झुकाव—Tendency
	ट
	टापू—Island



भारत का विधान

द्रुक—Fraction

टेलीफोन—Telephone

टैक्स—Tax

टोल टैक्स—Tolls

ट्रस्ट—Trust

ट्रस्टी—Trustee

ट्रामगाड़ी—Tramcar

ट्राममार्ग—Tramway

ट्रेड यूनियन—Trade Union

ट्रेनिंग—Training

ठ

ठहराव—Resolution

ठहराव पेश करना—To move a  
resolution

ठेका—Contract

ड

डाक और तार—Posts and  
Telegraphs

डाकघर—Post Office

डाकघर बचत बैंक—Post Office  
Savings Bank

डिग्री—Decree

डिजाइन—Design

डिप्टी कमिशनर—Deputy Com-  
missioner

डिवीजन अदालत—Division  
Court

डोमिनियन कानूनसभा—Dominion  
Legislature

त

तकनीकी—Technical

तकनीकी तालीम—Technical  
education

तखसीना—Estimate

तनखाह—Salary

तनपालन तल—Level of  
nutrition

तन्दुस्ती—Health

तफसील—Detail

तबदीलना—To transfer

तबादला—Transfer

तमसुक—Deed

तमाशा—Amusement

तरक्की—Promotion

तरजीह—Preference

तरल—Liquid, liquor

तलाक़—Divorce

तसदीक़ करना—To ratify

ताज़ीरात हिन्द—Indian Penal  
Code

तातील—Vacation

तालमेल—Co-ordination

तालिका—List

तालीम—Education

तालीमी देनगियाँ—Educational  
grants

तालीमी संस्था—Educational  
institution

## शब्दमाला

तिजारत—Commerce	दसखती सनद—Signed
तिजारती कारबार—Commercial	Certificate
undertaking	दस्तावेज—Document
तिजारती बेड़ा—Mercantile	दस्तूर—Procedure
marine	दस्तूरी मामला—Matter of
तिजारती माल—Commodity	Procedure
तिलहन—Oilseeds	दाखला—Admission
तीथयात्रा—Pilgrimage	दाखिल खारिज—Transfer
तेलछेत्र—Oil field	(of proprietary right in
तैनाती—Posting	land)
तोल—Weight	दाब अफसर—Comptroller
तोलने के बाट—Weights	दाब अफसर और सर पड़तालिया—
तौहीन—Contempt	Comptroller and Auditor
	General
थल मार्ग—Highway	दाम कंट्रोल—Price control
थेटर—Theatre	दावा—Claim
थोक कारबार—Wholesale	दावा करना—To claim
business	दाह—Cremation
	दाह भूमि—Cremation
द	ground
दफ्तर—Office	दिमाग की कमजोरी—Infirmary
दफ्तरी गज़ट—Official Gazette	of mind
दफ्तरी भाषा—Official	दिमागी कमी—Mental defi-
language	ciency
दफन—Burial	दिवाला—Insolvency
दफन भूमि—Burial ground	दिवालिया—Insolvent
दफ़ा—Article	दीपघर—Lighthouse
दबान—Control	दीप जहाज़—Lightship
दर—Rate	दीवानी—Civil
दवाखाना—Dispensary	दीवानी अदालत—Civil court

## भारत का विधान

दीवानी अमलदारी—Civil jurisdiction	धन का कीलना—Concentration of wealth
दीवानी कारवाई—Civil proceeding	धन दौलती—Economic
दीवानी दस्तूर—Civil procedure	धरती—Land
दीवानी नालिवा—Civil suit	धर्म—Religion
दीवानी पद्धत—Civil code	धारा—Clause
दुधारी डोर—Milch cattle	धार्मिक—Religious
दुबरसी चुनाव—Biennial election	धार्मिक आज़ादी—Freedom of religion
दुसरकी स्कूल—Secondary school	धार्मिक देन—Religious endowment
देन—Endowment	धार्मिक फ़िरका—Religious denomination
देनगी—Grant	धार्मिक शिक्षा—Religious instruction
देनगी करना—To grant, to make a grant	धार्मिक संस्था—Religious institution
देनगी की मांग—Demand for a grant	धुनपसार—Broadcasting
देनगी को पूरा करना—To meet a grant	धंधा—Occupation
देनदार—Liable	न
देनदारी—Liability	नक़दी बिल—Money Bill
देनस्थान—Destination of grant	नक़ल—Copy
देसीकरण—Naturalisation	नक़शा—Table
देसी रियासत—Indian State	नगर एकतनी—Municipal Corporation
दोशलेखा—Charge	नगर ट्राममार्ग—Municipal tramway
दंड—Penalty	नगर दीवानी अदालत—City Civil Court
ध	नगर सुधार ट्रस्ट—Improvement Trust
धन—Wealth	

शब्दमाला

नगरायत—Municipality	नायब सदर—Deputy President
नगरायत क्षेत्र—Municipal area	
नजरबन्दी—Detention	नालिश—Suit
नज़रसानी—Review	नालिश करना—To sue
नदी-घाटी—River-valley	नासरदुस्त—Invalid
नरविद्या—Anthropology	नासरदुस्त ठहराना—To invalidate
नरेश—Prince	
नशीला तरल—Intoxicating liquor	निकासनी महसूल—Excise duty
नशीला पान—Intoxicating drink	निकासी—Export
नसल—Descent, race, breed	निकासी महसूल—Export duty
नागर—Citizen	निगरानी—Superintendence
नागरता—Citizenship	निजनियम—Privilege
नागरी जगह—Civil post	निजी—Personal
नागरी नौकरी—Civil service	निजी क़ानून—Personal law
नागरी शक्ति—Civil power	निजी थैली—Privy purse
नागरी हैसियत से—In civil capacity	निजी हैसियत से—In personal capacity
नाठीक दिमास—Unsound mind	निबल पेनशन—Invalidity pension
नादार हो जाना—Bankruptcy	नियम—Rule
ना-निवास—Non-residence	नियोजन—Appointment
नाबालिग—Minor	नियोजना—To appoint
नामज़द करना—To nominate	निर्देश करना, निर्देश देना—To direct
नामज़दगी—Nomination	निर्देशक सिद्धान्त—Directive principle
नामी क़ानूनशास्त्री—Distinguished jurist	निर्देशन—Direction
नायब रियासतपति—Lieutenant Governor	निवास—Domicile
	निवेदनी—Address
	निसबत—Proportion

भारत का विधान

P oportio- nal representation	पट्टीदर्ज क्षेत्र—Scheduled area पट्टीदर्ज जाति—Scheduled caste
नीति—Policy	
नुक़सान भरपाई—Compensation	पड़ताल की रिपोर्ट—Audit report
नतिक आवारगी—Moral aban- donment	पड़तालना—To audit पड़ोसी रियासत—Neighbouring State
नोटिस—Notice	
नौकरी—Service	पत्तीपूँजी—Stock
नौकरी की शर्तें—Conditions of service	पद—Office पद का हलफ़—Oath of office पदगाहन—Succession पदगाही—Successor पदनाते—Ex-officio पद-मियाद—Term of office पद सूना करना—To vacate office
न्याय—Justice	
न्यायकारी—Judiciary	
न्याय शासन—Administration of justice	
न्यायी—Just, judicial	
न्यायी अधिकारी—Judicial authority	
न्यायी काम—Judicial fun- ction	पद संभालना—To enter upon office
न्यायी जगह—Judicial post	पनशक्ति—Water power
न्यायी नौकरी—Judicial service	परमिट—Permit
न्यायी पद—Judicial office	परवाना—Writ
न्यूज़ प्रिंट—Newsprint	परवाना अधिकारवताई—Quo Warranto
प	
पक्की वापसी—Permanent return	परवाना तनतलबी—Habeas Corpus
पटसन—Jute	परवाना मनाही—Prohibition
पट्टा—Instrument, lease	परवाना मिसलमंगाई—Certiorari
पट्टी—Schedule	परवाना हुकुम—Mandamus
पट्टीदर्ज कबीला—Scheduled tribe	परसौंपनी—Extradition परिनामी—Consequential

## शब्दमाला

परिणामी बन्धान—Consequential provision	पूरक खच—Supplementary expenditure
परिभाषा—Definition	पूरक देनगी—Supplementary grant
परीक्षा—Examination	
पशु-इलाज की ट्रेनिंग—Veterinary training	पूरक बन्धान—Supplemental provision
पशुपालन—Animal husbandry	पूरक शक्ति—Supplemental power
पहली सुनवाई का अधिकार—Original jurisdiction	पूरब पंजाब रियासत यूनियन—East Punjab States Union
पात्र—Eligible	पेटेंट—Patent
पात्रता—Eligibility	पेट्रोलियम—Petroleum
पानी का निकास—Drainage	पेनशन—Pension
पानी पहुँचाना—Water supply	पेशगी—Advance
पासपोर्ट—Passport	पेशनगदी—Imprest
पासंगी महसुल—Countervailing duty	पेश बाज़ार—Futures market
पिछड़ी हुई जमात—Backward class	पेशा—Profession
पिछलगता असर—Retrospective effect	पेशाई—Professional
	पैदावार—Product, production
पीनकवाली—Narcotic	पैमाना—Scale
पीनकवाली चीज़ें—Narcotics	पैरा—Paragraph
पुरातत्वी—Archaeological	पंच—Arbitrator
पुलिस—Police	पंचनामा—Arbitration
पुलिस बल—Police force	पंच क्रैसला—Arbitration, award
पूंजी—Capital	पंचायती अदालत—Arbitral tribunal
पूछताछ—Inquiry	
पूरक—Supplemental, supplementary	प्रतिनिधान—Representation
	प्रतिनिधि—Representative

## भारत का विधान

प्रधान वजीर, भारत का—Prime Minister of India	फ
प्रमाण लिखत—Authoritative text	फरज—Duty
प्रमुख चुनाव कमिशनर—Chief Election Commissioner	फरज निभारना—To discharge duty
प्रमुख जज—Chief Judge	फरीक—Party
प्रमुख प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट—Chief Presidency Magistrate	फिरका—Denomination
प्रसंग—Context	फिरकेश्वराना—Denominational
प्रसंगी—Incidental	फिरबसाव—Rehabilitation
प्रसंगी बन्वान—Incidental provision	फिराती रकम—Recurring sum
प्रसंगी मामला—Incidental matter	फ्रीस—Fee
प्रसंग से आया हुआ—Incidental	फुटकर—Miscellaneous
प्राइमरी तालीम—Primary education	फेल होना—To fail
प्राइमरी स्कूल—Primary school	फैक्टरी—Factory
प्राचीन—Ancient	फैलाव—Extent
प्राप्तिसरी नोट—Promissory note	फ सला—Decision, judgment
प्राविडेंट फंड—Provident fund	फै सला देना—To deliver judgment
प्रार्थना पत्र—Petition	फै सला सुनाना—To pronounce judgment
प्रिवी कौंसिल—Privy Council	फौजदारी—Criminal
प्रिवी कौंसिल अमलदारी अन्त एक्ट, 1949—Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949.	फौजदारी अमलदारी—Criminal jurisdiction
प्लीडर—Pleader	फौजदारी कानून—Criminal law
	फौजदारी कारवाई—Criminal proceedings
	फौजदारी दस्तर—Criminal procedure
	फौजदारी नाखिश्—Criminal suit
	फौजदारी मामला—Criminal matter

## भारत का विधान

बिल का रखा जाना—	भत्ता—Allowance
Introduction of a Bill	भयानक आगपकड़—
बिल की पहल करना—	Dangerously inflammable
To originate a Bill	भरती—Recruitment
बीमा—Insurance	भरपाई—Relief
बीमा पालिसी—Insurantee	भरपाई भत्ता—Compensatory
policy	allowance
बेकामगारी, बेकारी—Unempl-	भलमंसी—Decency
oyment	भलाई—Well-being,
बेक्यायदगी—Irregularity	welfare
बेघरबारगी—Material	भाईचारा—Fraternity
abandonment	भाग—Part
बेतार—Wireless	भाग देना—To divide
बेमेल—Inconsistent	भागफल—Quotient
बेवसीयती—Intestacy	भाड़ा, माल का—Freight
बैठक—Sitting	भारत—India
बैठ बिठाव—Adjustment	भारत का गज़ट—Gazette
बोरस्टली संस्था—Borstal	of India
institution	भारत का मूठकोश—
बोर्ड—Board	Consolidated Fund of
बैंकदारी—Banking	India
व्यापार—Traffic	भारत का रिज़र्व बैंक—Reserve
व्योपार—Trade	Bank of India
व्योपार छाप—Trade-mark	भारत का विधान—Constitution
व्योपारी—Trader	of India
व्योपारी एकतनी—Trading cor-	भारत की सर्वे—Survey of
poration	India
व्योरा—Description, state-	भारत पड़ताल और हिसाब महकमा—
ment, return	Indian Audit and
भ	Accounts Department
भक्ति—Allegiance	भारवाही ढोर—Draught cattle



शब्दमाला

भाषा—Language	मह-बटवारा—Appropriation
भीतरी गड़बड़ी—Internal disturbance	मह-बटवारा बिल—Appropriation Bill
भुगतान खर्च—Redemption charges	मनाही—Prohibition
भूभाग—Territory	मनोरंजन—Entertainment
भूभागपरे—Extra-territorial	मसनदी—Chairman
भूभागपरे असल—Extra-territorial operation	महसूल—Duty
भूभागपरे असर—Extra-territorial effect	महामारी—Pest
भूभागी—Territorial	मांग—Demand
भूभागी चुनाव इलक्का—Territorial constituency	मातहत—Subordinate
भूभागी समंदर—Territorial waters	मातहत अदालत—Subordinate court
भूमिदारी—Land tenure	माही साधन—Material resources
भूविद्या—Geology	मान—Standard
भेदभाव—Discrimination	मानहानि—Defamation
भंग करना—To dissolve	माप—Measure
भंग होना, सदन का—Dissolution of the House	माफ़ी देना, माफ़ कर देना—To grant pardon
म	माल—Finance, goods
मकानी गुंजाइश—House accommodation	माल कमीशन—Finance Commission
मछियारी—Fishery	माल की मिल्कियत—Property in goods
मज़दूरी झगड़ा—Labour dispute	मालगुजारी—Revenue
मतलब—Purpose	मालगुजारी खाते खर्च—Expenditure on revenue account
मद—Item	मालामाल करना—Enrichment
	मालियत—Value
	माली—Financial

## भारत का विधान

माली	अचानकी—Financial emergency	मिलनी—Meeting
माली	अमलदारी—Revenue jurisdiction	मिल मजदूर—Industrial worker
माली	एकतनी—Financial corporation	मिलाजुला कमीशन—Joint Commission
माली	काम—Financial business	मिलाजुला परिवार—Joint family
माली	जिम्मेदारी—Financial obligation	मिलाजुला रियासत सरकारी नौकरी
माली	टिकाव—Financial stability	कमीशन—Joint State Public Service Commission
माली	बन्धान—Financial provision	मिलावट—Adulteration
माली	बिल—Financial Bill	मिलीजुली कलचर—Composite culture
माली	ब्योरा—Financial statement	मिलीजुली बैठक—Joint sitting
माली	मदद—Financial assistance	मिलीजुली भरती—Joint recruitment
माली	मामला—Financial matter	मिलीजुली मिलनी—Joint meeting
माली	साल—Financial year	मुअत्तल करना—To suspend
मार्ग—Way		मुआहिदा—Covenant
मार्ग नियम—Rule of the road		मुकदमा—Cause, case
मार्ग संकेत—Beacon		मुकदमा उठा लेना—To withdraw a case
मियाद—Term		मुकदमा निपटाना—To dispose of a case
मियादबन्दी—Limitation		मुकामी—Local
मिलकियत—Estate, ownership		मुकामी अधिकारी—Local authority
मिलकियत महसूल—Estate duty		मुकामी क्षेत्र—Local area
मिलन पट्टा—Instrument of Accession		मुकामी टैक्स—Cess, local tax
		मुकामी बोर्ड—Local Board
		मुकामी मतलब—Local purpose
		मुकामी सीमा—Local limit

## शब्दमाला

मुकामी स्वराज—Local self-government	मंगैनी ले लेना—To requisition
मुकामी हुकूमत—Local government	मंडल—Council
	मंडी—Market
	मंत्रायत—Secretariat
मुखतार—Attorney	मंत्रायती अमला—Secretarial staff
मुखिया—Headman	
मुनाफ़ा—Profit	मंसूख करना—To revoke, to annul
मुनासिब क़ानूनसभा—Appropriate Legislature	
मुनासिब कारवाई—Appropriate proceedings	य
मुनासिब सूरतों में—In appropriate cases	यादगार—Monument
मुफ़्त और ज़बरी तालीम—Free and compulsory education	यादपत्र, यादी—Memorandum
मुलतवी करना—To adjourn	युक्त खासी जैन्तिया पहाड़ी ज़िला—The United Khasi and Jaintia Hills District
मुहय्या करना—To supply	यूनियन—Union
मूठकोश—Consolidated Fund	यूनियन तालिका—Union List
मूल अधिकार—Fundamental right	यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन—Union Public Service Commission
मेम्बर—Member	योजना—Scheme, planning
मेम्बरी—Membership	र
मेल बिठाना—To bring into accord	रकम जुटाना—To raise money
मेला—Fair	रक्षा—Protection
मेहनताना—Remuneration	रखवाली—Custody
मैजिस्ट्रेट—Magistrate	रखाया हुआ जंगल—Reserved forest
मोहर—Seal	रचना—Composition
मोहलत देना—To grant respite	रचाना पचाना—To assimilate
मौसमी क़बीला—Migratory tribe	रज़ामंदी—Approval

## भारत का विधान

रजिस्टरी—Registration	रियासत का मूठकोश—Consolidated Fund of the State
रद्द—Void, repeal	रियासत तालिका—State List
रद्द करना—To repeal	रियासतपति—Governor
रसद—Supply	रियासत सदन—Council of States
रसीद—Receipt	रियासत सरकारी नौकरी कमीशन—State Public Service Commission
रस्सा मार्ग—Ropeway	रियासतों का गुट—Group of States
राज—The State ( as defined in Part III )	रिहाइश—Residence
राजकाजी—Political	रिहाइश की जगह—Place of residence
राजदारी—Secrecy	रिहाइशी—Residential
राजदारी का हुक्म—Oath of secrecy	रीतरिवाज—Custom
राजदूत—Diplomatic	रुकावट—Restriction
राजपति—President	रुतबा घटाया जाना—Reduction in rank
राजपंचायत—Parliament	रुपया निकालना—Withdrawal of money
राजप्रमुख—Rajpramukh	रूप—Form
राजहुक्म—Ordinance	रूप देना—To formulate
राज्जीनामा—Agreement	रूपबिगाड़—Disfigurement
राय—Opinion	रेलमार्ग—Railway
रायल्टी—Royalty	रेलमार्ग कंपनी—Railway company
राहरीत पेदागी—Ways and means advance	रेलमार्ग क्षेत्र—Railway area
रिपोर्ट—Report	रेहन रखना—Mortgage
रियायत—Concession	रोक—Bar
रियासत—State	
रियासत का जोगाजोग कोश—Contingency Fund of the State	
रियासत का मिलना—Accession of a State	

शब्दमाला

रोकथाम—Prevention	लोक सदन—House of the
रोकथामी नज़रबन्दी—Preventive	People
detention	
रोज़गार—Calling, avocation	व
रोज़गारी—Vocational	वचन भरना—To affirm,
रोज़गारी ट्रेनिंग—Vocational	affirmation
training	
रोज़ी—Livelihood	वज़ीर—Minister
	वज़ीर मंडल—Council of
ल	Ministers
लगातार—Consecutive, in	वज़ीरायती अधिकारी—Ministerial
succession	authority
लगान—Rent	वफ़ादार रहना—To bear faith
लगाव—Adherence	वफ़ादारी से—Faithfully
लचर—Frivolous	वसीयत—Will
लदाई बिल्टी—Bill of lading	वाक़याती सवाल—Question of
लाइन—Line	fact
लाइसेंस—License	वारिस—Successor
लागू—Applicable	विकास—Development
लागू होना—To apply	विचार करना—To consider
लाटरी—Lottery	विचार के लिये रख देना—To
लाभ—Profit	reserve for consideration
लाभबंटावा—Dividend	विदेशी अमलदारी—Foreign
लाभ तोड़ना—Demobilisation	jurisdiction
लावारसी, वारिस न रहना—Bona	विदेशी उधारी—Foreign loan
vacantia	विदेशी मामला—Foreign affair
लेखे—Records	विदेशी राज—Foreign State
लेनदारी—Asset	विदेशी सिक्का बदलाव—Foreign
लोक महत्व—Public importance	exchange
लोकशाही—Democracy,	विद्यापीठ—University
democratic	विधान—Constitution

## भारत का विधान

विधान तोड़ना—Violation of	शपथ लेना—To swear
the Constitution	शब्दावली—Vocabulary
विधान सभा—Constituent	शर्त बटना—Betting
Assembly	शर्ते कि—Provided that
विधानी मशीन—Constitutional	शांति—Peace
machinery	शामलाती—Common
विरासत—Succession, inheritance	शामलाती कुल-भारत नौकरियाँ—Common All-India services
विशेष कर—In particular	शासक—Ruler
विशेष जोगता—Special qualification	शासन—Administration
विस्फोटक—Explosive	शासन की कुशलता—Efficiency of administration
वीसा—Visa	शासन तल—Level of administration
वेतन—Emolument	शासन सम्बन्धी—Relating to administration
वेतनी काम—Paid employment	शासनी—Administrative
वोट—Vote	शासनी खर्च—Administrative expenses
वोटर—Voter	शासनी क्षेत्र—Administrative area
वंश—Descent	शासनी शक्ति—Administrative power
व्यवस्था—Order	शासनी सम्बन्ध—Administrative relation
व्यवस्था कायम करना—Restoration of order	शिकायत—Complaint
व्यवस्था बनाए रखना—Maintenance of order	शेयर बाज़ार—Stock exchange
शक्ति—Power	शेरिफ़—Sheriff
शक्ति से काम लेना—Exercise of power	शैली—Style
शक्ति सौंपना—To confer power	

शब्दमाला

शहन—Exploitation	समन्दरी जहाज़रानी—Maritime navigation
स	
सकत—Ability	समन्दरी डकैती—Piracy
सज़ा—Punishment	समन्दरी फ़ौज—Naval force
सड़क—Road	समन्दरी विभाग—Admiralty
सत्ता—Authority	समय समय पर—From time to time
सदन—House	
सदन का बरखास्त होना—Prorogation of the House	समयोचित—Expedient
सदन का भंग होना—Dissolution of the House	समर्थन करना—To support
सदन को मुलतवी करना—To adjourn the House	समाज की भलाई—Social welfare
सदर—President	समाज सेवा—Social service
सदाचार—Morality	समाज सुधार—Social reform
सदारत करना—To preside	समाजी—Social
सनद—Sanad, certificate	समाजी अन्याय—Social injustice
सनद करना या देना—To certify	समाजी बीमा—Social insurance
सन्धिनामा—Treaty	समाजी व्यवस्था—Social order
सन्धि बन्धन—Treaty obligation	समेटना—To wind up
सब डिवीज़नल अफ़सर—Sub-Divisional Officer	सम्मान—Dignity
सबसे पहली अदालत—Court of first instance	सम्राट—Crown, His Majesty
समा—Association	सरकार—Government
समासुख—Speaker	सरकारी करज़ा—Public debt
समझाव—Explanation	सरकारी ज़ब्ती—Escheat
समझौता—Agreement	सरकारी ट्रस्टी—Official trustee
समन्दरी—Marine, maritime	सरकारी नौकरी कमीशन—Public Service Commission
समन्दरी जहाज़रानी—Maritime shipping	सरकारी मकान—Official residence
	सरकारी हुंडी—Treasury Bill

## भारत का विधान

सरजज—Chief Justice	सहायक बन्धान—Ancillary provision
सरदुरुस्त—Valid	
सरदुरुस्त ठहराना—To validate	सहायक सेशन जज—Assistant Sessions Judge
सरदुरुस्ती—Validity	
सरनामा—Title	सहायता—Aid
सरपड़तालिया—Auditor-General	सहायती देनगी—Grant-in-aid
	सहीकरण—Authentication
सरप्रबन्धक—Administrator-General	सही करना—To authenticate
	सही किया हुआ—Authenticated
सरबचन देना—To address	साइंस—Science
सरमुख—Head	साइंसी—Scientific
सरमुखतार—Attorney-General	साइंसी तालीम—Scientific education
सरलेख—Preamble	
सरबकील—Advocate General	साइंसी रीत—Scientific line
सरवे—Survey	साख—Credit
सरहदी खिन्ता—Frontier tract	साख पत्र—Letter of credit
सलामती—Safety	साझेदारी—Partnership
सलाहकार मंडल—Advisory Council, Council of Advisors	साधन—means, resources
सलाह देना—To advise	सायल—Suitor
सहकारी आधार—Co-operative basis	सारचारा—Concentrates
सहकारी आन्दोलन—Co-operative movement	सालाना माली ब्योरा—Annual financial statement
सहकारी समिति—Co-operative society	साहूकार—Money lender
सहमती—Concurrence	सिंगार—Toilet
सहायक—Ancillary, assistant	सिंचाई—Irrigation
सहायक ज़िला जज—Assistant District Judge	सिक्का गढ़न—Coinage
	सिक्का चलन—Currency
	सिद्धान्त—Principle
	सिनेमा—Cinema, cinematograph
	सिफारिश—Recommendation



## शब्दमाला

सीट—Seat	सूबापरे—Extra-Provincial
सीट को सूती ठहराना—To declare a seat vacant	सूबापरे अमलदारी एक्ट, 1947— Extra-Provincial Jurisdiction Act, 1947
सीटें अलग रखना—To reserve seats	सूबे का गवरनर—Governor of a Province
सीटों का बटवारा—Allocation of seats	सूबों का गुट—Group of Provinces
सीधा चुनाव—Direct election	सेवासुक्त—Retired
सीधे या नासीधे—Directly or indirectly	सेशन जज—Sessions Judge
सीमा—Limit	सोसाइटी—Society
सीमिताना—To limit	सौदागरी-माल छाप—Merchandise mark
सुझाव—Proposal	संगचारी तालिका—Concurrent List
सुधार—Amendment	संगठन—Organisation
सुधार करना—To amend, to make amendment	संगठित क्रौमै—Organised peoples
सुधारघर—Reformatory	संगत—Relevant
सुधार पेश करना—To move an amendment	संगी ज़िला जज—Joint District Judge
सुधार सुझाना—To suggest an amendment	संघ अदालत—Federal Court
सुनवाई—Hearing	संचालन—Conduct
सुनवाई का अधिकार—Right of audience	संदेश—Message
सुरक्षा—Security	संयुक्त क्रौमी संगठन—United Nations Organisation
सूचना—Information	संरक्षक—Guardian
सूझ, सूझ-ब्याज—Interest	संस्था—Body, institution
सूनी—Vacancy	स्कूल—School
सूनी करना—To vacate	स्टाम्प महसूल—Stamp duty
सूनी भरना—To fill a vacancy	स्टेट सेक्रेटरी—Secretary of State
सूबा—Province	स्तर—Standard

भारत का विधान

स्नातक — Graduate	हाजिरी तलब करना—To require attendance
स्वतंत्रता—Liberty	
स्वराज—Self-government	हित—Interest
स्वाधीन—Autonomous	हिदायत—Instruction
स्वाधीन इलाका—Autonomous region	हिन्द आज़ादी एक्ट, 1947—Indian Independence Act, 1947
स्वाधीन ज़िला—Autonomous district	हिन्द डोमिनियन—Dominion of India
ह	
हक़दार—Entitled, Competent	हिन्द पुलिस नौकरी—Indian Police Service
हथियार—Arms	
हथियारबन्द फ़ौज—Armed force	हिन्द शासनी नौकरी—Indian Administrative Service
हदबन्दी—Delimitation	हिन्द सम्राट—Crown in India
हद लांघना—Trespass	हिन्द सरकार एक्ट, 1935—Government of India Act, 1935
हदवारी टैक्स—Terminal tax	
हदियाना—To limit	
हलफ़—Oath	हिन्दसे—Numerals
हवाई अड्डा—Aerodrome	हिन्दी निकास—Indian origin
हवाई जहाज़—Aeroplane	हिन्दुस्तानी हिन्दसे—Indian numerals
हवाई फ़ौज—Air force	हिरासत—Custody
हवा जहाज़—Aircraft	हिसाब—Account
हवा जहाज़रानी—Air navigation	हिसाब किताब—Accounts
हवा व्यापार—Air traffic	हिस्सा—Share
हवा मार्ग—Airways	हिस्सा लेना—To participate
हवा विद्या की तालीम—Aeronautical education	हिस्सेदारी—Contributory
हाईकोर्ट—High Court	हुकूम—Order
हाजिरी—Attendance	हुकूमनामा—Process, warrant

# शब्दमाला

## अंगरेजी से हिन्दी

मूल अंगरेजी विधान के कुछ शब्द और उनके सामने

जवाबी हिन्दी शब्द जो इस अनुवाद में बरते गए हैं

<b>A</b>	<b>Additional District Judge</b>
Abolish—अन्त करना, तोड़ देना	—अधिक ज़िला जज
Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949—	<b>Additional Sessions Judge</b>
प्रिवी कौंसिल अमलदारी अन्त एक्ट, 1949	—अधिक सेशन जज
Abrogate—रद्द करना	<b>Address—</b> सरबचन, सरबचन देना,
Absence—नामौजूदगी	निवेदनी
Absent—नामौजूद	<b>Adherence—</b> लगाव
Absent on leave—छुट्टी पर	<b>Ad hoc—</b> ज़रूरती
Accession of a State—	<b>Ad hoc Judge—</b> ज़रूरती जज
रियासत का मिलना	<b>Adjourn—</b> मुलतवी करना
Account—हिसाब	<b>Adjourn the House—</b> सदन
Accounts—हिसाब किताब	को मुलतवी करना
Accused—मुलज़िम	<b>Adjudication—</b> अदालती फ़सला
Act—एक्ट, काम	<b>Adjustment—</b> बैठबिठाव
Acting—कारकर	<b>Administer—</b> प्रबन्ध करना,
Acting Chief Justice—	शासन करना
कारकर सरजज	<b>Administration—</b> शासन
Actual service—असल नौकरी	<b>Administration of justice—</b>
Adaptation—अनुकूलन	न्याय शासन
Additional—अधिक	<b>Administrative—</b> शासनी
Additional Chief Presidency Magistrate—अधिक	<b>Administrative area—</b>
प्रमुख प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट	शासनी क्षेत्र
	<b>Administrative expenses—</b>
	शासनी खर्च

## भारत का विधान

Administrative power— शासनी शक्ति	Agricultural income—खेती- बाड़ी की आमदनी
Administrator General— सरप्रबंधक	Agricultural land—खेती- बाड़ी की ज़मीन
Admiralty—समन्दरी विभाग	Agricultural worker— खेतिहर
Admission—दाखिला	Agriculture—खेतीबाड़ी
Adoption—अपनाना, गोद लेना	Aid—सहायता, सहायता देना
Adult—बालिय	Aircraft—हवा जहाज़
Adulteration—मिलावट	Air force—हवाई फ़ौज
Adult suffrage—बालिय वोट	Air navigation—हवा जहाज़रानी
Advance—पेशगी	Air traffic—हवा व्यापार
Advertisement—जाहिरात	Airways—हवा मार्ग
Advise—सलाह देना	Alcohol—अलकोहल
Advisory Board—सलाहकार बोर्ड	Alcoholic liquor—अलको- होली तरल
Advisory Council—सलाह- कार मंडल	Alien—विदेशी
Advocate—वक़ील	Allegiance—भक्ति
Advocate General— सरवकील	All-India service—कुल-भारत नौकरी
Aerodrome—हवाई अड्डा	Allocation of seats—सीटों का बटवारा
Aeronautical education— हवा विद्या की तालीम	Allotment—बांटना, किसी के नाम कर देना
Affirm, affirmation—वचन भरना	Allotment of land—ज़मीन का बांटा जाना
Aforesaid—ऊपर कहा	Allowance—भत्ता
Agency—एजेंसी	Amend—सुधार करना
Agent—एजेंट	Amendment—सुधार
Aggression—हमला	
Agreement—समझौता, राज़ीनामा	

### शब्दमाला

Ammunition—गोला बारूद	Appropriate Legislature—सुनासिब कानूनसभा
Amount—रकम	Appropriate proceedings—सुनासिब कारवाइ
Amusement—तमाशा	Appropriation—मद्-बटबारा
Ancient—प्राचीन	Appropriation Bill—मद्-बटबारा बिल
Ancillary—सहायक	Approval—रज़ामन्दी
Ancillary matter—सहायक मामला	Arbitral tribunal—पंचायती
Ancillary power—सहायक शक्ति	Arbitration—पंच क्र सला, पंचनामा
Ancillary provision—सहायक बन्धान	Arbitrator—पंच
Anglo Indian—एंग्लो इंडियन	Archaeological—पुरातत्वी
Animal husbandry—पशुपालन	Area—क्षेत्र
Annual admission—सालाना दाखला	Armed force—हथियार बन्द फ़ौज
Annual financial statement—सालाना माली ब्योरा	Arms—हथियार
Annuity—सालाना किस्त	Arrears—बक्राया
Annul—मंसुख करना	Arrest—गिरफ़्तारी
Answerable—जवाबदेह	Art—कला
Anthropology—नरविद्या	Article—दफ़्ता
Appeal—अपील	Assam Forest Regulation, 1891—आसाम जंगल कायदाबन्दी, 1891
Appellate jurisdiction—अपीली अमलदारी	Assent—मंजूरी
Applicable—लागू	Assess—आंकना
Application—दरखास्त, अरज़ी	Assess land for revenue purposes—मालगुज़ारी के मत-लबों के लिए ज़मीन आंकना
Appoint—नियोजना	
Appointment—नियोजन	
Appropriate—सुनासिब, खर्च की मद में डालना	

भारत का विधान

A sessment of revenue—	Authorised—अधिकारा हुआ
मालगुजारी तय करना	Authorised amount—
Asset—लेनदारी	अधिकारी हुई रकम
Assign—नाम कर देना	Authorised expenditure—
Assimilate—रचाना पचाना	अधिकारा हुआ खर्च
Assistant—सहायक	Authoritative text—प्रमान
Assistant District Judge—	लिखत
सहायक ज़िला जज	Authority—अधिकारी, अधिकारी
Assistant Sessions Judge—	संस्था, सत्ता
सहायक सेशन जज	Autonomous—स्वाधीन
Association—सभा 3-67	Autonomous district—
Assurance—भरोसा	स्वाधीन ज़िला
As the case may be—जैसी	Autonomous region—स्वाधीन
सूत हो	इलाक़ा
Atomic energy—एटम शक्ति	Average—औसत
Attachment—क़ुरक़ी	Avocation—रोज़गार
Attendance—हाज़िरी	Award—पंच फ़ैसला
Attorney—मुखतार	B
Attorney-General—सरमुखतार	Backward class—पिछड़ी हुई
Audit—पड़तालना	जमात
Auditor-General—सरपड़ता-	Bail—ज़मानत
लिया	Banking—बैंकदारी
Audit report—पड़ताल की	Bankruptcy—नादार हो जाना
रिपोर्ट	Basis—आधार
Authenticate—सही करना	Beacon—सार्ग संकेत
Authenticated—सही किया	Bear allegiance—भक्त रहना
हुआ	Bear faith—वफ़ादार रहना
Authentication—सहीकरण	Belief—विश्वास
Authorise—अधिकार देना,	Betting—शर्त बटना
अधिकारना	Biennial election—दुबरेसी
	चुनाव

## शब्दमाला

Bill—बिल	Canon—उसूल
Bill of exchange—बदलाव	Cantonment—छावनी
हुंडी	Capital—पूंजी
Bill of lading—लदाई बिल्टी	Capital value—कुल मालियत
Board—बोर्ड	Capitation tax—आदमीवार
Body—संस्था	टक्स
Body corporate—एकतन संस्था	Case—मुकदमा
Boiler—बायलर	Caste—जात
Bona vacantia—वारिस न	Casting vote—जिताऊ वोट
रहना, छावारिसी	Casual vacancy—औसरी सूनी
Borrowing—उधार लेना	Cattle pound—कांजी हौज़
Borstal institution—बोर-	Cause—मुकदमा, कारन
स्टली संस्था	Census—गिनावा
Botany—वनस्पति विद्या	Central Bureau of Intelligence and Investigation—जानकारी और जाँच का
Breed—नसल	मंत्रकज़ी महकमा
Bring into accord—मेल	Certificate—सनद
बिठाना	Certify, certification—
Broadcasting—धुनपसार	सनद करना, सनद देना
Burial—दफ़न	Certiorari—परवाना
Burial ground—दफ़न भूमि	मिसल
Business—कारबार, काम	मंगाई
Bye-law—छुटक़ानून	Cess—मुकामी टैक्स
By virtue of—की रू से	Chairman—मसनदी
<b>C</b>	Chapter—खंड
Calculation—हिसाब लगाना	Charge—जुर्म, दोशलेखा
Calling—रोज़गार	Charge on—खाते में डालना
Call in question—सवाल उठाना	Charitable and religious
Cancel—रद्द करना	endowments—खैराती और
Candidate—उम्मीदवार	धार्मिक देन

## भारत का विधान

Charitable institution— खैराती संस्था	Civil procedure—दीवानी दस्तूर
Charity—खैरात	Civil proceeding—दीवानी कारबाई
Cheque—चेक	Civil service—नागरी नौकरी
Chief—सरदार, प्रमुख	Civil suit—दीवानी नालिश
Chief Commissioner— चीफ कमिशनर	Claim—दावा, दावा करना
Chief Election Commi- ssioner—प्रमुख चुनाव कमिशनर	Class—जमात
Chief Judge—प्रमुख जज	Clause—धारा
Chief Justice—सरजज	Clerk—क्लर्क
Chief Minister ( of a State )—बड़ा बज़ीर (रियासत का)	Code—पद्धत
Chief Presidency Magis- trate—प्रमुख प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेट	Code of Civil Procedure —ज़ाबता दीवानी
Cinema, cinematograph— सिनेमा	Code of Criminal Proce- dure—ज़ाबता फ़ौजदारी
Circumstance—हालत, सूरत	Code of procedure—ज़ाबता
Circumstances exist— सूरतें ऐसी हैं	Coinage—सिक्का गढ़न
Citizen—नागर	Collect—जमा करना
Citizenship—नागरता	Colonization—बस्ती बसाना
City civil court—नगर दीवानी अदालत	Column—कालम
Civil—नागरी, दीवानी	Combine—गुट
Civil code—दीवानी पद्धत	Command—कमान
Civil court—दीवानी अदालत	Commencement—आरम्भ
Civil jurisdiction—दीवानी असलदारी	Commerce—तिजारत
Civil power—नागरी शक्ति	Commercial undertaking— तिजारती कारबार
	Commission—कमीशन
	Committee—कमेटी
	Commodity—तिजारती माल
	Common all-India services शामलता कुल-भारत नौकरियाँ



## शब्दमाला

Common interest—मिला- जुला हित	Compute—गिनना
Communication—आवाजाई, आपसी व्यवहार	Concentrates—सारचारा
Community—समाज	Concentration of wealth— धन का कीलना
Commute a sentence— सजा का रूप बदल देना	Concession—रियायत
Company—कम्पनी	Concurrence—सहमती
Compensation—नुकसान भरपाई	Concurrent List—संगचारी तालिका
Compensatory allowance— भरपाई भत्ता	Condition—हालत, शर्त
Competent—अधिकारी, हकदार	Conditions of service— नौकरी की शर्तें
Competent authority— हकदार अधिकारी	Conduct—चलन, संचालन
Competent court—अधिकारी अदालत	Conduct of business— काम का संचालन
Competent Legislature— अधिकारी कानूनसभा	Confer—सौंपना
Composite—मिलीजुली	Conference—कानफरेंस
Composite culture—मिली- जुली कलचर	Conscience—अन्तरात्मा
Composition—रचना	Consecutive—लगातार
Comptroller and Auditor General—दाब अफसर और सरपड़तालिया	Consent—अनुमति
Compulsory acquisition— जबरन हासिल करना	Consequential—परिणामी
Compulsory service— जबरी सेवा	Consequential provision— परिणामी बन्धान
	Conserve—बनाए रखना
	Consolidated Fund—मूठकोश
	Constituency—चुनाव इलक्का
	Constituent Assembly— विधान सभा
	Constitution—विधान, बनावट
	Constitutional—विधानी
	Constitutional machinery —विधानी मशीन

## भारत का विधान

Constitution of India— भारत का विधान	Cottage industry—घरेलू उद्योग
Construct—बनाना	Council—मंडल
Consular—वनिजदूती	Council of Advisors— सलाहकार मंडल
Consumption—खपत	Council of Ministers— वज़ीर मंडल
Contagious disease—छूत की बीमारी	Council of States—रियासत सदन
Contempt—तौहीन	Countervailing duty— पासंगी महसूल
Context—प्रसंग	Court—अदालत
Contingency—जोगाजोग	Court immediately below— ठीक निचली अदालत
Contingency Fund—जोगा- जोग कोश	Court Martial—फ़ौजी अदालत
Contract—ठीका	Court of appeal—अपीली अदालत
Contributory—हिस्सेदारी	Court of first instance— सबसे पहली अदालत
Control—दबान, कंट्रोल	Court of record—नज़ीरो अदालत
Convention—माना हुआ रिवाज	Court of wards—कोर्ट कचहरी
Convict—दोशी ठहराना	Covenant—मुआहिदा
Co-operative—सहकारी	Credit—साख
Co-operative movement— सहकारी आन्दोलन	Cremation—दाह
Co-operative society—सह- कारी समिति	Cremation ground—दाहभूमि
Co-ordination—तालमेल	Crime—ज़ुर्म
Copy—नक़ल	Criminal—फ़ौजदारी
Copyright—कापीराइट	Criminal court—फ़ौजदारी अदालत
Corporation—एकतनी	
Corporation tax—एकतनी टैक्स	
Corresponding—जवाबी	
Corrupt practice—घूसखोरी	

## शब्दमाला

Criminal jurisdiction—	Defamation—मानहानि
क्रौजदारी अमलदारी	Defence—बचाव
Criminal law—क्रौजदारी कानून	Defence force—बचाव क्रौज
Criminal procedure—क्रौज-	Defence service—बचाव
दारी दस्तूर	नौकरी
Criminal proceedings—	Defend—जवाबदेही करना, बचाव
क्रौजदारी कारवाई	करना
Crown in India—हिन्द सम्राट	Definition—परिभाषा
Cruelty—बेरहमी	Delimitation—हदबन्दी
Cultural—कलचरी	Deliver judgment—फ़सला
Culture—कलचर	देना
Currency—सिक्का चलन	Demand—मांग
Current—चालू	Demand for grant—देनगी
Current service—चालू सेवा	की मांग
Custody—हिरासत, रखवाली	Demobilisation—लाम तोड़ना
Custom—रीतरिवाज	Democracy, democratic—
Customs, custom duty—	लोकशाही
बिदेसनी महसूल	Denomination—फ़िरका
	Denominational — फ़िरके-
	वाराना
Debenture—करजपत्र	Deputy Commissioner—
Debt—करजा	डिप्टी कमिशनर
Debt charges—करजा खर्च	Deputy President—नायब
Decency—भलमंसी	सदर
Decision—फ़ैसला	Descent—वंश, नसल
Declare—एलान करना, ठहरा देना,	Design—डिज़ाइन
ज़ाहिर करना	Designate—नामज़द करना
Declare law—कानून ठहराना	Desirable—चहोती, चाहनी
Decree—डिगरी	Destination of grant—देन
Deed—तमसुक	स्थान

## भारत का विधान

Destruction—बर्बादी	Discussion—बहस
Detail—तफ़्सील	Disfigurement—रूप बिगाड़
Detention—नज़रबन्दी	Dismiss—बरखास्त करना
Development—विकास	Dispensary—दवाख़ाना
Devote oneself to—तन मन से लगना	Dispose of—निबटाना
Difference—फ़रक़	Disqualification—अजोगता
Difficulty—कठिनाई	Disqualify—अजोग ठहराना
Dignity—मान, सम्मान	Dissenting judgment— अनमिल फ़ैसला
Diplomatic—राजदूती	Dissenting opinion— अनमिल राय
Direct—निर्देश देना	Dissolution of a House— सदन का भंग होना
Direct election—सीधा चुनाव	Dissolve—भंग करना
Direction—निर्देश, निर्देशन	Distinction—उपाधि
Directive—निर्देश	Distinguished jurist— नामी क्रानूनशास्त्री
Directive principle—निर्देशक सिद्धान्त	Distribution—बटवारा, बांटना
Directly or indirectly— सीधे या नासीधे	District—ज़िला
Disability—अपाह्वी, असक्त	District Board—ज़िला बोर्ड
Disability pension—अपाह्वी पेनशन	District Council—ज़िला मंडल
Disabled—अपाह्व	District Court—ज़िला अदालत
Disablement—अंग भंग होना	District Judge—ज़िला जज
Disapprove—नापसन्द करना	Disturbance—गड़बड़ी
Discharge ones duty— अपना फ़रज़ निभारना	Divide—भाग देना
Discharge ones function— अपना काम निभारना	Dividend—लाभ बटावा
Discipline—क़ायदादारी	Division Court—डिविज़न अदालत
Discovery—खोज़ निकालना	Divorce—तलाक़
Discrimination—भेदभाव	Document—दस्तावेज़, कागज़ पत्तर

Domicile—निवास	Effective—असरदार
Domiciled—निवासी	Effectively—असरदार ढंग से
Dominion Legislature— डोमिनियन कानूनसभा	Efficiency of administration—शासन की कुशलता
Dominion of India—हिन्द डोमिनियन	Election—चुनाव
Draught cattle—भारवाही ढोर	Election Commission— चुनाव कमीशन
Drug—जड़ी बूटी	Election Commissioner— चुनाव कमिशनर
Duly—क़ायदे से	Election petition—चुनाव अर्ज़ी
Duration—सुदृढ़	Election tribunal—चुनाव अदालत
During the pleasure of— के इच्छाकाल तक	Electoral college—चुनाव मंडल
Duty—महसूल, फ़रज़	Electoral roll—चुनाव चिट्ठा
<b>E</b>	Electorate—चुनायत
East Punjab States Union —पूरब पंजाब रियासत यूनियन	Electricity—बिजली
Economic—आर्थिक, धनदौलती	Element—अंग
Economic capacity— आर्थिक सकल	Eligibility—पात्रता
Economic interest— आर्थिक हित	Eligible—पात्र
Economic organisation— आर्थिक संगठन	Embankment—बांध
Economic system—अर्थव्यवस्था	Emergency—अचानकी
Education—तालीम	Emergency provision— अचानकी बन्धोन
Educational grants— तालीमी देनगियां	Emigration—बाहर जा बसना
Educational institution— तालीमी संस्था	Emolument—वेतन
Effect—असर	Employ—काम पर लगाना
	Employee—कामगार
	Employment—कामगारी
	Empower—शक्ति देना

## भारत का विधान

Encourage—बढ़ावा देना	Excess grant—अधिक देनगी
Encumbered—करजादबी	Excess Profits Tax—बढ़ती नफ़ा टैक्स
Endowment—देन	Excise duty—निकासनी महसूल
Enforcement of atten- dance—हाज़िरी लाज़िमी करना	Executive—काजकारी
Engagement—इकरारनामा	Executive function—काज- कारी काम
Enrichment—मालामाल करना	Executive power—काजकारी शक्ति
Enter appeal—अपील दाखिल करना	Exemption—बरी होना
Entertain appeal—अपील लेना	Exercise jurisdiction— अमलदारी से काम लेना
Entertainment—मनोरंजन	Exercise power—शक्ति से काम लेना
Enter upon office—पद संभालना	Existing law—मौजूदा क़ानून
Entitled—हक़दार	Ex-officio—पदनाते
Entrust—सौंपना	Expedient—समयोचित
Entry—दाखला, अन्तरी, आमद	Expenditure, expense—खर्च
Enumerate—गिनाना	Expenditure on revenue account—मालगुज़ारी खाते खर्च
Equality—बराबरी	Expire—बीतना
Escheat—सरकारी ज़ब्ती	Explanation—समझाव
Establish—क्रायम करना	Exploitation—शोशन
Estate—मिलकियत	Explosive—विस्फोटक
Estate duty—मिलकियत महसूल	Export—निकासी
Estimate—तख्मीना	Export duty—निकासी महसूल
Evacuee—घरछुट	Expulsion—निकाला जाना
Evacuee property—घरछुट जायदाद	Extent—फैलाव, हद
Evidence—गवाही	Extract minerals—खनिजों को निकालना
Examination—परीक्षा	Extradition—परसपनी
Exception—अपवाद	
Excess expenditure—अधिक खर्च	

## शब्दमाला

Extra-Provincial—सूबापरे	Financial assistance—
Extra-Provincial Jurisdiction Act, 1947—सूबापरे	माछी मदद
अमलदारी एक्ट, 1947	Financial Bill—माछी बिल
Extra-territorial—भूभागपरे	Financial corporation—
Extra-territorial effect—	माछी एकतनी
भूभागपरे असर	Financial emergency—
Extra-territorial operation—भूभागपरे अमल	माछी अचानकी
	Financial obligation—
	माछी ज़िम्मेदारी
	Financial propriety—
	उचित माछी ब्योहार
	Financial provision—
	माछी बन्धान
	Financial stability—माछी
	टिकाव
	Financial statement—
	माछी ब्यौरा
	Financial year—माछी साल
	Fire-arms—आग हथियार
	Fishery—मछियारी
	Fishing—मछली पकड़ना
	Forced labour—जबरी मजदूरी
	Force of law—क़ानून का असर
	Foregoing—ऊपरलिखे
	Foreign affairs—विदेशी मामले
	Foreign exchange—विदेशी
	सिक्का बदलाव
	Foreign jurisdiction—
	विदेशी अमलदारी
	Foreign loan—विदेशी उधार
	Foreign State—विदेशी राज

## F

Facility—सुविधा
Factory—फ़ैक्टरी
Fail—फ़ेल होना
Faith—विश्वास, वफ़ादारी
Faithful—वफ़ादार
Faithfully—वफ़ादारी से
Fare—फ़िराया (सवारी का)
Favour—तरफ़दारी
Federal Court—संघ अदालत
Fee—फीस
Ferry—उतराई घाट
Figure—आंकड़ा
Fill a vacancy—सूती भरना
Film—फ़िल्म
Final order—आखिरी हुकुम
Finance—माछ, रुपया लगाना
Finance Commission—
माछ कमीशन
Financial—माछी

Forest—जंगल	Generality—आमियत
Forfeiture—जब्त	Generally—आम तौर पर
Form—रूप	General public—आम जनता
Formulate—रूप देना	Genius—आत्मा
Fraction—द्रव्य	Geology—भूविद्या
Fraternity—भाईचारा	Ginned cotton—ओटी रुई
Free and compulsory edu- cation—मुफ्त और जबरी तालीम	Give effect to—अमल में लाना
Freedom—आज़ादी	Goods—माल
Freedom of religion— धार्मिक आज़ादी	Governing body—प्रबन्ध कमेटी
Freight—भाड़ा (माल का)	Government—सरकार, हुकूमत
Frivolous—लचर	Government of India Act, 1935—हिन्द सरकार एक्ट, 1935
From time to time—समय समय पर	Government of India (Scheduled Castes) Order, 1936—हिन्द सरकार (पट्टी-दर्ज जातों) हुकूम, 1936
Frontier—सरहद, सीमा	Governor—रियासतपति, गवरनर
Frontier tract—सरहदी खिन्ता	Governor General—गवरनर जनरल
Function—काम	Governor's Province— गवरनरी सूबा
Fundamental right— मूल अधिकार	Graduate—स्नातक
Future market—पेश-बाज़ार	Grant—देनगी
G	Grant in-aid—सहायती देनगी
Gas—गैस	Grant pardon—माफ़ी देना, माफ़ कर देना
Gas works—गैस का कारखाना	Grant reprieve—सज़ा मुलतवी कर देना
Gazette of India—भारत का गज़ट	Grant respite—मुहलत देना
General Clauses Act, 1897—आम धारा एक्ट, 1897	
General election—आम चुनाव	
General electoral roll— आम चुनाव चिट्ठा	



Gratuity—इनामी रकम	His Majesty in Council—
Grave emergency—गहरी	कौंसिल समेत सम्राट
अचानकी	Historical—इतिहासी
Grazing—ढोर चराना	Honourable relation—
Ground—भूमि, बिना	सम्मानी रिश्ता
Ground of appeal—अपील	Hospital—अस्पताल
की बिना	House (of a Legislature)—
Group—गिरोह, गुट	सदन
Group of Provinces—सूबों	House accommodation—
का गुट	मकानी गुंजाइश
Group of States—रियासतों	House of the People—
का गुट	लोक सदन
Guarantee—गारंटी	I
Guardian—रक्षक	Illegal—परकानूनी
	Illwill—बैर
H	Immediately before—ठीक
Habeas Corpus—परवाना	पहले
तनतलबी	Immoveable—अचल
Habitually—आदतन	Immunity—बरीयत
Hazardous employment—	Impeach—दोश लगाना
जोखम का काम	Implement a treaty—
Head—सरमुख	सन्धिनामे पर अमल कराना
Headman—मुखिया	Import—आयासी
Health—तन्दुस्ती	Impose duty—फरज लगाना
Hearing—सुनवाई	Impose fine—जुरमाना करना
High Court—हाईकोर्ट	Impose restriction—रुकावट
Higher education—ऊँची तालीम	लगाना
Highsea—बीच समुन्दर	Impose tax—टैक्स लगाना
Highway—थल मार्ग	Imprest—पेशनगदी
His Majesty—सम्राट	Imprisonment—कैद

## भारत का विधान

Improvement trust—नगर सुधार ट्रस्ट	Indian Hemp—गांजा
In addition to—अलावा	Indian Independence Act 1947—हिन्द आज़ादी एक्ट, 1947
In appropriate cases—मुनासिब सूरतों में	Indian numerals—हिन्दु-स्तानी हिन्दसे
Incapacity—नाक़ाबिलियत	Indian origin—हिन्दी निकास
Incidental—प्रसंगी	Indian Penal Code—
Incidental matter—प्रसंगी मामला	ताज़ीरात हिन्द
Incidental provision—प्रसंगी बंधान	Indian State—देसी रियासत
In civil capacity—नागरी हैसियत से	Industrial dispute—उद्योगी मतगड़़ा
Income—आमदनी	Industrial undertaking—उद्योगी कारबार
Income tax—आमदनी टैक्स	Industrial worker—मिल मज़दूर
Incompetency—अनधिकार	Ineligible—अपात्र
Inconsistency—अनमेल होना	Infant—दुधमुँहा बच्चा
Inconsistent—बेमेल	Infectious disease—उड़नी बीमारी
Incorporate—एकतन करना	Infirmity of mind—दिमाग की कमज़ोरी
Incorporated company—एकतनी कंपनी	Inflammable—आगपकड़
Incur obligation—ज़िम्मेदारी लेना	In force, in operation—असल में
Indefinite character—अनिश्चित रूप	Inheritance—विरासत
Indemnify—बरीयत देना	In his discretion—अपनी समझ से
India—भारत, हिन्द	Initiate—शुरूआत करना
Indian Audit and Accounts Department—भारत पड़ताल और हिसाब महकमा	Injury—आघात
	Inland—देश-अन्दर

## शब्दमाला

Inn—सराय	Inter-State Council— अन्तर-रियासती मंडल
In part—कुछ इत तक	Intestacy—बेवसीयती
In particular circumstances—खास हालतों में	Intoxicating drink—नशीलापान
In personal capacity— निजी हैसियत से	Intoxicating liquor—नशीला तरल
In pursuance of—की तामील में	Introduction of a Bill— बिल का रखा जाना
Inquiry—पूछताछ	Invalid—नासरदुरुस्त
Insolvency—दिवाला	Invalidate—नासरदुरुस्त ठहराना
Insolvent—दिवालिया	Invalidity pension—निबल पेंशन
Institute proceedings— कारवाई शुरू करना	Invention—ईजाद
Institution—संस्था	Investigate—जांच करना
Instruction—हिदायत	Investigation—जांच
Instrument—पट्टा	Irregularity—बेक़ायदगी
Instrument of Accession —मिलन पट्टा	Irrigation—सिचाई
In succession—लगातार	Island—टापू
In such cases—ऐसी सूरतों में	Issue—उठावा, जारी करना, निकालना
Insurance—बीमा	Issue a Proclamation— ऐलान निकालना
Insurance policy—बीमा पालिसी	Issue a Treasury Bill— सरकारी हुंडी जारी करना
Intercourse—अन्तरव्योहार	Item—मद
Interest—सुद, सुद-ब्याज, हित, दिलचस्पी	<b>J</b>
Interfere—इखल देना	Joint Commission—मिला- जुला कमीशन
International—अन्तरक्रौमी	Joint District Judge— संगी ज़िला जज
Interpretation—अर्थ	Joint family—मिलाजुला परिवार
Inter se—आपस में	
Inter-State—अन्तर-रियासती	

भारत का विधान

Joint recruitment—मिली- जुली भरती	Lawful—क़ानूनसंगत
Joint sitting—मिलीजुली बैठक	Lease—पट्टा
Joint State Public Service Commission—मिलीजुला रिया- सत सरकारी नौकरी कमीशन	Leave, leave of absence— छुट्टी
Judge—जज	Legal—क़ानूनी
Judgment—फ़ैसला, विवेक	Legal profession—क़ानूनी पेशा
Judicial—न्यायी, अदालती	Legal right—क़ानूनी अधिकार
Judicial authority—न्यायी अधिकारी	Legal tender—क़ानूनी सिक्का
Judicial proceeding—अदा- लती कारवाई	Legislate—क़ानून बनाना
Judicial stamp—अदालती स्टाम्प	Legislative—क़ानूनकारी
Judiciary—न्यायकारी	Legislative Assembly— आम सदन
Jurisdiction—अमलदारी	Legislative Council—खास सदन
Jurist—क़ानूनशास्त्री	Legislative function— क़ानूनकारी काम
Just—न्यायी	Legislative power—क़ानून- कारी शक्ति
Justice—इन्साफ़, न्याय	Legislative relation—क़ानून- कारी संबंध
Jute—पटसन	Legislature—क़ानूनसभा
<b>L</b>	
Labour dispute—मज़दूरी झगड़ा	Leisure—फ़ुरसत
Landlord—ज़मींदार	Lend—उधार देना
Land tenure—भूमिदारी	Letter of credit—साख़ पत्र
Language—भाषा	Level of administration— शासन तल
Lapse—गिर जाना, हक़ ख़तम हो जाना	Level of nutrition—तन- पाछन तल
Law—क़ानून	Levy duty—महसूल लगाना
	Liability—देनदारी
	Liable—देनदार

Libel—अपमान लेख

Liberty—आज़ादी, स्वतंत्रता

Library—किताबघर

License—लाइसेंस

Lieutenant-Governor—

नायब रियासतपति

Lighthouse—दीपघर

Lightship—दीपजहाज़

Limit—इदियाना, सीमियाना, सीमा

Limitation—मियादबन्दी, सीमा

Line—लाइन

Liquid, liquor—तरल

List—तालिका

Literary—अदबी

Literature—अदब साहित्य

Livelihood—रोज़ी

Loan—उधारी

Local—मुकामी

Local authority—मुकामी  
अधिकारी

Local Board—मुकामी बोर्ड

Local government—मुकामी  
हकूमत

Local self-government—  
मुकामी स्वराज

Loss—घाटा

Lottery—लाटरी

Lunacy—पागलपन

Luxury—ऐश

## M

Magistrate—मैजिस्ट्रेट

Maintain—रखना, बनाए रखना

Maintain account—हिसाब  
रखना

Maintain order—व्यवस्था  
बनाए रखना

Maintain record—लेखा रखना

Major port—बड़ा बन्दरगाह

Majority—बड़ीयत

Make a loan—उधारी देना

Make order—हुकुम देना

Make payment—अदा करना

Make representation—  
अरज़ी पत्र देना

Male progenitor—जनक पुरुष

Mandamus—परवाना हुकुम

Manner—ढंग

Manufacture—बनाना

Manufactured goods—  
बना माल

Marine, maritime—समन्दरी

Maritime navigation—  
समन्दरी जहाज़रानी

Maritime shipping—  
समन्दरी जहाज़बानी

Market—मंडी

Martial law—फौजी क़ानून

Material abandonment—  
बेघरबारगी

भारत का विधान

Material resources—साही साधन	Merchandise mark— सौदागरी माल छाप
Maternity benefit—जापा रियायत	Merit—काबलियत
Maternity relief—जापा मदद	Message—संदेश
Matter—मामला	Meteorology—खगोल विद्या
Matter of procedure— दस्तूरी मामला	Mica—अबरक
Meaning—मानी	Migratory tribe—सौसमी कबीला
Means—साधन	Milch cattle—दुधारी डोर
Means of communication आवाजाई के साधन	Military—फौजी
Measure—माप, तरकीब	Military force—ज़मीनी फौज
Mechanically propelled— मशीनों से चलने वाले	Military importance— फौजी महत्व
Medical profession— डाक्टरों पेशा	Mine—खदान
Medicinal preparations— दवाई का सामान	Mineral—खनिज
Meet a grant—देनगी को पूरा करना	Mineral development— खनिज विकास
Meet an expenditure— खर्च को पूरा करना	Mineral oil—खनिज तेल
Meeting—मिलनी	Mineral resources—खनिज साधन
Member—मेम्बर	Mining settlement autho- rity—खदान आबादी अधिकारी
Membership—मेम्बरी	Minister—वज़ीर
Memorandum—यादो, यादपत्र	Ministerial authority— वज़ीरायती अधिकारी
Memorial—आवेदनपत्र	Ministry—वज़ीरायत
Mental deficiency—दिमागी कमी	Minor—नाबालिग
Mercantile marine— तिजारती बेड़ा	Minority—कमीयत
	Misbehaviour—बदव्योहार
	Miscellaneous—फुटकर

## शब्दमाला

Misconduct—बुरा चलन	National importance—
Modification—अदल बदल	क्रौमी महत्त्व
Modify—अदल बदल करना	National interest—क्रौमी हित
Money Bill—नकदी बिल	National life—क्रौमी जीवन
Money lender—साहूकार	National waterway—
Monopoly—इजारा	क्रौमी जल मार्ग
Monument—यादगार	Naturalisation—देसीकरण
Moral abandonment—	Naval force—समन्दरी फौज
नैतिक आवारगी	Navigation—जहाज़रानी
Morality—सदाचार	Neighbouring State—पड़ोसी
Mortgage—रेहन रखना	रियासत
Moveable—चल	Net proceeds—असल बसूली
Move an amendment—	Newsprint—न्यूज़प्रिन्ट
सुधार पेश करना	Nomadic—खानाबदोश
Move a resolution—ठहराव	Nominate—नामज़द करना
पेश करना	Nomination—नामज़दगी
Multiple—गुना	Non-distilled—बिनाखिंची
Municipal area—नगरायत क्षेत्र	Non-Hindi speaking area
Municipal corporation—	—यैर हिन्दीभाषी क्षेत्र
— नगर एकतनी	Non-tribals—यैर कबाइली लोग
Municipality—नगरायत	Notice—नोटिस
Municipal tramway—	Notice in writing—लिखा
नगर ट्राम मार्ग	नोटिस
Museum—अजयबख़र	Notwithstanding—के रहते
<b>N</b>	Number—गिनती, तादाद
Narcotic—पीनक वाली	Numerals—हिन्दसे
Narcotics—पीनक वाली चीज़ें	
Nation—क्रौमी	<b>0</b>
National highway—क्रौमी	Oath—इलफ़
थल मार्ग	Oath of office—पद का इलफ़

भारत का विधान

Oath of secrecy—राजदारी का हलफ़	Original jurisdiction—पहली सुनवाई का अधिकार
Obligation—ज़िम्मेदारी	Originate a Bill—बिल की
Occupation—कब्ज़ा, धन्धा	पहल करना
Occurrence of vacancy—सूनी होना	Overthrow—उलट देना
Office—पद, ओहदा, दफ़्तर	P
Officer—अफ़सर	Paid employment—वेतनी काम
Official Gazette—दफ़्तरी गज़ट	Paragraph—पैरा
Official language—दफ़्तरी भाषा	Parity—बराबरी
Official residence—सरकारी मकान	Parliament—राजपंचायत
Official trustee—सरकारी ट्रस्टी	Part—भाग
Oil field—तेल क्षेत्र	Participate—हिस्सा लेना, भाग लेना
Oilseeds—तिलहन	Partition—बटवारा
Ommission—छोड़ना	Partnership—साझेदारी
On the ground—इस बिना पर	Party—फ़रीक़
Open court—खुला इजलास	Pass—पास करना, पास होना
Operation—अमल, चलाना	Passenger—सवारी
Opinion—राय	Passport—पासपोर्ट
Opportunity—मौक़ा	Patent—पेटेन्ट
Order—हुकुम, व्यवस्था	Payment—अदायगी
Order of acquittal—बेगुनाही का हुकुम	Peace—शांति, सुलह
Ordinance—राजहुकुम	Penalty—दंड
Ordinarily—आम तौर पर	Pending—पेश, चालू
Organisation—संगठन	Pension—पेंशन
Organised peoples—संगठित क़ौमों	People—लोग
	Percentage—प्रति सैकड़ा
	Perform duty—फ़रज़ अदा करना, फ़रज़ पूरा करना



शब्दमाला

Period—अरसा	Pound—कांजी हौज़
Permanent return—पक्की वापसी	Power—शक्ति
Per mensem—माहवार	Practicable, practical—अमली
Permission—इजाज़त	Practical experience—अमली तजुर्बा
Permit—इजाज़त देना, परमिट	Preamble—सरलेख
Personal—निजी	Prefer a charge—दोशलेखा पेश करना
Personal law—निजी क़ानून	Preference—तरजीह
Personally—निजी तौर पर	Preside—सद्वारत करना
Personal right—निजी अधिकार	President—राजपति, सद्वर
Pest—महाभारी	Prevention—रोकथाम
Petition—प्रार्थना पत्र	Preventive detention—रोकथामी नज़रबन्दी
Petroleum—पेट्रोलियम	Previous sanction—पहले से मंजूरी
Pilgrimage—तीर्थ यात्रा	Previous service—पहले की नौकरी
Piracy—समन्दरी डकैती	Price control—दाम कंट्रोल
Place of birth—जन्मस्थान	Primary education—प्राइमरी तालीम
Planning—योजना	Primary school—प्राइमरी स्कूल
Plead—वकालत करना	Prime Minister (of India)—प्रधान वज़ीर (भारत का)
Pleader—प्लीडर	Prince—नरेश
Police—पुलिस	Principal seat—खास जगह
Police force—पुलिस बल	Principal value—असल क़ीमत
Policy—नीति	Principle—सिद्धान्त
Political—राजकाजी	Printing press—छपाखाना
Population—आबादी	
Port—बन्दरगाह	
Possession—कब्ज़ा	
Posting—तैनाती	
Post Office Savings Bank—डाकघर बचत बंक	
Posts and Telegraphs—डाक और तार	

## भारत का विधान

Prison—जेलखाना	Proportion—निसबत, हिस्सा
Prisoner—कैदी	Proportional representa- tion—निसबती प्रतिनिधान
Privilege—निजनियम	Proposal—सुझाव
Privy Council—प्रिवी कौंसिल	Prorogation of the House —सदन का बरखास्त होना
Privy purse—निजी थैली	Prorogue—बरखास्त करना
Procedure—दस्तूर	Prosecution of war—जंग चलाना
Procedure in general— आम दस्तूर	Prospect for minerals— खनिजों की खोज
Proceeding—कारवाई	Protection—रक्षा
Proceeds—वसूली	Prove—साबित करना
Process—हुकुमनामा	Provide—प्रबन्ध करना, बताना, बन्धान करना
Proclamation—ऐलान	Provided that—शर्तें कि
Proclamation of emer- gency—अचानकी का ऐलान	Provident fund—प्राविडेन्ट फंड
Product—पैदावार	Province—सूबा
Profession—पेशा	Provision—इन्तज़ाम, प्रबन्ध, बंधान
Professional—पेशाई	Provisional—कामचलाक
Prohibition—परवाना मनाही, मनाही	Provisional Legislature— कामचलाक कानूनसभा
Promissory note—प्रामिसरी नोट	Provisional Parliament— कामचलाक राजपंचायत
Promotion—तरक्की	Proviso—शर्त
Promulgate—जारी करना	Proxy—एवज़ी
Pronounce judgment—फ़ैसला सुनाना	Public—जनता, सरकारी, आम
Proof—सबूत	Public debt—सरकारी करज़ा
Propagate—प्रचार करना	Public health—जन-तन्दुस्ती
Property—जायदाद	
Property in goods—माल की मिलकियत	

## शब्दमाला

Public importance—लोक महत्व	Railway Company—रेलमार्ग
Public institution—जनसंस्था, जनता की संस्था	कंपनी Raise a loan—उधारी लेना
Public interest—जनहित, जनता का हित	Raise money—रकम जुटाना Rajpramukh—राजप्रमुख
Public notification—आम नोटिस	Rank—रतबा Rate—दर
Public order—जन-व्यवस्था	Ratify—तसदीक करना
Public Service Commi- ssion—सरकारी नौकरी कमीशन	Ratio—अनुपात Readjust—घटत बढ़त करना
Publish—निकालना	Reasonable—उचित
Punishment—सजा	Receipt—रसीद, आमदनी
Purchase—खरीद	Recess—छुट्टी के दिन
Purpose—मतलब	Recognise—मान लेना
<b>Q</b>	Recognised institution— मानी हुई संस्था
Qualification—जोगता	Recommendation—सिफारिश
Qualified—जोग	Reconsideration—फिर से विचार
Quarantine—बालीसिया	Records—लेखे
Question—सवाल	Recurring sum—फिराती रकम
Question of fact—वाक्याती सवाल	Recruitment—भरती
Question of law—कानूनी सवाल	Redemption charges— भुगतान खर्चे
Quorum—कोरम	Redemption of debt—करजा
Quotient—भागफल	चुकाना, करजा भुगतान
Quo Warranto—परवाना अधिकार- बताई	Reformatory—सुधारघर
<b>R</b>	Region—इलाका
Race—नसल	Regional Commissioner— इलाका कमिशनर
Railway—रेलमार्ग	

## भारत का विधान

Regional Council—इलाका मंडल	Remuneration—मेहनताना
Regional fund—इलाका कोश	Rent—लगान, किराया
Register—रजिस्टर करना	Repeal—रद्द, रद्द करना
Registration—रजिस्ट्री	Report—रिपोर्ट
Regulate—क्रायदाबन्दी करना	Representation—प्रतिनिधान, अरज़ी पत्र
Regulation—क्रायदा, क्रायदाबन्दी	Representative—प्रतिनिधि
Rehabilitation—फिरबसाव	Republic—जनराज
Reimburse a person for his expenses—किसी के खर्च को पूरा करना	Repugnant—खिलाफ़
	Require attendance—हाज़िरी तलब करना
Relevant—संगत	Requisition—मंगैनी ले लेना
Relief—मद्द, भरपाई	Research—खोज
Religion—धर्म	Reservation—अलग रखना
Religious—धार्मिक	Reserve Bank of India—भारत का रिज़र्व बैंक
Religious denomination—धार्मिक फ़िरका	Reserved forest—रखाया हुआ जंगल
Religious endowment—धार्मिक देन	Reserved seat—अलग रखी सीट
Religious institution—धार्मिक संस्था	Reserve for consideration—विचार के लिए रख देना
Religious instruction—धार्मिक शिक्षा	Reserve seats—सीटें अलग रखना
Remainder—बाक़ी	Reside—बसना, रहना
Remains—खंडहर	Residence—रिहाइस
Remedy—उपाय	Resident—बासी, बसने वाले, रहने वाले
Remission of tax—टैक्स में छूट देना	Residential—रिहाइस
Remit a sentence—सज़ा को कम कर देना	Residuary power—बचो शक्ति

शब्दमाला

Resign—इस्तीफा देना	Sale—बिक्री
Resolution—ठहराव	Sanad—सनद्
Responsible—ज़िम्मेदार	Sanction—मंजूरी
Restaurant—जलपान घर	Sanitation—सफ़ाई
Restriction—रुकावट	Save—सिवाय
Retail business—फुटकर कारबार	Saving—बचाव
Retired—सेवामुक्त	Scale—पैमाना
Retrospective effect— पिछलगता असर	Scarcity of goods—माल की कमी
Return—ज्यौरा	Schedule—पट्टी
Revenue—मालयुजारी	Scheduled—पट्टीदर्ज
Revenue jurisdiction— माली अमलदारी	Scheduled caste—पट्टीदर्ज जाति
Review—नज़रसानी	Scheduled tribe—पट्टीदर्ज क्रबीला
Revoke—मंसूख करना	Scheme—योजना
Right—अधिकार	School—स्कूल
Right of audience—सुनवाई का अधिकार	Science—साइंस
River valley—नदी घाटी	Scientific—साइंसी
Road—सड़क	Scientific education— साइंसी तालीम
Ropeway—रस्सा मार्ग	Scientific line—साइंसी रीति
Royalty—रायल्टी	Script—लिखावट
Rule—नियम	Seal—मोहर
Rule of the road—मार्ग नियम	Seaman—मल्लाह
Ruler—शासक	Seat—जगह
S	Secondary school—दूसरी स्कूल
Safeguard—बचावनी	Secrecy—राज्यदारी
Safety—सलामती	Secretarial staff—मंत्रायती अमला
Salary—तनखाह	

## भारत का विधान

Secretariat—मंत्रालय	Site—स्थान
Secretary of State—स्टेट सेक्रेटरी	Sitting—बैठक
Secret ballot—बन्द परची	Situation—हालत
Section—टुकड़ी	Slander—अपमान वचन
Security—सुरक्षा, जमानत, हुंडी	Small Cause Court— खफ़ीफ़ा अदालत
Select—छंटना	Social—समाजी
Self-government—स्वराज	Social injustice—समाजी अन्याय
Sentence—सज़ा का हुकुम	Social insurance—समाजी बीमा
Service—सेवा, नौकरी	Socially—समाजी निगाह से
Service of debt—करज़ा जारी रखना	Social order—समाजी व्यवस्था
Session—इजलास	Social reform—समाज सुधार
Session of Legislature— क्रानूनसभा का इजलास	Social service—समाज सेवा
Sessions Judge—सेशन जज	Social welfare—समाज की भलाई
Settle—बस जाना	Society—सोसाइटी
Sex—जिन्स	Solemnly—गंभीरता के साथ
Share—हिस्सा	Sovereign—खुदमालिक
Sheriff—शेरीफ़	Speaker—सभामुख
Shifting cultivation— बदलती जुताई	Special—खास, विशेष
Shipping—जहाज़, जहाज़बानी	Special address—खास सरबचन
Short title—छोटा सरनामा	Special directive—खास निर्देश
Signed certificate—दसखती सनद	Special electoral roll— खास चुनाव चिट्ठा
Single judge—अकेला जज	Special knowledge—खास जानकारी
Single transferable vote— इकहरा बदलता वोट	Special procedure—खास दस्तूर
Sinking fund—करज़ा चुकाई कोश	Special provision—खास बन्धान

## शब्दमाला

Special qualification— खास जोगता	Subordinate court—मातहत अदालत
Special representation— खास प्रतिनिधान	Substantial question of law—कानून का ठोस सवाल
Spoilation—छूट खसोट	Succession—पदगाहन, विरासत
Staff—अमला	Successor—पदगाही, वारिस
Stamp duty—स्टाम्प महसूल	Sue—नालिश करना
Standard—दर्जा, स्तर, मान	Suit—नालिश
Standard of living—जीवनस्तर	Suitor—सायल
Standard of quality—गुनमान	Superintendence—निगरानी
Standing order—क्रायमी हुकुम	Supplemental power—पूरक शक्ति
State—रियासत	Supplemental, suppleme- ntary—पूरक
State List—रियासत तालिका	Supplementary expendi- ture—पूरक खच
Statement—ब्यौरा	Supplementary grant— पूरक देनगी
State Public Service Com- mission—रियासत सरकारी नौकरी कमीशन	Supply—मुद्दया करना, रसद
Statistics—आंकड़े	Support—समर्थन करना
Status—दर्जा	Supreme Command—आला कमान
Stay of proceedings—कार- वाई रोक देना	Supreme Court—आला अदालत
Steel—फ़ौलाद	Surcharge—अधिक टैक्स
Stock—पत्तीपूजी, नसल ( मवेशियों की )	Survey—सरवे
Stock exchange—शेयर बाज़ार	Suspend—मुअत्तल करना, रोक देना
Style—शैली	Suspend a meeting—मिलनी को रोक देना
Sub-clause—उपधारा	Suspend a sentence—सज़ा के हुकुम को रोक देना
Sub-Divisional Officer— सबडिवीज़नल अफ़सर	
Subordinate—मातहत, अधीन	

## भारत का विधान

Swear—शपथ लेना	Through—भारकृत
<b>T</b>	Tidal waters—ज्वार जल
Table—नक्शा	Title—खिताब, सरनामा
Take step—कदम उठाना	Toilet—सिंघार
Tax—टैक्स	Toilet preparation—सिंघार सामान
Tax on income—आमदनी पर टैक्स	Tolls—टोल टैक्स
Technical—तकनीकी	Town—क़सबा
Technical education—तकनीकी तालीम	Town Committee—क़सबा कमेटी
Telephone—टेलीफ़ोन	Tract—ख़िस्ता
Temporary—आरज़ी	Trade—ब्योपार
Tenant—किसान	Trademark—ब्योपार छाप
Tendency—झुकाव	Trader—ब्योपारी
Tender age—कच्ची उमर	Trade Union—ट्रेड यूनियन
Term—शर्त, बंधन, मियाद	Trading corporation—ब्योपारी एकतनी
Terminal tax—हदवारी टैक्स	Traffic—ब्यापार
Terminate—ख़तम करना	Training—ट्रेनिंग
Term of office—पद-मियाद	Tramcar—ट्रामगाड़ी
Territorial—भूभागी	Tramway—ट्राममार्ग
Territorial constituency—भूभागी चुनाव हलक़ा	Transaction—सौदा
Territorial waters—भूभागी जल, भूभागी समन्दर	Transfer—बदलो करना, तबादला, तबदीलना, दाखिल खारिज
Territory—भूभाग	Transitional—बिचवक्ती
The State (as defined in Part III)—राज	Transitional provision—बिचवक्ती बंधान
Things of value—कीमती चीज़ें	Translation—अनुवाद
Thought—बिचार	Transport—छाना ले जाना
	Transporation for life—आजीवन काकापानी



शब्दमाला

Treasure trove—गड़ा लावारिसी खज़ाना	Uniformity—एकरूपता
Treasury Bill—सरकारी हुंडी	Union—यूनियन
Treaty—संधिनामा	Union List—यूनियन तालिका
Treaty obligations—संधि बंधन	Union Public Service Commission—यूनियन सरकारी नौकरी कमीशन
Trespass—हद लांघना	Unit—इकाई
Trial—जांच	United Khasi and Jaintia Hills District—युक्त खासी जैन्तिया पहाड़ी ज़िला
Tribal—क्रबाइली	United Nations Organisation—संयुक्त कौम संगठन
Tribal Council—क्रबाइली मंडल	Unity—एकता
Tribals—क्रबाइली लोग	University—विद्यापीठ
Tribe—कबीला	Unsound mind—नाठीक दिमाग
Tribes Advisory Council—कबीला सलाहकार मंडल	Unsoundness of mind—दिमाग ठीक न होना
Tribunal—पंच अदालत, पंचायती अदालत	Untouchability—अछूतपन
Trust—ट्रस्ट, भरोसा	Uprajpramukh—उपराजप्रमुख
Trustee—ट्रस्टी	Usage—रिवाज
U	Use—इस्तेमाल
Undermine—जड़ खोखली करना	V
Undertaking—कारबार	Vacancy—सूनी
Undeserved want—अनकरी ज़रूरत	Vacate—सूना करना
Unemployment—बेकारी, बेकामगारी	Vacation—तातील
Unexpected demand—अचानक मांग	Vagrancy—आवारागरदी
Unforeseen expenditure—अनसूझा खर्च	Validate—सरदुरुस्त ठहराना
Unginned cotton—अनबोटी रुई, कपास	Validity—सरदुरुस्ती
	Valley—घाटी
	Vehicle—गाड़ी

## भारत का विधान

Vessel—जहाज़	Waterway—जलमार्ग
Veterinary—पशु-इलाज	Ways and means advance— राष्ट्रीय पेशगी
Vice-President—उपराजपति	Weaker section—निबल टुकड़ी
Village administration— गांव शासन	Weight—तोल
Village committee—गांव कमेटी	Weights—तोलने के बाट
Village council—गांव मंडल	Welfare—भलाई, खुशहाली
Village court—गांव अदालत	Wholesale business— थोक कारबार
Violation of Constitu- tion—विधान तोड़ना	Will—वसीयत
Violation of law—क़ानून तोड़ना	Wind up—समेटना
Visa—वीसा	Wireless—बेतार
Vital statistics—जीवन आंकड़े	Withdraw a case—मुक़दमा उठा लेना
Vocabulary—शब्दावली	Withdrawal of money— रुपया निकालना
Vocation—रोज़गार	Worker—कामगार
Void—रद्द	Workmen's compensation —कामगारों की मुक़दमा भरपाई
Voluntarily—अपनी मरज़ी से, अपनी इच्छा से	Works—कारख़ाना, इमारत
Vote—वोट, वोट देना	Worship—पूजाबंदगी
Voter—वोटर	Wound pension—घायली पेंशन
<b>W</b>	Writ—परवाना
War—जंग	Writing under ones hand —दसखती लिखना
Warrant—हुक़मनामा	<b>Z</b>
Water power—पनशक्ति	Zoology—जन्तुबिद्या